



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष



मध्य प्रदेश शासन
2024 का प्रतिवेदन संख्या 10
(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**

मध्य प्रदेश शासन

2024 का प्रतिवेदन संख्या 10

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
अध्याय I-विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय	1.3	3
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	6
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	1.7	8
अभिस्वीकृति	1.8	15
अध्याय II-अनुपालन लेखापरीक्षा		
राजस्व विभाग		
प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा	2.1	17
शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा	2.2	47
श्रम विभाग		
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा	2.3	85

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण	123
1.2	व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु बकाया कंडिकाओं का विभागवार विवरण	125
1.3	31 मार्च 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थी	126
2.1.1	योजनावार व्यय का विवरण	128
2.1.2 (क)	सिवनी जिले में वित्तीय सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का विवरण	129
2.1.2 (ख)	सिवनी जिले में वेतन मद से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	131
2.1.2 (ग)	सिवनी जिले में ओलावृष्टि, बाढ़/अतिवृष्टि हेतु संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	133
2.1.3 (क)	श्योपुर जिले की बड़ौदा और श्योपुर तहसीलों में किए गए संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण- लाभार्थियों के नामों में विसंगति	134
2.1.3 (ख)	श्योपुर जिले की बड़ौदा और कराहल तहसीलों में अन्य संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण	140
2.1.4	सीहोर जिले की तहसीलों में किये गये संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	143
2.1.5 (क)	शिवपुरी जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	145
2.1.5 (ख)	शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में वेतन एवं अन्य मदों से संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण का विवरण	150
2.1.6	देवास जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण राहत वितरण का विवरण	154
2.1.7	छतरपुर जिले में रिफंड, सूखा एवं अतिवृष्टि संबंधी बिलों के	158

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	माध्यम से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	
2.1.8	खंडवा जिले की खालवा तहसील में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	159
2.1.9 (क)	मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ और सीतामऊ तहसीलों में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण- लाभार्थियों के नामों में विसंगति	160
2.1.9 (ख)	मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	161
2.1.9 (ग)	मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील में रिफंड बिलों से संदिग्ध कपटपूर्ण निकासी	162
2.1.10 (क)	रायसेन जिले में राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति	164
2.1.10 (ख)	रायसेन जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत राशि के संदेहस्पद कपटपूर्ण भुगतान	165
2.1.11 (क)	दमोह जिले में संदिग्ध कपटपूर्णता भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति	166
2.1.11 (ख)	दमोह जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान	167
2.1.12	सतना जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	168
2.1.13 (क)	आगर-मालवा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति	169
2.1.13 (ख)	आगर-मालवा जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान	170
2.1.14	विदिशा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	171
2.1.15	शिवपुरी जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण	174
2.1.16	देवास जिले में एकाधिक लेनदेन के माध्यम से अनियमित	176

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	संवितरण का विवरण	
2.1.17	देवास जिले की बागली तहसील में अनियमित वितरण का विवरण	177
2.1.18	विदिशा जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण	178
2.1.19	खंडवा जिले में समितियों के खातों में ₹164.31 करोड़ जमा करने का विवरण	183
2.1.20	सहकारी समितियों और तहसीलदारों के आंकड़ों के बीच ₹ 8.28 करोड़ की विसंगति का विवरण	187
2.1.21	तहसीलदारों द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से परे किए गए भुगतान का विवरण	189
2.2.1 (क)	चयनित जिलों, तहसीलों और ग्रामों की सूची	195
2.2.1 (ख)	संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित स्थलों की सूची	196
2.2.2	मार्गदर्शिका दरों के गलत अनुप्रयोग द्वारा बाजार मूल्य का कम मूल्यांकन	204
2.2.3	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. को शून्य प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि	205
2.2.4	प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम मूल्यांकन और बकाया राशि पर ब्याज का अनारोपण	209
2.2.5	स्थायी पट्टे का नवीनीकरण न होने से शासकीय राजस्व की हानि	211
2.2.6	म.प्र. राज्य भण्डारगृह निगम को भूमि आवंटन पर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का अनारोपण	225
2.2.7	शास्ति लगाने और आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि को खाली न करना/ शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा जारी रखने पर शास्ति की वसूली न करना	228
2.2.8	राज्य शासन के विभागों को आवंटित शासकीय भूमि का	231

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अनुपयोगी रहना	
2.2.9	राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर शासकीय भूमि की हानि	233
2.2.10	जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए और मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल में दर्शाए गए आंकड़ों में अंतर (31 मार्च 2022 की स्थिति में)	236
2.2.11	एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का पालन न करने के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ	237
2.3.1	चयनित जिलों, जनपद पंचायत/नगर निगम/पालिका एवं ग्राम पंचायत/वार्ड का विवरण	238
2.3.2	अपील प्रकरणों जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने आवेदक को पंजीकरण के लिए पात्र घोषित किया का विवरण	239
2.3.3	असंगठित श्रमिकों के लंबित भौतिक सत्यापन का विवरण	240
2.3.4	व्यक्तियों जो मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य नहीं थे के बैंक खातों में किए गए भुगतान का विवरण	241
2.3.5	प्रकरणों जिनमें संबल एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दोनों योजनाओं से सहायता राशि का भुगतान किया गया का विवरण	242
2.3.6	प्रकरणों जिनमें संबल लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता का भुगतान किया गया का विवरण	252
2.3.7	प्रकरणों जिनमें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को संबल योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता स्वीकृत की गई का विवरण	265
2.3.8	प्रकरणों जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण	267
2.3.9	प्रकरणों जिनमें अनुग्रह सहायता का भुगतान अधिक दर पर किया गया का विवरण	270
2.3.10	प्रकरणों जिनमें सहायता का दोहरा भुगतान किया गया का	276

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	विवरण	
2.3.11	प्रकरणों जिनमें श्रमिक की मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया एवं उत्तराधिकारी को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण	277
2.3.12	प्रकरणों जिनमें गलत उत्तराधिकारी को सहायता का भुगतान किया गया का विवरण	281
2.3.13	चयनित शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्था वार प्रकरणों जिसमें अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया गया की संख्या दर्शाने वाला विवरण	284
2.3.14	चयनित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त, उपयोग किये गए एवं अव्ययित निधि का विवरण	285
2.3.15 (क)	प्रकरणों जिनमें पदाभिहित अधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ से इनकार किया का विवरण	288
2.3.15 (ख)	प्रकरणों जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ अस्वीकृत कर दिया का विवरण	291
	संक्षिप्तों की शब्दावली	294

प्राक्कथन

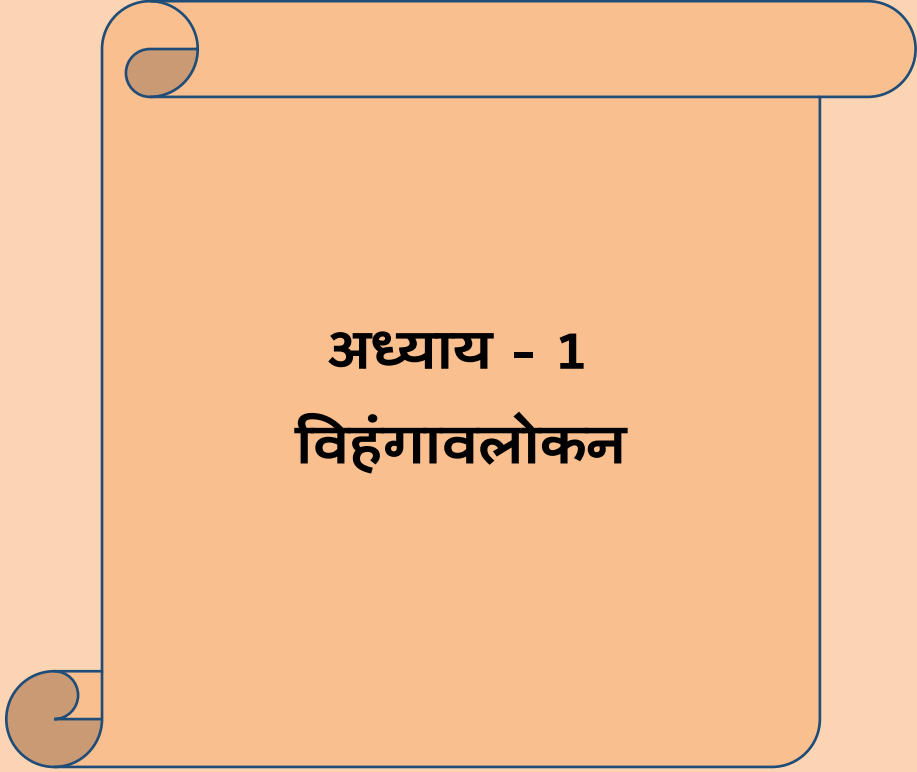
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिये, यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश के राजस्व और श्रम विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाहित हैं। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2021-22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए। वे मामले जो पिछले वर्षों में जानकारी में आए थे, लेकिन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाये जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उल्लिखित तथ्य मान्य होंगे।



अध्याय - 1
विहंगावलोकन

अध्याय-I : विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न लेखापरीक्षित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ ऐसे निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना और कार्यक्षेत्र, लेन-देन की लेखापरीक्षा के दौरान किए गए निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों और सरकार की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

वर्ष 2019-22 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से 33¹ लेखापरीक्षित विभागों द्वारा किए गए व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका: 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1.	स्कूल शिक्षा विभाग	19,046.17	20,953.88	22,286.89
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	24,663.38	24,194.34	20,367.12
3.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	15,172.39	13,706.75	15,553.35
4.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6,762.62	7,226.08	9,719.12
5.	जनजातीय कार्य विभाग	7,448.83	6,858.82	7,364.68
6.	गृह विभाग	7,258.04	7,338.56	7,350.06
7.	राजस्व विभाग	7,796.97	12,095.11	7,287.22
8.	जल संसाधन विभाग	7,182.45	6,251.08	6,603.61
9.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	3,224.97	5,031.95	4,776.21
10.	महिला एवं बाल विकास विभाग	4,659.36	4,833.02	4,774.85

¹ मध्यप्रदेश शासन के 55 विभागों में से शेष 22 महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में हैं।

क्र.सं.	विभाग का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
11.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	749.07	668.90	3,787.15
12.	उच्च शिक्षा विभाग	2,218.28	2,634.92	2,736.97
13.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,033.95	1,770.65	2,033.93
14.	सहकारिता विभाग	501.41	582.00	1,711.23
15.	श्रम विभाग	778.87	938.05	1,601.76
16.	कानून एवं विधायी कार्य विभाग	1,626.13	1,537.62	1,504.63
17.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	1,062.49	1,282.96	1,488.06
18.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	854.10	896.15	1,399.96
19.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	958.78	864.69	1,291.24
20.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	948.19	967.50	1,127.88
21.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	987.64	849.76	914.03
22.	सामान्य प्रशासन विभाग	597.72	602.77	668.83
23.	आयुष विभाग	511.04	436.03	577.74
24.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	617.20	406.98	463.13
25.	जेल विभाग	383.63	423.91	447.13
26.	जनसंपर्क विभाग	330.49	331.48	369.88
27.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	139.25	145.26	199.61
28.	मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग	80.08	112.46	156.18
29.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग	102.75	109.98	117.44
30.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ²	121.60	92.09	89.06
31.	संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग	81.48	80.49	78.47
32.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	53.82	47.83	47.49
33.	विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण विभाग	18.43	17.57	18.44
कुल		1,18,971.58	1,24,289.64	1,28,913.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के विनियोग खाते और वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन से एकत्रित आँकड़े)

² दो निदेशालय अर्थात हथकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय तथा रेशम उत्पादन निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के अधीन हैं। रेशम उत्पादन निदेशालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), मध्य प्रदेश के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन है।

1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से 33 विभागों के साथ-साथ आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) एवं तीन स्वायत्त निकायों³ की लेखापरीक्षा की जाती है।



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13⁴ के तहत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)⁵ के अन्तर्गत की जाती है;

³ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (50 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित)।

⁴ (i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन-देन (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन तथा (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना-पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

⁵ सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

- **स्वायत्त निकायों** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी अधिनियम की धारा 19(2)⁶ और 20(1)⁷ के अन्तर्गत की जाती है;
- **स्थानीय निकायों** की लेखा परीक्षा डी.पी.सी अधिनियम की धारा 20(1) के तहत की जाती है;
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14⁸ के अन्तर्गत शासन द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित **अन्य स्वायत्त निकायों** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया निम्न चित्र दर्शाता है:

⁶ राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की संबंधित विधान के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा।

⁷ राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे निबंधनो एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों, की लेखापरीक्षा।

⁸ (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा
(ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो, के प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

चित्र 1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी

जोखिम का आकलन - इकाईयों/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिये योजना, जोखिम आकलन में शामिल कुछ मानदंडों पर आधारित है जैसे,

- किया गया व्यय
- लेखापरीक्षा का अंतराल
- गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिये दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रण का आकलन
- हितधारकों का हित, आदि

लेखापरीक्षा की योजना में विनिश्चित करना शामिल है

- लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रकार- वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा इकाईयों एवं लेन-देनों का नमूना चयन

निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/ आँकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख /स्थानीय प्रबंधन से चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो निरीक्षण प्रतिवेदनों या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, एवं
- राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यपाल को सौंपा जाना।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुये इकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं,

लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत हो जाते हैं या अनुपालन के लिये आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्भावित समावेश के पूर्व, शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये प्रारूप कंडिकाओं के रूप में जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाने हेतु सौंपे जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों और अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदन में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अंतरालो पर जिला/राज्य स्तर पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2023 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 13,839 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 51,746 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थीं जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से 1,775 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 9,113 कंडिकाओं (17.61 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुये। विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.2

वर्ष	31 मार्च 2023 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या		31 मार्च 2023 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकायें जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये।	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
2017-18 एवं पूर्व वर्षों में	11,964	38,521	1,051	4,231
2018-19	772	4,949	197	1,030
2019-20	1,072	8,033	497	3,629
2020-21	31	243	30	223
कुल योग	13,839	51,746	1,775	9,113

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को बनाये रखने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय, कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिये, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनो एवं कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिये एवं इनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर इनकी प्राप्ति से विशिष्ट समयावधि⁹ के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। हमने इन तीन प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो को, विभागों¹⁰ के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किया था। यह उनके वैयक्तिक ध्यान में लाया गया था कि यह प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्भवतः भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना वांछनीय होगा। विभाग द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर दिये गये प्रत्युत्तरो को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह¹¹ के भीतर, की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही को अंकित करते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित आठ विभागों के 20 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थी विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

⁹ लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2020 की कंडिका 137 एवं 138 के अनुसार

¹⁰ श्रम विभाग एवं राजस्व विभाग।

¹¹ भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.30 के अनुसार।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की दिनांक से छः माह¹² के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मार्च 2023 की स्थिति में, 14 विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 60 कंडिकाओं पर 28 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के दो विभागों¹³ के लेखों एवं लेन-देनों की नमूना जाँच से उद्भूत तीन अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम का सार नीचे दिया गया है:

1.7.1 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश शासन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, असमय वर्षा, पाला, शीतलहर, कीट, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (आर.बी.सी. 6-4) के माध्यम से प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को देय अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा तथा मानदंड निर्धारित किए हैं।

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के रूप में ₹10,060 करोड़ की राशि वितरित की।

चयनित 13 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के तहत वितरित विभिन्न राहतों से संबंधित अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नानुसार है :

हमने चयनित 13 जिलों में कर्मचारियों एवं उनके रिश्तेदारों सहित अनधिकृत व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत के लिए ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण पाया। जाली स्वीकृति आदेश तैयार करके, वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में राहत का भुगतान करके, ई-भुगतान में लाभार्थियों के जाली नामों का उपयोग करके कपटपूर्ण लेनदेन किए गए, जबकि ये खाते बैंक अभिलेखों में अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। ग्लोबल बजट प्रणाली तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

¹² भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन के कंडिका 4.33 के अनुसार।

¹³ श्रम विभाग एवं राजस्व विभाग।

(आई.एफ.एम.आई.एस.) की कमियों ने कर्मचारियों को शासकीय धन को गबन करने में सक्षम बनाया।

(कंडिका 2.1.8.5)

लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राहत जमा करने के भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, खंडवा जिले के सभी तहसीलदारों ने अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति की राहत राशि वितरित करने के लिए 105 सहकारी समितियों को ₹164.31 करोड़ का भुगतान किया। इन समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमें लाभार्थियों की उचित पहचान के बिना भुगतान, तहसीलदारों एवं सहकारी समितियों के आंकड़ों के बीच ₹8.28 करोड़ की विसंगति तथा ₹4.93 करोड़ के अधिक भुगतान जैसी अनियमितताएं मिलीं।

(कंडिका 2.1.10)

आठ जिलों (आगर-मालवा, दमोह, देवास, रायसेन, सतना, सीहोर, शिवपुरी, विदिशा) में, हमने सूखे तथा कीट प्रकोप से प्रभावित 6.91 लाख लोगों को ₹563.72 करोड़ की राहत राशि के वितरण में छः माह से 29 माह तक का विलम्ब पाया, जिसने इन योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया।

(कंडिका 2.1.14)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणालीगत कमियाँ जैसे कि ग्लोबल बजटिंग में कमी, आई.एफ.एम.आई.एस. में खामियाँ और बिलों के साथ हानि पत्रक एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन जैसे आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न न होना, कपटपूर्ण भुगतान की घटना को सक्षम बनाया।

(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4)

अनुशंसाओं का सारांश

मध्य प्रदेश शासन को पर्यवेक्षी अधिकारियों सहित जिम्मेदार अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अनुकरणीय दंड देना चाहिए और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से उन जिलों में जांच शुरू करनी चाहिए, जो लेखापरीक्षा में शामिल नहीं थे। इसके अलावा, शासन को भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ग्लोबल बजट प्रणाली तथा आई.एफ.एम.आई.एस. की कमियों की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए।

1.7.2 शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, निजी निकायों/व्यक्तियों, राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों, चैरिटेबल संस्थानों आदि को शासकीय भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959, राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.), मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 (24-09-2020 से प्रभावी), शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्रों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की उचित जांच के बाद, आवश्यकता का आकलन एवं

निश्चित मानदंडों की पूर्ति के अधीन, विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों के संबंध में निर्दिष्ट दरों पर प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया के भुगतान पर अस्थायी या स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटित की जाती है।

आठ चयनित जिलों में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:

जिला भोपाल की हुजुर तहसील (ग्रामीण) में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बेंगलुरु को बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए 20.234 हेक्टेयर भू-खंड के आवंटन के प्रकरण में भू-खंड के बाजार मूल्य के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरूप प्रीमियम, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के कम आरोपण/कम भुगतान के परिणामस्वरूप शासकीय कोष को ₹ 65.05 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 2.2.6.1)

कलेक्ट्रेट धार में लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आई.एच.बी.एल. इंदौर को भूमि आवंटन के एक प्रकरण में, बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत इंद्रावल में आवंटित 3.750 हेक्टेयर भू-खंड के सम्बन्ध में निर्धारित प्रीमियम एवं पट्टा किराया पर पंचायत उपकर नहीं लगाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 70.13 लाख की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 2.2.6.2)

जिला इंदौर के ग्राम बड़ा बांगड़दा में एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर शासकीय भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ के प्रीमियम एवं ₹ 4.18 लाख प्रति वर्ष के वार्षिक पट्टा किराये की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.7.1)

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर भूमि आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 26.64 करोड़ राजस्व की हानि हुई/राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 2.2.7.2)

स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर शासकीय भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप प्रीमियम (₹ 12.94 लाख) एवं वार्षिक पट्टा किराया (₹ 25,889 प्रति वर्ष) की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 2.2.7.3)

कलेक्ट्रेट जबलपुर एवं शहडोल के नौ भूमि आवंटन प्रकरणों (फरवरी 2020 एवं जनवरी 2021) में एम.पी. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को शून्य प्रीमियम एवं शून्य वार्षिक पट्टा किराये पर अस्थायी कैम्प/सायलो-बैग बनाने हेतु 68.966 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 1.75 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.7.4)

अनुगामी अधिसूचना के संदर्भ में प्रकरण को पुनः खोलने एवं राजस्व की राशि का पुनर्मूल्यांकन करके पट्टेदार को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 0.86 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.8.1)

प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराये के कम निर्धारण तथा बकाया राशि पर ब्याज के अनारोपण के कारण मध्यप्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल से वसूली योग्य राशि ₹ 3.99 करोड़ थी।

(कंडिका 2.2.8.2)

पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के संबंध में उचित कार्रवाई प्रारम्भ न करने के कारण पट्टेदारों से कुल राशि ₹ 93.86 लाख का राजस्व वसूल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.8.3)

मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को 25.620 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पर (कलेक्ट्रेट शहडोल एवं सिंगरौली के नौ प्रकरणों में) निर्दिष्ट दरों पर प्रीमियम, वार्षिक पट्टा किराया एवं पंचायत उपकर नहीं लगाने के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.8.4)

वल्लभ भवन एवं कलेक्ट्रेट भोपाल के समीपस्थ तीन इलाकों में, 10 सर्वे नंबरों वाली 37.69 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर झुग्गीवासियों ने अस्थायी शिविर एवं संरचनाएं बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। कार्रवाई शुरू न करने/शास्ति न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 322.71 करोड़ के बाजार मूल्य की शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा हो गया।

(कंडिका 2.2.9.1)

चयनित आठ जिलों की 23 तहसीलों में 2,371 प्रकरणों के नमूना जाँच में पता चला कि सम्बंधित तहसीलदारों ने 2,364 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित करते हुए बेदखली आदेश जारी किए थे लेकिन 1,037 प्रकरणों में अधिरोपित शास्ति की राशि ₹38.64 लाख की वसूली नहीं की गयी

थी। इसके अलावा पहले बेदखली आदेश की दिनांक से अनधिकृत कब्जा जारी रहने के कारण कुल मिलकर ₹71.68 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 2.2.9.2)

आवंटन के दिनांक से 77 वर्षों के पश्चात भी रॉबर्ट नर्सिंग होम, इंदौर द्वारा 0.8 हेक्टेयर (8,093 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग न करना इंगित करता है कि बाज़ार मूल्य ₹38.85 करोड़ की उपरोक्त भूमि पट्टेदार की वास्तविक आवश्यकता से अधिक थी।

(कंडिका 2.2.10.1)

मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम (एम.पी.आई.डी.सी.) को हस्तांतरित भूमि उपयोग न होने की स्थिति में वापस नहीं ली गई।

(कंडिका 2.2.10.2)

सात जिलों की 12 तहसीलों के 15 गांवों के 66 प्रकरणों में भौतिक रूप से संधारित खसरे एवं ऑनलाइन वर्तमान खसरे में क्षेत्रफल की विसंगति देखी गई। 23 प्रकरणों में शासकीय भूमि का क्षेत्रफल कम (0.01 हेक्टेयर से 5.695 हेक्टेयर) हुआ, जबकि 43 प्रकरणों में संबंधित खसरे का क्षेत्रफल में वृद्धि (0.002 हेक्टेयर से 20.264 हेक्टेयर) हुई। क्षेत्रफल में उपरोक्त विसंगति से भविष्य में मुकदमेबाजी और शासकीय भूमि की हानि हो सकती है।

(कंडिका 2.2.11.1)

विकासकर्ता को अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क (₹ 2.35 करोड़) एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 37.60 लाख) का कम आरोपण/वसूली नहीं हुई तथा एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ई.एम.डी. ₹ 70 लाख कम जमा हुई और राजस्व शीर्ष “0029-भूमि राजस्व” के तहत ₹ 71 करोड़ का प्रीमियम जमा करने में अनुचित छूट मिली।

(कंडिका 2.2.12.4)

अनुशंसाओं का सारांश

शासन को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रीमियम के साथ-साथ किराये पर पंचायत उपकर लगाने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निर्माण कार्य के समापन हेतु अधिकतम अवधि निर्धारित करते हुए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा, शासन को शासकीय भूमि के आवंटन हेतु आवेदनों के निराकरण के लिए एक समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है। विभाग को शासकीय भूमि के अभिलेखों के रखरखाव में खामियों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए।

1.7.3 मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने असंगठित श्रमिकों (श्रमिक जो किसी रोजगार, स्व-रोजगार अथवा अस्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे हुए हैं एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी इत्यादि के हकदार नहीं हैं तथा सरकारी सेवा में/करदाता नहीं होना चाहिए एवं एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना (अप्रैल 2018) लागू की। संबल योजना में, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन चार श्रेणियों अर्थात् अंत्येष्टि सहायता, अपंगता/मृत्यु के प्रकरण में अनुग्रह सहायता, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। संबल योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिलक्षित हुए जैसी नीचे चर्चा की गई है:

विभाग ने श्रमिकों के पंजीकरण के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान 2.18 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से 67.48 लाख (31 प्रतिशत) को विभिन्न कारणों जैसे आवेदकों के पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि थी, सरकारी सेवा में थे, करदाता थे एवं कुछ अन्य कारणों से अपात्र घोषित कर दिया गया। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि 67.48 लाख असंगठित श्रमिकों में से 14.34 लाख को उनकी अपात्रता के लिए विशिष्ट कारण बताए बिना अपात्र घोषित किया गया। आगे, लेखापरीक्षित जिलों में, 1,320 में से 1,085 (82 प्रतिशत) पंजीकृत असंगठित श्रमिक, जिन्हें भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किया गया था, अपीलारी प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया था।

(कंडिका 2.3.6.1)

निर्देशों के बावजूद, पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता के संग्रहण में लगे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिक का पंजीयन नहीं हुआ क्योंकि संबल पोर्टल पर पंजीयन खुला नहीं था। आगे, विभाग ने दो योजनायें अर्थात् उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना लागू नहीं किया क्योंकि विभाग ने न तो इन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया और न ही योजनाओं के कार्यान्वित न होने का संज्ञान ही लिया।

(कंडिकाएं 2.3.6.2 और 2.3.6.3)

जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने लेखापाल के साथ मिलीभगत करके ₹2.47 करोड़ के योजना निधि का संदिग्ध कपटपूर्वक आहरित किया एवं कर्मचारी, कर्मचारी के रिश्तेदारों एवं अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किया।

(कंडिका 2.3.7.1)

एक ही मृत श्रमिक के विरुद्ध संबल योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना दोनों से ₹89.21 लाख की अनुग्रह सहायता की निकासी के प्रकरण देखे गए। आगे, पदाभिहित अधिकारियों ने अपात्र लाभार्थियों जिन्हें पहले से ही संबल योजना से ₹7.86 करोड़ की अनुग्रह सहायता प्राप्त हो चुकी थी को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत अनियमित रूप से ₹72.60 लाख की सहायता का भुगतान किया। इस प्रकार, एक ही प्राधिकारी जो दो अलग-अलग योजनाओं में दो लाभ स्वीकृति कर रहा था लाभ की स्वीकृति के समय प्रकरणों को सत्यापित करने में विफल रहा।

(कंडिकाएं 2.3.7.2(स) और 2.3.7.2(द))

60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को लाभ की स्वीकृति के लिए संबल पोर्टल में जांच एवं सत्यापन का अभाव होने से पदाभिहित अधिकारी 60 वर्ष से अधिक आयु के अपात्र व्यक्तियों एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.पी.एस.) के लाभार्थियों को ₹1.04 करोड़ की अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने में सक्षम हुए।

(कंडिकाएं 2.3.7.3 और 2.3.9.4)

पदाभिहित अधिकारियों ने 86 प्रकरणों में ₹1.72 करोड़ की अधिक सहायता का भुगतान किया। आगे, विभाग मृत व्यक्तियों जो मृत्यु के बाद असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हुए थे के उत्तराधिकारियों से ₹54 लाख की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका।

(कंडिकाएं 2.3.7.4 और 2.3.7.9)

4,398 (36 प्रतिशत) प्रकरणों में, नगर निगम/पालिका के अधिकृत कर्मचारियों अथवा सचिव, ग्राम पंचायत ने पंजीकृत असंगठित श्रमिकों/मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹2.20 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया। पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध न कराने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.7.12)

विभाग ने अनियमित रूप से ₹2,077 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि आहरित की एवं बैंक खाते में जमा की। आगे, इस बैंक खाते पर अर्जित ब्याज की राशि ₹3.86 करोड़ शासकीय खाते में जमा नहीं की।

(कंडिकाएं 2.3.8.1 और 2.3.8.2)

1,07,076 (64 प्रतिशत) प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने एक से 1,272 दिनों के विलम्ब से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की एवं 60,674 प्रकरणों में, विभाग ने स्वीकृति के बाद दो से 1,013 दिनों के विलम्ब से भुगतान वितरित किया। अनुग्रह सहायता की स्वीकृति एवं अग्रेषित करने में विलम्ब से योजना के उद्देश्य विफल हो गये।

(कंडिका 2.3.9.1)

अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि आयोजना, योजना कार्यान्वयन, निधि प्रबंधन एवं निगरानी में कई कमियाँ थीं। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि मध्य प्रदेश शासन को उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने संबल योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में उचित कर्मठता सुनिश्चित नहीं की, के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

अध्याय-2

अनुपालन लेखापरीक्षा

- प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा
- शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा

अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा

राजस्व विभाग

2.1 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा

2.1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश शासन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, असमय वर्षा, पाला, शीतलहर, कीट, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा और अग्नि दुर्घटनाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (आर.बी.सी. 6-4) के माध्यम से प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को देय अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा और मानदंड निर्धारित किए हैं।

मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व विभाग के अंतर्गत वर्ष 1979-80 में राहत आयुक्त का कार्यालय प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की जानकारी एकत्रित करने, पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और वितरित की जा रही राहत की सतत निगरानी करने के लिए स्थापित किया।

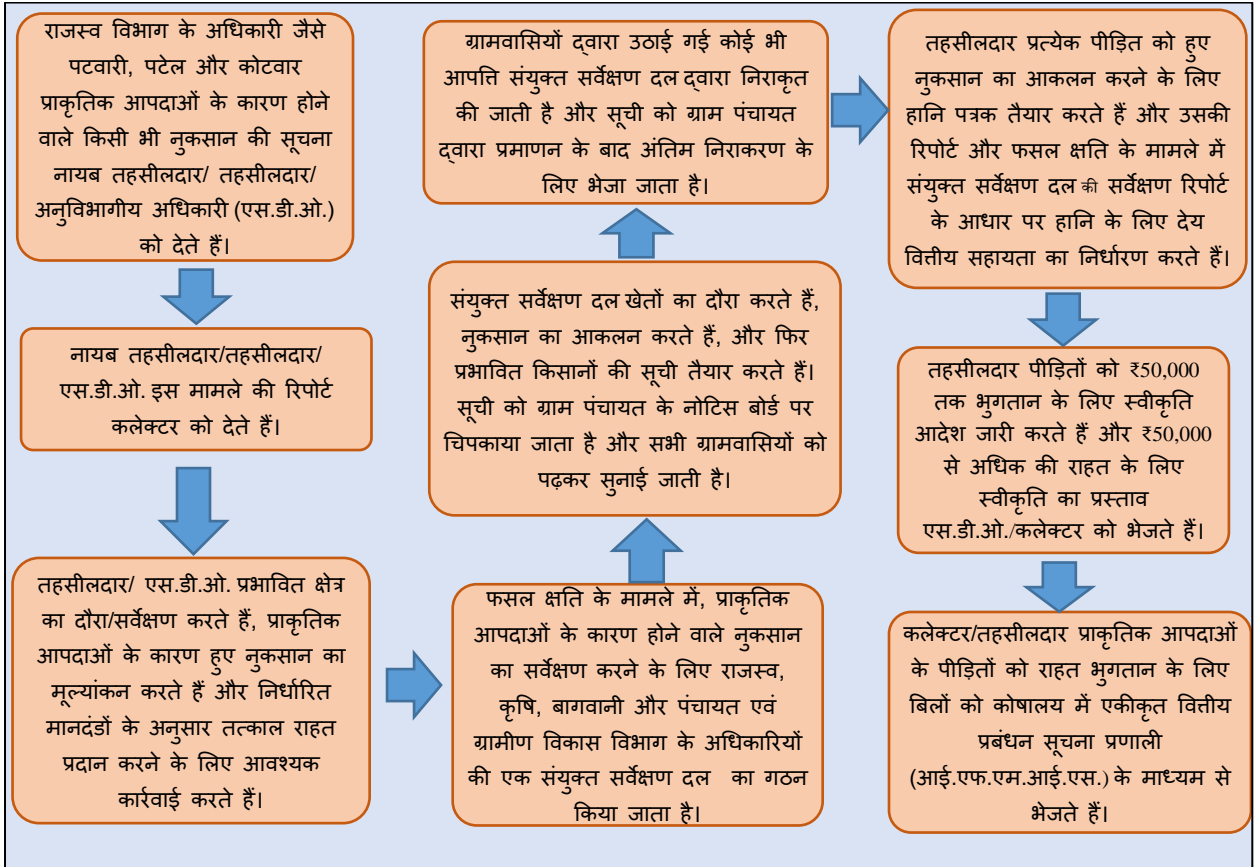
2.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। राहत आयुक्त, विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिन्हें एक उप राहत आयुक्त सहायता करता है। राज्य में 52 जिला कलेक्टर और 424 तहसीलदार हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित लोगों की पहचान करते हैं और चिन्हित पीड़ितों को तत्काल राहत वितरित करते हैं।

2.1.3 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत पीड़ितों की पहचान और राहत वितरण की प्रक्रिया

प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत पीड़ितों की पहचान और राहत वितरण की प्रक्रिया चार्ट 2.1.1 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.1.1: पीड़ितों की पहचान और राहत वितरण की प्रक्रिया



(स्रोत: आर.बी.सी. 6-4)

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने हेतु की गई कि क्या:

- योजनाओं में पर्याप्त धन उपलब्ध था और इसका उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया,
- पीड़ितों की पहचान और उन्हें राहत का वितरण तुरंत और आर.बी.सी.6-4 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया गया,
- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उचित निगरानी प्रणाली मौजूद है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए हैं:

- आर.बी.सी. 6-4;

- विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, आदेश और अधिसूचनाएँ;
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.);
- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.)।

2.1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन चार योजनाओं¹ पर राज्य शासन ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की थी उसके वितरण की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा (अक्टूबर और नवंबर 2022) की गई थी। इसके अतिरिक्त, हमने उन जिलों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं की योजनाओं के अभिलेखों की भी जांच की, जहाँ डेटा विश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिलक्षित हुए। हमने विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों के अभिलेखों (भौतिक एवं डिजिटल) की जांच की।

(क) राहत आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।

(ख) 52 में से 13² कलेक्टर कार्यालय।

पूर्व लेखापरीक्षा के दौरान हमें चार³ जिला कलेक्टर कार्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों को सूखा राहत के वितरण में धोखाधड़ी के भुगतान के प्रकरणों का संज्ञान हुआ था। इसलिए, हमने विवेकानुसार प्रतिचयन के आधार पर चार जिलों का चयन किया। शेष नौ⁴ जिला कलेक्टर कार्यालयों का चयन आइडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यय डेटा के यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। चयनित¹³ जिलों में योजना अनुसार व्यय **परिशिष्ट 2.1.1** में दिया गया है।

(ग) चयनित 13 जिलों के अंतर्गत सभी 100 तहसीलदारों के कार्यालय।

निर्गम सम्मेलन 07 जून 2023 को आयोजित किया गया और शासन से प्राप्त उत्तर (जून 2023) को उचित रूप से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

¹ 1. 2018- बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राहत, 2. 5504- आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत आपदाओं में वित्तीय सहायता, 3. 6422- सूखे से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों के लिए सहायता, 4. 7249- कीटों से फसल नुकसान।

² 1. शिवपुरी, 2. सतना, 3. दमोह, 4. विदिशा, 5. छतरपुर, 6. देवास, 7. सीहोर, 8. खंडवा, 9. सिवनी, 10. रायसेन, 11. मंदसौर, 12. आगर-मालवा, 13. श्योपुर।

³ 1. शिवपुरी, 2. सतना, 3. दमोह और 4. विदिशा।

⁴ 1. छतरपुर, 2. देवास, 3. सीहोर, 4. खंडवा, 5. सिवनी, 6. रायसेन, 7. मंदसौर, 8. आगर-मालवा, 9. श्योपुर।

2.1.7 वित्तीय परिव्यय

मध्य प्रदेश शासन ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए वर्ष 2018-22 के दौरान ₹10,060⁵ करोड़ की राहत वितरित की, जिसमें से चयनित चार योजनाओं के अंतर्गत ₹8,680 करोड़ (86 प्रतिशत) वितरित किए गए थे। इन चार योजनाओं के बजट और व्यय का विवरण और वर्ष 2018-22 के दौरान वितरित कुल राहत में इन चार योजनाओं का अंश क्रमशः नीचे तालिका 2.1.1 और चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.1: 2018-19 से 2021-22 के दौरान बजट और व्यय									
(₹ करोड़ में)									
योजना	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2018-22
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	कुल व्यय
2018- बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के लिए राहत	73.12	73.02	2,302.92	2,267.14	1,069.30	931.83	623.30	607.84	3,879.83
5504- आर.बी.सी.6-4 के अंतर्गत आपदाओं में वित्तीय सहायता	122.00	121.76	183.77	182.65	878.00	863.25	531.60	518.13	1,685.79
6422- सूखा संबंधित फसल क्षति और अन्य कार्यों के लिए सहायता	1,710.78	846.38	110.07	51.15	22.83	0.27	0.30	0.15	897.95
7249- कीटों से फसल हानि	448.45	36.24	8.85	8.53	2,270.18	2,118.62	53.18	53.17	2,216.56
योग	2,354.35	1,077.40	2,605.61	2,509.47	4,240.31	3,913.97	1,208.38	1,179.29	8,680.13

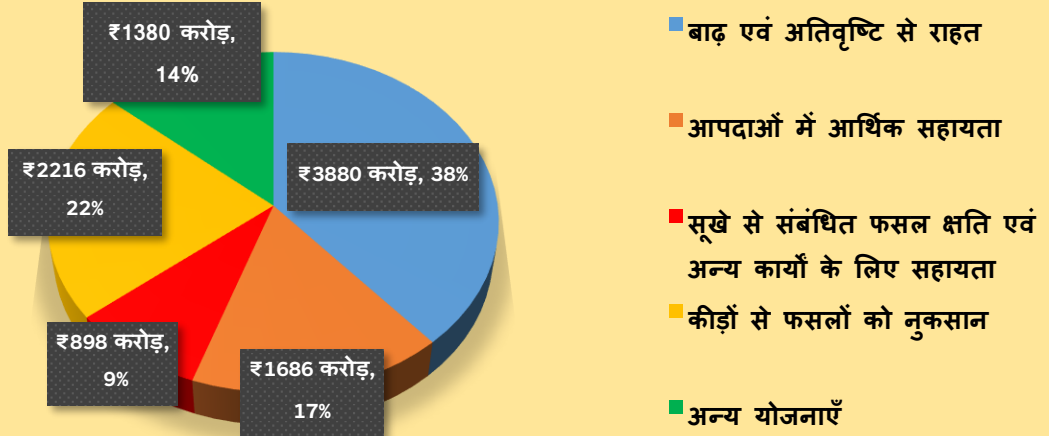
(स्रोत: राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

मध्य प्रदेश में वर्ष 2018-22 की अवधि के दौरान चयनित चार योजनाओं पर वितरित ₹8,680 करोड़ में से, हमने चयनित जिलों में ₹3,692 करोड़ के वितरण की जांच की, जो राज्य में कुल वितरण का 42.53 प्रतिशत था।

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2018-22 की अवधि के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़, सूखा और कीट संक्रमण जैसी आपदाओं के संबंध में जारी मेमोरेण्डम में 1.15 करोड़ किसानों/लाभार्थियों को लाभान्वित दिखाया। जिसमें 1.15 करोड़ किसानों/लाभार्थियों में से चयनित 13 जिलों में 0.23 करोड़ (20 प्रतिशत) लाभान्वित दर्शाए गए।

⁵ 1. वर्ष 2018-19: ₹ 1,410 करोड़, वर्ष 2019-20: ₹ 2,813 करोड़, 3. वर्ष 2020-21: ₹ 4,316 करोड़ और 4. वर्ष 2021-22: ₹ 1,521 करोड़।

चार्ट 2.1.2: वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वितरित कुल राहत में चयनित चार योजनाओं का अंश



टीप : अन्य योजनाओं में, 0747: ओलावृष्टि पीड़ितों को राहत, 6097: सर्पदंश पीड़ितों को राहत, 7021: पाले से क्षति, 7250: जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति शामिल है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.8 प्राकृतिक आपदाओं की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संदिग्ध कपटपूर्ण तरीके से धन का आहरण

प्रणालीगत कमियां जिनके कारण संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान संभव हुए

चयनित 13 जिलों के कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रणालीगत कमियों को पाया जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1.8.1 ग्लोबल बजट में कमियां

राज्य शासन ने वर्ष 2012-13 से ग्लोबल बजट प्रणाली लागू की, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) अनुसार व्यय सीमा को हटा दिया गया और डी.डी.ओ. तब तक राशि आहरित कर सकता है जब तक कि बजट नियंत्रक अधिकारी स्तर पर राशि उपलब्ध हो।

शासन ने लेखापरीक्षा टीप को स्वीकार किया (जून 2023) और आश्वासन दिया कि ग्लोबल बजट के अंतर्गत योजनाओं⁶ के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में डी.डी.ओ. के लिए व्यय सीमा को कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

⁶ 1. 6422: सूखे से संबंधित फसल क्षति और अन्य कार्यों के लिए सहायता, 2. 6097: सांप काटने पर वित्तीय सहायता, 3. 7021: पाले से क्षति के लिए वित्तीय सहायता, 4. 7249: कीड़ों से फसल की हानि।

2.1.8.2 आई.एफ.एम.आई.एस. में पुनर्भुगतान हेतु देयक तैयार करने से संबंधित कमियां

एम.पी.टी.सी. के अनुसार, पुनर्भुगतान देयक तैयार करते समय, देयक को उस मूल चालान द्वारा संयोजित होना चाहिए जिसके माध्यम से राशि जमा की गई थी, साथ ही उन व्यक्तियों का विवरण भी होना चाहिए जिनकी राशि जमा शीर्ष में उन्हें देय है। डी.डी.ओ. इन भुगतानों को करते समय उपरोक्त विवरणों से दावेदारों की वास्तविकता सुनिश्चित कर सकेगा।

आई.एफ.एम.आई.एस. में, डी.डी.ओ. दावेदारों की ई-भुगतान सूची अपलोड करके देयक इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करता है, जिसमें दावेदारों के नाम, बैंक खाता नंबर, बैंक खाते का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आई.एफ.एस.सी.), दावेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि, और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि स्कैन की गई स्वीकृतियाँ एवं व्हाउचर आदि शामिल होते हैं और भुगतान के लिए देयक को कोषालय को भेजता है। जब कोई लेनदेन विफल हो जाता है, तो बैंक भौतिक चालान के माध्यम से असफल संव्यवहार की राशि को जमा शीर्ष 8443-101-0120 (सिविल डिपॉजिट) में जमा करता है और इन चालानों के साथ असफल संव्यवहार का विवरण कोषालय को भेजता है। इसके बाद कोषालय असफल संव्यवहार का विवरण, जैसे खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी., राशि, मूल देयक संख्या, चालान आदि संबंधित डी.डी.ओ. को भेजता है। अंततः, डी.डी.ओ. चालान की प्रति और असफल संव्यवहार का विवरण संलग्न कर फॉर्म एम.पी.टी.सी.-66 का उपयोग करके जिन व्यक्तियों, के संव्यवहार असफल हुए थे, उन्हें भुगतान करने के लिए एक पुनर्भुगतान देयक तैयार करता है।

तथापि, ऑडिट के दौरान आई.एफ.एम.आई.एस. में असफल संव्यवहार के पुनर्भुगतान देयक बनाने के लिए कोई नियंत्रण नहीं मिला। जैसे सिस्टम में स्वतः ही मूल देयक से संयोजित होना, भुगतान करने वालों का विवरण, खाता संख्या और देय राशि। जबकि कोषालय से प्राप्त विवरण से पुनर्भुगतान देयक बनाते समय इन्हें डी.डी.ओ. द्वारा मैनुअल रूप से सत्यापित किया जाना था। इस प्रकार, पुनर्भुगतान देयक में उनके बैंक खाता संख्या तथा अन्य विवरण दर्ज करके अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करने की गुंजाइश थी क्योंकि मूल देयक में शामिल नाम और बैंक खातों की मिलान करने के लिए आई.एफ.एम.आई.एस. पर कोई लिंक उपलब्ध नहीं था।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और सूचित किया कि अनुविभागीय अधिकारियों और कलेक्टरों को क्रमशः साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से असफल संव्यवहारों की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.8.3 आई.एफ.एम.आई.एस. से ई-स्वीकृतियों का जारी न होना

चयनित 13 जिलों के कलेक्टरों और तहसीलदारों के अभिलेखों की जांच में, हमने पाया कि यद्यपि देयक आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए गए थे, परन्तु स्वीकृतियां मैनुअल रूप से तैयार की गई थी और स्वीकृति की स्कैन की गई प्रतियां

आई.एफ.एम.आई.एस. में अपलोड की गई थीं। ई-स्वीकृति जनरेट न होने के कारण, आई.एफ.एम.आई.एस. देयक तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्कैन किए गए दस्तावेज को स्वीकार कर सकता है, चाहे वह उस देयक से संबंधित हो या नहीं। इस कमी से धोखाधड़ी का जोखिम उत्पन्न होता है क्योंकि मैनुअल रूप से तैयार की गई स्वीकृति का धोखाधड़ी वाले भुगतान के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में ई-स्वीकृति जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, हालाँकि, सभी देयकों को डी.डी.ओ. के ई-हस्ताक्षर के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। वित्त विभाग समय-समय पर आई.एफ.एम.आई.एस. में आवश्यक संशोधन करता रहता है।

तथ्य यह है कि आई.एफ.एम.आई.एस. में ई-स्वीकृति जारी करने के लिए एक मॉड्यूल मौजूद था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था।

2.1.8.4 देयकों के साथ हानि पत्रक और सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को संलग्न न करना

आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार, तहसीलदार आपदाओं से प्रभावित स्थान का सर्वेक्षण करेगा और प्रत्येक पीड़ित को हुए नुकसान का और शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता का आकलन करेगा। तहसीलदार हानि पत्रक तैयार करता है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित को हुए नुकसान का आकलन एवं नुकसान के लिए देय वित्तीय सहायता, स्वयं के प्रतिवेदन/फसल क्षति के मामले में संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन के आधार पर, शामिल होती है।

चयनित 13 जिलों के कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों में विभिन्न राहतों से संबंधित भौतिक देयकों की जांच में, हमने पाया कि सर्वेक्षण अभिलेख और हानि पत्रक, जिसमें किसानों का विवरण, फसलों का प्रकार, खसरा नंबर, फसल क्षति का प्रतिशत और स्वीकृत राशि शामिल है, उपलब्ध और संधारित थे। परन्तु हमने पाया कि केवल स्वीकृतियाँ भौतिक देयकों के साथ संलग्न थीं। सर्वेक्षण प्रतिवेदन और हानि पत्रकों को संबंधित स्वीकृतियों के बिना किसी लिंक या संदर्भ के अलग रखा गया था। भौतिक देयकों के साथ इन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या देयकों के माध्यम से किए गए भुगतान वास्तविक लाभार्थियों को किए गए थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि हानि पत्रक और सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक सर्वे नंबर के लिए अलग से तैयार किये जाते हैं और ये दस्तावेज बड़ी संख्या में होते हैं, जो प्रकरण नस्ति के साथ संलग्न होते हैं। आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर दो एम.बी. तक के संलग्नकों की अनुमति देता है। इसलिए, सभी अभिलेखों को आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में शामिल करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानि पत्रक और सर्वेक्षण प्रतिवेदन भौतिक देयकों के साथ भी संलग्न नहीं थे। इसके अलावा, यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर की क्षमताएं सीमित हैं जिनका मूल्यांकन सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले नहीं किया गया था।

उपर्युक्त प्रणालीगत कमियों के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत विभिन्न राहतों में ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण हुआ, जिस पर कंडिका 2.1.8.5 में विस्तृत चर्चा की गई है।

2.1.8.5 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत वितरण में ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

आर.बी.सी. 6-4 में निर्धारित विभिन्न आपदाओं के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति को देय अधिकतम वित्तीय सहायता का विवरण तालिका 2.1.2 में दिया गया है:

तालिका 2.1.2: विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को देय अधिकतम वित्तीय सहायता का विवरण		
क्र.	विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान/क्षति के प्रकार	आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार देय अधिकतम राहत राशि (₹ में)
1.	28 फरवरी 2018 तक प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति	60,000
2.	01 मार्च 2018 से प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति	1,20,000
3.	साँप के काटने, डूबने, आकाशीय बिजली आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु	4,00,000
4.	आपदा से पशु हानि	30,000
5.	पूर्णतः नष्ट/गंभीर रूप से नष्ट (जहां क्षति 50 प्रतिशत से अधिक थी) कच्चे और पक्के मकान	95,100 वास्तविक नुकसान के आकलन के आधार पर और 1,01,900 उन जिलों में जिनके लिए एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।
6.	आंशिक रूप से नष्ट पक्का मकान (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है)	5,200
7.	आंशिक रूप से नष्ट कच्चा मकान (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है)	3,200
8.	कपड़ों, बर्तनों और अनाज को हुए नुकसान	5,000

(स्रोत: राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर.बी.सी. 6-4)

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना (नवंबर 2015) में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और कोषालय अधिकारियों द्वारा वास्तविक लाभार्थियों को किए गए ई- भुगतान को सत्यापित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। विभागीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा में ₹23.81 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान परिलक्षित हुआ, जिसका विवरण नीचे तालिका 2.1.3 में दिया गया है:

तालिका 2.1.3: प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत विभिन्न राहतों के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	जिला	कर्मचारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों के बैंक खातों में कपटपूर्ण वितरण का विवरण		अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में कपटपूर्ण वितरण का विवरण		कपटपूर्ण रूप से वितरित की गई कुल राशि	उपयोग की गई कार्यप्रणाली	प्रणालीगत कमियाँ जिससे कपटपूर्ण वितरण हो सका
		बैंक खातों की संख्या	जमा राशि	बैंक खातों की संख्या	जमा राशि			
1.	सिवनी	-	-	59	11.79	11.79	डी.डी.ओ. और दोषी कर्मचारियों ने 291 जाली स्वीकृति आदेश, प्रत्येक ₹4 लाख का, तैयार कर 59 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा किए।	आई.एफ.एम.आई.एस. में कमजोरी और डी.डी.ओ. वार सीमा को हटाने से कपटपूर्ण भुगतान संभव हो सका।
2.	श्यापुर	06	0.16	210	3.20	3.36	1. डी.डी.ओ. ने ई-भुगतान में फर्जी नामों का इस्तेमाल किया और इन खातों में कई लेनदेन किए, जबकि ये खाते अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पाए गए।	
3.	सीहोर	11	0.76	34	0.41	1.17	2. अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के 93 खातों में ₹2.67 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।	
4.	शिवपुरी	25	0.63	146	2.37	3.00	3. अनधिकृत व्यक्तियों के 650 खातों में ₹21.14 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।	
5.	देवास	34	0.72	27	0.54	1.26	4. धोखाधड़ी करने के लिए अलग-अलग बैंकों में एक ही व्यक्ति के दो से चार खातों का इस्तेमाल किया गया।	
6.	छतरपुर	-	-	20	0.42	0.42	5. डी.डी.ओ. ने अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में, लाभार्थियों को स्वीकृत राहत का भुगतान किया।	
7.	खंडवा	04	0.12	-	-	0.12		
8.	मन्दसौर	04	0.17	26	0.52	0.69		
9.	रायसेन	01	0.04	39	0.80	0.84		
10.	दमोह	-	-	27	0.31	0.31		
11.	सतना	-	-	12	0.13	0.13		
12.	आगर-मालवा	-	-	17	0.25	0.25		
13.	विदिशा	08	0.07	33	0.40	0.47		
कुल		93	2.67	650	21.14	23.81		

(स्रोत: संबंधित कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए भुगतान आदेश सूचियां, देयक और स्वीकृति आदेश)

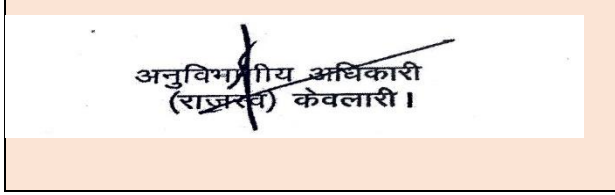
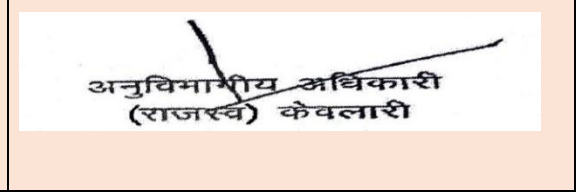
जिलेवार निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

1. सिवनी

आर.बी.सी.6-4 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बिजली गिरने, आग या विषैले जानवर जैसे सांप के काटने से मृत्यु होने पर, मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को ₹चार लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मानव हानि की स्थिति में, एस.डी.ओ./तहसीलदार को मृत्यु के कारण का निर्धारण करने के लिए स्थल का दौरा करना आवश्यक है, और जहाँ भी संभव हो, शव परीक्षण करवाना चाहिए। विषैले जानवर के काटने से मृत्यु होने पर, अनुदान को स्वीकृति देते समय सक्षम प्राधिकारी पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन और पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) जैसे दस्तावेजों के आधार पर मृत्यु के कारण का निर्धारण करेगा।

हमने सिवनी जिले के 1948 देयकों में से 81 देयकों (केवलारी तहसील के) की जांच की और पाया कि ₹11.64 करोड़ की राशि, 291 जाली स्वीकृति आदेशों (डूबने/बिजली गिरने: 201 और सर्पदंश: 90), प्रत्येक का मूल्य ₹4 लाख, के माध्यम से उन मृत व्यक्तियों के नाम पर जो कथित रूप से सांप के काटने, डूबने या बिजली गिरने से मरे थे, 59 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा की गई थी। विवरण परिशिष्ट 2.1.2 (क) में दिए गए हैं। हमें कोई पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन और पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ.आई.आर. इन देयकों के साथ संलग्न नहीं मिली, जिसकी जांच मृतक के परिजनों को वित्तीय सहायता के लिए भुगतान करने के पूर्व की जानी आवश्यक थी।

ग्लोबल बजट प्रणाली और आई.एफ.एम.आई.एस. की कमियों के कारण कर्मचारी प्रणाली की कमियों का दुरुपयोग कर शासकीय धन की हेराफेरी करने में सफल रहे। राजस्व अधिकारियों ने स्वीकृति आदेशों में पूर्ण हस्ताक्षरों के बजाय संक्षिप्ताक्षर का उपयोग किया, जिससे कर्मचारियों को स्वीकृति आदेशों पर एस.डी.ओ., केवलारी के जाली संक्षिप्ताक्षर बनाने में मदद मिली और एक ही जाली स्वीकृति आदेशों का कई लेनदेन (एक से 30 तक) करने के लिए बार-बार उपयोग किया गया। वास्तविक और जाली स्वीकृति आदेशों पर पाए गए एस.डी.ओ. के संक्षिप्ताक्षर नीचे दर्शाए गए हैं:

वास्तविक स्वीकृति आदेश पर पाए गए एस.डी.ओ. के संक्षिप्ताक्षर	जाली स्वीकृति आदेश पर पाए गए एस.डी.ओ. के संक्षिप्ताक्षर
	

इसके अलावा, हमने देखा कि तहसीलदार, केवलारी ने मार्च 2020 और अगस्त 2020 के दौरान कोटवारों⁷ के मजदूरी की राशि ₹1.84 लाख का भुगतान चार अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में कर दिया, जो ₹11.64 करोड़ के गबन में शामिल थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.2 (ख) में दिया गया है।

हमने यह भी पाया कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि राहत और पुनर्भुगतान से संबंधित देयकों के माध्यम से दो अनधिकृत व्यक्तियों को ₹13.21 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया, जो उपरोक्त गबन में शामिल थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.2 (ग) में दिया गया है।

यह केवलारी तहसील के डी.डी.ओ. और श्री सचिन दहायत, नाज़िर की संलिप्तता को दर्शाता है, क्योंकि वे ही उपरोक्त किए गए भुगतानों को करने के लिए अधिकृत अधिकारी थे। कोषालय अधिकारियों ने देयकों के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन और एफ.आई.आर. प्रस्तुत न होने के बावजूद भी मुआवजे के भुगतान को मंजूरी दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.डी.ओ., कोषालय अधिकारी और अनधिकृत लाभार्थियों के बीच मिलीभगत से राज्य के राजकोष में घोटाले की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और एक तहसीलदार तथा एक नायब तहसीलदार सहित चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। एक कर्मचारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की और मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए समिति का गठन किया है।

2. श्योपुर

श्योपुर जिले में 30 जुलाई 2021 से 03 अगस्त 2021 के दौरान आई भारी बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत वितरित की गई थी। अभिलेखों की जांच में हमें

⁷ मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के नियम 230 के अंतर्गत कोटवार को किसी गाँव अथवा गाँव के समूह में ग्राम चौकीदार अथवा चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्योपुर जिले के बड़ौदा, श्योपुर और कराहल तहसील में अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण को ई-भुगतान आदेश में शामिल करके 216 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹3.36 करोड़ के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का पता चला। 216 खातों में से, छह⁸ खाते, जिनमें ₹15.54 लाख जमा किया गया, एक कर्मचारी के तीन रिश्तेदारों के थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.3(क) और 2.1.3(ख) में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कपटपूर्ण भुगतान प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं, और जिन खातों में राशि धोखाधड़ी से स्थानांतरित की गई है, उन्हें लम्बित रखा गया है। पटवारियों और उनके रिश्तेदारों के खातों में पैसे जमा करने में शामिल लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक जिला स्तरीय दल गठित किया गया है। अब तक राशि ₹11 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली बकाएदारों के खातों में उपलब्ध शेष राशि का समायोजन करके और बकाएदारों के अधिग्रहित भूखंडों और अन्य अचल संपत्तियों को बेचकर की जा रही है।

3. सीहोर

कार्यालय कलेक्टर, सीहोर तथा तहसीलदार कार्यालय इच्छावर, रेहटी और आष्टा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर बैंक में खोले गए 45 खातों में ई-भुगतान में जाली नामों का उपयोग करके ₹1.17 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया गया। ई-भुगतान आदेश में अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण शामिल कर इन 45 खातों में से, 11⁹ खातों में ₹76.22 लाख का कपटपूर्ण तरीके से जमा किये गए जो कि तीन कर्मचारियों और उनके चार रिश्तेदारों के थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.4 में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) एवं सूचित किया कि दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और इच्छावर तहसील के चार कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। रेहटी और आष्टा तहसीलों में एक विस्तृत जांच प्रगति पर थी। विस्तृत जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी।

4. शिवपुरी

शिवपुरी जिले में वर्ष 2017-18 के सूखा राहत से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में हमने ₹तीन करोड़ के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया। ₹तीन करोड़ में से, ₹2.77 करोड़ सूखा राहत और ₹22.87 लाख वेतन, कार्यालय व्यय और रखरखाव के मद

⁸ परिशिष्ट 2.1.3 (क) के क्रमांक एक से छह में उल्लेखित।

⁹ परिशिष्ट 2.1.4 के क्रमांक एक से 11 में उल्लेखित।

से संबंधित थे। राशि ₹2.77 करोड़ को वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अनधिकृत व्यक्तियों के 164 खातों में जमा किया गया था। स्वीकृति आदेशों में लाभार्थियों के नाम या खाता विवरण को अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण के साथ बदला गया था। संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण परिशिष्ट 2.1.5(क) में दिया गया है और तहसीलवार विवरण तालिका 2.1.4 में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: शिवपुरी जिले में कपटपूर्ण संवितरण का तहसीलवार विवरण			
क्र.	तहसील का नाम	अनधिकृत व्यक्तियों के खातों की संख्या	कपटपूर्ण संवितरण की राशि (₹ करोड़ में)
1	कोलारस	71	1.14
2	खनियाधाना	57	1.03
3	पिछोर	21	0.33
4	पोहरी	15	0.27
कुल		164	2.77

(स्रोत: कलेक्टर कार्यालय, शिवपुरी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

164 खातों में से 19 खाते¹⁰, इन तहसीलों के आठ कर्मचारियों और उनके सात रिश्तेदारों के थे, जिसमें ₹41.30 लाख जमा किये गए। हमने यह भी देखा कि कोलारस तहसील के कर्मचारियों ने देयक नंबर 20003613656 की ई-भुगतान सूची में वास्तविक लाभार्थियों का नाम और खाता विवरण अनधिकृत व्यक्तियों के साथ बदला। इसके बाद कर्मचारियों ने सभी वास्तविक लाभार्थियों को देयक नंबर 20003613656 से स्वीकृत राशि का भुगतान करने के लिए एक पुनर्भुगतान देयक नंबर 20003803716 तैयार किया। हालाँकि, पुनर्भुगतान देयक जिन असफल संव्यवहार के विरुद्ध तैयार किया गया था उसके विवरण भी देयक के साथ संलग्न नहीं पाये गए।

हमने पोहरी तहसील में भी वेतन, कार्यालय व्यय और रखरखाव के मद से ₹22.87 लाख के संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण पाया, जो कि फर्जी कर्मचारियों/व्यक्तियों के नाम पर सात खातों में जमा किया गया था। इन सात खातों में से छः खाते एक कर्मचारी और उसके तीन रिश्तेदारों के थे, जिनमें ₹21.33 लाख जमा किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.5(ख) में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जून 2023) और एक कर्मचारी को निलंबित किया और तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की। संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित व्यक्तियों की चल संपत्ति और अचल संपत्ति से धोखाधड़ी से भुगतान की गई राशि वसूल करें।

¹⁰ परिशिष्ट 2.1.5 (क) के क्रमांक एक से 19 में उल्लेखित।

5. देवास

कार्यालय कलेक्टर, देवास तथा पांच¹¹ तहसीलों के तहसीलदारों के अभिलेखों की नमूना जांच में, पाया गया कि ई-भुगतान आदेश में अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण शामिल कर 61 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में कीट प्रकोप, अत्यधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि राहत के लिए ₹1.26 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण किया गया। विवरण परिशिष्ट 2.1.6 में दिया गया है। 61 खातों में से 34¹² खाते छह कर्मचारियों तथा उनके 15 रिश्तेदारों के थे, जिनमें तीन से 22 के बीच लेनदेन के माध्यम से ₹72 लाख जमा किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और यह बताया किया कि विस्तृत जांच प्रगति पर है तथा अनियमित भुगतानों को संबंधित व्यक्तियों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और इसे शासन के खाते में जमा किया जाएगा। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. छतरपुर

कार्यालय कलेक्टर, छतरपुर के भुगतान आदेश सूचियों और देयकों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने 20 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹42 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान पाया, जिसमें ई-भुगतान में जाली नामों का उपयोग किया गया था, जबकि ये खाते बैंक अभिलेखों में विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। ₹42 लाख में से, ₹32.33 लाख को एक से 38 तक के कई फर्जी रिफंड देयकों के माध्यम से भुगतान किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.7 में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित व्यक्तियों से ₹34 लाख वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। यह बताया किया गया कि ₹ चार लाख का भुगतान जो अनधिकृत व्यक्ति को किया गया था, उसे अब वास्तविक लाभार्थी को भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि वसूल करने के लिए विस्तृत जांच प्रगति पर है। जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

7. खंडवा

खंडवा जिले की खालवा तहसील के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने चार खातों में ₹11.62 लाख की अत्यधिक वर्षा के लिए राहत राशि ई-भुगतान में फर्जी लाभार्थियों के नामों का उपयोग करके जमा पाया। बैंक अभिलेखों में, ये चार खाते श्री भगवान सिंह,

¹¹ 1. बागली, 2. कन्नौद, 3. खातेगांव, 4. सतवास, 5. टोंक खुर्द।

¹² परिशिष्ट 2.1.6 के क्रमांक एक से 34 में उल्लेखित।

नाजिर, खालवा तहसील एवं नाजिर के भाई श्री नरेंद्र सिंह के नाम पर पंजीकृत थे। संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण परिशिष्ट 2.1.8 में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित कर्मचारी से ₹11.62 लाख वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित की गई है।

8. मंदसौर

मंदसौर जिले के मालहारगढ़ एवं सीतामऊ तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि एवं रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से 30 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹69.49 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया। अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.9(क), परिशिष्ट 2.1.9(ख) एवं परिशिष्ट 2.1.9(ग) में दिया गया है। एक कर्मचारी एवं उसके तीन रिश्तेदारों के चार¹³ खातों में नौ से 12 के बीच के कई रिफंड देयकों के माध्यम से ₹17 लाख जमा किया गया।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित व्यक्तियों से ₹65 लाख वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और संबंधित तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

9. रायसेन

लेखापरीक्षा में रायसेन जिले के बेगमगंज, गैरतगंज, सुल्तानपुर एवं उदयपुरा तहसीलों में अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि एवं रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से 40 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹84 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान पाया गया। विवरण परिशिष्ट 2.1.10(क) एवं परिशिष्ट 2.1.10(ख) में दिया गया है। ई-भुगतान में उल्लेखित लाभार्थियों के नाम या तो बैंक अथवा भौतिक देयकों/स्वीकृति आदेश से भिन्न पाए गए। इस प्रकार, उपरोक्त लेनदेन के लिए अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण को ई-भुगतान आदेश में शामिल किया गया था। एक कर्मचारी के रिश्तेदार के खाते¹⁴ में ₹3.82 लाख कपटपूर्ण तरीके से जमा किया गया।

¹³ परिशिष्ट 2.1.9 (ग) के क्रमांक एक से चार में उल्लेखित।

¹⁴ परिशिष्ट 2.1.10 (क) के क्रमांक 15 में उल्लेखित।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और ₹71 लाख का कपटपूर्ण भुगतान पाया, जिसमें से ₹69 लाख संबंधित व्यक्तियों से वसूल किए गए और इसे शासन के खाते में जमा किया गया। इस धोखाधड़ी में शामिल चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

10. दमोह

कार्यालय कलेक्टर, दमोह तथा तहसीलदार, दमोह, पतेरा एवं पठरिया के अभिलेखों की नमूना जांच में अत्यधिक वर्षा, सूखा, कीट प्रकोप और रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से अनधिकृत व्यक्तियों के 27 बैंक खातों में ₹31 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान पाया गया। विवरण परिशिष्ट 2.1.11(क) एवं परिशिष्ट 2.1.11(ख) में दिया गया है। ई-भुगतान में उल्लेखित लाभार्थियों के नाम भौतिक देयकों/स्वीकृति आदेशों तथा बैंकों में दर्ज नामों से भिन्न थे। इसमें अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि राहत की राशि विभिन्न व्यक्तियों के खाते में किसानों की सहमति के आधार पर हस्तांतरित की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य जिलों की तरह यहाँ कोई स्वतंत्र जांच नहीं करायी गई और यह तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर आधारित है। इसके अलावा, किसानों से प्राप्त सहमति की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गईं।

11. सतना

कार्यालय कलेक्टर, सतना के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने 12 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में सूखा राहत के वितरण में ₹13 लाख के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया। अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.12 में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित व्यक्तियों से ₹20.71 लाख (12 प्रतिशत ब्याज सहित) वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। तीन कर्मचारियों, जो दोषी पाये गए, को निलंबित कर दिया गया है।

12. आगर-मालवा

कार्यालय कलेक्टर, आगर-मालवा तथा तहसीलदार, आगर, नलखेड़ा, बड़ौद एवं सुसनेर के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने अनधिकृत व्यक्तियों के 17 खातों में ₹25.30 लाख की राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण को पाया, जो कई लेनदेन के माध्यम से किया

गया था। अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था। इन 17 खातों में से नौ खातों के लिए ई-भुगतान में उल्लेखित लाभार्थियों के नाम बैंक में दर्ज नामों से भिन्न पाए गए। विवरण परिशिष्ट 2.1.13(क) एवं परिशिष्ट 2.1.13(ख) में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि आगर-मालवा जिले में जांच प्रगति पर है।

13. विदिशा

कार्यालय कलेक्टर, विदिशा तथा तहसीलदार, गुलाबगंज एवं कुरवई तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने सूखा, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, कीट संक्रमण एवं रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से 41 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹47 लाख के कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया। विवरण परिशिष्ट 2.1.14 में दिया गया है। छः कर्मचारियों एवं उनके एक रिश्तेदार के आठ¹⁵ खातों में ₹6.58 लाख जमा किया गया। उपरोक्त सभी प्रकरणों में, अनधिकृत बैंक खातों में राहत राशि का कपटपूर्ण भुगतान करने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों का विवरण डी.डी.ओ. स्तर पर ई-भुगतान आदेशों में दर्ज किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और ₹40 लाख का कपटपूर्ण भुगतान पाया। तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राशि की वसूली की जा रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की जा रही है।

उपरोक्त 13 जिलों में शासकीय धन की हेराफेरी डी.डी.ओ., नाजिरों एवं पटवारियों की संलिप्तता को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं की जा रही थी कि राहत वास्तविक लाभार्थियों के खातों में वितरित की गई थी या नहीं।

2.1.8.6 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत वितरण में ₹2.73 करोड़ का अनियमित भुगतान

आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार, फसल के नुकसान के लिए प्रभावित व्यक्ति को अधिकतम वित्तीय सहायता, 28 फरवरी 2018 तक ₹60,000 तथा 01 मार्च 2018 से आगे ₹1,20,000 का भुगतान किया जा सकता है। तहसीलदारों को प्रत्येक पीड़ित को हुए हानि का आकलन करने एवं उसके प्रतिवेदन /संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन के आधार पर हानि के लिए भुगतान योग्य वित्तीय सहायता के साथ हानि पत्रक को तैयार करना है।

¹⁵ परिशिष्ट 2.1.14 के क्रमांक एक से आठ में उल्लेखित।

हालांकि, कलेक्टर, शिवपुरी, देवास, विदिशा और इनकी तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में, निर्धारित सीमाओं से परे ₹2.73 करोड़ का अनियमित भुगतान होना पाया। विवरण तालिका 2.1.5 में दिया गया है:

तालिका 2.1.5: प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत विभिन्न राहतों के अनियमित वितरण का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
क्र.	जिला	खातों की संख्या	अनियमित भुगतान की राशि	वह अवधि जिसमें लेनदेन किया गया	आपदाओं के प्रकार
1.	शिवपुरी	41	0.50	अप्रैल 2018 से अप्रैल 2021	सूखा
2.	देवास	402	0.68	मई 2018 से मार्च 2022	अतिवृष्टि एवं कीटों का प्रकोप
3.	विदिशा	149	1.55	अप्रैल 2018 से मार्च 2021	सूखा
योग		592	2.73		

(स्रोत: संबंधित कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए भुगतान आदेश सूचियां, देयक एवं स्वीकृति आदेश)

हमने इन जिलों में अनियमित भुगतान का संकेत देने वाले निम्नलिखित निष्कर्ष देखे:

1. शिवपुरी

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी के भुगतान आदेश सूचियों की जांच में, वर्ष 2017-18 में सूखा राहत के लिए 41 व्यक्तियों को सूखा राहत एवं रिफंड देयकों के माध्यम से दो से 11 के बीच कई लेनदेनों से ₹50 लाख का अनियमित भुगतानों हुआ इन खातों में जो राशि जमा की गई, वह आर.बी.सी. 6-4 में निर्धारित अधिकतम सहायता राशि ₹60,000 से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट 2.1.15 में दिया गया है।

2. देवास

कार्यालय कलेक्टर, देवास तथा कार्यालय तहसीलदार, खातेगांव, कन्नौद एवं सतवास तहसीलों के अभिलेखों की जांच में, हमने 17 खातों में चार से 19 के बीच कई लेनदेन के माध्यम से ₹35.46 लाख का अनियमित भुगतान पाया। देयकों के साथ हानि पत्रक संलग्न नहीं पाए गए। इतने अधिक लेनदेन की संख्या इन भुगतानों को संदिग्ध बनाती है। विवरण परिशिष्ट 2.1.16 में दिया गया है।

देयक सन्दर्भ संख्या 20009018358 दिनांक 27 मार्च 2021 की जांच में, हमने देखा कि कीट प्रकोप से फसलों को हुए नुकसान के लिए 382 किसानों को ₹22.32 लाख की राहत का भुगतान किया गया, हालांकि, हमें इस देयक के साथ राहत वितरण के लिए विस्तृत ग्रामवार स्वीकृतियाँ संलग्न नहीं मिलीं। 35 गांवों के नामों की केवल सूची इस देयक के साथ संलग्न थी। एक

कर्मचारी तथा उसके रिश्तेदारों के छः खातों में इस देयक के माध्यम से ₹0.85 लाख का भुगतान किया गया।

हमें यह भी पाया गया कि मानव/पशु हानि के लिए नौ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹10.80 लाख वितरित किए गए। जबकि, इन नौ देयकों के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पंचनामा, पोस्टमार्टम प्रतिवेदन एवं एफ.आई.आर. संलग्न नहीं थे। देयकों के साथ आवश्यक दस्तावेजों की आभाव ₹10.80 लाख के भुगतान को अनियमित बनाती है। विवरण **परिशिष्ट 2.1.17** में दिया गया है।

3. विदिशा

विदिशा जिला वर्ष 2017-18 में सूखा से प्रभावित था तथा इससे प्रभावित किसानों को फसल की हानि के लिए अधिकतम राहत राशि ₹60,000 प्राप्त करने का अधिकार था। जबकि, हमने पाया कि कलेक्टर विदिशा ने 149 व्यक्तियों को ₹60,000 की अधिकतम सीमा से अधिक राहत राशि का भुगतान किया, जो तीन से 18 के बीच कई लेनदेन के माध्यम से किया गया। इन 149 व्यक्तियों को कुल ₹1.52 करोड़ वितरित किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.1.18** में दिया गया है।

यह भी पाया गया कि विदिशा, कलेक्टर ने वर्ष 2018-19 के दौरान 18 लेनदेनों के माध्यम से एक लाभार्थी, श्रीमती संतोष¹⁶ को सूखा राहत के रूप में ₹2.55 लाख का भुगतान किया, जबकि तहसीलदार, सिरोंज ने भी वर्ष 2019-21 के दौरान कीट प्रकोप एवं अत्यधिक वर्षा के लिए श्रीमती संतोष को 28 लेनदेन के माध्यम से ₹2.64 लाख का भुगतान किया। श्रीमती संतोष को 46 लेनदेन के माध्यम से ₹5.19 लाख का वितरण संदिग्ध प्रतीत होता है।

शासन ने शिवपुरी एवं देवास जिले के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023)। विदिशा जिले में 40 प्रतिशत प्रकरणों की जांच में यह पाया गया कि किसानों के विभिन्न गाँव में अलग-अलग कृषि भूमि के लिए पृथक-पृथक देयकों के माध्यम से प्रत्येक ₹60,000 की सीमा के भीतर भुगतान किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार एक किसान को सूखा राहत के रूप में अधिकतम ₹60,000 का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि इन 149 व्यक्तियों को तीन से 18 के बीच कई लेन-देन के माध्यम से ₹70,000 से लेकर ₹2.55 लाख का भुगतान किया गया था। इनमें से कई लेन-देन एक ही दिनांक को किए गए, जिससे ये भुगतान संदिग्ध भुगतान की श्रेणी में आते हैं।

¹⁶ **परिशिष्ट 2.1.18** के क्रमांक एक में उल्लेखित।

अनुशंसाएं:

1. मध्य प्रदेश शासन को असफल लेनदेन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करनी चाहिए। आई.एफ.एम.आई.एस. में असफल लेनदेन के भुगतान के मामले में मूल देयकों एवं रिफंड देयकों के बीच लिंक बनाने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए।
2. मध्य प्रदेश शासन को ई-स्वीकृति आई.एफ.एम.आई.एस. के स्वीकृति मॉड्यूल से तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए और स्वीकृति आदेशों के भौतिक रूप से अपलोड को तुरंत रोकना चाहिए।
3. मध्य प्रदेश शासन को कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए तथा जिम्मेदार कर्मचारियों को दंडित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शासन को भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ग्लोबल बजट प्रणाली की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए।

2.1.9 प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत वितरण में ₹0.52 करोड़ का दोहरा भुगतान

कार्यालय कलेक्टर, विदिशा एवं दमोह के भुगतान आदेश सूचियों की जांच में, हमने चार ऐसे देयक पाए जो सभी प्रकार से चार अन्य देयकों के समान थे, जिससे ज्ञात हुआ कि 732 लाभार्थियों को उनके हक से दोगुना भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.52 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इन देयकों का विवरण नीचे दी गई तालिका 2.1.6 में दिया गया है:

तालिका 2.1.6: उन देयकों का विवरण जिनके माध्यम से दोहरा भुगतान किया गया है								
(₹ लाख में)								
क्रमांक	जिला	देयक संख्या	दिनांक	राशि	लाभार्थियों की संख्या	दोहरा भुगतान		
1.	विदिशा	अनुदान/2000948858	29 अगस्त 2018	14.95	175	14.95		
2.		अनुदान/2000948861	05 सितंबर 2018	14.95				
3.		अनुदान/2000559503	06 जुलाई 2018	8.01			102	8.01
4.		अनुदान/2000752524	03 अगस्त 2018	8.01				
5.		अनुदान/2000752395	02 अगस्त 2018	12.60			143	12.60
6.		अनुदान/2000818932	09 अगस्त 2018	12.60				
7.	दमोह	अनुदान/20001416684	12 अक्टूबर 2018	16.30	312	16.30		
8.		अनुदान/20002183090	29 जनवरी 2019	16.30				
कुल				103.72	732	51.86		

(स्रोत: कार्यालय कलेक्टर, विदिशा एवं दमोह द्वारा उपलब्ध कराई गई भुगतान आदेश सूची)

शासन ने (जून 2023) विदिशा जिले के लिए प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा ₹21 लाख की वसूली की। वसूली की गई राशि को शासकीय खाते में जमा किया गया है तथा शेष राशि की वसूली की जा रही है। दमोह जिले के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

2.1.10 खंडवा जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से राहत का अनियमित वितरण

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत राशि जारी करते समय मध्य प्रदेश शासन को निर्देशित (जनवरी 2020) किया कि व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित सहायता का वितरण अनिवार्य रूप से लाभार्थी के खाते के माध्यम से किया जाए। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने भी सभी कलेक्टर को निर्देश दिया (जुलाई 2019) कि वे राहत राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करें।

हमने खंडवा जिले के सभी पांच तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि खंडवा जिले ने वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा का सामना किया। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार, राहत राशि प्रभावित किसानों के खातों में सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि का उपयोग करके भुगतान की जानी थी। जबकि, खंडवा जिले की सभी तहसीलों के तहसीलदारों ने 105 सहकारी समितियों के 107 खातों में ₹164.31 करोड़ की राहत राशि का भुगतान किया और उन प्रभावित किसानों की सूची प्रदान की जिनको राहत वितरित की जानी थी। इन समितियों ने तहसीलदारों से प्राप्त राहत राशि को अपनी समिति स्तर पर संचालित बचत खातों में भौतिक खाताबही में जमा किया। यह भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था। सहकारी समितियों के खातों में ₹164.31 करोड़ के जमा होने का विवरण परिशिष्ट 2.1.19 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि सहकारी समितियों के माध्यम से राहत राशि का वितरण करने का निर्णय, प्रभावित व्यक्तियों को राहत का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था।

तथ्य यह है कि विभागीय प्राधिकारियों की कार्रवाई भारत सरकार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था और यह भी स्पष्ट नहीं है कि केवल एक जिले में ही इस प्रक्रिया को क्यों लागू किया गया।

इसके अतिरिक्त, समितियों के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अभियुक्तियाँ भी संज्ञान में आईं:

2.1.10.1 लाभार्थियों की सही पहचान के बिना भुगतान

मध्य प्रदेश शासन ने डी.डी.ओ. स्तर पर अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित किया (नवंबर 2015), जिसमें बताया कि जिन दावेदारों को भुगतान किया जाना है, उनके द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरणों की पुष्टि निरस्त किए गए चेक अथवा चेक की कॉपी अथवा अद्यतन बैंक

पासबुक अथवा बैंक खाता के सत्यापित पत्रक से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक खाता विवरण उस वास्तविक दावेदार से संबंधित हो, जिसे भुगतान किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 105 सहकारी समितियों ने तहसीलदारों द्वारा प्रदान की गई किसानों की सूची के आधार पर किसानों के खातों में राहत की राशि जमा की, जबकि तहसीलदारों¹⁷ ने वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों को भेजी गई किसानों की सूची में कोई पहचान विवरण शामिल नहीं किया। आगे, वर्ष 2020-21 के लिए, तहसीलदारों ने लाभार्थियों की पहचान के लिए केवल खसरा नंबर को ही सूची में शामिल किया। लाभार्थियों के बचत खाता संख्या को तहसीलदार द्वारा भेजी गई सूची में शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि सहकारी समितियों ने उन किसानों की पहचान कैसे की, जिन्हें तहसीलदारों द्वारा राहत स्वीकृत की गई थी, और लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि वास्तव में राहत वास्तविक लाभार्थियों को ही वितरित की गई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि किसानों को राहत राशि का भुगतान पूर्व से संचालित बचत खातों में किया गया था तथा कोई नया खाता नहीं खोला गया। इसलिए, अलग से के.वाई.सी. नहीं ली गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तहसीलदारों को लाभार्थी की उचित पहचान की सुविधा के लिए समितियों को भेजी गई सूची में सहकारी समितियों में संचालित बचत खाता संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना चाहिए था।

2.1.10.2 तहसीलदारों और सहकारी समितियों के आंकड़ों में ₹8.28 करोड़ की विसंगति

तहसीलदारों द्वारा सहकारी समितियों को जारी की गई राहत राशि के संबंध में ई-भुगतान विवरण की जांच में, यह पाया गया कि तहसीलदारों ने वर्ष 2019-21 के दौरान आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से 41 सहकारी समितियों के खातों में ₹56.91 करोड़ जमा किए थे। लेखापरीक्षा ने संबंधित समितियों के बैंक खाते के विवरण से सत्यापन किया और पाया कि तहसीलदारों द्वारा जारी की गई ₹56.91 करोड़ की राशि उनके खातों में जमा की गई है। जबकि, इन समितियों ने केवल ₹48.63 करोड़ की प्राप्ति प्रमाणित की। इस प्रकार, इन समितियों द्वारा प्रमाणित प्राप्तियों एवं वास्तव में उनके बैंक खातों में जमा की गई राशि के बीच ₹8.28 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतर था। इस प्रकार इन सहकारी समितियों द्वारा ₹8.28 करोड़ के संदिग्ध दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विवरण **परिशिष्ट 2.1.20** में दिया गया है।

¹⁷ 1. तहसीलदार, खंडवा, 2. तहसीलदार, खालवा, 3. तहसीलदार, पुनासा

इसके अतिरिक्त हमने यह भी पाया कि इन 41 सहकारी समितियों में से 12¹⁸ सहकारी समितियों ने संबंधित तहसीलदारों को इसी प्रकार के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि सहकारी समितियों को भुगतान की गई राशि का मिलान कर लिया गया है और कोई अंतर नहीं पाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस दावे को सत्यापित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज (मिलान पत्रक) प्रदान नहीं किया गया कि कोई दुर्विनियोजन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खंडवा के प्रतिवेदन पर आधारित है, जिनकी सहकारी समितियों पर धन के दुरुपयोग का संदेह है। इसके अलावा, कलेक्टर खंडवा ने मामले की जांच के लिए कोई अलग समिति का गठन नहीं किया।

अनुशंसा 4: मध्य प्रदेश शासन को इस तरह की विसंगति के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए एवं दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

2.1.10.3 पुनासा तहसील में अतिवृष्टि से फसल क्षति हेतु ₹4.93 करोड़ का अधिक भुगतान

ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, ग्राम सचिव और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त दल द्वारा तैयार किए गए पंचनामा के अनुसार, पुनासा तहसील के 14¹⁹ गांवों में 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक फसल की क्षति हुई थी। जबकि, पुनासा तहसील के तहसीलदार द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए 2,752 किसानों के लिए समितियों को 100 प्रतिशत तक फसल क्षति मानते हुए राहत का भुगतान किया। तहसीलदार की इस उदासीनता से समितियों को ₹4.93 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि फसल क्षति का प्रतिशत, पूर्वमुद्रित पंचनामा में 25 से 33 प्रतिशत के रूप में दर्ज था, जिसे सर्वेक्षण के समय सही नहीं किया गया। जबकि, भुगतान हानि पत्रक के आधार पर किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जो 100 प्रतिशत तक फसल क्षति को मान्य करने के उनके निर्णय को उचित ठहराते हों। जबकि, कृषि, राजस्व एवं पंचायत विभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ 10 ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामे स्पष्ट रूप से 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक फसल क्षति को दर्शाते हैं।

¹⁸ परिशिष्ट 2.1.20 के क्रमांक 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 30 और 40 में उल्लेखित।

¹⁹ 1. धावड़िया, 2. डुहिक्या, 3. कोठी, 4. बिलोराखुर्द, 5. गोधदपुरा, 6. कटार, 7. बाखरगांव, 8. करोली, 9. पिपल्यासेलानी, 10. लोंधी, 11. मसलाय, 12. सुलगांव, 13. सेलानी, 14. मथेला।

अनुशंसा 5: मध्य प्रदेश शासन को अधिक भुगतान की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

2.1.11 सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ₹5.85 करोड़ के सूखा राहत का भुगतान

एम.पी.एफ.सी. भाग एक के नियम 8 में प्रावधान है कि कोई भी शासकीय सेवक लोक निधि से कोई भी व्यय नहीं कर सकता, जब तक कि व्यय सक्षम प्राधिकारी जो ऐसे व्यय के स्वीकृति देने हेतु सक्षम है, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्वीकृत हो।

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी जिले के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमें प्रभावित किसानों को राहत के लिए भुगतान किए गए ₹5.85 करोड़ के नौ देयकों के साथ सक्षम प्राधिकारी अर्थात संबंधित तहसीलों के तहसीलदार के स्वीकृति आदेश नहीं मिले। विवरण तालिका 2.1.7 में दिया गया है:

तालिका 2.1.7: सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना भुगतान किए गए देयकों का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
क्रमांक	देयक संख्या	दिनांक	जिस तहसील से सम्बंधित है	जिला	राशि
1	अनुदान/20001142763	14-09-18	खनियाधाना	शिवपुरी	0.47
2	अनुदान /20001210107	25-09-18	खनियाधाना	शिवपुरी	1.00
3	अनुदान /20001198832	25-09-18	कोलारस	शिवपुरी	1.38
4	अनुदान /20001085498	10-09-18	कोलारस	शिवपुरी	0.54
5	अनुदान /20001150126	18-09-18	कोलारस	शिवपुरी	0.10
6	अनुदान /20001215007	28-09-18	कोलारस	शिवपुरी	0.28
7	अनुदान /20001142729	18-09-18	कोलारस	शिवपुरी	0.59
8	अनुदान /20001115307	10-09-18	कोलारस	शिवपुरी	0.65
9	अनुदान /20001218587	28-09-18	कोलारस	शिवपुरी	0.84
योग					5.85

(स्रोत: कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए देयक)

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना एम.पी.एफ.सी. के नियम 8 का उल्लंघन कर ₹5.85 करोड़ का किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि जांच प्रगति पर है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

2.1.12 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

2.1.12.1 बिना व्यय किये ₹10 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी के अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी को वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹176

करोड़ एवं ₹25.91 करोड़ की सूखा राहत राशि आवंटित की थी। इस ₹201.91 करोड़ के विरुद्ध प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं वास्तव में वितरित की गई राशि का विवरण **तालिका 2.1.8** में दिया गया है:

तालिका 2.1.8: प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाई गई राशि एवं वास्तव में वितरित की गई राशि का विवरण							
(₹ करोड़ में)							
वर्ष	योजना 6422 के अंतर्गत आवंटित राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र में वितरित के रूप में दिखाई गई राशि	संव्यवहारों के असफल होने पर जमा शीर्ष 8443 के अंतर्गत जमा की गई राशि	पुनर्भुगतान देयकों के माध्यम से जमा शीर्ष 8443 से भुगतान की गई राशि	जमा शीर्ष 8443 के अंतर्गत असंवितरित पड़ी राशि	वास्तव में वितरित की गई राशि	बिना व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र में सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7=3-6	8=3-7
2018-19	176.00	176.00	14.25	5.45	8.80	167.20	8.80
2019-20	25.91	14.77	1.25	0.00	1.25	13.52	1.25
योग	201.91	190.77	15.50	5.45	10.05	180.72	10.05

(स्रोत: कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए देयक)

हमने पाया की जब बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. में कोई विसंगति होती है, तो संव्यवहार असफल हो जाता है। बैंक असफल संव्यवहारों की राशि को जमा शीर्ष 8443-101-0120 (सिविल जमा) के अंतर्गत जमा करता है। जमा शीर्ष में जमा राशि को वास्तव में व्यय मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राशि अभी भी शासकीय खाते में जमा है। **तालिका 2.1.8** दिखाती है कि ₹10.05 करोड़ जमा शीर्ष 8443 के अंतर्गत अवितरित जमा थी। जबकि, कलेक्टर शिवपुरी ने राहत आयुक्त को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों में ₹10.05 करोड़ की असफल संव्यवहारों की राशि सम्मिलित की, जो उपरोक्त जमा शीर्ष 8443 में जमा थी। इस प्रकार, ₹10.05 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र राहत आयुक्त को बिना धन के उपयोग की सुनिश्चितता के प्रस्तुत किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि शिवपुरी जिले से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

2.1.12.2 निधियों का विचलन तथा भारत सरकार को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के गठन तथा प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि एस.डी.आर.एफ. का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट के प्रकोप तथा पाला एवं शीतलहर से प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए होने वाले व्ययों को करने के लिए किया जाएगा।

कार्यालय राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-21 के दौरान एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत प्राप्त ₹731.37 करोड़, सांप के काटने, पानी में डूबने/ आकाशीय बिजली गिरने, जंगली जानवरों के कारण फसल क्षति, सिंचाई परियोजनाओं में मरम्मत, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन के लिए राहत पर व्यय किया गया था, जबकि ये मद एस.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों में निहित नहीं हैं। विवरण तालिका 2.1.9 में दिया गया है:

तालिका 2.1.9: भारत सरकार को प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
वर्ष	एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत कुल व्यय	भारत सरकार को भेजी गई उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	उन मदों पर व्यय जो एस.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों में निहित नहीं है	एस.डी.आर.एफ. में निहित मदों पर वास्तविक व्यय	भारत सरकार को भेजी गई गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि
1	2	3	4	5=2-4	6=3-5
2018-19	1,430.80	1,350.00	193.39 ²⁰	1,237.41	112.59
2019-20	2,780.38	2,778.14	181.53 ²¹	2,598.85	179.29
2020-21	4,147.01	3,833.39	753.11 ²²	3,393.90	439.49
योग	8,358.19	7,961.53	1,128.03	7,230.16	731.37

(स्रोत: कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी)

जिसके परिणामस्वरूप निधियों का विचलन हुआ और भारत सरकार को ₹731.37 करोड़ के त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि लेखापरीक्षा ने एस.डी.आर.एफ. के लिए योजना 5504 के अंतर्गत किए गए व्यय पर विचार नहीं किया, जबकि इस योजना के अंतर्गत बिजली गिरने, डूबने, असामयिक वर्षा के कारण मानव एवं पशु जीवन की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में इन मदों का उल्लेख नहीं किया है।

²⁰ 1. डूबना अथवा बिजली गिरना ₹ 121.76 करोड़, 2. सर्पदंश ₹ 70.84 करोड़, 3. जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति ₹ 0.79 करोड़।

²¹ 1. डूबना अथवा बिजली गिरना ₹ 181.48 करोड़, 2. पुनर्वास पर खर्च ₹ 0.05 करोड़।

²² 1. सिंचाई परियोजनाओं में मरम्मत ₹ 0.04 करोड़, 2. आपदा प्रबंधन बनाने पर व्यय ₹ 23.73 करोड़, 3. आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार आपदा के अंतर्गत वित्तीय सहायता ₹ 729.25 करोड़, 4. पुनर्वास पर खर्च ₹ 0.09 करोड़।

2.1.13 ₹10 लाख की निधि का विचलन

कार्यालय राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में पड़े सूखा के कारण मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 133 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। वर्ष 2020-21 में होशंगाबाद जिले में ₹9.88 लाख की सूखा राहत राशि वितरित की गई, जो वर्ष 2017-18 के सूखा प्रभावित जिलों की सूची सम्मिलित नहीं था।

आगे की जांच में पाया गया कि तहसीलदार, डोलरिया ने योजना मद 2018-अतिवृष्टि से अधिक वर्षा के कारण हुई फसल क्षति के लिए 163 किसानों को ₹9.88 लाख स्वीकृत किए (मार्च 2021)। जबकि, व्यय को योजना शीर्ष 6422-सूखा राहत के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निधि का विचलन हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कलेक्टर होशंगाबाद से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

2.1.14 लाभार्थियों को विलम्ब से राहत का वितरण

आर.बी.सी. 6-4 प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

आठ जिलों के कलेक्टर एवं सभी तहसीलदारों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में, पाया गया की सूखे एवं कीट प्रकोप से प्रभावित 6.91 लाख किसानों को ₹563.72 करोड़ रुपये की राहत छः माह से 29 माह तक के विलम्ब से वितरित की गयी, जो योजनाओं के उद्देश्य को विफल किया। विवरण तालिका 2.1.10 में दिया गया है:

तालिका 2.1.10: राहत के वितरण में विलम्ब का विवरण					
जिला	आपदा का प्रकार	अवधि जिसमें आपदा आई	राहत वितरण में विलम्ब	किसानों की संख्या जिन्हें विलम्ब से राहत वितरित हुई। (लाख में)	राहत की वितरित राशि (₹ करोड़ में)
आगर-मालवा	कीट प्रकोप	जून-अगस्त 2020	6 से 17 महीने	1.12	71.98
दमोह	सूखा	जून-सितंबर 2017	6 से 27 महीने	0.71	47.19
	कीट प्रकोप	जून-अगस्त 2020	6 से 7 महीने	0.49	16.73
देवास	कीट प्रकोप	जून-अगस्त 2020	6 से 17 महीने	0.83	77.53
रायसेन	कीट प्रकोप	जून-अगस्त 2020	6 से 10 महीने	0.10	6.43
सतना	सूखा	जून-सितंबर 2017	6 से 17 महीने	0.42	25.28
सीहोर	कीट प्रकोप	जून-अगस्त 2020	6 से 12 महीने	0.97	96.10
शिवपुरी	सूखा	जून-सितंबर 2017	6 से 29 महीने	1.14	101.20
विदिशा	सूखा	जून-सितंबर 2017	6 से 21 महीने	1.13	121.28
योग				6.91	563.72

(स्रोत: संबंधित जिलों के कलेक्टरों एवं तहसीलदारों द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूची)

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और उत्तर दिया कि जिला कलेक्टरों को भविष्य में राहत के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.1.15 तहसीलदारों द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का उल्लंघन

आर.बी.सी. 6-4 में प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत पीड़ितों या पीड़ितों के परिवार को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए तहसीलदार, एस.डी.ओ. एवं कलेक्टर को क्रमशः ₹0.50 लाख, ₹ चार लाख एवं ₹ पांच लाख तक की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गईं।

भुगतान आदेश सूचियों की नमूना जांच में, हमने पाया गया कि छः²³ जिलों के 20 तहसीलदारों ने 216 देयकों के माध्यम से 3391 व्यक्तियों को वित्तीय शक्तियों से परे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत के लिए ₹26 करोड़ की राहत का भुगतान किया, जिनके साथ सक्षम प्राधिकारी अर्थात् एस.डी.ओ. का स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं था। विवरण परिशिष्ट 2.1.21 में दिया गया है।

इस प्रकार, इन 20 तहसीलदारों द्वारा वित्तीय शक्तियों से परे ₹26 करोड़ का भुगतान किया गया जो प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि तहसीलदारों ने एस.डी.ओ. की स्वीकृति मिलने के बाद स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भौतिक देयकों के साथ एस.डी.ओ. की स्वीकृति संलग्न नहीं थी और उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.1.16 जमा शीर्ष 8443-101-0120 के अंतर्गत जमा धनराशि का लेखांकन न किया जाना

चयनित 13 जिलों के कलेक्टर एवं तहसीलदार कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, पाया गया कि संबंधित डी.डी.ओ. के पास जमा शीर्ष 8443-101-0120 के अंतर्गत प्रत्येक योजना के असफल संव्यवहारों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो भुगतान के लिए लंबित थी। आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से आहरित डी.डी.ओ. के आबंटन एवं व्यय प्रतिवेदन में असफल संव्यवहारों को भी वास्तविक व्यय के रूप में दर्शाया गया, और उपयोगिता प्रमाणपत्र भी इसी प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर कंडिका 2.1.12.1 में पूर्व में ही टिप्पणी की गई है। इस प्रकार, जमा शीर्ष 8443-101-0120 (सिविल जमा) के अंतर्गत जमा धन पर कोई निगरानी नहीं है।

²³ 1. आगर-मालवा, 2. मंदसौर, 3. रायसेन, 4. सिवनी, 5. श्योपुर, 6. विदिशा।

छतरपुर, मंदसौर, शिवपुरी एवं सीहोर जिलों में दोषी कर्मचारियों ने कपटपूर्ण भुगतान करने के लिए जमा शीर्ष 8443-101-0120 के अंतर्गत उपलब्ध बड़ी मात्रा में धनराशि का दुरुपयोग किया।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और सूचित किया कि डी.डी.ओ. को 100 प्रतिशत समाधान करके तीन से छः दिनों में असफल संव्यवहार के देयकों को पुनः तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं कलेक्टर को असफल संव्यवहारों की क्रमशः साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

2.1.17 राहत वितरण में निगरानी तंत्र का अभाव

राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश और चयनित 13 जिलों के कलेक्टर कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में राहत वितरण में निगरानी तंत्र नहीं पाया गया। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों को विभिन्न राहतों के वितरण की निगरानी के लिए न तो कोई समिति गठित की गई और न ही कोई प्रणाली स्थापित की गई।

इस प्रकार, निगरानी तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप राहत के वितरण में देरी हुई और अनधिकृत व्यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान हुए, जैसा कि **कंडिका 2.1.8.5** में बताया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उन्होंने संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को निरीक्षण के दौरान राहत प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किया है। उन्हें प्रकरणों को स्वीकृति देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रकरणों के निपटान में लगने वाले समय तथा स्वीकृति के बाद संवितरण में लगने वाले समय की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 6: मध्य प्रदेश शासन को लाभार्थियों को राहत के उचित वितरण के लिए मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.18.1 निष्कर्ष

- लेखा परीक्षा में चयनित 13 जिलों में कर्मचारियों एवं उनके रिश्तेदारों सहित अनधिकृत व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत के लिए ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण पाया गया। जाली स्वीकृति आदेश तैयार करके, वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में राहत का भुगतान करके, ई-भुगतान में लाभार्थियों के जाली नामों का उपयोग करके कपटपूर्ण लेनदेन किए गए, जबकि ये खाते बैंक अभिलेखों में अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। ग्लोबल बजट प्रणाली एवं

आई.एफ.एम.आई.एस. में कमी ने कर्मचारियों को शासकीय धन का गबन करने में सक्षम बना दिया था।

- लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राहत जमा करने के भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, खंडवा जिले के सभी तहसीलदारों ने अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति की राहत राशि वितरित करने के लिए 105 सहकारी समितियों को ₹164.31 करोड़ का भुगतान किया। इन समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में, लाभार्थियों की उचित पहचान के बिना भुगतान, तहसीलदारों तथा सहकारी समितियों के आंकड़ों के बीच ₹8.28 करोड़ की विसंगति एवं ₹4.93 करोड़ के अधिक भुगतान जैसी अनियमितताएं परिलक्षित हुईं।
- आठ जिलों (आगर-मालवा, दमोह, देवास, रायसेन, सतना, सीहोर, शिवपुरी, विदिशा) में हमने पाया कि सूखे एवं कीट प्रकोप से प्रभावित 6.91 लाख लोगों को ₹563.72 करोड़ की राहत राशि के वितरण में छः माह से 29 माह तक का विलम्ब हुआ, जिसने इन योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया।
- हमने पाया कि प्रणालीगत कमियाँ जैसे कि ग्लोबल बजटिंग में कमी, आई.एफ.एम.आई.एस. में खामियां और देयकों के साथ हानि पत्रक एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन जैसे आवश्यक दस्तावेजों का सलंगन न करना संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान करने में सहायता प्रदान की।

राजस्व विभाग

2.2 शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

2.2.1 प्रस्तावना

भूमि सीमित परिमाण की परिसम्पत्ति है। अतः भूमि के उपयोग को ऐसे नीतिगत ढांचे के तहत नियंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण है जो लोकहित के अनुकूल हो एवं भूमि की विभिन्न प्रतिस्पर्धी मांगों का समाधान करती हो। शासकीय भूमि शासन के विभागों, निजी संस्थाओं/व्यक्तियों, राजनैतिक दलों, स्थानीय निकायों, चैरिटेबल संस्थाओं आदि को विभिन्न उद्देश्यों हेतु या तो नीलामी से अथवा अन्य माध्यम से आवंटित की जाती है। मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) एवं मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 (एम.पी.एन.बी.एन.एन.) में सम्भावित आवेदकों को विभिन्न प्रकार की भूमि के आवंटन हेतु दी जाने वाली विभिन्न रियायतों को निर्धारित किया गया है। राज्य में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन हेतु राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन उत्तरदायी है।

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन के एम.पी. भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध (31.03.2022) आकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में शासकीय भूमि का कुल क्षेत्रफल 8710580 हेक्टेयर है, जबकि लेखापरीक्षा में समाहित शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 1428375 हेक्टेयर (16.40 प्रतिशत) है।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के प्रमुख हैं। प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख हैं। आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन शासकीय भूमि के भू-सर्वेक्षण के प्रबंधन एवं अभिलेखों को तैयार कर संधारित करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक जिले में, कलेक्टर विभाग की गतिविधियों को प्रशासित करता है। उपखण्ड का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) के पास होता है। अनुविभागीय अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करते हैं। अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की पदस्थापना राजस्व अभिलेखों के संधारण हेतु कलेक्ट्रेट में की जाती है। तहसीलदार/अपर तहसीलदार तहसीलों में विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

“शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन” पर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई थी कि:-

1. शासकीय भूमि का आवंटन विभागीय संहिता, नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया गया था।
2. शासकीय भूमि के सर्वोत्तम प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवंटित भूमि की उपयोगिता की स्थिति की समीक्षा की गई थी।
3. भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली हेतु प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावकारिता पर्याप्त थी।
4. शासकीय भूमि के सर्वोत्तम प्रबंधन एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (म.प्र.भू.रा.स.), 1959, मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.), म.प्र.भू.रा.स. (भू-राजस्व के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018, मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020, म. प्र. भू. रा.स. (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020, म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993, भारतीय स्टाम्प (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 2014, महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा जारी सामान्य अनुदेश (उपबंध²⁴), कलेक्टर बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) एवं विभाग/शासन द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं से लिए गए थे।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-22 की अवधि सम्मिलित है। हमने विभाग स्तर पर कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल एवं आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन से सम्बंधित अभिलेखों का परीक्षण किया है। हमने कलेक्टर एवं तहसीलों में अभिलेखों की नमूना जांच के लिए आठ जिलों का चयन किया जैसा की विवरण निम्नवत है।

- आठ चयनित जिलों में चार²⁵ महानगर हैं जिन्हें बेहतर कवरेज के लिए सम्मिलित किया गया है।
- तीन²⁶ जिलों का चयन प्रतिस्थापन रहित साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति द्वारा किया गया। इन तीन चयनित जिलों में सिंगरौली (औद्योगिक जिला) सम्मिलित था।

²⁴ मार्गदर्शिका में सामान्य प्रावधान

²⁵ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर

²⁶ देवास, शहडोल, सिंगरौली

- एक और औद्योगिक इकाई को सम्मिलित करने के लिए, धार को निर्णयात्मक प्रतिचयन द्वारा चयनित किया गया।

नजूल भूमि के प्रबंधन का परीक्षण करने की दृष्टि से, हमने प्रत्येक चयनित जिले में शासकीय भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वोच्च दो शहरी तहसील एवं एक निम्नतम ग्रामीण तहसील का चयन किया। लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में वर्ष 2019-22 की अवधि से सम्बंधित कुल 301 भूमि आवंटन प्रकरणों²⁷ तथा 369 नवीनीकरण प्रकरणों²⁸ की नमूना जांच की। चयनित जिलों, तहसीलों एवं ग्रामों का विवरण **परिशिष्ट -2.2.1 (क)** में दिया गया है एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित 76 भूमि आवंटन से सम्बंधित स्थलों का विवरण **परिशिष्ट-2.2.1(ख)** में दिया गया है। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करते समय स्थलों की फोटोग्राफी भी की गई।

प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आयुक्त, भू-अभिलेख के साथ 22 जुलाई 2022 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली एवं लेखापरीक्षा मानदंडों पर चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मलेन 07 जून 2023 को आयोजित किया गया और शासन से प्राप्त उत्तर (जून 2023) को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 बाजार मूल्य के अवनिर्धारण एवं पंचायत उपकर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि

2.2.6.1 मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) दरों को गलत ढंग से लागू किए जाने के कारण बाजार मूल्य का अवनिर्धारण

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 31 के अनुसार, किसी चैरिटेबल संस्था को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन के प्रकरण में, भूमि के बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम एवं निर्धारित दरों की दो गुने दर से वार्षिक पट्टा किराया आरोपित किया जाएगा। उक्त निर्देशों की कंडिका 65 में प्रावधान है कि स्थायी पट्टे की अवधि को 99 वर्ष तक बढ़ाने के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 59 में प्रावधान है कि भू-राजस्व का निर्धारण भूमि के उपयोग के संदर्भ में ऐसी दरों पर, जो निर्धारित की जाए, किया जाएगा। महानिरीक्षक, पंजीयन की मार्गदर्शिका के उपबंधों के अनुसार, राजमार्ग या उसके बाईपास पर स्थित किसी भी भूमि का मूल्य, उन क्षेत्रों एवं

²⁷ भोपाल-26, देवास-05, धार-50, ग्वालियर-53, इन्दौर-34, जबलपुर-54, शहडोल-29 एवं सिंगरौली-50

²⁸ भोपाल-36, देवास-148, धार-05, ग्वालियर-01, इन्दौर-20, जबलपुर-145, शहडोल-14

गांवों जिनके लिए मार्गदर्शिका दरें (सड़क विशिष्ट) अलग से निर्दिष्ट की गई हैं, को छोड़ कर, दोगुना किया जाएगा।

जिला भोपाल की तहसील हुजूर (ग्रामीण) में भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच (दिसंबर 2022) में पता चला कि राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (दिसंबर 2020) के अनुसार, 20.234 हेक्टेयर भूमि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बंगलुरु को एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 99 साल की अवधि हेतु स्थायी पट्टे पर आवंटित (दिसंबर 2020) की गई थी। आर.बी.सी. के प्रावधानों एवं मध्य प्रदेश शासन के आवंटन आदेश के अनुसार कलेक्टर ने वर्ष 2019-20 की कलेक्टर मार्गदर्शिका दरों के अनुसार बाजार मूल्य ₹109.26 करोड़ का अनुमोदन किया। जबकि, पट्टा विलेख को ₹38.85 करोड़ के बाजार मूल्य पर निष्पादित (जनवरी 2021) किया गया और संस्थान ने ₹9.71 करोड़ (बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत) प्रीमियम का भुगतान किया। स्वीकृत दरों से कम पर पट्टा विलेख निष्पादित करने का कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पट्टा विलेख के अनुसार, भू-खंड राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर स्थित था। इस प्रकरण में, कलेक्टर मार्गदर्शिका में आवंटित भूमि की सड़क-विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए भूमि का बाजार मूल्य दो गुना किया जाना आवश्यक था, जबकि अपर तहसीलदार ने भूमि का बाजार मूल्य सामान्य बाजार मूल्य से दोगुना करने के बजाय सामान्य दर पर प्रस्तावित किया, जिसके परिणामस्वरूप भू-खंड के बाजार मूल्य का ₹179.68 करोड़²⁹ अवनिर्धारण हुआ। कलेक्टर ने भी मार्गदर्शिका के प्रावधानों की उपेक्षा की।

इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुसार, 99 साल की अवधि के लिए पट्टा विलेख (लीज डीड) पर स्टाम्प शुल्क, प्रीमियम और औसत वार्षिक पट्टा किराया (लीज रेंट) के योग या भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर देय है। चूंकि पट्टा विलेख में प्रीमियम की राशि गलत तरीके से कम करके बताई गई थी, प्रीमियम कम बताने के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई जैसा कि निम्न तालिका 2.2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.1: बाजार मूल्य के कम निर्धारण के कारण कुल राजस्व की हानि (₹ करोड़ में)			
प्रीमियम की हानि	स्टांप शुल्क की हानि	पंजीयन शुल्क की हानि	कुल हानि
44.92	11.48	8.65	65.05

कुल हानि की विस्तृत गणना परिशिष्ट-2.2.2 में दर्शाई गई है।

जैसा कि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 65 के तहत अनिवार्य है, पट्टा अवधि को 99 वर्ष तक बढ़ाने के संबंध में वित्त विभाग की सहमति भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। उपरोक्त

²⁹ बाजार मूल्य ₹109.26 करोड़ X 2 - ₹38.85 करोड़ = ₹179.67 करोड़

अपेक्षित सहमति के बिना भूमि आवंटन तथा प्रीमियम, स्टॉप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के कम आरोपण/ कम भुगतान के परिणामस्वरूप भूमि का अनियमित आवंटन हुआ, जिससे शासकीय राजकोष को ₹65.05 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था। मंत्रिपरिषद का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों से परे नहीं जा सकता। इसके अलावा, प्रमुख सचिव ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस मुद्दे पर कैबिनेट नोट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि कैबिनेट नोट में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, उचित तथ्य शामिल हैं अथवा नहीं।

अनुशंसा 1: विभाग को अवनिर्धारित राजस्व की आक्षेपित राशि की वसूली करनी चाहिए।

2.2.6.2 पंचायत उपकर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 74 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्दिष्ट दरों (50 पैसे प्रति एक रुपया राजस्व) पर पंचायत उपकर आरोपित किए जाने का प्रावधान है। म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 2 (एम-1) के अनुसार, पंचायत उपकर की गणना के लिए प्रीमियम और किराया भी शामिल है।

कलेक्टर, धार के कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण में, बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत इंद्रावल में 3.750 हेक्टेयर³⁰ शासकीय भूमि एल.पी.जी. पाइपलाइन के लिए इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन के निर्माण हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड³¹, इंदौर को आवंटित की गई थी (जनवरी 2022)। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निर्धारित किए गए प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराये पर पंचायत उपकर आरोपित किया जाना आवश्यक था, क्योंकि भू-खंड पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित था, लेकिन कोई पंचायत उपकर नहीं लगाया गया और न ही आवेदक से वसूल किया गया। निम्न तालिका 2.2.2 पंचायत उपकर के अनारोपण को दर्शाती है:-

तालिका 2.2.2: पंचायत उपकर का अनारोपण			
			(राशि ₹ में)
बाजार मूल्य	प्रमियम ³²	पट्टा किराया	अधिरोपित किए जाने योग्य उपकर (कॉलम 2 एवं 3 के योग का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4
1,39,50,000	1,39,50,000	75,000	70,12,500
वसूली योग्य राशि = ₹70,12,500			

³⁰ खसरा नं. 129/1

³¹ तीन अग्रणी तेल एवं गैस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों – इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड - का संयुक्त उद्यम

³² भूमि के बाजार मूल्य के बराबर।

इस प्रकार, पंचायत उपकर के अनारोपण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 70.13 लाख की राजस्व हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित जिले धार से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

अन्तिम उत्तर अप्राप्त रहा। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.15 में इसी तरह के प्रकरण को इंगित करने के बाद भी कमी दोहराई गई।

अनुशंसा 2: शासन को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रीमियम के साथ-साथ किराए पर पंचायत उपकर लगाने के लिए अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.7 शासकीय भूमि का शून्य प्रीमियम पर आवंटन

2.2.7.1 शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शासकीय भूमि के आवंटन के कारण राजस्व की हानि

आर.बी.सी. खण्ड 4 क्रमांक 2 की कंडिका 26 के अनुसार, चैरिटेबल संस्थानों या लोक स्वास्थ्य संस्थानों को शासकीय भूमि का आवंटन, बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और सामान्य वार्षिक पट्टा किराए के 50 प्रतिशत पर किया जाएगा। एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 32(2)(ख) के अनुसार, आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य आवंटन तिथि से एक वर्ष के भीतर आरंभ कर तीन वर्ष के भीतर पूर्ण करना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि –

- राजस्व विभाग ने श्री सत्य साईं मेडिकल एंड हेल्थ केयर ट्रस्ट को सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के समीपस्थ ग्राम बड़ा बांगड़दा³³, इंदौर में शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर बच्चों के हृदय रोग के इलाज के लिए चिकित्सालय के निर्माण हेतु 2.231 हेक्टेयर भूमि आवंटित की (दिसम्बर 2019)। यह बताना प्रासंगिक होगा कि जिला कलेक्टर, इंदौर ने संभागीय आयुक्त के माध्यम से सचिव, राजस्व विभाग को भेजे गए (मई 2019) अपने प्रस्ताव में, लागू प्रावधानों के अनुसार आवंटित भूमि के बाजार मूल्य (₹5.58 करोड़) के बदले में आरोपणीय ₹5.58 करोड़³⁴ के प्रीमियम एवं ₹4.18 लाख के वार्षिक पट्टा किराये के निर्धारण कर इंगित किया था।
- राजस्व निरीक्षक (आर.आई.) ने उपरोक्त भूमि के अपने स्थल सत्यापन प्रतिवेदन (अगस्त 2022) में कहा कि भूमि अप्रयुक्त/रिक्त थी और भूमि के चारों ओर केवल एक

³³ सर्वे नम्बर 216, 217, 218, 224, 225, 226

³⁴ ₹2.50 करोड़ प्रति हेक्टेयर की दर से 2.231 हेक्टेयर भूमि का बाजार मूल्य

चारदीवारी का निर्माण किया गया था। दो वर्ष नौ माह के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होना यह इंगित करता है कि नजूल अधिकारी द्वारा आर.बी.सी. खण्ड 4, क्रमांक 1 की कंडिका 31 के अन्तर्गत अपेक्षित पट्टे की शर्तों का सत्यापन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2022) में प्रतिवेदन के तथ्यों की पुष्टि हुई।

इस प्रकार, शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि का आवंटन न तो लोक हित और न ही राजस्व हित में था, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय राजकोष को प्रीमियम ₹4.19 करोड़³⁵ और वार्षिक पट्टा किराये के रूप में ₹4.18 लाख (विद्यमान नियमों के अनुसार आरोपण योग्य) की हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था। मंत्रिपरिषद का निर्णय आर.बी.सी. के प्रावधानों से परे नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस मुद्दे पर कैबिनेट नोट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि कैबिनेट नोट में, आर.बी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप, उचित तथ्य शामिल हैं अथवा नहीं।

2.2.7.2 भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि

आर.बी.सी. खण्ड 4, क्रमांक 1 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के उपक्रम को भूमि का आवंटन प्रभावी नियमों के अनुसार बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम और बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक पट्टा किराया पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्व विभाग के आदेश (जुलाई 2018) के अनुसरण में, जिला कलेक्टर, इंदौर ने वर्ष 2018-19 की मार्गदर्शिका के अनुसार बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम और बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत वार्षिक किराया पट्टे पर ए.ए.आई. को 8.291 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जो तहसीलदार द्वारा किए गए मूल्यांकन (मार्च 2018) के अनुसार, ₹26.64 करोड़ (प्रीमियम ₹24.78 करोड़ और वार्षिक पट्टा किराया ₹1.86 करोड़) निकाला गया था।

आगामी संवीक्षा से पता चला कि राजस्व विभाग के संशोधित आदेश (अक्टूबर 2018) के अनुसार, भूमि शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि का कब्जा दिसंबर 2018 में ए.ए.आई. को सौंप दिया गया था।

³⁵ बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत

राजस्व विभाग द्वारा आर.बी.सी. प्रावधानों के उल्लंघन में शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के परिणामस्वरूप ₹26.64 करोड़ की राजस्व हानि हुई/ राजस्व प्राप्ति नहीं हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था। मंत्रिपरिषद का निर्णय आर.बी.सी. के प्रावधानों से परे नहीं जा सकता। इसके अलावा, प्रमुख सचिव ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस मुद्दे पर कैबिनेट नोट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि कैबिनेट नोट में आर.बी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप उचित तथ्य शामिल हैं।

2.2.7.3 स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर शासकीय भूमि का आवंटन

स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान, इंदौर ने तकनीकी संस्थान भवन के निर्माण हेतु एक भू-खंड के लिए आवेदन किया (अप्रैल 2002)। कलेक्टर ने लागू आर.बी.सी. प्रावधानों को आयुक्त के माध्यम से सचिव, राजस्व विभाग को भेजा (मई 2002) तथा प्रस्तावित किया कि आवंटित भूमि का मूल्यांकन आर.बी.सी. खण्ड 4, क्रमांक 1 की कंडिका 23 एवं 26 के अनुसार किया जाना आवश्यक था।

जैसा कि कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन³⁶ किया गया था, भू-खण्ड के आवंटन पर भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम के दो प्रतिशत पर वार्षिक पट्टा किराया आरोपणीय था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कलेक्टर के प्रस्ताव पर उचित विचार किए बिना, राजस्व विभाग ने सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी संस्थान, दतोदा तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर के पक्ष में दतोदा में छह सर्वे नम्बरों³⁷ में सन्निहित कुल 9.246 हेक्टेयर क्षेत्रफल के भू-खण्ड के आवंटन को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर स्वीकृति दी (सितंबर 2002)। आवंटित भूमि का कब्जा पट्टेदार को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2002) और उपरोक्त संस्थान के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित/पंजीकृत किया गया (नवंबर 2002)।

³⁶ वर्ष 2002-03 की मार्गदर्शिका दर = ₹2,80,000 प्रति हेक्टेयर;

आवंटित भूमि का क्षेत्रफल=9.246 हेक्टेयर;

भूमि का बाजार मूल्य= ₹25,88,880

प्रीमियम= बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत=₹12,94,440, वार्षिक पट्टा किराया=प्रीमियम का 2 प्रतिशत=₹25,889

³⁷ सर्वे नम्बर 2722/5, 2723/3, 2725/2, 2726/2-क्षेत्रफल 4.836 हेक्टेयर एवं 2725/1, 2726/1-क्षेत्रफल 4.410 हेक्टेयर

उपरोक्त भूमि आवंटन, आर.बी.सी. प्रावधानों और कलेक्टर के प्रस्ताव की पूर्ण उपेक्षा करते हुए, राजस्व हित में नहीं था। शून्य प्रीमियम और एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप प्रीमियम (₹12.94 लाख) और वार्षिक पट्टा किराया (₹25,889 प्रति वर्ष) की वसूली न होने से शासकीय कोष को राजस्व की हानि हुई।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 में शासकीय विभागों को आवंटित भूमि के उपयोग की स्थिति की समीक्षा तथा अप्रयुक्त भूमि को आवंटित विभाग से वापस लेने के संबंध में प्रावधान हैं। जबकि, एम.पी.एन.बी.एन.एन. में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या उक्त प्रावधानों को अशासकीय आवंटितों के लिए लागू किया जा सकता है। हालाँकि, स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर 2022) से पता चला कि आवंटित भूमि का 2.300 हेक्टेयर क्षेत्रफल अप्रयुक्त था और वर्ष 2002 से इसके अनुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इसे वापस लेने की आवश्यकता थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था तथा यह कि कलेक्टर इंदौर ने अप्रयुक्त भूमि को वापस लेने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। शासन ने आगे बताया कि म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 182 में अशासकीय आवंटन के संबंध में प्रावधान हैं।

प्रमुख सचिव को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बावजूद, शासन ने न तो मंत्रिपरिषद के निर्णय की प्रति और न ही कैबिनेट नोट उपलब्ध कराया। इसलिए, लेखापरीक्षा लिए गए निर्णय के औचित्य को सुनिश्चित नहीं कर सका।

अनुशंसा 3: शासन को अप्रयुक्त आवंटित भूमि की समीक्षा के प्रावधान को शामिल करके म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 182 को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए।

2.2.7.4 एम.पी. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को शून्य प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराये पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि

आर.बी.सी. खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 32 के अनुसार, तीन वर्ष तक के लिए अस्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन (01.04.1994 के पश्चात 23.09.2020 तक) के प्रकरण में, बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और कुल प्रीमियम के 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक पट्टा किराया वसूल किया जाएगा। आयुक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अस्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 126 के अनुसार, कलेक्टर द्वारा अस्थायी शिविरों और किसी भी सामग्री के भंडारण के लिए लाइसेंस देने के प्रकरण में, भू-खंड के बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत

के बराबर लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह या उसके किसी भी भाग के लिए आरोपणीय होगा/वसूली योग्य होगा।

जबलपुर एवं शहडोल कलेक्ट्रेट में भूमि आवंटन के 83 प्रकरणों³⁸ की जांच से पता चला कि उपरोक्त कलेक्ट्रेट के राजस्व न्यायालयों में निर्णीत (फरवरी 2020 एवं जनवरी 2021) नौ प्रकरणों³⁹ में 68.966 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन शून्य प्रीमियम एवं शून्य वार्षिक पट्टा किराये पर एम.पी. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.) को अस्थायी शिविर/साइलो-बैग बनाने के लिए किया गया था। यह आर.बी.सी. खण्ड-4 क्रमांक-1 और एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹174.92 लाख के राजस्व की हानि हुई। विवरण **परिशिष्ट-2.2.3** में दिया गया है।

राजस्व अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2022) से पता चला कि आवंटिती द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरणों में आवंटित भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और इस प्रकार आवंटित भूमि को इसके अनुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व विभाग को वापस किया जाना आवश्यक था।

कलेक्टर जबलपुर एवं शहडोल आर.बी.सी./ एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन कर शून्य प्रीमियम और शून्य वार्षिक पट्टा किराया पर शासकीय भूमि के आवंटन हेतु उत्तरदायी थे, जबकि शासकीय भूमि का उपयोग न होने के बावजूद एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. द्वारा इसे अपने पास रखना आर.बी.सी. की कंडिका 31 के तहत नजूल अधिकारी द्वारा अपेक्षित निगरानी की कमी के कारण था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

अंतिम उत्तर अप्राप्त रहा।

2.2.8 पट्टा आवंटन/नवीनीकरण प्रकरणों में राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण

2.2.8.1 पट्टे के नवीनीकरण में पट्टेदार को अनुचित लाभ

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 82 में प्रावधान है कि पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात, निर्माण न करने की स्थिति में, बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति के भुगतान एवं

³⁸ जबलपुर-54, शहडोल- 29

³⁹ श्री वी.पी. द्विवेदी, ए.डी.एम.(ग्रामीण) के राजस्व न्यायालय के सात प्रकरण; श्री ललित दाहिमा, कलेक्टर शहडोल एवं डॉ. सत्येन्द्र सिंह, कलेक्टर शहडोल के दो प्रकरण (छह प्रकरण - एम.पी.एन.बी.एन.एन. के लागू होने से पहले और तीन प्रकरण एम.पी.एन.बी.एन.एन. के लागू होने के बाद)

कंडिका 81 के सामान्य प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक पट्टा किराया का निर्धारण कर निर्माण अवधि में तीन साल के विस्तार के साथ पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकता है।

राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र (मई 2018) में प्रावधान है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात, आवंटित भूमि पर निर्माण न होने की स्थिति में निर्माण के लिए तीन साल की विस्तारित अवधि के साथ पट्टे का नवीनीकरण, बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति एवं भूमि उपयोग के अनुसार निर्धारित वार्षिक पट्टा किराए के भुगतान पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शमन शुल्क का भुगतान करने में चूक के मामले में अथवा उचित अवसर देने के बाद भी नवीनीकरण न कराने के प्रकरण में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा छह माह के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाना आवश्यक है और प्रकरण के निराकरण में आवंटित भूमि पर पुनः प्रवेश शामिल होगा।

कलेक्टर भोपाल की तहसील हुजूर (एम.पी. नगर वृत्त) में पट्टा विलेखों के तीन नवीनीकरण प्रकरणों की जांच से पता चला कि एक पट्टा विलेख⁴⁰ की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई। पट्टा विलेख के नवीनीकरण के लिए पट्टेदार⁴¹ ने आवेदन किया (जुलाई 2019) तथा प्रकरण का परीक्षण राजस्व विभाग के उपरोक्त परिपत्र (मई 2018) के परिप्रेक्ष्य में किया गया। अपर कलेक्टर, भोपाल ने शासकीय खाते में ₹3.38 करोड़ जमा करने की शर्त के अधीन पट्टा विलेख के नवीनीकरण का निर्णय लिया (सितंबर 2019), जिसके लिए सितंबर 2019 तथा फरवरी 2021 के मध्य मांग नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन पट्टेदार ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

पट्टेदार ने पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 78 (4) के संदर्भ में, अपने प्रकरण पर पुनर्विचार करने के लिए राजस्व की पुनर्निर्धारित राशि के विरुद्ध कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (जुलाई 2021)। कलेक्टर ने तदनुसार प्रकरण की पुनः जांच की एवं संबंधित शीर्ष में ₹2.52 करोड़ जमा करने की शर्त के अधीन पट्टे के नवीनीकरण की अनुमति प्रदान कर प्रकरण निर्णीत किया (फरवरी 2022)। पट्टेदार द्वारा उक्त राशि जमा करा दी गई (मार्च 2022)।

यह नियमानुसार नहीं था क्योंकि उपर्युक्त अनुच्छेद 78 (4) केवल ऐसे प्रकरणों पर लागू था जिनका निर्णय पूर्व में निरसित किए गए परिपत्रों या एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 148⁴² के अन्तर्गत निरसित किए गए परिपत्रों के आधार पर लिया गया था। चूंकि परिपत्र (मई 2018), जिसके आधार पर नवीनीकरण का निर्णय लिया गया था, न तो निरसित किया गया था और न

⁴⁰ प्रकरण क्रमांक 0032/ए-20(1)/2019-20, श्री राजेश गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी

⁴¹ दैनिक जागरण समाचार

⁴² एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 148 में उन परिपत्रों, नियमों और प्रावधानों का विवरण है जिन्हें 24.09.2020 की अधिसूचना के साथ निरस्त कर दिया गया है।

ही कंडिका 78(4) के अन्तर्गत समाहित था। सितंबर 2020 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनर्निर्धारण त्रुटिपूर्ण एवं अनियमित था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राजस्व की राशि का कम निर्धारण कर पट्टेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के परोक्ष उद्देश्य से प्रकरण को अनुवर्ती अधिसूचना के संदर्भ में पुनः खोला जाकर उसका पुनः परीक्षण किया गया जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹0.86 करोड़ की हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रकरण का निराकरण एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर भोपाल का निर्णय राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र (मई 2018) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन था। मौजूदा प्रकरण में, पट्टेदार ने मांग नोटिस देने के बावजूद शमन शुल्क जमा नहीं किया। कलेक्टर ने पट्टेदार को अनुचित लाभ देने के लिए आवंटित भूमि पर पुनर्प्रवेश करने के बजाय पहला मांग नोटिस देने के 21 माह बाद प्रकरण की पुनः जांच की (जुलाई 2021)।

2.2.8.2 प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम निर्धारण और बकाया राशि पर ब्याज न लगाना

राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2014) के अनुसार, औपचारिक और अंतिम आदेश जारी होने से पूर्व, आवंटन की प्रत्याशा में राज्य शासन के किसी भी उपक्रम (निगम, मंडल और विकास प्राधिकरण) को दिए गए अग्रिम कब्जे के सभी प्रकरणों में, अग्रिम कब्जे के समय जमा की गई राशि के समायोजन के अधीन, लागू मार्गदर्शिका दरों के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम आरोपित किया जाएगा। आवासीय प्रयोजन के लिए, प्रीमियम का पांच प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराया आरोपित किया जाएगा। यदि अंतर राशि शासन के पक्ष में देय है, तो ऐसी बकाया राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आवंटिती से वसूल किया जाएगा।

कलेक्टर, शहडोल के नजूल अनुभाग में 29 भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण⁴³ में, ग्राम सोहागपुर में 2.023 हेक्टेयर शासकीय भूमि का अग्रिम कब्जा कार्यपालन अभियंता, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, (एम.पी.एच.आई.डी.बी.) सोहागपुर को आवासीय प्रयोजन हेतु दिया गया था (मई 2019)। राजस्व विभाग के औपचारिक आदेशों (जुलाई 2018) के जारी होने के अनुसरण में, भूमि का आवंटन वर्ष 2018-19 की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के आधार पर निर्धारित प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया के भुगतान पर किया जाना था।

⁴³ श्रीमती वंदना वैद्य, कलेक्टर शहडोल का राजस्व न्यायलय प्रकरण क्रमांक 24/अ-20(1)/2011-12

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि राजस्व निरीक्षक ने पूर्वोक्त परिपत्र (मार्च 2014) के अनुसार, भूमि के बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम का निर्धारण करने के बजाय, जनवरी 1992 में जारी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, (बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत के बराबर) दरें लागू कर प्रीमियम की गणना की, जो की संदर्भित प्रकरण में लागू नहीं थी। इस प्रकार, विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रीमियम की गणना (सितंबर 2021) ₹1.44 करोड़ की और इसके परिणामस्वरूप वार्षिक पट्टा किराये की गणना ₹ 1.79 लाख भी गलत हुई (क्योंकि वार्षिक पट्टा किराये की गणना प्रीमियम के पांच प्रतिशत पर की जानी थी)। आरोपणीय प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया वित्तीय वर्ष 2018-19 से देय था।

पट्टेदार ने मार्च 2016 में कुल राशि ₹ 1.06 करोड़⁴⁴ एवं दिसंबर 2021 में राशि ₹ 43.07 लाख⁴⁵ जमा की थी।

राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत दरें लागू करके प्रीमियम की त्रुटिपूर्ण गणना करने, निर्धारित अवधि के भीतर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराये की बकाया राशि का भुगतान न करने और ऐसे विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज के अनारोपण के कारण, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से ₹3.99 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जैसा कि निम्न तालिका 2.2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.3: बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज से सम्बंधित गणना (₹ करोड़ में)				
भुगतान का विवरण	देय राशि	भुगतान की राशि	बकाया राशि	बकाया राशि पर ब्याज
1	2	3	4	5
प्रीमियम	3.03	1.44	1.59	1.39
पट्टा किराया	0.76	0.05	0.71	0.30
योग	3.79	1.49	2.30	1.69
कुल वसूली योग्य राशि (कॉलम 4 एवं 5 का योग)			3.99	

(विस्तृत गणना परिशिष्ट-2.2.4 में दर्शाई गई है।)

इस प्रकार, प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया के कम निर्धारण तथा बकाया राशि पर ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹3.99 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित राशि के संबंध में एम.पी.एच.आई.डी.बी. को मांग नोटिस जारी किया गया है (अक्टूबर 2022, मई 2023)।

⁴⁴ प्रीमियम- ₹1.01 करोड़ एवं पट्टा किराया- ₹5.04 लाख

⁴⁵ प्रीमियम- ₹42.73 लाख एवं पट्टा किराया- ₹ 0.34 लाख

2.2.8.3 स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने के कारण शासकीय राजस्व की हानि

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 78 के अनुसार, एक पट्टेदार को समाप्ति वर्ष के 1 अप्रैल और पट्टा विलेख की समाप्ति दिनांक के बीच किसी भी दिनांक को स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। उपरोक्त कंडिका 78 (3) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उचित परीक्षण के उपरान्त, ऐसे स्थायी पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में स्व:प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करेगा। उपरोक्त कंडिका 81 (1) में प्रावधान है कि यदि स्थायी पट्टे की अवधि एम.पी.एन.बी.एन.एन. के जारी होने के दिनांक (24-9-2020) को या उसके पश्चात समाप्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी, नवीनीकरण के समय, वार्षिक पट्टे का पुनर्निर्धारण करेगा जो म.प्र.भू.रा.सं. (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में अधिसूचित निर्धारित दरों से दोगुना होगा।

पूर्वोक्त कंडिका 81 (2) के अनुसार, यदि स्थायी पट्टे की अवधि इन निर्देशों के दिनांक से पूर्व समाप्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी वार्षिक पट्टा किराये का पुनर्निर्धारण, अंतिम निर्धारण किए गए वार्षिक पट्टा किराए के छह गुना पर करेगा। म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 108 ख के अनुसरण में, नजूल अधिकारियों द्वारा एक स्थायी पट्टा पंजी संधारित किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों (धार को छोड़कर) में, प्राधिकारियों ने स्थायी पट्टा पंजी संधारित नहीं किया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा नवीनीकरण योग्य प्रकरणों की सटीक संख्या का निर्धारण नहीं कर सका। हालाँकि, आठ चयनित जिलों में चार के नजूल अनुभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर स्थायी पट्टा प्रकरणों की जांच से पता चला कि 185 प्रकरण पट्टे की समाप्ति से एक वर्ष से 64 वर्ष तक की अवधि से नवीनीकरण के लिए बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.5** में दर्शाया गया है:

निम्न **तालिका 2.2.4** में दर्शाए गए स्थायी पट्टों के नवीनीकरण न होने के कारण जिलेवार राजस्व हानि की गणना केवल उन प्रकरणों के सम्बंध में की गई है जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे:

तालिका-2.2.4: स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि (रुलाख में)		
जिला	नवीनीकरण योग्य प्रकरणों की संख्या	अन्तर्निहित राजस्व की हानि
धार	5	7.06
देवास	148	4.35
इंदौर	20	81.95
शहडोल	12	0.50
योग	185	93.86

चयनित जिलों में नजूल अधिकारियों ने कंडिका 78 (3) के प्रावधानों के अनुसरण में इन पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के लिए स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई (जनवरी 2023 तक) आरम्भ नहीं की। पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ न करने के कारण, कुल राशि ₹ 93.86 लाख का राजस्व (जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.5** में दर्शाया गया है) पट्टेदारों से वसूल नहीं किया जा सका।

इसी तरह का प्रकरण पूर्व में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.9 में इंगित किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि कुल 185 आक्षेपित प्रकरणों में से, जिला धार और शहडोल के 11 प्रकरणों के सम्बंध में नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं शेष 174 प्रकरणों में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

अनुशंसा 4: शासकीय भूमि के अभिलेखों के रखरखाव और शासकीय बकाया के लिए समय पर मांग सृजित करने में चूक के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए ।

2.2.8.4 एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कापॉरेशन को प्रदान की गई भूमि पर प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराए का अनारोपण

राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) खण्ड 4 क्र. 1 की कंडिका 26 के अनुसार, जब वेयरहाउस के निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम या केंद्रीय भंडारण निगम को भूमि प्रदान की जाती है, तो आवेदक से बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर से सामान्य दरों पर वार्षिक पट्टा किराया वसूल किया जाना आवश्यक है।

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-74 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्दिष्ट दरों (50 पैसे प्रति एक रुपया राजस्व) पर पंचायत उपकर के आरोपण का प्रावधान है। म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 2 (एम-1) के अनुसार, भू-राजस्व की परिभाषा में प्रीमियम भी शामिल है, जैसा कि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 19 (1) के अंतर्गत तालिका के क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट है, वेयरहाउस के निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम को प्रदान की गई भूमि के प्रकरण में, बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और म.प्र.भू.रा.सं. (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में अधिसूचित निर्धारित दरों से दोगुना वार्षिक पट्टा किराया पट्टेदार पर आरोपित किया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रकरणों में, राज्य नजूल निर्वर्तन समिति भूमि आवंटन के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।

कलेक्टर शहडोल और सिंगरौली के कार्यालय में भूमि आवंटन के 79 प्रकरणों⁴⁶ की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (सितंबर एवं नवम्बर 2022) कि नौ प्रकरणों में, 25.620

⁴⁶ शहडोल - 29 प्रकरण; सिंगरौली - 50 प्रकरण

हेक्टेयर (ग्राम पंचायतों की परिधि के भीतर स्थित) शासकीय भूमि को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेतु आवंटित कर, वेयरहाउस और कैप भंडारण⁴⁷ के निर्माण के लिए एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के उपयोग के लिए दिया गया था। अभिलेखों की आगामी संवीक्षा में पता चला कि इनमें से किसी भी भूमि आवंटन प्रकरण में लागू दरों पर प्रीमियम, वार्षिक पट्टा किराया एवं पंचायत उपकर आरोपित नहीं किया गया था। आर.बी.सी./ एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रीमियम (₹2.57 करोड़), वार्षिक पट्टा किराया (₹23.37 लाख) और पंचायत उपकर (₹1.40 करोड़) के अनारोपण के परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.6** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पांच भू-स्थलों⁴⁸ के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि सभी पांच भू-स्थलों को राजस्व विभाग से किसी वैध प्राधिकार के बिना एक निजी संस्था मैसर्स गोव्रीन वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड (मुख्यालय-अहमदाबाद) को आवंटिती द्वारा उप-पट्टे पर दिया गया था। साथ ही, आवंटन की शर्तों और पट्टेदार द्वारा भूमि के उपयोग के सत्यापन के लिए नजूल अधिकारी द्वारा आवंटन के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को आवंटित की गई थी जो एक शासकीय विभाग है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और आर.बी.सी./ एम.पी.एन.बी.एन.एन. में निर्धारित प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया की दरों के अनुसार वसूली की जानी आवश्यक थी।

अनुशंसा 5: विभाग को म.प्र.भू.रा.सं. के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिस हेतु इसे आवंटित किया गया है।

2.2.9 शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा

2.2.9.1 शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा किए जाने पर कार्रवाई आरम्भ न करना/शास्ति अधिरोपित न करना

म.प्र. राजपत्र अधिसूचना (सितंबर 2018) के नियम 16 (1) के अनुसार, प्रत्येक पटवारी/ राजस्व निरीक्षक अपने निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रत्येक सर्वे नम्बर/भूखंड संख्या का निरीक्षण करेगा और म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 104 के अन्तर्गत बनाए गए नियम 28 के अनुसार, वह एक अतिक्रमण

⁴⁷ कवर एवं प्लिंथ स्टोरेज-इस प्रकार का खुला भंडारण मध्यवर्ती भंडारण माना जाता है तथा अल्प अवधि के लिए बैगों में खाद्यान्नों के भण्डारण के उद्देश्य की पूर्ति करता है।

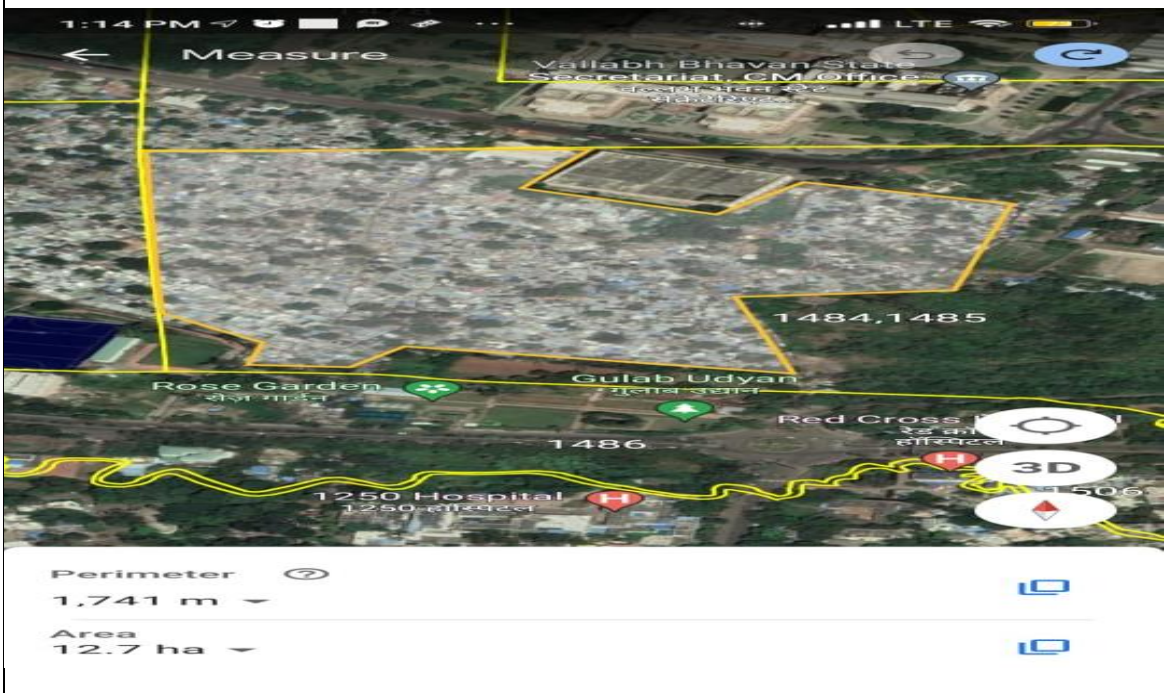
⁴⁸ ग्राम चेतवई तहसील सोहागपुर, 2. ग्राम करी तहसील गोहपारू, 3. ग्राम अमलाई तहसील जैतपुर, 4. ग्राम जारूखारा तहसील जयसिंहनगर, 5. ग्राम चन्नोदी तहसील जैतपुर

पंजी संधारित करेगा जिसमें प्रत्येक अतिक्रमित भूमि के सभी प्रासंगिक विवरण जैसे कि उसका क्षेत्रफल, अतिक्रमण का प्रकार, आरेख आदि सम्मिलित होंगे।

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 248 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से किसी खाली भूमि, आबादी, सेवा भूमि अथवा किसी अन्य भूमि को, जो धारा 237 के तहत किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अलग रखी गई हो, अथवा किसी ऐसी भूमि पर, जो कि शासन की संपत्ति है, कब्जा कर लेता है अथवा अपने कब्जे में रखता है, तहसीलदार के आदेश से तुरंत बेदखल किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेक पर, ₹ एक लाख तक के अर्धदण्ड के लिए उत्तरदायी होगा और यदि ऐसा अनधिकृत कब्जा पहली बेदखली के आदेश के दिनांक के बाद भी जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए शहरी क्षेत्र में ₹2,000 और गैर-शहरी क्षेत्र में ₹500 का अतिरिक्त अर्धदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

वल्लभ भवन और कलेक्ट्रेट भोपाल के समीपवर्ती क्षेत्र में लेखापरीक्षा द्वारा अतिक्रमणों का संयुक्त भौतिक सत्यापन और के.एम.एल. फाइल⁴⁹ से सृजित आंकड़ों की जांच से पता चला कि तीन इलाकों में 10 सर्वे नम्बरों में अन्तर्निहित 37.69 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अस्थायी शिविर एवं संरचनाएँ बनाकर अतिक्रमण किया गया था।

चित्र 1: 23.12.2022 को वल्लभ भवन, भोपाल के समीपवर्ती क्षेत्र में अतिक्रमण के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सारा ऐप से लिया गया स्क्रीनशॉट



⁴⁹ के.एम.एल.- गूगल अर्थ एप एवं सारा एप द्वारा समर्थित कीहोल मार्कअप लेंगवेज फाइल

प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (2022-23) के अनुसार गणना की गई अतिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य ₹322.71 करोड़ है जैसा कि निम्नलिखित तालिका 2.2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.5: अतिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य				
(₹ करोड़ में)				
तहसील/इलाका	अन्तर्निहित सर्वे नम्बर	अतिक्रमित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	मार्गदर्शिका दर प्रति वर्ग मीटर	बाजार मूल्य
हुजूर (शहरी वृत्त) वल्लभ भवन, भीमनगर, भोपाल	1484, 1485, 1483, 1511, 1479, 1480, 1478	264900	8800	233.11
ईदगाह हिल्स कलेक्ट्रेट के पास भोपाल	105, 106, 107	112000	8000	89.60
योग				322.71

उक्त शासकीय भूमि कब से अतिक्रमण के अधीन रही, इसकी तिथि/अवधि निर्धारित करने के लिए न तो पटवारी/राजस्व निरीक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन था और न ही अतिक्रमण पंजी संधारित की गई थी। यह स्पष्ट था कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमित क्षेत्र के संबंध में प्रतिवेदन न तो पटवारी/ राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही तहसीलदार द्वारा म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 248 के अनुसरण में उचित कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु मांगा गया था।

यदि पटवारी/ राजस्व निरीक्षक ने अतिक्रमण पंजी संधारित की होती एवं उसे नियमित रूप से अद्यतन किया होता तथा तहसीलदार ने उनकी निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में त्वरित कार्रवाई की होती, तो अनधिकृत कब्जे का क्षेत्र एवं अवधि तथा उस पर अधिरोपित किए जाने योग्य शास्ति का आकलन किया जा सकता था।

शासन ने कहा (जून 2023) कि वल्लभ भवन के समीपवर्ती भीमनगर और वल्लभनगर में रहने वाले झुग्गीवासियों को आश्रय योजना के तहत उनके कब्जे वाली भूमि पर अस्थायी पट्टा दिया गया था (वर्ष 1998, 2003 और 2008) तथा कब्जा की गई भूमि को अतिक्रमित नहीं माना जा सकता है। शासन ने यह भी कहा कि प्रत्येक खसरा संख्या के सम्बंध में वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है और अतिक्रमण पंजी भी संधारित की जाती है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित पटवारी प्रकरण की सूचना तहसीलदार को देते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने लेखापरीक्षा के सत्यापन के लिए उत्तर के साथ अस्थायी पट्टे की अवधि, आवंटित क्षेत्र के साथ खसरा संख्या, आवंटियों का नाम, पटवारियों की निरीक्षण प्रतिवेदन आदि जैसे सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। ईदगाह हिल्स, भोपाल में अतिक्रमित भूमि की स्थिति पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

2.2.9.2 शास्ति अधिरोपित करने एवं आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि को खाली न करना/शास्ति की वसूली न करना

आठ चयनित जिलों की 23 तहसीलों में अतिक्रमण के मामलों की जांच के दौरान नमूना जांच किए गए 2,371 प्रकरणों में यह पाया गया कि संबंधित तहसीलदारों ने शास्ति अधिरोपित करते हुए 2,364 प्रकरणों में बेदखली आदेश जारी किए थे। तथापि, 1,037 प्रकरणों में अधिरोपित शास्ति की राशि ₹ 38.64 लाख की वसूली नहीं की गई। नमूना जांच किये गये कुल प्रकरण, ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें शास्ति (अर्थदंड) अधिरोपित करते हुए बेदखली आदेश जारी किये गये, वे प्रकरण जिनमें बेदखली प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे, प्रकरण, जिनमें शास्ति की वसूली नहीं की गयी, उनका तहसीलवार विवरण **परिशिष्ट-2.2.7** में दर्शाया गया है।

जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.7** में दर्शाया गया है, कुल 2,364 प्रकरणों में से (जिनमें बेदखली आदेश जारी किये गए थे), अनधिकृत कब्जे को हटाने की पुष्टि के लिए केवल 902 प्रकरणों में बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए। शेष 1462 प्रकरणों में से, जिनमें बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गए थे, 1460 प्रकरणों में, ₹398.23 करोड़ मूल्य की शासकीय भूमि (मार्गदर्शिका 2021-22 के अनुसार गणना की गयी) अतिक्रमण के अधीन थी तथा जिला ग्वालियर की तहसील तानसेन के शेष दो प्रकरणों में⁵⁰, अतिक्रमित भूमि का विवरण उपलब्ध न होने के कारण बाजार मूल्य की गणना नहीं की जा सकी। इन प्रकरणों में, अतिक्रमित भूमि का बेदखली आदेश जारी होने के बावजूद, बेदखली नहीं की गई थी, न तो पटवारियों द्वारा बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए और न ही तहसीलदारों द्वारा मांगे गए थे। इस प्रकार, भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति, प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें प्रथम बेदखली आदेश के दिनांक से ऐसा अनधिकृत कब्जा जारी रहा, गैर-शहरी क्षेत्र में ₹ 500 और शहरी क्षेत्र में ₹ 2,000 प्रति दिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदण्ड के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। इस प्रकार, धारा 248 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ न करने के कारण, अतिक्रमणकर्ताओं से कुल ₹ 71.68 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की जा सकी।

अतिक्रमण के प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए, अनधिकृत कब्जा हटाने तथा शास्ति की वसूली के सम्बंध में तहसील कार्यालय में कोई निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं था।

इसी तरह का प्रकरण पहले 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.11 में इंगित किया गया था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि भोपाल में, तहसील हुजूर में पंजीकृत कुल 86 प्रकरणों में से 20 प्रकरणों में कुल ₹44,000 की राशि वसूल की गई थी। एम.पी. नगर के नजूल वृत्त में

⁵⁰ राजस्व प्रकरण संख्या 0009/ए-68/ 2019-20 और 0010/ ए-68/ 2019-20

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के सभी 12 प्रकरणों में बेदखली हो चुकी है। पटवारियों से बेदखली प्रतिवेदन मांगे गए थे। बैरसिया के सभी आठ प्रकरणों में बेदखली हो चुकी है। टी.टी. नगर में शासकीय भूमि (सर्वे नम्बर 66/2, 66/3, 66/4 ग्राम चूनाभट्टी) पर 18 व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के प्रकरण में उन्हें बेदखल किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण के पश्चात वसूली की कार्रवाई की जायेगी। नजूल हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त में सात प्रकरणों में ₹ 6000 की वसूली बकाया है।

शहडोल में संबंधित तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

देवास में, तहसीलदारों को अतिक्रमण के प्रकरणों का स्वतः संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के उपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर में तहसील हातोद के 29 अतिक्रमण प्रकरणों में ₹ 48,000 तथा डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के 44 प्रकरणों में ₹ 1,08,000 की राशि वसूल की जा चुकी है।

प्रतिक्रिया में विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

2.2.10 निगरानी के आभाव में शासकीय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन सुनिश्चित नहीं हो पाया

2.2.10.1 रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर को आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं होना

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 32 (2) के अनुसार, किसी चैरिटेबल संस्था को स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमि पर आवंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना और तीन साल के भीतर पूर्ण करना आवश्यक है।

रॉबर्ट नर्सिंग होम, रेजीडेंसी क्षेत्र, इंदौर को भूमि {2.92 हेक्टेयर (7.21 एकड़)} ₹135 के वार्षिक पट्टा किराये पर 10 साल की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी (जुलाई 1945)। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, पट्टे का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया था, एवं वर्तमान में पट्टा 14 जून 2047 तक वैध है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन (दिसंबर 1997) के अनुसार, आवंटित भूमि में से 1.50 हेक्टेयर (3.71 एकड़) भूमि अप्रयुक्त थी और इसका उपयोग खेती के लिए किया जा रहा था। जैसा कि आर.आई. द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2006), 0.8 हेक्टेयर (दो एकड़) भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा था। दिनांक 13.09.2022 को लेखापरीक्षा दल द्वारा पटवारी के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में आर.आई. की रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि हुई।

आवंटन के दिनांक से 77 वर्ष बाद भी सम्पूर्ण भूमि का उपयोग न होना यह दर्शाता है कि शहर के प्रमुख स्थान पर उपरोक्त 0.8 हेक्टेयर (8,093 वर्गमीटर) भूमि पट्टेदार की वास्तविक आवश्यकता से अधिक थी और इसे वापस ले लिया जाना चाहिए था तथा एम.पी.एन.बी.एन.एन. के तहत उल्लिखित निर्धारित दर के दो गुना के बराबर वार्षिक पट्टा किराया और उसके बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम पर अन्य संभावित चैरिटेबल संस्था को सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवंटित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने ₹48,000 प्रति वर्गमीटर की दर से 8,093 वर्गमीटर (अप्रयुक्त क्षेत्र) के प्रचलित बाजार मूल्य (कलेक्टर मार्गदर्शिका 2022-23) के अनुसार गणना ₹38.85 करोड़ की। इस प्रकार, विभाग की निष्क्रियता के कारण, भूमि की आवश्यकता वाले अन्य संभावित पट्टा आवेदक सर्वोत्तम उपयोग हेतु भूमि से वंचित हो गए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि रॉबर्ट नर्सिंग होम, इंदौर की प्रबंधन समिति ने नर्सिंग कॉलेज छात्रावास और कर्मचारी आवास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने लेखापरीक्षा के सत्यापन हेतु सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये। तथ्य यह है कि आवंटन के 77 वर्ष बाद भी भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।

2.2.10.2 मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम (एम.पी.आई.डी.सी.) को हस्तांतरित भूमि उपयोग न होने की स्थिति में वापस नहीं लिया जाना

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 45 के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को ₹10,000 प्रक्रिया व्यय शासकीय खाते में जमा करना होगा। उपरोक्त निर्देशों की कंडिका 44 में प्रावधान है कि गैर शहरी क्षेत्र में, निवेशकों को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन के प्रकरण में, पांच हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10 हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड के आवंटन के लिए, जिसका बाजार मूल्य ₹ पांच करोड़ तक हो, संभागीय नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी होगी। एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 में विभिन्न विभागों को आवंटित भूमि की आवधिक समीक्षा करने का प्रावधान है एवं अप्रयुक्त भूमि को आगामी आवंटन हेतु विभागों से वापस लिया जाना अपेक्षित था।

कलेक्ट्रेट जबलपुर में 54 भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:-

- ए.डी.एम.⁵¹ (ग्रामीण) के राजस्व न्यायालय में श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल ने इथेनॉल संयंत्र (औद्योगिक उपयोग) की स्थापना हेतु ग्राम भीटा (जबलपुर) में 15.00 हेक्टेयर⁵² भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया था (जून 2021)। उपरोक्त आवेदक का आवेदन निर्धारित

⁵¹ अपर जिला मजिस्ट्रेट

⁵² खसरा क्र. 243/1

प्रक्रिया शुल्क ₹10,000 जमा किये बिना ही स्वीकार कर लिया गया जो कि भूमि आवंटन न होने की स्थिति में भी वापसी योग्य नहीं है।

- राज्य स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के अनुमोदन के बिना श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल को आवंटन हेतु एम.पी.आई.डी.सी. को भूमि हस्तांतरित की गई (अगस्त 2021)।
- यद्यपि आवंटन आदेश में यह शर्त थी कि उपयोग न होने की स्थिति में भूमि वापस लौटा दी जाएगी, भूमि न तो श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल को हस्तांतरित की गई (दिसंबर 2022) और न ही राजस्व विभाग को वापस लौटाई गई।

इस प्रकार, एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और अपेक्षित शुल्क की वसूली न होने के कारण, उपरोक्त आवंटन अनियमित था।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 के तहत एम.पी.आई.डी.सी. को आवंटित भूमि की आवश्यकता की समीक्षा करना और बाजार मूल्य ₹ 1.06 करोड़⁵³ की अप्रयुक्त भूमि को विभाग से वापस लिया जाना वांछित है।

शासन ने बताया (जून 2023) कि संबंधित जिले से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

2.2.10.3 राज्य शासन के विभागों को आवंटित शासकीय भूमि के उपयोग की निगरानी न करना

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 में विभिन्न विभागों को आवंटित भूमि की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रावधान है और उपयोग न की गई भूमि को आगामी आवंटन हेतु विभागों से वापस लिया जाना अपेक्षित है।

सभी नमूना जांच किए गए जिलों के एस.एल.आर./नजूल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए 301 भूमि आवंटन प्रकरणों⁵⁴ की जांच से पता चला कि ग्वालियर जिले के दो प्रकरणों में दो विभागों⁵⁵ को आवंटित की गई 45.686 हेक्टेयर भूमि 12 वर्षों तक अप्रयुक्त रही। उपरोक्त 45.686 हेक्टेयर में से 19.931 हेक्टेयर भूमि दो अन्य मांगकर्ता विभागों को पुनः आवंटित कर दी गई और शेष 25.755 हेक्टेयर भूमि अप्रयुक्त रह गई। राजस्व अधिकारियों की निरीक्षण प्रतिवेदन (मार्च 2019 से जून 2021 के बीच) ने भी इन तथ्यों की पुष्टि की। विभागवार विवरण **परिशिष्ट-2.2.8** में दर्शाया गया है।

⁵³ भूमि का बाजार मूल्य = वर्ष 2021-22 की मार्गदर्शिका दर: ₹ 7.04 लाख प्रति हेक्टेयर (असिंचित भूमि के लिए) * क्षेत्रफल = ₹ 7.04 लाख * 15 = ₹ 105.60 लाख अर्थात् ₹1.06 करोड़

⁵⁴ जबलपुर-54, इन्दौर-34, देवास-05, ग्वालियर-53, भोपाल-26, शहडोल-29, सिंगरौली-50 तथा धार-50

⁵⁵ मध्य प्रदेश पर्यटन(5.686 हेक्टेयर), सूचना एवं प्रौद्योगिकी (40.00 हेक्टेयर)

2.2.11 राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने में अनियमितताएं

2.2.11.1 राजस्व अभिलेखों में विसंगति के कारण शासकीय भूमि की हानि

म.प्र.भू.रा.सं. (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020, में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भू-अभिलेखों को तैयार करने एवं उनके संधारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। उक्त नियमों की कंडिका 23 एवं 33 के अनुसार, भू-सर्वेक्षण में तैयार किए गए भू-अभिलेखों का अंतिम संस्करण पटवारी को उपलब्ध कराया जाता है। सम्बंधित तहसीलदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह पूर्ववर्ती अभिलेखों से सत्यापन कर एवं वास्तविक स्थल पर भौतिक निरीक्षण करके भू-अभिलेखों में उल्लिखित मानचित्र, सर्वे नम्बर एवं क्षेत्रफल में किसी भी विसंगति पर नजर रखते हुए उसमें संशोधन करें।

चयनित जिलों की 23 चयनित तहसीलों के 45 गांवों के कुल 460 नमूना ऑनलाइन खसरों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- सात जिलों⁵⁶ की 12 तहसीलों⁵⁷ के 15 गांवों⁵⁸ के 66 प्रकरणों में भौतिक रूप से संधारित खसरे और ऑनलाइन वर्तमान खसरे में क्षेत्रफल की विसंगति देखी गई। 23 प्रकरणों में शासकीय भूमि का क्षेत्रफल कम (0.01 हेक्टेयर से 5.695 हेक्टेयर) हुआ, जबकि 43 प्रकरणों में सम्बंधित खसरे के क्षेत्रफल में वृद्धि (0.002 हेक्टेयर से 20.264 हेक्टेयर) हुई। विवरण **परिशिष्ट 2.2.9** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, पटवारी की शिथिलता और तहसीलदार द्वारा निगरानी की कमी के कारण भौतिक खसरे से ऑनलाइन खसरे में क्षेत्रफल को अद्यतन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय भूमि की हानि हुई।

- जबलपुर जिले में चार ग्रामों⁵⁹ के पांच सर्वे नम्बरों⁶⁰ में सन्निहित 5.98⁶¹ हेक्टेयर शासकीय भूमि को, जिसका वर्ष 2022-23 की मार्गदर्शिका दरों के अनुसार बाजार मूल्य ₹56.63

⁵⁶ भोपाल, देवास, धार, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल एवं सिंगरौली

⁵⁷ बुढ़हार, देवास शहरी, गंधवानी, हुजूर, जबलपुर, कुक्षी, मुरार, सरदारपुर, सिंगरौली ग्रामीण, सिंगरौली शहरी, सुहागपुर एवं तानसेन

⁵⁸ भंडेरी, देहरी, डोलाहनुमान, फुसावली, गुमानपुरा, झींगुरदाह, जोगीढाना, खजूरिया, खानीअंबा, निरावली, लालपुर, लोहारपुर, मुगलिया, पतुलखी, सोनहा

⁵⁹ ग्राम सिंघलद्वीप 1 एवं 2, ग्राम लखना, ग्राम जैतना

⁶⁰ सर्वे नम्बर 148, सर्वे नम्बर 190, सर्वे नम्बर 53, सर्वे नम्बर 59, सर्वे नम्बर 101

⁶¹ ग्राम सिंघलद्वीप 1 एवं 2, सर्वे नम्बर 148 एवं 190, क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर, ग्राम लखना सर्वे नम्बर 53 एवं 59, क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर, ग्राम जैतना सर्वे नम्बर 101 क्षेत्रफल 2.62 हेक्टेयर

लाख है जो मिसल अभिलेख⁶² में तालाब के रूप में दर्ज, है, बिना किसी वैध अधिकार के निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था जैसा कि वर्तमान खसरे में दर्शाया गया है। बार-बार अनुरोध के बावजूद भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की सत्यता को सत्यापित करने के लिए कोई वैध अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया (जून 2023) कि शहडोल में संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ग्वालियर में सभी शासकीय सर्वे नंबरों का मिसल अभिलेख से सत्यापन किया जा रहा है और किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में संबंधित तहसीलदार को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। धार में म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 115 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। देवास में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस सम्बंध में विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु पत्र जारी किया गया है। भोपाल और सिंगरौली जिलों से जानकारी प्रतीक्षित है।

अनुशंसा 6: भू-अभिलेखों में विसंगतियों को दूर करने के लिए विभाग को भू-सर्वेक्षण करना चाहिए।

2.2.11.2 आवंटन आदेश में निर्दिष्ट खसरा नंबरों से विचलन की स्वीकृति प्राप्त न किया जाना

शहडोल, सिंगरौली और धार जिलों में शासकीय भूमि आवंटन के कुल 30 स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार अवलोकित किया:

- **सबस्टेशन का निर्माण:** एक प्रकरण में, जिला कलेक्टर, शहडोल ने म.प्र. राज्य ऊर्जा विभाग के माध्यम से कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 0.405 हेक्टेयर⁶³ शासकीय भूमि आवंटित⁶⁴ की (मार्च 2020)। लेकिन, उपरोक्त कंपनी द्वारा 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण आवंटन आदेश में निर्दिष्ट खसरा नंबर 32/1 के बजाय एक अलग खसरा नंबर 29/1 पर किया गया था। खसरा नंबर परिवर्तन के संबंध में कोई अभिलेख आवंटन नस्ती में उपलब्ध नहीं था।
- **रिसॉर्ट का विकास:** एक अन्य प्रकरण में, कलेक्टर शहडोल ने बाणसागर बांध के अधिकतम जलस्तर द्वीप में सरसी द्वीप रिसॉर्ट के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को

⁶² मिसल अभिलेख म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 64 के अनुसरण में समय-समय पर किए गए भू-सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए अभिलेख हैं।

⁶³ खसरा नम्बर 32/1, क्षेत्रफल 7.345 हेक्टेयर

⁶⁴ राजस्व प्रकरण क्रमांक 0013/अ-19(3)/2019-20 दिनांक 16.03.2020, राजस्व न्यायालय, श्री ललित दाहिमा, कलेक्टर शहडोल

78.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि (ग्राम सरसी में 48 खसरों⁶⁵ और ग्राम पहड़िया में 30 खसरों⁶⁶ में सन्निहित) आवंटित की (दिसंबर 2020)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम सरसी में आवंटित भूमि, जैसा कि आवंटन आदेश में उल्लिखित है, पानी में डूबी हुई थी और जिस भूमि पर म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मौजूदा द्वीप रिजॉर्ट विकसित/ निर्माणाधीन था, उसमें पूरी तरह से अलग-अलग 224 खसरा नंबर⁶⁷ शामिल थे। आवंटित भूमि के खसरा नंबर में परिवर्तन के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

बिना किसी कारण का उल्लेख किए खसरा नंबर में परिवर्तन स्पष्ट रूप से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि की निगरानी में गंभीर चूक को इंगित करता है।

आवंटित भूमि का कब्जा सौंपते समय, उसके खसरा नंबरों को राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटन आदेश में उल्लिखित खसरा नंबरों से सत्यापित किया जाना चाहिए था। यदि निर्दिष्ट खसरा नंबरों पर कब्जा देना संभव नहीं था तो इस तथ्य की सूचना उच्च प्राधिकारियों को देनी चाहिए थी और निर्धारित खसरा नंबरों से विचलन के लिए उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि शहडोल में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा प्रकरण नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुशंसा 7: विभाग को आवंटित भूमि का कब्जा सौंपते समय राजस्व निरीक्षक /पटवारी द्वारा भूमि के वास्तविक स्थान के साथ निर्दिष्ट खसरा नंबरों का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए और यदि कोई विचलन हो तो उसे उचित स्तर पर अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

2.2.12 अन्य विविध प्रेक्षण

2.2.12.1 एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के उल्लंघन में एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस.ए.आई.सी.एल.) को शासकीय भूमि का आवंटन

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 237 के अनुसार, कलेक्टर, गांव की कुल कृषि भूमि का दो प्रतिशत चरनोई⁶⁸ के लिए सुरक्षित करने के बाद, शेष खाली भूमि को सड़कों, राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, नहरों, चिकित्सालयों, महाविद्यालयों और किसी भी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के

⁶⁵ खसरा नंबर 1878/1 से 1878/14, 1879/1 से 1879/11, 1901/1 से 1901/3 तथा 1936/1 से 1936/20

⁶⁶ खसरा नंबर 451/1 से 451/14, 452/1 से 452/3, 505/1 से 505/2, 506/1 से 506/2, 507/1 से 507/2, 540/1 से 540/2, 541/1 से 541/2, 542, 543, 544

⁶⁷ खसरा नंबर 718 से 728, 731/1 से 731/5, 732/1 से 732/2, 732/2433/1 से 732/2433/5, 733, 736/1 से 736/7, 737, 738/1 से 738/9, 740/1 से 740/2, 741/1 से 741/7, 742 से 746, 1036, 1037/1 से 1037/3, 1050 से 1152 तथा 1436 से 1497

⁶⁸ चरनोई से तात्पर्य है सार्वजनिक चारागाह भूमि

निर्माण, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, के लिए परिवर्तित (डायवर्ट) कर सकता है। एम.पी.एन.बी.एन.एन. में राज्य सरकार के उपक्रमों को भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

कलेक्टर ग्वालियर के नजूल अनुभाग में भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच में पाया गया कि प्रबंध निदेशक, एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर ने उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने के लिए कलेक्टर को भू-खण्ड (1,048 वर्गमीटर) के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (दिसंबर 2020)। राजस्व निरीक्षक (नजूल) ने तहसीलदार को सौंपे अपने प्रतिवेदन (दिनांक का उल्लेख नहीं) में बताया कि राज्य सरकार के उपक्रमों को शासकीय भूमि के आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को तहसीलदार नजूल द्वारा अपर कलेक्टर को पृष्ठांकित किया गया (फरवरी 2021)।

यद्यपि, एम.पी.एन.बी.एन.एन. में उपरोक्त भूमि आवंटन के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, कलेक्टर ने ₹83,840⁶⁹ (कृषि दर पर गणना की गई जबकि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक था) के प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया ₹ 2,096 पर 1,048 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की (जून 2021)। कलेक्टर द्वारा जारी आवंटन आदेश विरोधाभासी था। एक ओर, आदेश की प्रारंभिक पंक्तियों में यह उल्लेख किया गया था कि भूमि को उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने के लिए आवंटित किया जा रहा था, दूसरी ओर, द्वितीय पैराग्राफ में कहा गया था कि भूमि शासकीय अभिलेख में सड़क के रूप में दर्ज है और आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए संस्था को भूमि आवंटित की जा रही है। सड़क के लिए आरक्षित भूमि का आवंटन उसकी नोडयत (भूमि की विशिष्ट प्रकृति) में परिवर्तन की शर्त पर किया गया था, लेकिन ऐसा कोई आदेश अभिलेख में नहीं था। यह इंगित करना प्रासंगिक होगा कि कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना के लिए किसी भी भूमि की नोडयत में उस गाँव की कुल भूमि का दो प्रतिशत चरनोई हेतु सुरक्षित रखने की शर्त पर परिवर्तन कर सकता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए अभिलेख में कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि दो प्रतिशत भूमि चरनोई के लिए सुरक्षित की गई थी और म.प्र.भू.रा.सं. के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के लिए नोडयत में परिवर्तन किया गया था।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. में बिना किसी प्रावधान के राज्य सरकार के उपक्रम को भूमि आवंटित करना कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। प्रचलित मार्गदर्शिका (वर्ष 2021-22) दरों पर की गई गणना के अनुसार, ₹12.58⁷⁰ लाख मूल्य की भूमि का आवंटन आवंटिती द्वारा

⁶⁹ 0.1048 हेक्टेयर * ₹8.00 लाख = ₹83,840 (गाइडलाइन वर्ष 2020-21 के अनुसार, ₹8.00 प्रति हेक्टेयर की कृषि दर से बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत पर परिगणित)

⁷⁰ 1048*₹1200=₹12.58 लाख; (₹1200 प्रतिवर्ग मीटर वाणिज्यिक की दर से)

₹73,848 (प्रीमियम और पट्टा किराया) के भुगतान पर किया जाना अनियमित और एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि भूमि आवंटन प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.2.12.2 आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय में नजूल भूमि की उपलब्धता के सम्बंध में जिलेवार आंकड़ों का संधारण न किया जाना

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 4 के अनुसार, समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, आयुक्त, भू-अभिलेख(सी.एल.आर.) नजूल भूमि के अभिलेख तैयार कर उनका संधारण करेंगे। लेखापरीक्षा ने सी.एल.आर. से नजूल भूमि की उपलब्धता के सम्बंध में जिलेवार आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (मई 2022) लेकिन सी.एल.आर. के पास समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि, सी.एल.आर. ने बताया (मई 2022) कि सभी जिलों से अपेक्षित जानकारी मांगी गई थी। सी.एल.आर. द्वारा मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में, केवल 17 जिलों⁷¹ ने शासकीय भूमि के सम्बंध में आंकड़े प्रस्तुत किये। शेष 35 जिलों के सम्बंध में सी.एल.आर. से अपेक्षित जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2023)।

इसके अलावा, जिलों से प्राप्त आंकड़ों की जांच से पता चला कि जिलों द्वारा संधारित आंकड़े एम.पी. भूलेख पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों से भिन्न थे। भिन्नता का विवरण **परिशिष्ट-2.2.10** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि शासकीय भूमि के सम्बंध में आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए विभाग स्तर पर कोई प्रणाली नहीं थी।

सी.एल.आर. के कार्यालय में अथवा शेष जिलों के कलेक्टर में नजूल भूमि के समेकित आंकड़ों की अनुपलब्धता स्पष्ट रूप से एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 4 का अनुपालन न किए जाने एवं विभाग स्तर पर निष्प्रभावी निगरानी को रेखांकित करता है।

शासन ने बताया (जून 2023) कि सी.एल.आर. को तथ्यों के परीक्षण हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

2.2.12.3 निगरानी के अभाव में राजस्व विभाग की भूमि पर वन विभाग का अतिक्रमण

संभाग स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति ने इंदौर जिले के ग्राम बेटमाखुर्द में 10 सर्वे नंबरों⁷² में सन्निहित 185.019 हेक्टेयर भूमि को फर्नीचर क्लस्टर के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) विभाग को हस्तांतरित करने के लिए जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के

⁷¹ आगर-मालवा, बालाघाट, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, इन्दौर कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रतलाम, श्योपुर, सीधी, उमरिया

⁷² 50/1, 50/14, 135/6, 228/13, 347/2, 388/1/2, 390/1, 395/2, 437/2, 228/1

प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (जुलाई 2021)। राजस्व अभिलेखों में पहाड़ और चट्टान के रूप में दर्ज 185.019 हेक्टेयर भूमि की नोडयत को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित कर दिया गया।

पटवारी की रिपोर्ट (फरवरी 2021) के अनुसार, बेटमाखुर्द गांव में, वन विभाग ने कांटेदार बाड़ लगाकर 60.00 हेक्टेयर⁷³ पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और इस अनुचित प्रवेश के समर्थन में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। कब्जा रसीद (07-01-2022) के अनुसार, केवल 46.271 हेक्टेयर भूमि ही महाप्रबंधक, जिला वाणिज्य एवं उद्योग केन्द्र को सौंपी जा सकी (जनवरी 2022)। लेकिन लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण (06-09-2022) से पता चला कि दो सर्वे नम्बरों⁷⁴ में सन्निहित भूमि के क्षेत्र (22.881 हेक्टेयर) को छोड़कर, शेष भूमि (162.138 हेक्टेयर⁷⁵) पर वन विभाग ने दावा किया था।

यह स्पष्ट है कि राजस्व विभाग की भूमि पर वन विभाग का यह अतिक्रमण स्पष्ट तौर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों के नियमित निरीक्षण की कमी और राजस्व विभाग की अप्रभावी निगरानी के कारण है।

शासन ने बताया (जून 2023) कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2.2.12.4 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण/कम वसूली के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ

भारतीय स्टाम्प (म.प्र.) संशोधन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 (डी)(i) में प्रावधान है कि यदि भूमि के विकास से सम्बंधित किसी अनुबंध में शर्त है कि विकास के उपरान्त, विकासकर्ता द्वारा ऐसी विकसित भूमि या उसके किसी भाग को अलग-अलग या संयुक्त रूप से धारित/विक्रय किया जाएगा, तो ऐसे संव्यवहार को अंतरण मानते हुए विकसित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाएगा।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 115 के अनुसार, भूमिस्वामी अधिकार में नीलामी द्वारा नजूल भूमि के निर्वर्तन की स्थिति में, जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि भू-खण्ड के आरक्षित मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर होगी।

कलेक्टर कार्यालय देवास के नजूल अनुभाग में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कलेक्टर देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी; (सी.ई.ओ.), देवास विकास प्राधिकरण; (डी.डी.ए.) तथा समदड़िया बिल्डर्स (देवास) लिमिटेड (विकासकर्ता) के मध्य, मध्य प्रदेश शासन की

⁷³ सर्वे नम्बर 388/1/2(30 हेक्टेयर); 395/2 (30.00 हेक्टेयर)

⁷⁴ सर्वे नम्बर 50/1-11.347 हेक्टेयर तथा 50/14-11.534 हेक्टेयर

⁷⁵ 185.019 हेक्टेयर - 22.881 हेक्टेयर = 162.138 हेक्टेयर

पुनर्घनत्विकरण योजना 2016 के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय सुविधाओं के निर्माण एवं विकास हेतु एक विकास अनुबंध निष्पादित किया गया था (मई 2022)।

परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण एजेंसी होने के नाते डी.डी.ए. ने परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार किया। इस परियोजना में मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण तथा विकास और देवास में भवन निर्माण सेवाओं तथा स्थल (साइट) के बुनियादी ढांचे को सम्मिलित कर सिविल लाइंस में शासकीय कर्मचारी आवास का निर्माण और विकास के साथ-साथ भूमि स्वामी के अधिकारों पर प्रतिपूरक भू-खण्ड (सी.एल.पी.) का निपटान भी शामिल है जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.11** में दर्शाया गया है।

अनुबंध के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन, देवास विकास प्राधिकरण के परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के अधीन निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजना का विकास करने का इच्छुक है, जहां चयनित विकासकर्ता स्थल अधोसंरचना का निर्माण एवं विकास कार्य करेगा। चयनित विकासकर्ता को बदले में भूमि-स्वामी अधिकारों सहित सी.एल.पी. एवं उस पर निर्मित सम्पत्तियों पर डिजाइन, निर्माण, विकास, संचालन, संधारण तथा विकास कार्यों का प्रबंधन तथा उस पर निर्मित आवसीय/ वाणिज्यिक इकाइयों के विक्रय द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार होगा।

उक्त वर्णित भूमि-स्वामी के अधिकार चयनित विकासकर्ता द्वारा उद्धरित प्रीमियम के भुगतान पर चयनित विकासकर्ता को प्रदान किए जाएंगे। अनुबंध की निर्धारित भुगतान अनुसूची-घ के अनुसार, चयनित विकासकर्ता द्वारा प्रीमियम का भुगतान, आंशिक रूप से पूर्ण की गई स्थल अधोसंरचना के निर्माण, विकास, उसके सौंपे जाने एवं अंतरण के रूप में तथा अंशतः मौद्रिक रूप में (प्रीमियम के मौद्रिक भुगतान के रूप में उल्लिखित) किया जाना प्रस्तावित है।

स्थल अधोसंरचना की कुल लागत को प्रीमियम का वस्तुरूपी भुगतान माना गया है, जिसका निर्धारण दिनांक 01.12.2020 से प्रभावी मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.डी.ए. ने एकल चरण की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोलियां आमंत्रित की (जनवरी 2022) जिसमें पसंदीदा बोलीदाता द्वारा उद्धरित ₹ 71 करोड़ उच्चतम बोली मूल्य था तथा तदनुसार पसंदीदा बोलीदाता को प्रीमियम की उच्चतम बोली मूल्य के रूप में निर्णीत किया गया। अभिलेखों की आगामी संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईं:-

- **विकास अनुबंध पर स्टम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण**

अनुबंध के अनुसार, विकासकर्ता द्वारा भूमि धारित एवं विक्रय की जाएगी, अतः विकास एवं सी.एल.पी. के रूप में, बिक्री हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड के बाजार मूल्य पर वही शुल्क (पांच प्रतिशत)

जो भूमि के अंतरण पर लगता है, आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त पंजीयन अधिनियम, 1908 की अनुसूची-1 के अनुसार, उस राशि पर, जिस पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है, पंजीयन फीस की गणना 0.8 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध मात्र ₹1000 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क⁷⁶ (₹2.35 करोड़) एवं पंजीयन फीस (₹37.60 लाख) का कम आरोपण हुआ।

- **प्रतिभूति जमा राशि कम जमा किया जाना एवं विकासकर्ता को उसका अनियमित प्रतिदाय**

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 115(6) के अनुसार, भू-खण्ड की नीलामी में भागीदारी हेतु बोलीदाता द्वारा आरक्षित मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा राशि ₹ 94.00 लाख⁷⁷ जमा किया जाना वांछित था। उक्त निर्देशों की कंडिका 117 में प्रावधान है कि उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर, सभी बोलीदाताओं की प्रतिभूति जमा राशि उनके बैंक खातों में वापस कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया (कंडिका 9.5.2) था कि विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रतिभूति जमा राशि चयनित बोलीदाता को वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति जमा राशि के रूप में केवल राशि ₹24.00 लाख जमा कराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति जमा राशि ₹ 70.00 लाख कम जमा हुई तथा जमा कराई गई प्रतिभूति जमा राशि (₹ 24.00 लाख) विकास अनुबंध के निष्पादन के उपरान्त चयनित बोलीदाता को अनियमित रूप से वापस (जून 2022) कर दी गई।

- **भूमि का प्रीमियम जमा करने में विकासकर्ता को अनुचित छूट**

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 117(5) में प्रावधान है कि यदि प्रीमियम की अपेक्षित राशि निर्धारित अवधि (30 दिन) एवं चयनित बोलीदाता के अनुरोध पर कलेक्टर द्वारा अनुमत्य विस्तारित अवधि 60 दिन तक, यदि कोई हो, के भीतर लेखा शीर्ष “0029-भू-राजस्व” के अन्तर्गत सफल बोलीदाता अपेक्षित राशि जमा नहीं करता है तो बोली स्वतः निरस्त हो जाएगी एवं बोलीदाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात हो जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रतिपूरक भू-खण्डों पर चयनित विकासकर्ता को भूमि स्वामी अधिकार प्रीमियम राशि ₹ 71.00 करोड़ के भुगतान पर

⁷⁶ आरोपणीय स्टाम्प शुल्क- ₹47 करोड़ (बाजार मूल्य) का पांच प्रतिशत= ₹2.35 करोड़; पंजीकरण फीस - ₹47 करोड़ (बाजार मूल्य) का 0.8 प्रतिशत= ₹37.60 लाख

⁷⁷ प्रतिभूति जमा राशि- आरक्षित मूल्य (₹47.00 करोड़) का दो प्रतिशत= ₹94.00 लाख

दिया जाना है। चयनित विकासकर्ता द्वारा प्रीमियम का भुगतान अंशतः वस्तु रूप में (₹ 37.22 करोड़) तथा अंशतः मौद्रिक रूप में (₹ 33.78 करोड़) किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की पूर्व शर्त के रूप में, विकासकर्ता ने प्रीमियम के मौद्रिक भुगतान की पहली किस्त के रूप में प्रीमियम का केवल पांच प्रतिशत (₹ 3.55 करोड़) डी.डी.ए. के बैंक खाते में जमा किया (मई 2022)। प्रीमियम का शेष मौद्रिक भुगतान उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत उसे नियत दिनांक से 10 त्रैमासिक किस्तों में करना था। जबकि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 117 के अनुसार, सम्पूर्ण राशि (₹33.78 करोड़) का भुगतान 30 दिन के भीतर किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि अनुबंध की शर्तें मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत थीं तथा शासन के हित में नहीं थीं और इस प्रकार चयनित बोलीदाता को अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के समतुल्य थीं। न तो कलेक्टर ने और न ही डिप्टी कलेक्टर ने यह सुनिश्चित किया कि नियम और शर्तें शासन के हित में थीं या एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के अनुरूप थीं।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि डी.डी.ए. द्वारा विकासकर्ता से प्राप्त पहली किस्त (₹ 3.55 करोड़) भी शीर्ष “0029-भूमि राजस्व” के अंतर्गत जमा नहीं की थी (अक्टूबर 2022); और यह राशि डी.डी.ए. के बैंक खाते में रखी गई थी।

- **विकासकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी की वैधता निर्धारित अवधि तक की न होना**

पुनर्घनत्विकरण नीति 2016 की कंडिका 13(क) के अनुसार, बैंक गारंटी नवम्बर 2029 तक (कार्य पूर्णता के प्रत्याशित दिनांक अर्थात् नवम्बर 2024 से पांच वर्ष तक) वैध होना वांछित थी। उपरोक्त प्रावधानों में यह भी है कि, दोष दायित्व अवधि के दौरान निर्माण कार्य में किसी दोष या कमी में सुधार करना पर्यवेक्षण एजेंसी का कर्तव्य है।

अनुबंध के अनुसार, दोष दायित्व अवधि निर्माण कार्य के पूर्ण होने तथा इसे पर्यवेक्षण एजेंसी को सौंपने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक थी। बैंक गारंटी की अवधि अनिवार्य रूप से दोष दायित्व अवधि के बराबर होना चाहिए जिससे कार्य पूर्णता के पश्चात निर्माण कार्य में आए किसी दोष के सुधार में हुए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति बैंक गारंटी से की जा सके। लेकिन लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विकासकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी केवल मई 2025 तक वैध थी। बैंक गारंटी की अवधि निर्धारित अवधि से चार वर्ष कम थी अतः यह स्पष्ट था कि पर्यवेक्षण एजेंसी (डी.डी.ए.) ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए शासन के हितों के साथ समझौता किया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि देवास में, लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटारे और कम निर्धारित किए गए राजस्व की वसूली के लिए डी.डी.ए. के सी.ई.ओ. को पत्र जारी किया गया है।

2.2.12.5 आवंटन आवेदनों के प्रभावी एवं कुशल निराकरण का अभाव

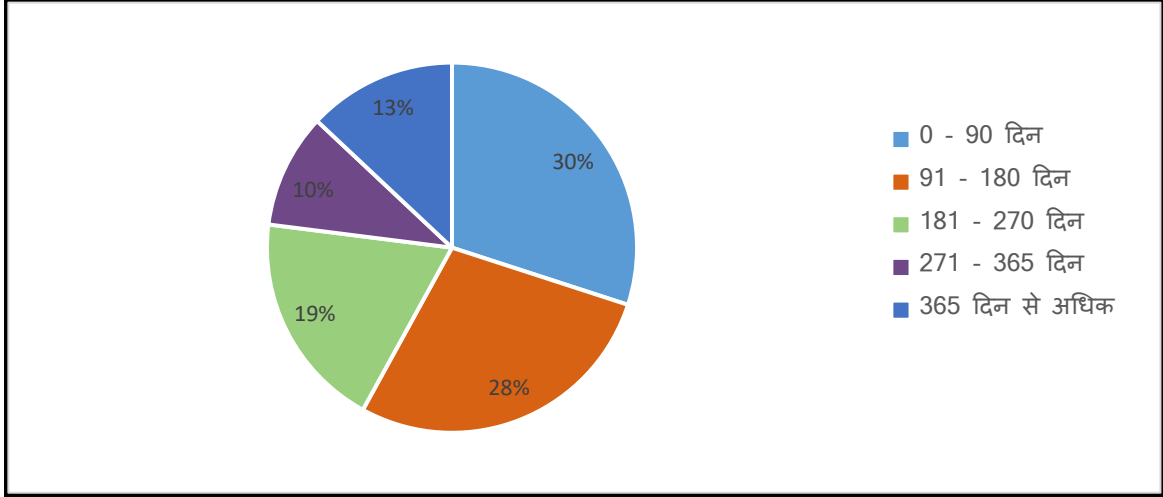
लेखापरीक्षा पृच्छा (जनवरी 2023) के प्रत्युत्तर में प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग ने शासकीय भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु विभागीय नियमों/विनियमों एवं दिशानिर्देशों में कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूमि आवंटन के 29.93 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण 90 दिन के भीतर किया गया, जबकि 13.27 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण में एक वर्ष से अधिक का समय लगा। निम्नलिखित तालिका एवं चार्ट विभिन्न समयान्तरालों के भीतर आवेदनों के निराकरण के समयवार विश्लेषण को दर्शाता है।

तालिका 2.2.6: विभिन्न समयान्तरालों के भीतर आवेदनों के निराकरण का विवरण						
जिला	निराकृत किए गए आवेदनों की संख्या					कुल
	0 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 से 270 दिन	271 से 365 दिन	365 दिन से अधिक	
शहडोल	11	5	6	3	4	29
सिंगरौली	20	22	3	4	1	50
धार	15	15	14	3	3	50
ग्वालियर	15	13	14	5	5	52
भोपाल	2	5	10	5	4	26
इन्दौर	5	7	3	4	15	34
देवास	2	0	1	0	1	4
जबलपुर	18	14	6	5	6	49
योग	88	81	57	29	39	294

निम्नलिखित चार्ट आवेदनों के निराकरण में लिए गए समय का समयान्तरालवार विश्लेषण को दर्शाता है:

चार्ट 1: आवेदन के निपटान में लगने वाले समय का समयान्तरालवार विश्लेषण



भूमि आवंटन प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा के संबंध में दिशानिर्देशों के अभाव में, प्रकरणों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलम्ब हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि समयावधि निर्धारित करना एक व्यावहारिक समाधान नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन मांगा जाना शामिल है। यह भी बताया कि भूमि का आवंटन आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी समयसीमा के अभाव में आवंटन प्रकरणों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब हुआ और अत्यधिक विलम्ब का कोई कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

अनुशंसा 8: शासन को आवेदनों की प्राप्ति से लेकर शासकीय भूमि के आवंटन तक उनके निराकरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा आवेदनों के निराकरण में विलम्ब के कारणों को भी अभिलिखित किया जाना चाहिए।

2.2.12.6 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(1)(ख) में प्रावधान है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्राधिकार होगा कि वह यह अपेक्षा करे कि कोई भी लेखे, बहियां, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों, जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बंधित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिए जाए जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा के दौरान, कलेक्टर एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख से बार-बार अनुरोध किए जाने तथा सम्बंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ, प्रमुख सचिव, राजस्व (मार्च 2023) तथा

प्रमुख राजस्व आयुक्त को सूचित करने (फरवरी 2023) के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए: 1. स्थायी पट्टा पंजी, 2. नवीनीकरण के लिए बकाया स्थायी पट्टा प्रकरण, 3. शासकीय भूमि का निजी भूमि से विनिमय के प्रकरण, 4. निजी व्यक्तियों, ट्रस्ट एवं संस्थाओं को शासकीय भूमि के आवंटन की सूची एवं प्रकरण नस्तियां।

प्रमुख सचिव, राजस्व से मांगे गए (मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023) शून्य प्रीमियम पर शासकीय भूमि के आवंटन के संबंध में शासन स्तर पर उपलब्ध अन्य अभिलेख जैसे नोट शीट / कैबिनेट नोट भी प्रतीक्षित हैं।

शासन ने बताया (जून 2023) कि कलेक्टर ग्वालियर को लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

2.2.13 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली है कि विभागीय संक्रियायें लागू नियमों, विनियमों, तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी तरीके से संचालित की जा रही हैं तथा अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेख, पंजियां/लेखा पुस्तिकाएं उचित तथा सही ढंग से संधारित कर रहे हैं तथा राजस्व की वसूली न होने/कम होने या राजस्व के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है।

2.2.13.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना न किया जाना तथा अधीनस्थ इकाईयों से सुझाव/फीडबैक न मांगा जाना

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक प्रमुख अवयव है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त में भू-राजस्व के अधिनियमों तथा नियमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग की लेखापरीक्षा के लिए विशेष तौर पर संलग्न आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा विद्यमान नहीं थी। विभाग हेतु एक समर्पित आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभाव में, लगातार होने वाली अनियमितताएं, जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई है, शासन के ध्यान में नहीं आईं। राजस्व अधिकारियों के समक्ष आने वाली बाध्यताएं एवं व्यावहारिक कठिनाईयों का समाधान करने के दृष्टिकोण से भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन के सम्बंध में अधीनस्थ जिलों से सुझाव/फीडबैक मांगा जाना वांछित है। आवश्यक सुझाव/फीडबैक से सम्बंधित जानकारी मांगे जाने पर, उपायुक्त, राजस्व ने बताया कि किसी भी प्रकरण में अधीनस्थ जिलों से ऐसा कोई फीडबैक नहीं मांगा गया है।

2.2.13.2 शासकीय भूमि के प्रबंधन की समीक्षा हेतु न तो विभागीय निरीक्षण किए गए और न ही आवधिक बैठकें आयोजित की गईं

आर.बी.सी.- II-1 की कंडिका 34 के अनुसार, संभागीय आयुक्त को एक वर्ष में प्रत्येक कलेक्ट्रेट एवं तहसील के राजस्व कार्यालयों का क्रमशः एक एवं तीन वर्ष में निरीक्षण करना चाहिए, जबकि कलेक्टर को प्रत्येक वर्ष अपने जिले की प्रत्येक तहसील (राजस्व न्यायालय) का निरीक्षण करना चाहिए।

नमूना जांच की गई कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान न तो आयुक्त ने और न ही जिला कलेक्टर ने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चयनित जिलों/तहसीलों में विभागीय निरीक्षण किए। अधीनस्थ इकाईयों के आवधिक निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार करने से सम्बंधित एक लेखापरीक्षा पृच्छा (जनवरी 2023) के प्रत्युत्तर में, विभाग द्वारा कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया गया।

शासकीय भूमि के प्रबंधन हेतु आवधिक बैठकों से सम्बंधित एक लेखापरीक्षा पृच्छा के प्रत्युत्तर में, उपायुक्त, राजस्व, कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 8 के अनुसरण में, शासकीय भूमि के निर्वर्तन हेतु जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर समितियां⁷⁸ विद्यमान हैं और विभाग स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। शासकीय भूमि के प्रबंधन के सम्बंध में आवधिक बैठकें आयोजित किए जाने के सम्बंध में विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। जबकि, यहां यह इंगित किया जाना प्रासंगिक होगा कि पूर्वोक्त समितियां केवल भूमि आवंटन के उद्देश्य हेतु गठित की गई हैं, न कि शासकीय भूमि के समग्र प्रबंधन हेतु।

यदि प्रमुख राजस्व आयुक्त/आयुक्त, भू-अभिलेख ने आवधिक बैठकों के माध्यम से जिलों की निगरानी की होती तो जिलों द्वारा संधारित डाटा तथा पोर्टल पर अपलोड डाटा में भिन्नता से बचा जा सकता था। विभाग में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा, अप्रयुक्त भूमि तथा अवनिर्धारण तथा लागू नियमों का पालन न किए जाने के कारण राजस्व हानि से सम्बंधित मामलों के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण का अत्यधिक अभाव है। शीर्ष स्तर पर शासकीय भूमि के प्रबंधन हेतु आवधिक बैठकों का आयोजन न किए जाने से विभाग स्तर पर निगरानी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

यदि कलेक्टरों/आयुक्तों ने चयनित तहसीलों/जिलों में आवधिक निरीक्षण किए होते तो प्रक्रियात्मक चूकों के साथ-साथ राजस्व की भारी हानि की अन्तर्निहित अन्य अनियमितताओं, जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई है, से बचा जा सकता था।

⁷⁸ जिला नजूल निर्वर्तन समिति, संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा राज्य नजूल निर्वर्तन समिति

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कलेक्टरों/आयुक्तों ने नियमित रूप से अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निर्धारित समयावधि में निरीक्षण किया था।

शासन का उत्तर नमूना परीक्षित की गई कलेक्टरों/तहसीलों द्वारा दी गई जानकारी के विपरीत है जिसके अनुसार न तो आयुक्तों और न ही जिला कलेक्टरों ने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभागीय निरीक्षण किए थे।

अनुशंसा 9: शासन को राजस्व विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करना चाहिए तथा संभागीय आयुक्तों/कलेक्टरों द्वारा राजस्व कार्यालयों/तहसीलों के आवधिक निरीक्षणों को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.13.3 आवश्यक अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

- **अतिक्रमण पंजी का संधारण न किया जाना**

म.प्र.भू.रा.सं.(दिनांक 28.09.2018 से प्रभावी) की धारा 59 एवं 60 के अन्तर्गत निर्मित म.प्र.भू.रा.सं.(भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम 2018 की कंडिका 16(1) में प्रावधान है कि पटवारी या राजस्व निरीक्षक वर्ष में एक बार अपने अधिकारिता राजस्व क्षेत्र के भीतर स्थित प्रत्येक सर्वे नम्बर एवं प्लॉट नम्बर का निरीक्षण करेंगे।

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 104 के अन्तर्गत निर्मित नियम 28 के अनुसरण में, पटवारी द्वारा अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में, भूमि के विवरण, अतिक्रमित क्षेत्र तथा नक्शा दर्शाते हुए, एक अतिक्रमण पंजी संधारित किया जाना वांछित है। नियम 9 के उपखण्ड 3 के अनुसार, शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण की लिखित सूचना तहसीलदार को देना पटवारी का कर्तव्य होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पटवारियों/राजस्व निरीक्षकों ने किसी भी चयनित तहसील में विभिन्न अभिलेख जैसे कि अतिक्रमण पंजी तथा स्थलों/भू-भागों के भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन, जो संहिता, आर.बी.सी. तथा विभागीय परिपत्रों के प्रावधानों के अन्तर्गत संधारित किए जाने अपेक्षित थे, संधारित नहीं किए गए थे।

भूमि का भ्रमण कर स्व-प्रेरणा से कार्यवाही करने तथा उसकी स्थिति तहसीलदार/एस.डी.ओ. को सूचित करने के बजाय, पटवारियों ने केवल ऐसे भू-खण्डों पर अतिक्रमण के सम्बंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिनके सम्बंध में तहसीलदार को शिकायत की गई थी। पूर्ववर्ती कंडिका 2.2.9.2 में की गई विवेचना के अनुसार, उपरोक्त अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई।

• **स्थायी पट्टा पंजी का संधारण न किया जाना**

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 108(ख) के अनुसरण में, नजूल अधिकारी द्वारा स्थायी पट्टा धारकों की कुल संख्या, आवंटन दिनांक, पट्टे की अवधि, संग्रहीत किए जाने वाली वार्षिक किराया की राशि तथा नवीनीकरण का नियत दिनांक दर्शाते हुए एक पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (सितम्बर 2022) कि धार को छोड़कर किसी भी चयनित जिले में नजूल अधिकारियों ने स्थायी पट्टा पंजी संधारित नहीं की थी। पट्टा आवंटन प्रकरणों के आधारभूत अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा पूर्व में स्वीकृत किए गए उन पट्टों की सही संख्या का निर्धारण नहीं कर सका जो नवीनीकरण किए जाने योग्य थे तथा जिन पर किराये की वसूली की जानी थी। बार-बार अनुरोध किए जाने पर, एक तदर्थ सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जिसमें भूमि आवंटन प्रकरणों के पूर्वोक्त विवरण शामिल नहीं थे। भूमि आवंटन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के लिए नजूल अनुभाग में न तो कोई समेकित जानकारी थी और न ही कोई निगरानी प्रणाली विद्यमान थी।

पूर्व में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.9 में ऐसे ही तथ्य को इंगित किया गया था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि भोपाल एवं जबलपुर में सभी पट्टवारियों द्वारा अतिक्रमण एवं पट्टा पंजी संधारित किए जाते हैं। ग्वालियर में, सभी राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण पंजी तैयार करने तथा वर्तमान पट्टा पंजी अद्यतन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देवास, धार, इन्दौर, शहडोल तथा सिंगरौली जिलों के सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अतिक्रमण पंजी किसी भी तहसील में संधारित किया जाना नहीं पाई गई तथा पट्टा पंजी धार को छोड़कर किसी भी जिले में संधारित नहीं पाई गई।

अनुशंसा 10: विभाग को पट्टवारियों/राजस्व निरीक्षकों से अतिक्रमण एवं भूमि उपयोग के सम्बंध में उनका निरीक्षण प्रतिवेदन मांग कर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए तथा शासकीय भूमि के स्थायी पट्टों का सम्पूर्ण अभिलेख संधारित करना चाहिए जिससे सामयिक नवीनीकरण तथा शासकीय देय राशियों हेतु सृजित मांग की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। विभाग को शासकीय भूमि के अभिलेखों के संधारण में त्रुटि करने वाले चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण भी करना चाहिए।

2.2.14 निष्कर्ष

जैसी कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है, शासकीय भूमि का आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा में, मार्गदर्शिका की दरों के गलत लागू किए जाने के कारण बाजार मूल्य का

अवनिर्धारण, पंचायत उपकर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि, शून्य प्रीमियम पर शासकीय भूमि का आवंटन, पट्टे के नवीनीकरण में पट्टेदार को अवनिर्धारण के रूप में अनुचित लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि, प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम निर्धारण और बकाया राशि पर ब्याज का अनारोपण, स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने के कारण शासकीय राजस्व की हानि, भूमि के आवंटन पर प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया का अनारोपण, शासकीय भूमि के अनधिकृत कब्जे पर कार्रवाई प्रारंभ न किया जाना एवं शास्ति का अनारोपण, शास्ति के आरोपण एवं बेदखली आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि का खाली न कराया जाना/शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा जारी रखने पर शास्ति की वसूली न होना परिलक्षित हुई।

मध्य प्रदेश शासन के विभागों को आवंटित भूमि के उपयोग की निगरानी न किया जाना, पूर्व खसरा एवं वर्तमान ऑनलाइन खसरा के क्षेत्रफल में भिन्नता, आवंटन आदेश में निर्दिष्ट खसरा नम्बरों से बिना अनुमोदन के विचलन, एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन कर शासकीय भूमि का आवंटन, आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय में नजूल भूमि की उपलब्धता से सम्बंधित जिलेवार डाटा संधारित न होना, राजस्व विभाग की भूमि पर वन विभाग का कब्जा, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण/वसूल न किए जाने के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ, आवंटन आवेदनों के प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन की कमी तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना न होना भी लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया।

विभागीय प्राधिकारियों ने विभागीय निरीक्षण नहीं किए और न ही उन्होंने शासकीय भूमि के प्रबंधन की समीक्षा हेतु आवधिक बैठकों का आयोजन किया। आवश्यक अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई।

श्रम विभाग

2.3 मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी) ने राज्य के असंगठित श्रमिकों⁷⁹ को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना (अप्रैल 2018) लागू की। संबल योजना के लक्षित लाभार्थी 18 से 60 वर्ष के मध्य आयु वाले असंगठित श्रमिक हैं। श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन संबल योजना के अंतर्गत, चार श्रेणियों में सहायता प्रदान करता है जैसा कि **तालिका-2.3.1** में वर्णित है।

तालिका-2.3.1: संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का विवरण		
स.क्र.	सहायता का नाम	प्रति लाभार्थी सहायता (₹ में)
1.	अंत्येष्टि सहायता	5,000
2.	अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु के प्रकरण में)	2,00,000
	अनुग्रह सहायता (दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में)	4,00,000
	अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता के प्रकरण में)	2,00,000
	अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता के प्रकरण में)	1,00,000
3.	उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना ⁸⁰	ऋण राशि का 10 प्रतिशत या 5,000 जो भी कम हो
4.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना ⁸¹	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित समरूप योजना के अनुसार

(स्रोत: सम्बल योजना दिशानिर्देश)

⁷⁹ श्रमिक जो किसी रोजगार, स्व-रोजगार अथवा अस्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे हुए हैं एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि के हकदार नहीं हैं तथा सरकारी सेवा में/करदाता नहीं होना चाहिए एवं एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, असंगठित श्रमिक माना जाएगा।

⁸⁰ श्रमिक के काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जानी थी। यह योजना प्रारंभ (मई 2018) से ही निष्क्रिय रही।

⁸¹ श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश (दिनांक 14.05.2018) जारी किया जिसके अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना का कार्यान्वयन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना था। बाद में, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश (दिनांक 29.05.2018) जारी किया कि श्रम विभाग 'व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना' का कार्यान्वयन करेगा। यह योजना भी प्रारंभ (मई 2018) से ही निष्क्रिय रही।

2018-22 के दौरान, श्रम विभाग ने 1,68,342 लाभार्थियों को ₹3,697.46 करोड़ की अनुग्रह सहायता एवं 2,17,385 लाभार्थियों को ₹108.67 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता स्वीकृत की।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

संबल योजना के कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारियों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व तालिका-2.3.2 में वर्णित हैं:

तालिका-2.3.2: प्राधिकारियों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व	
प्राधिकारी	कार्य एवं उत्तरदायित्व
राज्य स्तर	
प्रमुख सचिव (पी.एस.), श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन	श्रम विभाग के प्रशासनिक प्रमुख
श्रम आयुक्त (एल.सी.), मध्य प्रदेश	संबल योजना की कार्ययोजना बनाना, बजट तैयार करना एवं निगरानी करना
सचिव, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल)	नीति निर्धारण में शासन के साथ समन्वय एवं जिला स्तर पर आने वाली समस्याओं का मार्गदर्शन/समाधान प्रदान करना।
जिला स्तर	
जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी	किसी व्यक्ति के पंजीकरण एवं लाभ की स्वीकृति के संबंध में पदाभिहित अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी.)/जिला श्रम अधिकारी (डी.एल.ओ.)	सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी हैं एवं इन्हें जिला स्तर पर विभाग के निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना है।
आयुक्त, नगर निगम (एन.एन.)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.), नगर पालिका/ परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जनपद पंचायत (जे.पी.)	पंजीकरण एवं लाभ की स्वीकृति के लिए पदाभिहित अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
वार्ड/जोन एवं ग्राम स्तर	
वार्ड अधिकारी/ सचिव, ग्राम पंचायत (जी.पी.)	असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन/दावे के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारियों को अग्रोषित करना। आगे, वार्ड अधिकारी/सचिव अंत्येष्टि सहायता प्रदान करते हैं।
(स्रोत: मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं संबल योजना दिशानिर्देश)	

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या सभी पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया था, पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था तथा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण मौजूद था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 दिशानिर्देश;
- मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (अधिनियम 2003) एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियम 2005;
- राज्य शासन तथा कल्याण मण्डलों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक आदेश, परिपत्र एवं राजपत्र अधिसूचनाएं।

2.3.5 कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने श्रम विभाग द्वारा संबल योजना के कार्यान्वयन⁸² से संबंधित अवधि 2018-19 से 2021-22 तक के अभिलेखों की प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन, श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के कार्यालयों में संवीक्षा की। आगे, हमने रैंडम सैंपलिंग का उपयोग करके एवं प्रवेश सम्मेलन (सितंबर 2022) के दौरान प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के सुझाव पर विचार करते हुए चयनित 10 जिलों⁸³ (राज्य के प्रत्येक संभाग से एक जिला) में संबल योजना से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। हमने 10 जनपद पंचायतों (प्रत्येक चयनित जिले से एक), 10 नगर निगम/पालिका (प्रत्येक चयनित जिले से एक), 10 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत से एक) एवं 10 वार्डों (प्रत्येक चयनित नगर निगम/पालिका से एक) का भी चयन किया। चयनित जिलों, जनपद पंचायतों, नगर निगम/पालिका एवं ग्राम पंचायतों/वार्डों का विवरण **परिशिष्ट-2.3.1** में दिया गया है।

आगे, हमने पंजीकृत श्रमिकों की वास्तविकता एवं पात्र लाभार्थियों को सहायता भुगतान का पता लगाने के लिए चयनित ग्राम पंचायतों/वार्डों में 258 पंजीकृत श्रमिकों/लाभार्थियों का संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण किया। इसके अतिरिक्त, हमने संबल योजना के एन.आई.सी. डेटा का भी विश्लेषण किया। प्रतिवेदन में डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है।

हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित (सितंबर 2022) किया। आगे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित (जून 2023) किया गया। शासन ने पैरा-वार उत्तर

⁸² श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन को संबल योजना के अंतर्गत चार योजनाओं का क्रियान्वयन करना था। यद्यपि, 2018-22 के दौरान विभाग दो योजनायें अर्थात् अंत्येष्टि सहायता योजना एवं अनुग्रह सहायता योजना लागू कर सका।

⁸³ जिला स्तर पर, लेखापरीक्षा ने जिला श्रम कार्यालयों, कलक्ट्रेट (अपीलीय प्राधिकारी) एवं जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच की।

प्रस्तुत (जून 2023 एवं मार्च 2024) किये जिन्हें प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.6 आयोजना

2.3.6.1 असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में कमियाँ

मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 23 में प्रावधान है कि असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आयु का प्रमाण एवं असंगठित कर्मकार होने का प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

यद्यपि, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राज्यव्यापी अभियान के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी (मार्च एवं मई 2018) किए। निर्देशों में आवेदक से स्व-घोषणा पत्र (आयु एवं असंगठित श्रमिक होने के संबंध में) प्राप्त करके असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए प्रावधान किया गया। विभाग ने आयु एवं असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए उनकी पात्रता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्राप्त किए बिना 2.18 करोड़ आवेदकों को असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकृत किया। श्रमिकों के पंजीकरण के लिए, समग्र पोर्टल डेटाबेस को आधार बनाया गया जहां गांव/वार्ड के सभी परिवारों की जानकारी पहले से ही उपलब्ध थी। पंजीकरण संबंधी अभिलेख एवं पोर्टल डेटा की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- श्रम विभाग ने पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की पात्रता का सत्यापन⁸⁴ करने एवं अपात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को बाहर करने के निर्देश (जून 2019) दिये। विभाग ने इस प्रकार 2.18 करोड़ में से 67.48⁸⁵ लाख (31 प्रतिशत) अपात्र आवेदकों जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि थी, शासकीय सेवा में थे, करदाता थे एवं कुछ अन्य कारणों से बाहर कर दिया। हमने आगे देखा कि भौतिक सत्यापन के दौरान, 67.48 लाख में से 14.34 लाख असंगठित श्रमिकों को उनकी अपात्रता के लिए विशिष्ट कारण⁸⁶ बताए बिना अपात्र घोषित किया गया था जो दर्शाता है कि भौतिक सत्यापन इस सीमा तक दोषपूर्ण था। पात्रता की पुष्टि किए बिना आवेदकों के पंजीकरण के परिणामस्वरूप अपात्र आवेदकों का पंजीकरण हुआ एवं आगे ₹1.14 करोड़ की सहायता का अनियमित संवितरण हुआ जैसा कि **कंडिका 2.3.7.8 और 2.3.7.9** में चर्चा की गई है।

⁸⁴ शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव, ग्राम पंचायत भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी थे।

⁸⁵ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के डेटा के अनुसार।

⁸⁶ मूल आवेदन नहीं मिला (3.46 लाख), अन्य कारणों से (10.49 लाख) एवं मौजूद नहीं (0.39 लाख)।

- श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने जिलास्तरीय श्रम कार्यालयों को भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित असंगठित श्रमिकों की नमूना जांच करने के निर्देश (अगस्त 2019) दिये। हमने देखा कि पांच⁸⁷ लेखापरीक्षित जिलों में, श्रम विभाग के अधिकारियों ने 339 श्रमिकों जिन्हें भौतिक सत्यापन के दौरान उनकी अपात्रता के लिए विशिष्ट कारण बताए बिना अपात्र घोषित किया गया था का नमूना जांच किया। हमने देखा कि जाँच के दौरान 339 में से 107 (32 प्रतिशत) असंगठित श्रमिक पात्र पाए गए। शेष पांच जिलों⁸⁸ में, श्रम विभाग के अधिकारियों ने अपात्र प्रकरणों की जांच नहीं की।
- हमने देखा कि लेखापरीक्षित जिलों में, 1,320 पंजीकृत असंगठित श्रमिकों जो भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किये गये थे, ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। हमने देखा कि संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर, अपीलीय प्राधिकारी ने 1,085 (82 प्रतिशत) असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण बहाल कर दिया एवं उन्हें पात्र घोषित किया। यह दर्शाता है कि भौतिक सत्यापन त्रुटिपूर्ण था एवं भौतिक सत्यापन में पात्र श्रमिकों को अपात्र घोषित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट-2.3.2** में है।
- हमने देखा कि सचिव, ग्राम पंचायत, बरई (जनपद पंचायत, घाटीगांव), ग्वालियर एवं वार्ड क्रमांक 60, नगर निगम, ग्वालियर के वार्ड अधिकारी ने सितंबर 2019 से दिसंबर 2019 के मध्य पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया एवं 1,999⁸⁹ पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मूल आवेदन उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया। लेखापरीक्षा को ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में इन असंगठित श्रमिकों के मूल आवेदन मिले (अक्टूबर 2022)। इस प्रकार, भौतिक सत्यापन करने में वार्ड अधिकारी/सचिव की लापरवाही के कारण, आवेदक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गये।
- विभाग ने लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन 1 सितंबर 2020 से 20 सितंबर 2020 के मध्य पूरा करने का निर्देश (अगस्त 2020) दिया। चयनित 20 जनपद पंचायतों/नगर निगम/पालिका के संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि 18⁹⁰ लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों/नगर निगम/पालिका में 1,00,938 असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन दिसंबर 2022 तक नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट-2.3.3** में है। हमने यह भी

⁸⁷ भिंड, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद एवं सतना।

⁸⁸ भोपाल, छतरपुर, इंदौर, जबलपुर एवं उमरिया।

⁸⁹ ग्राम पंचायत, बरई (जनपद पंचायत, घाटीगांव), ग्वालियर के 403 पंजीकृत श्रमिक एवं वार्ड 60 (नगर निगम) ग्वालियर के 1596 पंजीकृत श्रमिक।

⁹⁰ नगर निगम, भोपाल एवं जनपद पंचायत, फंदा (ग्रामीण), भोपाल ने जानकारी नहीं दी।

देखा कि दो प्रकरणों⁹¹ (नगर निगम, ग्वालियर एवं नगर पालिका, भिंड) में अनुग्रह सहायता का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया कि संबंधित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में देरी के कारण आवेदक योजना के लाभ से वंचित रहें।

स्पष्टतः, विभाग ने उचित सत्यापन किए बिना असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जिसके परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ। इस प्रकार, असंगठित श्रमिकों का डेटा ठीक से नहीं बनाया गया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का नमूना भौतिक सत्यापन किया गया। प्रासंगिक अभिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने अथवा श्रमिकों जो प्रवासी थे के अनुपलब्ध होने से, सत्यापन करने वाले प्राधिकारियों ने तदनुसार जानकारी दर्ज की। संबल 2.0 के अंतर्गत श्रमिकों को मई 2022 में पंजीकरण का अवसर दिया गया। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि रोजगार/कृषि भूमि की स्थिति में बदलाव के कारण, पंजीकरण एवं भौतिक सत्यापन के समय श्रमिक की पात्रता परिवर्तित हो सकती है। वर्तमान में, भौतिक सत्यापन के स्थान पर, पंजीकरण से पहले कृषि भूमि आदि की जांच उपरांत श्रमिक की पात्रता की पुष्टि करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वास्तविक श्रमिक की पहचान एवं मृत श्रमिक के वास्तविक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आधार के.वाई.सी. एवं आधार आधारित भुगतान प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा, पोर्टल को संशोधित किया गया है एवं अब लंबित मामले पदाभिहित अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर उचित निगरानी हेतु प्रदर्शित होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को अपात्र व्यक्तियों के असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित सत्यापन के बाद ही असंगठित श्रमिक का पंजीकरण करना चाहिए था। आगे, विभाग पंजीकृत श्रमिकों के भौतिक सत्यापन की निगरानी में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक निकाल दिए गए।

अनुशंसा 1: विभाग को त्रुटिपूर्ण भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए एवं शेष प्रकरणों में भौतिक सत्यापन तुरंत पूर्ण करना चाहिए। विभाग को भौतिक सत्यापन के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली तैयार करनी चाहिए एवं नियमित निगरानी करनी चाहिए।

⁹¹ श्रमिक आई.डी. 169250398 एवं 200133711

2.3.6.2 श्रमिकों का पंजीकरण न होना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने असंगठित श्रमिकों का नियमित पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु आदेश (मई 2018) जारी किया। आगे, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने पात्रता मानदंडों की पूर्ति होने पर पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता के संग्रह में लगे श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिकों के असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकरण के लिए आदेश जारी (अक्टूबर 2018, मई 2020 एवं जून 2021) किए।

हमने देखा कि लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं लेखापरीक्षित नगर निगम/पालिका के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान किसी भी असंगठित श्रमिक का पंजीकरण नहीं किया क्योंकि संबल पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण हेतु विभागीय आदेशों (अक्टूबर 2018, मई 2020 एवं जून 2021) के बावजूद, कोई पंजीकरण नहीं किया गया। हमने आगे देखा कि लेखापरीक्षित 12⁹² जनपद पंचायतों/नगर निगम/नगर पालिका में, 4,856 प्रवासी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र थे, की जानकारी संबल पोर्टल पर उपलब्ध थी परन्तु इसके बावजूद लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लेखापरीक्षित नगर निगम/पालिका के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी इन श्रमिकों का पंजीकरण नहीं कर सके क्योंकि पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, यद्यपि श्रम विभाग ने पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता के संग्रहण में लगे श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिक के पंजीकरण हेतु आदेश जारी किया, तथापि संबल पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा की उपलब्धता की निगरानी करने में विफल रहा।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता एवं प्रवासी श्रमिक समय-समय पर जारी पंजीकरण के लिए निर्देशों के अनुसार पोर्टल पर पंजीकृत किये जाते थे। अद्यतनीकरण/ रखरखाव कार्य हेतु पोर्टल बंद होने के कारण पंजीकरण बंद था। भारत सरकार ने भी प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। शासन ने आगे सूचित किया (मार्च 2024) कि श्रमिकों का पंजीकरण नहीं किया गया क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने आधार आधारित के.वाई.सी. के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया था। शासन ने जून 2021 में तेंदूपत्ता श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई-के.वाई.सी. की शर्तों में ढील दी एवं उसके बाद 73,166 तेंदूपत्ता श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। पुजारी/सेवादारी को

⁹² जनपद पंचायत, गोहद, भिंड (927), जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल (199), नगर निगम, भोपाल (13), जनपद पंचायत, छतरपुर (1182), नगर पालिका, छतरपुर (43), नगर निगम, देवास (28), नगर निगम, ग्वालियर (577), नगर पालिका, होशंगाबाद (3), नगर निगम, जबलपुर (1042), नगर निगम, सतना (33), जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया (802) एवं नगर पालिका, उमरिया (07)।

अलग से श्रेणी नहीं दी गई थी, इसलिए, पंजीकरण की संख्या बताना संभव नहीं है। आगे, 2.18 लाख प्रवासी श्रमिकों को भी पंजीकृत किया गया था एवं राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण एवं अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए अलग प्रवासी श्रमिक आयोग की स्थापना की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान पोर्टल पर कोई पंजीकरण नहीं किया गया था। उत्तर में, विभाग ने उस अवधि का उल्लेख नहीं किया जिसके दौरान तेंदूपत्ता एवं प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया।

अनुशंसा 2: विभाग को संबल पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा बंद/अनुपलब्ध होने के लिए जिम्मेदारी तय करना चाहिए एवं पात्र लाभार्थियों का निरंतर पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.6.3 उपकरण अनुदान एवं निःशुल्क कोचिंग योजनाओं का कार्यान्वयन न होना

संबल योजना के अंतर्गत, असंगठित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन को चार योजनाएं यथा अंत्येष्टि सहायता, अनुग्रह भुगतान सहायता, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना लागू करना था।

हमने देखा कि विभाग ने उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए न तो कोई आदेश/परिपत्र जारी किया और न ही बजट प्रावधान किया परिणामस्वरूप प्रारंभ से ही ये योजनायें असंचालित रही। आगे, हमें इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारणों को दर्शाने वाले अभिलेख नहीं मिले। इस प्रकार, श्रम आयुक्त इन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहे परिणामस्वरूप लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

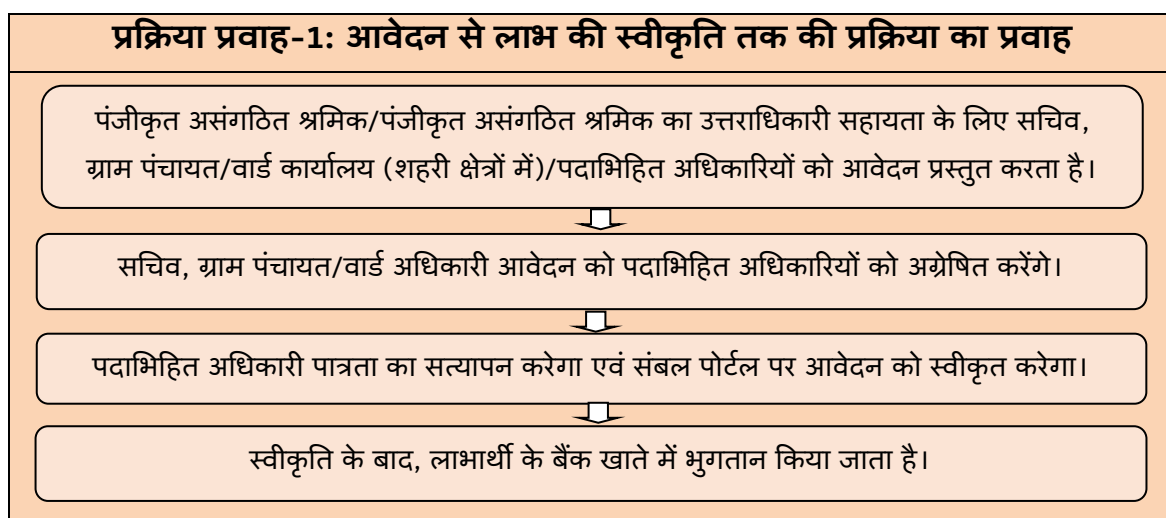
शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि राज्य शासन के पत्र दिनांक 14.05.2018 के अनुसार, निःशुल्क कोचिंग योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। चूंकि श्रम विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाना था एवं उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश (दिनांक 29.05.2018) जारी किया था जिसमें प्रावधान था कि श्रम विभाग 'व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना' का क्रियान्वयन करेगा। आगे, विभाग उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त न होने का संज्ञान लेने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा।

अनुशंसा-3: शासन को उत्तरदायी अधिकारी जिन्होंने योजना के लिए बजट प्रावधान तक नहीं किया की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

2.3.7 योजना कार्यान्वयन

संबल योजना के योजना दिशानिर्देशों में प्रावधानित है कि पंजीकृत असंगठित श्रमिक की अपंगता/मृत्यु की स्थिति में, श्रम विभाग पंजीकृत असंगठित श्रमिक/मृत पंजीकृत असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को अनुग्रह सहायता प्रदान करेगा। आवेदन से लाभ की स्वीकृति तक की प्रक्रिया का प्रवाह **प्रक्रिया प्रवाह-1** में दिया गया है:



हमने लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों/नगर निगम/पालिका में अनुग्रह सहायता के अंतर्गत किए गए भुगतानों की जांच की एवं एन.आई.सी. डेटा का भी विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:

2.3.7.1 योजना निधि की राशि कर्मचारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदारों के बैंक खातों में संदिग्ध कपटपूर्वक जमा किया जाना, ₹2.47 करोड़

संबल योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(i) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) से एकत्र किए गए संबल योजना के भुगतान डेटा की जांच में अनुग्रह सहायता का एकाधिक भुगतान अनधिकृत व्यक्तियों

के छ: बैंक खातों में होने का पता चला। आगे की जांच से पता चला कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा ने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता एक सहायक ग्रेड -2 (पुष्पेंद्र यादव) के रिश्तेदारों एवं अन्य असंबंधित व्यक्तियों के नाम तथा बैंक खातों को शामिल करते हुए कपटपूर्वक ई-भुगतान आदेश (ई.पी.ओ.) निकाले एवं इन ई-भुगतान आदेशों द्वारा आहरित किए गए ₹77.97 लाख 23 लेनदेनों के माध्यम से रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा किए जैसा कि तालिका-2.3.3 में वर्णित है।

तालिका 2.3.3: अनुग्रह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्वक जमा का विवरण					
स.क्र.	राशि जिनके बैंक खाते में जमा की गई	कर्मचारी से संबंध (सहायक ग्रेड-2)	राशि (₹ लाख में)	लेनदेनों की संख्या	लेनदेन की अवधि
जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी					
1	रामरतन	दादा	4.00	01	26.02.2019
जनपद पंचायत, सेंधवा, बड़वानी					
2	रामरतन	दादा	15.97	05	03.03.2020 से 28.09.2020
3	रंजीता बाई	पत्नी	22.00	06	11.08.2020 से 04.11.2020
4	राजकुवर बाई	माता	16.00	05	11.08.2020 से 28.09.2020
5	पवन तुलसीराम	अन्य	10.00	03	24.08.2020 से 04.11.2020
6	प्रिया छगन	अन्य	6.00	02	23.08.2020 एवं 28.09.2020
7	सपना बाई	अन्य	4.00	01	23.08.2020
कुल			77.97	23	

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संबल योजना भुगतान डेटा एवं संबंधित जनपद पंचायत के अभिलेख)

आगे की जांच से पता चला कि पुष्पेंद्र यादव, सहायक ग्रेड -2 जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी में (9 जनवरी 2020 तक) एवं आगे जनवरी 2020 से जनपद पंचायत, सेंधवा, बड़वानी में लेखापाल के रूप में पदस्थ थे। हमने देखा कि ई-भुगतान आदेश इन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पुष्पेंद्र यादव, लेखापाल के डिजिटल हस्ताक्षरों से निकाले गए थे। इन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने ई-भुगतान आदेश के अतिरिक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, इसलिए, हम यह पता नहीं लगा सके कि किसके भुगतान बदले गए अथवा क्या किसी लाभार्थी को वंचित किया गया अथवा नहीं।

(ii) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल डेटा की जांच से आगे पता चला कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजपुर एवं सेंधवा ने अन्य योजनाओं अर्थात् जनपद पंचायत निधि, ग्राम पंचायत भवन संधारण, निर्वाचन संबंधी राशि, राष्ट्रीय परिवार सहायता, मध्याह्न भोजन, बस्ती विकास योजना (जनजातीय कार्य विभाग) एवं बैंक खाते में अर्जित ब्याज के ₹1.69 करोड़ रुपये निकाले तथा कर्मचारी (पुष्पेंद्र यादव), कर्मचारी के रिश्तेदारों एवं चार अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में राशि जमा किये जैसा कि तालिका-2.3.4 में वर्णित है।

तालिका 2.3.4: अन्य योजनाओं से संदिग्ध कपटपूर्वक आहरण का विवरण						
स. क्र.	योजना का नाम	राशि जिनके बैंक खाते में जमा की गई	कर्मचारी से संबंध	राशि (₹ लाख में)	लेनदेनों की संख्या	लेनदेन की अवधि
जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी						
1	जनपद पंचायत निधि, ग्राम पंचायत भवन संधारण, निर्वाचन संबंधी राशि, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं बस्ती विकास योजना (जनजातीय कार्य विभाग)	रामरतन	दादा	32.22	06	10.12.2018 से 12.02.2020
2	मध्याह्न भोजन (प्राथमिक)	पुष्पेंद्र यादव	स्वयं	4.00	01	31.07.2019
जनपद पंचायत, सेंधवा, बड़वानी						
3	जनपद पंचायत निधि	रंजीता बाई	पत्नी	34.00	10	24.05.2021 से 24.09.2022
4	जनपद पंचायत निधि एवं बस्ती विकास योजना	रामरतन	दादा	8.00	02	12.02.2020 एवं 16.11.2020
5	जनपद पंचायत निधि	राजकुवर बाई	माता	24.00	08	08.05.2021 से 05.11.2022
6	जनपद पंचायत निधि	प्रिया छगन	अन्य (अज्ञात)	22.00	10	08.05.2021 से 05.11.2022
7	जनपद पंचायत निधि	पवन तुलसीराम	अन्य (अज्ञात)	20.00	08	20.06.2021 से 30.11.2022
8	जनपद पंचायत निधि	शिवा अशोक	अन्य (अज्ञात)	16.16	06	21.11.2020 से 29.09.2022
9	जनपद पंचायत निधि	सपना बाई	अन्य (अज्ञात)	6.00	02	11.03.2022 से 07.11.2022
10	बैंक का ब्याज	पुष्पेंद्र यादव	स्वयं	2.45	11	19.03.2020 से 29.11.2022
कुल				168.83	64	

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भुगतान डेटा एवं संबंधित जनपद पंचायत के अभिलेख)

हमने देखा कि पवन तुलसीराम के बैंक खाते से पुष्पेंद्र यादव, लेखापाल के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई थी। आगे, लेखापरीक्षा प्रिया छगन, शिवा अशोक एवं सपना बाई की पहचान को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि हमें जनपद पंचायत कार्यालय में प्रिया छगन, शिवा अशोक एवं सपना बाई के बैंक खातों में ₹54.16 लाख जमा होने के औचित्य को सत्यापित करने के लिए अभिलेख नहीं मिले।

इस प्रकार, जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने पुष्पेन्द्र यादव, लेखापाल के साथ मिलीभगत करके ₹2.47 करोड़ की योजना निधि को संदिग्ध कपटपूर्वक आहरित किया एवं अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किया।

शासन ने उत्तर (जून 2023 एवं मार्च 2024) दिया कि जिला कोषालय अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित (जून 2023) की गई थी। जिसकी जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। इसके पूर्व, कलेक्टर एवं श्रम अधिकारी, बड़वानी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा को पत्र जारी (अप्रैल एवं मई 2023) किया था, यद्यपि, संबंधितों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये है।

अनुशंसा-4: विभाग को जांच एवं अनियमितताओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

2.3.7.2 अपात्र/अस्वीकार्य भुगतान, ₹1.57 करोड़

संबल योजना के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में, मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान की जानी थी।

(अ) अनुग्रह सहायता का उन व्यक्तियों को भुगतान जो मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्य नहीं थे

संबल पोर्टल डेटा, भुगतान डेटा की जांच एवं आगे समग्र पोर्टल से अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम के सत्यापन से पता चला कि सात जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने सात व्यक्तियों जो समग्र विवरण के अनुसार मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्य नहीं थे, को ₹14 लाख की अनुग्रह सहायता वितरित की। विवरण **परिशिष्ट-2.3.4** में दिया गया है।

(ब) अपात्र प्रकरणों में अनुग्रह सहायता की स्वीकृति

श्रम विभाग ने निर्देश (अक्टूबर 2019) जारी किया कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सांप/अन्य जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु/अपंगता एवं घर में आग लगने, नदी में डूबने, आदि से मृत्यु के प्रकरणों में, अनुग्रह अनुदान का लाभ राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन प्रकरणों में, विभाग ने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता को अस्वीकार कर दिया।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि दो प्रकरणों (श्रमिक आई.डी. 131168264 एवं 107154044) में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका, होशंगाबाद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर ने अनियमित रूप से दो श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹6 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत एवं वितरित की जिनकी मृत्यु क्रमशः नदी में डूबने एवं सांप के काटने के कारण हुई थी। इन दोनों लाभार्थियों को राजस्व विभाग से भी अनुग्रह सहायता (₹8 लाख) का भुगतान प्राप्त (नवंबर 2019 एवं सितंबर 2020) हुआ था। योजना दिशानिर्देशों एवं श्रम विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 2019) के अनुसार ये लाभार्थी संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के भुगतान हेतु पात्र नहीं थे।

इसी तरह, चार⁹³ प्रकरणों में, पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु कुएं में डूबने, घर में आग लगने एवं सांप के काटने से हुई थी। पदाभिहित अधिकारियों⁹⁴ ने इन श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को संबल योजना के तहत अनियमित रूप से ₹16 लाख की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत एवं वितरित की जबकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रकरणों में अनुग्रह सहायता का भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया जाना था। राजस्व विभाग से भुगतान के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

इन छः प्रकरणों में अनुग्रह सहायता का भुगतान विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत था एवं परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत सहायता का अनियमित भुगतान हुआ।

(स) दो योजनाओं से अनुग्रह राशि का भुगतान

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) के डेटा के साथ अनुग्रह भुगतान डेटा के प्रति सत्यापन से पता चला कि 19 प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को दोनों योजनाओं (संबल योजना से ₹46.25 लाख एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना से ₹42.96 लाख) से ₹89.21 लाख की अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता स्वीकृति की। इन 19 प्रकरणों की आगे की जांच से निम्नलिखित पता चला:

- 11 प्रकरणों में, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना से भुगतान किये गये ₹26.48 लाख की अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता उन व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की गई जो मृत असंगठित श्रमिकों के परिवार के सदस्य नहीं थे। 11 में से छः प्रकरणों में, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं संबल योजना में एक ही मृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु के दिनांक

⁹³ मृत श्रमिक की श्रमिक आई.डी. (1) 123901664 (2) 177094317 (3) 161187336 एवं (4) 119404927

⁹⁴ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, छतरपुर, घाटीगांव (ग्वालियर), मानपुर (उमरिया) एवं आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर।

अलग-अलग थे जो मृत्यु के दिनांक में हेरफेर करके कपटपूर्वक भुगतान किया जाना दर्शाता है।

- एक प्रकरण में, आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर ने दिशानिर्देशों के विरुद्ध बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना एवं संबल योजना दोनों से अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता राशि ₹4.06 लाख का भुगतान किया।
- सात प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारी ने दोनों योजनाओं से अनुग्रह सहायता राशि ₹32.57 लाख (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना से ₹14.42 लाख एवं संबल योजना से ₹18.15 लाख) का वितरण किया। सात में से दो प्रकरणों में, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना एवं संबल योजना के अंतर्गत दावे के लिए संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में एक ही मृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु के दिनांक अलग-अलग थे जो कपटपूर्वक भुगतान दर्शाता है।

विवरण **परिशिष्ट-2.3.5** में दिया गया है।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारियों (आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर, मुरैना एवं इंदौर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, होशंगाबाद तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना एवं रामपुर बाघेलान, सतना) ने लाभ स्वीकृत करते समय प्रकरणों का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना एवं संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता का अनियमित दोहरा भुगतान हुआ।

(द) संबल लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता का भुगतान

संबल योजना के योजना दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु/अपंगता पर शासन की दो योजनाओं का समान लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। आगे, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया (सितंबर 2020) कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ उन प्रकरणों में प्रदान किया जाना चाहिए जहां लाभार्थी के पास संबल कार्ड (संबल योजना में पंजीकृत) नहीं है। चयनित जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका में संबल योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता के अभिलेखों एवं डेटा की जांच से पता चला कि 363 प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने संबल योजना के तहत ₹7.86 करोड़ की अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया। हमने आगे देखा कि इन लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से ₹72.60 लाख का भुगतान समान पंजीकृत असंगठित श्रमिक के मृत्यु हेतु किया गया। संबल योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत सहायता की स्वीकृति अनियमित थी। विवरण **परिशिष्ट-2.3.6** में है। इस प्रकार, समान प्राधिकारी जो दो अलग-अलग योजनाओं के तहत दो लाभों की स्वीकृति दे रहा था लाभ की स्वीकृति के समय प्रकरणों को सत्यापित करने में विफल रहा।

(य) अनियमित दावा

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) में प्रावधानित है कि जो श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें लाभार्थी माना जाएगा।

जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घाटीगांव ने उस व्यक्ति⁹⁵ को ₹2.05 लाख की अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का लाभ स्वीकृत किया, जो असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दावा करने के लिए, एक अन्य समान नाम⁹⁶ के पंजीकृत असंगठित श्रमिक का दस्तावेज दावा आवेदन में संलग्न किया गया था। यह दर्शाता है कि मृत लाभार्थी के विवरण को सत्यापित किए बिना सहायता प्रदान की गई थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र जारी किया (जून 2023)। इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई का अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि संबंधित नगर निगमों/पालिकाओं/जनपद पंचायतों से जानकारी एकत्र किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिम प्रतिवेदनों में, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास जिलों ने केवल पदाभिहित अधिकारियों को जारी पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की। कार्रवाई प्रतिवेदन में अपात्र/अस्वीकार्य भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं उसकी वसूली का कोई उल्लेख नहीं था।

अनुशंसा-5: विभाग को जांच गठित करनी चाहिए एवं एक से अधिक योजनाओं से भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश शासन को एक ही लाभार्थी द्वारा विभिन्न योजनाओं से भुगतान प्राप्त करना समाप्त करने के लिए सभी डेटाबेसों को आपस में जोड़ना भी चाहिए।

2.3.7.3 60 वर्ष से अधिक आयु के अपात्र व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता की स्वीकृति, ₹1.04 करोड़

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) में प्रावधान है कि पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु/अपंगता के दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक के होने पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.पी.एस.) के संबंध में सामाजिक न्याय

⁹⁵ रामहेत आदिवासी (समग्र आई.डी. 163727084) की मृत्यु 15.01.2020 को हुई एवं वह असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं था।

⁹⁶ रामहेत (समग्र आई.डी. 175263140)।

विभाग, मध्य प्रदेश शासन का परिपत्र (अप्रैल 2013) कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

लेखापरीक्षित जिलों में अनुग्रह सहायता के स्वीकृत प्रकरणों की जांच एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के डेटा के साथ प्रकरणों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि 2,132 व्यक्ति जन्मतिथि में हेरफेर करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे एवं संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के रूप में भी पंजीकृत थे। यह दर्शाता है कि पोर्टल में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को निकालने के लिए नियंत्रण नहीं है। हमने चयनित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में देखा कि पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से 10 व्यक्तियों को ₹20 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत एवं वितरित की जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी थे तथा अपने मृत्यु के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। विवरण **परिशिष्ट-2.3.7** में दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि 52 में से 27 जिलों में, पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से 41 व्यक्तियों को ₹84 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत एवं संवितरित की जो अपने मृत्यु के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। विवरण **परिशिष्ट-2.3.8** में है।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारियों ने संबल योजना के अंतर्गत 51 अपात्र व्यक्तियों जो अपने मृत्यु के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के थे, को ₹1.04 करोड़ की अनुग्रह सहायता संवितरित की।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र जारी (जून 2023) किया। इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि चार मामलों में, आधार/वोटर कार्ड के अनुसार, मृत श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से कम थी एवं शेष मामलों में संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिम प्रतिवेदनों में, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास जिलों ने पदाभिहित अधिकारियों को जारी पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की। कार्रवाई रिपोर्ट में सहायता के अनियमित भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं उसकी वसूली का कोई उल्लेख नहीं था। आगे, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के स्पष्टीकरण (दिसंबर 2018 एवं जून 2022) के अनुसार, पंजीकृत श्रमिक की जन्म तिथि समग्र आई.डी. में उल्लेखित जन्म तिथि होगी। अतः आधार/वोटर कार्ड के अनुसार जन्मतिथि स्वीकार्य नहीं है।

2.3.7.4 अनुग्रह सहायता का अधिक भुगतान, ₹1.72 करोड़

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) में प्रावधान है कि दुर्घटना मृत्यु के मामले में, अनुग्रह सहायता के दावे के लिए आवेदन के साथ पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संलग्न होनी चाहिए। आगे योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि दुर्घटना मृत्यु के मामले में, ₹4 लाख की दर से अनुग्रह सहायता एवं सामान्य मृत्यु के मामले में, ₹2 लाख की दर से अनुग्रह सहायता पंजीकृत असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जानी थी। मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल ने स्पष्ट किया (जनवरी 2020) कि यदि दावा आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं है, तो मामले को सामान्य मृत्यु के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

चयनित सात जिलों के 14 जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 86 प्रकरणों में, दावा आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं थी। पदाभिहित अधिकारी ने फिर भी प्रकरणों को दुर्घटना मृत्यु के रूप में दर्ज किया एवं प्रति प्रकरण ₹4 लाख की दर से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की तथा लाभार्थियों को ₹3.44 करोड़ संवितरित किए। यद्यपि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रकरणों को सामान्य मृत्यु मानते हुए अनुग्रह सहायता का लाभ ₹2 लाख प्रति प्रकरण की दर से देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.72 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.3.9** में वर्णित है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्द्ध-शासकीय पत्र जारी (जून 2023) किया था। इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिम प्रतिवेदनों में, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास जिलों ने पदाभिहित अधिकारियों को जारी पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की। कार्रवाई प्रतिवेदन में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं उसकी वसूली का कोई उल्लेख नहीं था।

2.3.7.5 अनुग्रह सहायता का कम भुगतान, ₹2 लाख

जनपद पंचायत, गोहद, भिंड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण में (श्रमिक आई.डी. 149360961) सचिव, ग्राम पंचायत, खनेटा (जनपद पंचायत, गोहद) ने गलती से प्रकरण को दुर्घटना मृत्यु के स्थान पर सामान्य मृत्यु के रूप में दर्ज कर दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद ने पोर्टल पर मृत्यु के प्रकार (सामान्य मृत्यु से आकस्मिक मृत्यु) में परिवर्तन करने के लिए सचिव, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार

कल्याण मंडल से अनुरोध (दिसंबर 2019) किया। मध्य प्रदेश असंगठित (शहरी/ग्रामीण) कर्मकार कल्याण मंडल ने न तो पोर्टल पर मृत्यु का प्रकार बदला एवं न ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद ने इस संबंध में आगे कोई पत्राचार किया। हमने देखा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गोहद ने मृत असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को

₹2 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत (जनवरी 2021) एवं संवितरित की जिसके परिणामस्वरूप अनुग्रह सहायता ₹2 लाख का कम भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि भिंड जिले से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

2.3.7.6 अनुग्रह सहायता का दोहरा भुगतान, ₹14 लाख

संबल योजना के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, अपंगता की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक एवं मृत्यु की स्थिति में मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य अनुग्रह सहायता के पात्र होंगे।

संवीक्षा में पता चला कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद (भिंड), राजपुर (बड़वानी) एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल ने पांच प्रकरणों में ₹14⁹⁷ लाख की अनुग्रह सहायता राशि का दोहरा भुगतान किया जैसा की **परिशिष्ट-2.3.10** में वर्णित है। यह भुगतान के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद (भिंड), राजपुर (बड़वानी) एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल की लापरवाही को दर्शाता है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित जिलों से प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे थे। आगे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्द्ध-शासकीय पत्र जारी (जून 2023) किया गया था। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

2.3.7.7 लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने 258 लाभार्थियों/पंजीकृत श्रमिकों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया। हमने देखा कि दो प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की, जैसा कि **तालिका-2.3.5** में वर्णित है:

⁹⁷ एक प्रकरण में श्रमिक आई.डी. 131016445, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर (बड़वानी) ने राशि ₹2.62 लाख वसूली की।

तालिका 2.3.5: लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण			
स. क्र.	लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया	पंजीकृत श्रमिक का विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	वार्ड 60, नगर निगम, ग्वालियर	मृत पंजीकृत श्रमिक (श्रमिक आई.डी. 137691317) के पति को राशि ₹2.00 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ मिला।	मृत असंगठित श्रमिक का पति मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग में उप-अभियंता है, इसलिए, वह सहायता का हकदार नहीं था।
2.	वार्ड 10, नगर पालिका, भिंड	मृत पंजीकृत श्रमिक (श्रमिक आई.डी. 185475687) के उत्तराधिकारी को ₹2.00 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई।	पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी एवं इसलिए, मृत श्रमिक का उत्तराधिकारी संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता का हकदार नहीं था।

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी)

इस प्रकार, आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, भिंड ने इन दो प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की जो स्वीकृति योग्य नहीं थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि सम्बंधित जिलों/शहरी स्थानीय निकायों से प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे थे।

2.3.7.8 योजनांतर्गत अपात्र व्यक्तियों को सहायता की अनियमित स्वीकृति, ₹60 लाख

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (जुलाई 2018) में प्रावधान है कि यदि पति अथवा पत्नी के पास 2.5 एकड़/एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो वे असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे। मध्य प्रदेश शासन के आदेश (जून 2019) प्रावधान है कि अपात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को हटाने के लिए पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आगे, श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों की 36 श्रेणियां निर्धारित (मार्च 2018) किया जिनका असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत किया जाना था।

चार जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि आठ⁹⁸ प्रकरणों में, संबंधित जनपद पंचायतों के पदाभिहित अधिकारियों ने पंजीकृत मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारी को ₹16 लाख की

⁹⁸ जनपद पंचायत, गोहद भिंड (श्रमिक आई.डी. 137921566), जनपद पंचायत, छतरपुर (श्रमिक आई.डी. 146458647), जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया (श्रमिक आई.डी. 127150006, 120007379, 135624266, 179553496 एवं 145117204) एवं जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर (श्रमिक आई.डी. 119015130)

अनुग्रह सहायता का लाभ स्वीकृत किया। हमने देखा कि इन सभी प्रकरणों में पंजीकृत मृत श्रमिकों के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी एवं वे संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं थे। आगे संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकृत तीन⁹⁹ व्यक्तियों को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा भौतिक सत्यापन (जुलाई एवं अक्टूबर 2019 के मध्य) के दौरान इस आधार पर अयोग्य पाया गया कि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पदाभिहित अधिकारियों ने इन तीन अपात्र व्यक्तियों को ₹8 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत (मार्च 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) की। हमने आगे पाया कि दो प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारी ने सचिव की टिप्पणी को नजरअंदाज किया एवं ₹4 लाख की सहायता स्वीकृत की तथा शेष एक प्रकरण मामले में सहायता की स्वीकृति (मार्च 2019) के बाद भौतिक सत्यापन किया (सितंबर 2019) गया।

आगे अभिलेखों की जांच से पता चला कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, भिंड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद (भिंड), सोहागपुर (होशंगाबाद) एवं छतरपुर ने 16¹⁰⁰ प्रकरणों में ₹32 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की। हमने देखा कि पंजीकृत मृत श्रमिक जिनके विरुद्ध ये दावे किए गए थे, वे गृहिणी (हाउस वाइफ) के रूप में पंजीकृत थी। गृहिणी असंगठित श्रमिकों की 36 रोजगार श्रेणियों में से किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती थी।

आगे, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान हमने देखा कि दो¹⁰¹ प्रकरणों में, मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारी जिन्होंने ₹4 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ प्राप्त किया था, ने कहा कि मृतक गृहिणियां थीं एवं कहीं भी नियोजित नहीं थीं।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारी असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण से पूर्व एवं यहां तक कि लाभ स्वीकृत करते समय भी आवेदकों की पात्रता की पुष्टि करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹60 लाख का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि संबंधित जिलों/नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं से जानकारी/प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे थे।

⁹⁹ जनपद पंचायत, लांझी, बालाघाट (श्रमिक आई.डी. 182752269, ₹2 लाख), जनपद पंचायत, बैतूल (श्रमिक आई.डी. 118078568, ₹2 लाख) एवं जनपद पंचायत, सोंडवा, अलीराजपुर (137377708, ₹4 लाख)।

¹⁰⁰ नगर पालिका, भिंड (श्रमिक आई.डी. 300830824), जनपद पंचायत, गोहद, भिंड (श्रमिक आई.डी. 189843613 एवं 150363524), जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद (श्रमिक आई.डी. 139345795, 111752542, 102753733, 187723820, 110361299 एवं 141084069) एवं जनपद पंचायत, छतरपुर (श्रमिक आई.डी. 125979023, 128283828, 118211246, 121922709, 155853376, 117788424 एवं 117575410)।

¹⁰¹ श्रमिक आई.डी. 304285368 एवं 169556831

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

अनुशंसा 6: विभाग को अनियमित रूप से संवितरित राशि की वसूली के अलावा दावा आवेदन के सत्यापन के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

2.3.7.9 मृत्यु के बाद पंजीकृत व्यक्तियों को भुगतान की गई सहायता की वसूली न होना, ₹54 लाख

संबल योजना के दिशानिर्देश एवं विभागीय निर्देश (मार्च 2018 एवं मई 2018) प्रावधानित करते हैं कि केवल पंजीकृत असंगठित श्रमिक ही योजना का लाभार्थी होगा। विभागीय निर्देश आगे प्रावधानित करते हैं कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति सत्यापन के दौरान अपात्र पाया जाता है अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। आगे, यदि ऐसे अपात्र व्यक्ति को लाभ मिला है, तो उससे प्राप्त लाभ की वसूली की जाएगी। पदाभिहित अधिकारी वसूली योग्य राशि की जानकारी संबंधित तहसीलदार को देंगे जो राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) जारी करके राशि की वसूली करेगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा श्रमिक भविष्य में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होगा।

संवीक्षा से पता चला कि 10 जिलों के पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से 37 व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के बाद पंजीकृत (अप्रैल-जून 2018) किया एवं इन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को ₹90 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत (जून-जुलाई 2018) की जैसा कि **परिशिष्ट-2.3.11** में वर्णित है। 37 व्यक्तियों को स्वीकृत ₹90 लाख में से, पदाभिहित अधिकारियों ने 28 प्रकरणों में ₹66 लाख का संवितरण किया एवं शेष नौ प्रकरणों में, भुगतान संवितरित नहीं किया गया था। हमने देखा कि मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल ने इन प्रकरणों में दिए गए लाभ की वसूली एवं इतनी गंभीर अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ पत्राचार (अक्टूबर 2018 एवं नवंबर 2018) किया था। दिसंबर 2022 तक, पदाभिहित अधिकारियों ने पांच प्रकरणों में ₹12 लाख की वसूली की एवं शेष 23 प्रकरणों में, जनवरी 2023 तक ₹54 लाख की वसूली लंबित थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि देवास जिले में, दोनों प्रकरणों में राशि की वसूली कर ली गयी थी। आगे, संबंधित जिला कलेक्टरों को जांच कराने एवं दोषी पाए जाने पर वसूली करने के लिए पत्र लिखा गया है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग ने समय पर एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

अनुशंसा-7: विभाग को मृत व्यक्तियों के अनियमित पंजीकरण के लिए जिम्मेदारी तय करना चाहिए एवं राशि की तुरंत वसूली करना चाहिए।

2.3.7.10 गलत उत्तराधिकारियों को अनुग्रह सहायता का भुगतान, ₹40 लाख

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) कहता है कि मृत असंगठित श्रमिकों के पुत्र एवं पुत्री (यदि पति/पत्नी उपलब्ध नहीं है) को अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। सहायता माता-पिता (यदि पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री उपलब्ध नहीं है) तथा भाइयों एवं बहनों (यदि पति/पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं) को देय है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि 18¹⁰² प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को 40 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जो असंगठित श्रमिक के पात्र उत्तराधिकारी नहीं थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 14 प्रकरणों में, पुत्र/पुत्री को लाभ प्रदान किया गया जबकि पति/पत्नी लाभ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध थे।
- चार प्रकरणों में, माता/पिता को लाभ प्रदान किया गया जबकि मृत कर्मचारी की पत्नी/पुत्र/पुत्री लाभ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध थे। विवरण **परिशिष्ट-2.3.12** में दिया गया है।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारियों ने दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपात्र उत्तराधिकारियों को ₹40 लाख की अनुग्रह सहायता संवितरित की।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2.3.7.11 अनियमित रूप से आवेदन स्वीकार किया जाना

श्रम विभाग ने उन प्रकरणों में जहां श्रमिक की मृत्यु सात दिवस के भीतर पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई थी अनुग्रह सहायता के लिए दावा आवेदन जमा किये जाने के 90 दिनों की मौजूदा समय सीमा को बढ़ाकर (जून 2021) 180 दिन कर दिया। 180 दिनों के बाद आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर जांच के बाद लिखित

¹⁰² नगर पालिका, भिंड के दो प्रकरण, जनपद पंचायत, गोहद के तीन प्रकरण, नगर निगम, ग्वालियर के दो प्रकरण, जनपद पंचायत, छतरपुर के पांच प्रकरण, नगर निगम, जबलपुर का एक प्रकरण, जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया के चार प्रकरण एवं नगर पालिका, उमरिया का एक प्रकरण।

आदेश द्वारा समय सीमा में छूट देंगे एवं पदाभिहित अधिकारी को ई-भुगतान आदेश निकालने के पूर्व पोर्टल पर ऐसा आदेश अपलोड करना होगा।

नगर निगम, ग्वालियर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि चार¹⁰³ प्रकरणों में आवेदन निर्धारित समय-सीमा 180 दिन के बाद प्राप्त हुए थे। आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर ने समय सीमा में छूट के लिए जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर का आदेश प्राप्त किए बिना चारों प्रकरणों में ₹8.00 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की।

हमने आगे देखा कि एक प्रकरण (श्रमिक आई.डी. 193063155) में, पदाभिहित अधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर (नोडल अधिकारी) के माध्यम से समय सीमा में छूट के लिए प्रकरण को जिला कलेक्टर अथवा जिला कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर को अग्रेषित किया, परन्तु नोडल अधिकारी ने प्रकरण को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि यदि पोर्टल पहले ही प्रकरण को स्वीकार कर रहा है, तो अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है एवं इसलिए, पदाभिहित अधिकारी ने ₹2 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारी/नोडल अधिकारी ने श्रम विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया एवं पांच प्रकरणों में अनियमित रूप से ₹10 लाख की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि नगर निगम, ग्वालियर से जानकारी एकत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जानकारी प्रतीक्षित है।

2.3.7.12 अंत्येष्टि सहायता का भुगतान न होना

(अ) संबल योजना के दिशानिर्देशों (मई 2018) प्रावधानित करते हैं कि पंजीकृत श्रमिक या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु के प्रकरण में, नगर निगम/पालिका के अधिकृत अधिकारी अथवा सचिव, ग्राम पंचायत तुरंत पंजीकृत श्रमिक (पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में) को अथवा पंजीकृत श्रमिक के उत्तराधिकारी (पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु के मामले में) को ₹5,000 की नकद अंत्येष्टि सहायता का भुगतान करेंगे। इसके बाद, नगर निगम/पालिका का अधिकृत अधिकारी अथवा सचिव संबल पोर्टल पर पंचनामा अपलोड करेगा एवं श्रम विभाग पदाभिहित अधिकारी के बैंक खाते में राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। अंत्येष्टि सहायता का लाभ देने हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं थी। आगे, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने संभाग/जिला श्रम कार्यालयों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त

¹⁰³ श्रमिक आई.डी. 116948025, 122629352, 187520489 एवं 192979692।

(मई 2021) किया एवं निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को एक दिन के भीतर अंत्येष्टि सहायता का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

चयनित 10 जिलों के 20 जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका के संबल पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच से पता चला कि 12,141 प्रकरणों में से 4,398 (36 प्रतिशत) प्रकरणों में, नगर निगम/पालिका के अधिकृत अधिकारी अथवा सचिव, ग्राम पंचायत ने 2018-22 के दौरान पंजीकृत असंगठित श्रमिक/मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारी को ₹2.20 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट-2.3.13** में है।

आगे, हमने नगर पालिका, भिंड एवं होशंगाबाद में देखा कि 151 प्रकरणों में, अधिकृत अधिकारियों ने अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया बल्कि उन्होंने यह मानते हुए कि राशि लाभार्थी को प्राप्त हो जाएगी लाभार्थी के नाम पर संबल पोर्टल पर स्वीकृति आदेश तैयार किया। यद्यपि, जैसा की दिशानिर्देशों में प्रावधानित था राशियाँ पदाभिहित अधिकारियों अर्थात् मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, भिंड एवं होशंगाबाद के बैंक खातों में जमा हुईं। इस प्रकार, अधिकृत अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाभार्थी तत्काल सहायता से वंचित रह गये।

(ब) आगे, हमने जनपद पंचायत, घाटीगांव की जांच प्रतिवेदनों से देखा कि सचिव, ग्राम पंचायत, रायपुर कलां, रेहट एवं सिरसा (जनपद पंचायत, घाटीगांव) ने तीन मृत असंगठित श्रमिकों¹⁰⁴ के उत्तराधिकारियों को ₹15,000/- (प्रत्येक प्रकरण में ₹5,000/-) की अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया तथापि उन्होंने प्रतिपूर्ति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घाटीगांव को पंचनामा कपटपूर्वक प्रस्तुत किया।

इस प्रकार, इन प्रकरणों में पंजीकृत श्रमिक के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया था। आगे कोई उत्तर नहीं दिया गया।

¹⁰⁴ मृत श्रमिकों के श्रमिक आई.डी. 191366354, 166447129 एवं 116602188 थे।

2.3.7.13 अनियमित भौतिक सत्यापन के कारण सहायता स्वीकृत न होना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सभी पदाभिहित अधिकारियों को अपात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को हटाने के लिए पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश (जून 2019) दिए।

संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि भौतिक सत्यापन के दौरान राज्य में 3.46 लाख पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 'मूल आवेदन उपलब्ध नहीं होने' के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया था।

हमने देखा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घाटीगांव ने तीन¹⁰⁵ प्रकरणों में ₹5 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत नहीं की क्योंकि पंजीकृत असंगठित श्रमिक को 'मूल आवेदन उपलब्ध नहीं है' के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हमने आगे देखा कि सचिव, ग्राम पंचायत ने दावा आवेदन के साथ मूल आवेदन भी संलग्न किया था। इस प्रकार, असंगठित श्रमिकों के भौतिक सत्यापन में पदाभिहित अधिकारी की लापरवाही के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा। आगे, मूल आवेदन दावा आवेदनों के साथ संलग्न थे, इसलिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को आवेदकों की वास्तविकता को सत्यापित करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी एवं सहायता जारी करनी चाहिए थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। आगे की जानकारी प्रतीक्षित है।

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2.3.7.14 अनुग्रह सहायता अनियमित रूप से अस्वीकृत किया जाना

अभिलेखों की जांच से पता चला कि सात¹⁰⁶ प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹14 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ इस आधार पर देने से मना कर दिया कि परिवार के सदस्य शासकीय सेवाओं में थे, परिवार के संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी, पंजीकरण प्रमाण पत्र, राशन कार्ड प्रदान नहीं किया गया था,

¹⁰⁵ श्रमिक आई.डी. 303307908 (एक प्रकरण अपंगता का एवं एक प्रकरण सामान्य मृत्यु का) तथा 126938156 (मृत्यु का एक प्रकरण)।

¹⁰⁶ जनपद पंचायत, गोहद, भिंड (श्रमिक आई.डी. 152086025), जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद (श्रमिक आई.डी. 119339930, 300792867 एवं 149784262), नगर पालिका, होशंगाबाद (श्रमिक आई.डी. 144697785), तथा जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर (श्रमिक आई.डी. 150730111 एवं 194319095)।

उत्तराधिकारी (पत्नी) का नाम मतदाता सूची में नहीं था एवं विवाह का अभिलेख नहीं थे। लेखापरीक्षा में यद्यपि पाया गया कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दिए गए कारण लाभ से मना करने के लिए वैध कारण नहीं थे एवं संलग्न दस्तावेज लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जानकारी प्रतीक्षित है।

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2.3.7.15 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाभ अस्वीकृत किया जाना

संबल योजना के योजना दिशानिर्देश प्रावधानित (मई 2018) करते हैं कि पदाभिहित अधिकारी दावा आवेदन की जांच करने के उपरांत लाभ को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा एवं स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाएंगे तथा इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत, शोभापुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक¹⁰⁷ प्रकरण में, सचिव, ग्राम पंचायत शोभापुर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद (पदाभिहित अधिकारी) को दावा आवेदन इस आधार पर अग्रेषित नहीं किया कि मृतक के पिता के पास 2.54 एकड़ जमीन थी। सचिव द्वारा की गई कार्रवाई उचित नहीं थी क्योंकि दावा आवेदन की जांच पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी। इसी प्रकार, हमने नगर पालिका, होशंगाबाद में पाया कि पांच¹⁰⁸ प्रकरणों में, उत्तरदायी कर्मचारी ने पदाभिहित अधिकारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, होशंगाबाद) को प्रकरण इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किए कि भौतिक सत्यापन के दौरान मृत असंगठित श्रमिक को पोर्टल पर अपात्र घोषित किया गया था। लाभ अस्वीकृत होने की सूचना भी आवेदकों को नहीं दी गई थी। हमने देखा कि पदाभिहित अधिकारी ने इसी तरह के प्रकरणों को समाधान के लिए अपीलिय प्राधिकारी को अग्रेषित किया था। पदाभिहित अधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत न किया जाना, आवेदक को सूचित न किया जाना एवं यहां तक कि प्रकरण अपीलिय प्राधिकारी को प्रकरण अग्रेषित न किये जाने से लाभार्थी सुनवाई से वंचित रहे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

¹⁰⁷ श्रमिक आई.डी. 114365498

¹⁰⁸ श्रमिक आई.डी. 168983635, 125093404, 192138614, 300258673 एवं 130796855

अनुशंसा-8: विभाग को अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए। आगे, विभाग को पात्र लाभार्थियों को सहायता का वितरण न करने के प्रकरणों की समीक्षा करना चाहिए।

2.3.7.16 स्वीकृति के बावजूद सहायता का भुगतान न होना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (अगस्त 2020) किया कि यदि लाभ की स्वीकृति के दौरान अथवा लाभ की स्वीकृति के बाद पोर्टल पर लाभार्थी के बारे में कोई विसंगति दिखता है, जो लाभार्थी को लाभ देने से रोकती है, तो पदाभिहित अधिकारी, तथ्यों की जांच एवं आवश्यक निरीक्षण के बाद, प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी को विसंगतियों के सुधार के लिए अग्रेषित करेगा।

नगर पालिका, होशंगाबाद के अभिलेखों की जांच से पता चला कि सात¹⁰⁹ प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारी ने ₹14.00 लाख की अनुग्रह सहायता राशि का लाभ स्वीकृत किया था। यद्यपि, बाद में प्रकरणों को इस आधार पर लंबित रखा गया कि इन मृत असंगठित श्रमिकों को भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किया गया था। पदाभिहित अधिकारी ने न तो प्रकरणों को अपीलीय प्राधिकारी को भेजा न ही आवेदकों को विसंगतियों के सुधार के लिए सूचित किया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जानकारी प्रतीक्षित है।

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2.3.8 वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने संबल योजना 1 अप्रैल 2018 से लागू की। 1 अप्रैल 2018 से 5 दिसंबर 2019 के दौरान, श्रम विभाग ने कोषालय से सीधे पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में राशि प्रदान की। इसके पश्चात, पदाभिहित अधिकारी संबल पोर्टल पर प्रकरण स्वीकृत करते हैं एवं श्रम विभाग स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से करता है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान संबल योजना (योजना कोड-2365) के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय तालिका-2.3.6 में दिया गया है:

¹⁰⁹ श्रमिक आई.डी. 111302548, 191130589, 167983693, 148614800, 106623609, 173050372 एवं 113892439

तालिका 2.3.6: बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण		
(₹ करोड़ में)		
अवधि	आवंटन	व्यय (प्रतिशत में)
2018-19	799.99	774.95 (96.87)
2019-20	641.61	551.59 (85.97)
2020-21	736.00	736.00 (100)
2021-22	1325.00	1325.00 (100)
कुल	3502.60	3387.54 (96.71)

(स्रोत: श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखों से एकत्रित आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 को छोड़कर आवंटित राशि का 100 प्रतिशत उपयोग किया जाना प्रतिवेदित किया। श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश की कैश बुक एवं वाउचरों की जांच से पता चला कि श्रम आयुक्त ने कोषालय से राशि निकाली एवं श्रम आयुक्त के एक बैंक खाते में जमा की। हमने देखा कि मार्च 2019, 2020, 2021 एवं 2022 के अंत में श्रम आयुक्त (संबल योजना) के बैंक खाते में क्रमशः ₹9.82 करोड़, ₹40.55 करोड़, ₹0.52 करोड़ एवं ₹372.73 करोड़ की बड़ी धनराशि रखी थी। आगे, हमने देखा कि लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के पास ₹6.26 करोड़ अनुपयोगी पड़े थे जैसा कि अनुवर्ती कंडिका 2.3.8.3 में चर्चा की गई है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि संबल योजना के तहत भुगतान एक सतत प्रक्रिया थी एवं बजट राशि का पूर्ण उपयोग किया गया था।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि वर्ष 2019-22 के दौरान मार्च माह के अंत में श्रम आयुक्त के बैंक खाते में अनुपयुक्त पड़ी बड़ी धनराशि पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

अनुशंसा-9: मध्य प्रदेश शासन को फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

2.3.8.1 बैंक खाते में अनियमित जमा

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (खंड-1) के नियम 6 में उल्लिखित है कि जब तक अन्यथा किसी कानून अथवा नियम अथवा कानून की शक्ति निहित आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया जाता, तब तक वित्त विभाग की सहमति के बिना निवेश अथवा अन्यत्र जमा करने के लिए समेकित निधि एवं लोक लेखा से राशि नहीं निकाला जा सकता है।

प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्त विभाग ने अंत्येष्टि सहायता की धनराशि रखने के लिए एक बैंक खाता खोलने की सहमति प्रदान (जुलाई 2018) की। तदनुसार, श्रम विभाग ने अगस्त 2018 में पंजाब नेशनल बैंक, इंदौर में एक बैंक खाता खोला। हमने देखा कि आयुक्त, श्रम विभाग ने वर्ष 2018-22 के दौरान राशि ₹2,077 करोड़ की अनुग्रह सहायता निधि आहरित की एवं इस बैंक खाते में जमा की। 31 मार्च 2022 को इस बैंक खाते में शेष राशि ₹372.73 करोड़ थी। इस बैंक खाते में अनुग्रह सहायता राशि जमा करना अनियमित था क्योंकि वित्त विभाग ने बैंक खाते में केवल अंत्येष्टि सहायता की राशि रखने की अनुमति दी थी।

इस प्रकार, विभाग ने ₹2,077 करोड़ की बड़ी धनराशि अनियमित रूप से बैंक खाते में जमा करके लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन किया। शासकीय निधि को अनियमित रूप से बैंक खाते में जमा करना शासकीय निधि के अस्थायी दुर्विनियोजन का कारण बना।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि विभाग ने संभावित सिंगल क्लिक के लिए ₹375 करोड़ की मांग की (मार्च 2022)। 16 मई 2022 को, 25,982 लाभार्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया। सिंगल क्लिक नहीं होने के कारण, राशि नोडल बैंक खाते में ही रह गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नोडल बैंक खाते में अनुग्रह सहायता निधि के अनियमित जमा पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है जबकि वित्त विभाग ने केवल अंत्येष्टि सहायता राशि को नोडल बैंक खाते में जमा करने की सहमति दी थी। आगे, यदि धनराशि नियत समय में लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, तो इसे शासकीय खाते में वापस कर दिया जाना चाहिए था।

अनुशंसा-10: मध्य प्रदेश शासन को शीघ्र विभाग को अनुग्रह राशि शासकीय खाते में वापस करने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

2.3.8.2 शासकीय खाते में ब्याज जमा न होना

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (मई 2011) किया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी उन प्रकरणों में जहां अर्जित ब्याज राशि को योजना में उपयोग करने की अनुमति नहीं थी बैंक खातों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को शासकीय खाता शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्ति" में जमा करेगा।

श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश के कार्यालय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि श्रम आयुक्त ने बैंक खाता संचालित किया तथा उसमें अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता की धनराशि रखी। हमने देखा कि वर्ष 2018-22 के दौरान, बैंक खाते में जमा राशि पर ₹3.86 करोड़ का ब्याज

अर्जित हुआ था जिसे शासकीय खातों में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, श्रम आयुक्त ने वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि बचत बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग योजना के अंतर्गत सहायता के भुगतान के लिए किया गया। शासन ने आगे उत्तर दिया (मार्च 2024) कि ब्याज राशि को शासकीय प्राप्ति मद में जमा करने की प्रक्रिया जारी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार (मई 2011) अर्जित ब्याज शासकीय खाते में जमा किया जाना था। आगे, विभाग ने सहायता के भुगतान के लिए ब्याज राशि के उपयोग हेतु आदेश की प्रति प्रेषित नहीं की।

2.3.8.3 स्थानीय निकायों के पास निधि का अवरुद्ध रहना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा लाभ प्रदान करने के प्रारंभ¹¹⁰ से पूर्व अनुग्रह सहायता के लाभ के वितरण तथा कंप्यूटर की खरीद तथा स्मार्ट कार्ड एवं ब्रोशर की छपाई के लिए पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत) के एकल बैंक खाते में धनराशि प्रदान की थी।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका ने संबल योजना की अनुपयोगी राशि ₹6.26 करोड़ श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश को वापस नहीं की जैसा कि **परिशिष्ट-2.3.14** में वर्णित है। हमने देखा कि श्रम विभाग ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को उनके पास पड़ी निधि वापस करने के लिए परिपत्र जारी (सितंबर 2018) किया था। यद्यपि, लेखापरीक्षित नौ जिला पंचायतों (जिला पंचायत, सतना को छोड़कर) में से किसी ने भी अनुपयोगी धनराशि वापस नहीं की। हमने यह भी देखा कि श्रम विभाग ने अनुपयोगी धनराशि की वापसी के लिए शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं से आगामी कोई पत्राचार नहीं किया था।

आगे, हमने देखा कि श्रम विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कितनी निधि का उपयोग किया गया एवं कितनी निधि उनके पास अनुपयोगी थी अभिलेख संधारित नहीं किये थे जो यह दर्शाता है कि विभाग का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था।

¹¹⁰ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) की शुरुआत 6 दिसंबर 2019 से हुई थी

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि विभाग ने सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश (अक्टूबर 2019) दिया था।

उत्तर सामान्य है तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद भी शासकीय शीर्ष में राशि जमा कराना सुनिश्चित नहीं कर सका।

अनुशंसा-11: विभाग को शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के पास अनुपयोगी पड़ी निधि की वसूली की कार्रवाई में तेजी लाने एवं ब्याज राशि को शीघ्र शासकीय खाते में जमा करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

2.3.9 निगरानी

2.3.9.1 सहायता राशि की स्वीकृति एवं संवितरण में विलंब

संबल योजना (मई 2018) के योजना दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि अनुग्रह सहायता के लिए प्राप्त आवेदन, इसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाया जाएगा।

एन.आई.सी. डेटा एवं संबल योजना के संयुक्त बैंक खाता के डेटा की जांच से पता चला कि अनुग्रह सहायता के 1,68,342 में से 1,07,076 (64 प्रतिशत) प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने एक से 1,272 दिनों के विलंब से लाभ स्वीकृत किया जैसा कि **तालिका-2.3.7** में वर्णित है।

तालिका-2.3.7: लाभ की स्वीकृति में विलंब		
स. क्र.	दावे की स्वीकृति में पदाभिहित कार्यालय स्तर पर विलंब	
	प्रकरणों की संख्या	विलंब (दिनों में)
1.	93,602	1 से 180
2.	9,669	181 से 365
3.	3,805	366 से 1272

(स्रोत: श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एन.आई.सी. डेटा एवं बैंक डेटा)

अनुग्रह सहायता की स्वीकृति एवं भुगतान डेटा के आगे के विश्लेषण से पता चला कि राशि ₹1,349.92 करोड़ के 60,674 प्रकरणों में, श्रम विभाग ने दो से 1,013 दिनों के विलंब से भुगतान संवितरित किया जैसा कि **तालिका-2.3.8** में वर्णित है।

तालिका-2.3.8: लाभ की स्वीकृति के बाद भुगतान में विलंब			
स. क्र.	अंतिम भुगतान में विभाग स्तर पर विलंब		
	प्रकरणों की संख्या	विलंब (दिनों में)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	31,512	2 से 180	699.08
2.	19,495	181 से 365	431.72
3.	9,667	366 से 1013	219.12

(स्रोत: श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एन.आई.सी. डेटा एवं बैंक डेटा)

आगे चयनित जनपद पंचायतों एवं नगर निगम/पालिका के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 12,141 में से 7,417 प्रकरणों (61 प्रतिशत) में, पदाभिहित अधिकारियों ने एक से 1,130 दिनों के विलंब से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की। इसके अलावा, 4,101 प्रकरणों (34 प्रतिशत) में, श्रम विभाग ने आठ से 996 दिनों के विलंब से अनुग्रह सहायता संवितरित की।

हमने आगे देखा कि तीन कार्यालयों में, मार्च 2022 में अथवा उससे पहले प्राप्त 31¹¹¹ प्रकरण अभी भी बिना किसी कारण के (24 प्रकरणों में) अथवा भौतिक सत्यापन में विलंब के कारण स्वीकृति के लिए लंबित थे। यह भी देखा गया कि 512 प्रकरणों में जहां पदाभिहित अधिकारियों ने मार्च 2022 में अथवा उससे पहले स्वीकृति दे दी थी, भुगतान अभी भी लंबित थे क्योंकि भुगतान श्रम विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाना था।

विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने प्रत्येक चयनित पदाभिहित कार्यालय में 10 प्रकरणों की विस्तृत जांच भी की। इन चयनित प्रकरणों की जांच से पता चला कि पदाभिहित अधिकारियों ने बिना किसी कारण के विलंब किया अथवा असंगठित श्रमिकों को अनियमित रूप से अपात्र घोषित करने के कारण विलंब हुआ एवं अपील के बाद इन श्रमिकों को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया अथवा भौतिक सत्यापन में विलंब हुआ।

मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच से यह भी पता चला कि 2,993 प्रकरणों में, सचिव, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड ने प्राथमिकता क्रम तोड़ते हुए अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया क्योंकि इन मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारियों ने मुख्य मंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। इस प्रकार, मुख्य मंत्री हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण के लिए, भुगतान के प्राथमिकता¹¹²

¹¹¹ नगर पालिका, भिंड (6), जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास (1) एवं नगर निगम, जबलपुर (24)।

¹¹² श्रम विभाग के आदेश (मई 2021) में उल्लेखित है कि अनुग्रह सहायता का भुगतान असंगठित श्रमिक की मृत्यु के दिनांक के प्राथमिकता क्रम में होगा।

क्रम का उल्लंघन करते हुए भुगतान किया गया एवं जिन लाभार्थियों ने शिकायत नहीं की उन्हें अनुग्रह सहायता का लाभ विलंब से प्राप्त हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि सहायता स्वीकृत करने से पहले, लाभार्थी एवं उत्तराधिकारी का भौतिक सत्यापन किया जाना था। कई मामलों में, संबंधित व्यक्ति के उपलब्ध न होने एवं प्रासंगिक अभिलेख जमा न करने के कारण सहायता की स्वीकृति एवं भुगतान में विलंब हुआ। संबल 2.0 योजना में, सत्यापन सहित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। आगे, लाभार्थियों की समस्याओं एवं समयसीमा के सत्यापन के बाद मुख्य मंत्री हेल्पलाइन के मामलों में प्राथमिकता क्रम तोड़ा गया। इसके अलावा, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए एम.आई.एस. के माध्यम से राज्य स्तरीय निगरानी भी की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उन प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जो संबंधित व्यक्ति की गैर-मौजूदगी एवं प्रासंगिक अभिलेख जमा न करने के कारण विलंबित हुए थे।

अनुशंसा-12: विभाग को सहायता की स्वीकृति एवं संवितरण में विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करनी चाहिए।

2.3.9.2 नोडल अधिकारियों द्वारा निगरानी न करना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाने एवं श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संभाग/जिला श्रम कार्यालयों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त (मई 2021) किया। नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि पदाभिहित अधिकारियों ने दावा आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया था एवं अंत्येष्टि सहायता का भुगतान एक दिवस के भीतर किया जा रहा था।

चयनित 10 जिलों के नोडल कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 10 में से नौ (भिंड को छोड़कर) नोडल कार्यालयों ने प्रकरणों के समय पर निपटान की निगरानी के लिए पदाभिहित कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। भिंड जिले में, नोडल अधिकारी ने एक मासिक पत्रक निर्धारित किया था, हालांकि, हमें जिला श्रम अधिकारी, भिंड के अभिलेख में ऐसी मासिक पत्रकों की प्रतियां नहीं मिलीं जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षित जिलों में सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारियों ने कोई निगरानी नहीं की थी।

यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाग ने योजना के प्रारंभ (मार्च 2018) से तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जिला स्तरीय निगरानी एवं समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

(मई 2021) की। नोडल अधिकारियों (सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी) को लाभार्थियों को सहायता की प्रगति एवं समय पर स्वीकृति की समीक्षा करने के लिए, तथापि, संबल पोर्टल पर कोई लॉगिन एक्सेस प्रदान नहीं किया गया था। निगरानी नहीं होने के कारण, लाभार्थियों को अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का लाभ समय पर नहीं मिल सका।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि योजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए, श्रम अधिकारियों जिन्हें नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के साथ बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यद्यपि, पदाभिहित अधिकारी श्रम विभाग के अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए, वे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस संबंध में, कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। जैसे की, पदाभिहित अधिकारियों ने इन निर्देशों के अनुपालन में रुचि नहीं दिखाई, ऐसे उदाहरण सामने आए। नोडल अधिकारी पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। आगे, जिला कलेक्टरों को योजना की समीक्षा एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग केवल यह कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि पदाभिहित अधिकारी विभागीय अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं। विभाग को पदाभिहित अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से समन्वय करना चाहिए।

अनुशंसा-13: विभाग को योजना की प्रभावी निगरानी में कमी के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

2.3.9.3 नोडल अधिकारी का स्पष्टीकरण/अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय त्रुटिपूर्ण होना

श्रम विभाग ने अपने परिपत्र (जुलाई 2018) में असंगठित श्रमिक की पात्रता परिभाषित करते हुए कहा कि यदि असंगठित श्रमिक अथवा उसके पति/पत्नी के पास 2.5 एकड़ (एक हेक्टेयर) से अधिक भूमि है, तो दोनों को असंगठित श्रमिक नहीं माना जाएगा।

- जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 20 प्रकरणों में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹44 लाख की अनुग्रह सहायता राशि इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्य के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि था अथवा मृत असंगठित श्रमिक के संयुक्त नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। हमने देखा कि सहायक श्रम आयुक्त, होशंगाबाद ने स्पष्टीकरण (सितंबर 2020) दिया कि यदि मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि था, तो श्रमिक सहायता

के लिए पात्र नहीं होगा। यद्यपि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, असंगठित श्रमिक अथवा उसके पति/पत्नी के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच से पता चला कि सभी 20 प्रकरणों में मृत असंगठित श्रमिक के नाम पर भूमि या तो शून्य थी या भूमि का हिस्सा एक हेक्टेयर से कम था। इस प्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोहागपुर ने अनियमित रूप से सहायता अस्वीकृत किया।

- अपीलीय प्राधिकारी, होशंगाबाद में अपील प्रकरणों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 10 प्रकरणों में, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील निरस्त कर दिया एवं इस आधार पर लाभ से इंकार किया कि मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्य के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी अथवा मृत असंगठित श्रमिक के संयुक्त नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि सभी 10 प्रकरणों में मृत असंगठित श्रमिक के नाम पर भूमि या तो शून्य थी या भूमि का हिस्सा एक हेक्टेयर से कम था। हमने आगे पाया कि एक मामले में अपीलीय प्राधिकारी ने अपील निरस्त किया एवं इस आधार पर लाभ से इंकार किया कि मृत असंगठित श्रमिक के पिता शासकीय कर्मचारी थे एवं अब वह पेंशनभोगी हैं। इस प्रकार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्रता मानदंड की गलत व्याख्या के कारण, 11 लाभार्थी योजनांतर्गत ₹22 लाख की अनुग्रह सहायता के लाभ से वंचित रह गए।

विवरण **परिशिष्ट-2.3.15 (क) एवं 2.3.15 (ख)** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये प्रकरणों में की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

2.3.9.4 संबल पोर्टल पर जांच एवं सत्यापन का अभाव

संबल पोर्टल पर जांच सत्यापन का अभाव था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- संबल पोर्टल पर 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के आवेदकों का पंजीकरण स्वीकार करने के लिए जांच एवं सत्यापन होना चाहिए था। हमने देखा कि पोर्टल ने पंजीकरण के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के एक आवेदक का पंजीकरण स्वीकार कर लिया।
- इसी तरह, संबल पोर्टल में मृत पंजीकृत श्रमिक के 60 वर्ष से अधिक आयु के होने पर, चेतावनी जारी करने के लिए जांच एवं सत्यापन होना चाहिए था।

- अनियमित भुगतान को रोकने के लिए संबल पोर्टल को ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं करने चाहिए थे जिनमें मृत्यु का दिनांक असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के दिनांक से पहले का हो।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि संबल 2.0 पोर्टल मई 2022 से शुरू किया गया था एवं संबल 2.0 में सभी विसंगतियों को सुधार लिया गया था।

अनुशंसा-14: विभाग को 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता के अनियमित भुगतान को रोकने के लिए पोर्टल में जांच एवं सत्यापन शामिल करना चाहिए।

2.3.10 निष्कर्ष

श्रम विभाग ने राज्य के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना लागू की। विभाग ने श्रमिकों के पंजीकरण के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान 67.48 लाख (31 प्रतिशत) पंजीकृत श्रमिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। आगे, भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण थी क्योंकि 14.34 लाख श्रमिकों को उनकी अपात्रता हेतु विशिष्ट कारण बताए बिना भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित कर दिया गया था। हमने देखा कि अपात्र श्रमिकों को पुनः सत्यापन के दौरान एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्र पाया गया।

आगे, हमने योजना निधि से राशि ₹2.47 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्वक आहरण तथा एक कर्मचारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदारों के बैंक खाते में जमा किया जाना, योजना के अंतर्गत ₹1.57 करोड़ के अस्वीकार्य अनुग्रह सहायता का अनियमित भुगतान एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के अपात्र व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता की राशि ₹1.04 करोड़ का अनियमित भुगतान देखा। हमने सहायता ₹1.72 करोड़ का अधिक भुगतान, ₹14 लाख दोहरा भुगतान एवं अपात्र व्यक्तियों को ₹60 लाख की सहायता की अनियमित स्वीकृति के मामले भी देखे। हमने आगे देखा कि व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया एवं ₹66 लाख की अनुग्रह सहायता राशि संवितरित की गई। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत कार्यालयों ने 4,398 प्रकरणों में अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया।

वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था क्योंकि विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित ₹6.26 करोड़ की निष्क्रिय निधि के उपयोग की निगरानी नहीं की एवं ब्याज की राशि ₹3.86 करोड़ भी शासकीय खाते में जमा नहीं की।

हमने 1,07,076 प्रकरणों (64 प्रतिशत) में सहायता राशि की स्वीकृति में तीन वर्ष एवं छः माह तक का विलंब देखा। विभाग ने जिला स्तर पर योजना की निगरानी के लिए जिला श्रम अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था, हालांकि, हमने देखा कि लेखापरीक्षित जिलों के जिला श्रम अधिकारियों द्वारा योजना की कोई निगरानी नहीं की गई थी। संबल पोर्टल में जांच एवं सत्यापन का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता की अनियमित स्वीकृति एवं संवितरण हुआ।



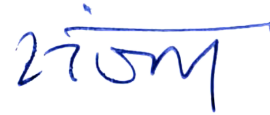
(प्रिया पारिख)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
मध्य प्रदेश

ग्वालियर

दिनांक : 12 दिसम्बर 2024

प्रतिहस्ताक्षरित



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 24 दिसम्बर 2024

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका सं. 1.6.1, पृष्ठ सं. 6)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	31 मार्च 2023 तक की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1,620	6,489
2.	जेल विभाग	98	199
3.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	266	531
4.	गृह विभाग	337	909
5.	महिला एवं बाल विकास विभाग	998	2,998
6.	जनजातीय कार्य विभाग	721	2,143
7.	विमुक्त घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु कल्याण विभाग	6	18
8.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	123	492
9.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	207	897
10.	आयुष विभाग	228	695
11.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	331	1,084
12.	भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग	21	66
13.	पुनर्वास विभाग	12	28
14.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,006	5,094
15.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	207	1,036
16.	उच्च शिक्षा विभाग	809	3,400
17.	स्कूल शिक्षा विभाग	2,361	8,351
18.	श्रम विभाग	191	464
19.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	122	423

क्र.सं.	विभाग का नाम	31 मार्च 2023 तक की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
20.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	396	1,307
21.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	99	496
22.	सहकारिता विभाग	84	873
23.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	196	1,194
24.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	21	62
25.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	135	357
26.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	43	331
27.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	72	239
28.	कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग	27	248
29.	जल संसाधन विभाग	282	1,739
30.	सामान्य प्रशासन विभाग	132	352
31.	संसदीय कार्य (राज्य विधानसभा) विभाग	8	15
32.	जनसंपर्क विभाग	28	89
33.	राजस्व विभाग	2,652	9,127
योग		13,839	51,746

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका सं. 1.6.3, पृष्ठ सं. 8)

व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु बकाया कंडिकाओं का विभागवार विवरण

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग का नाम	31.03.2023 की स्थिति में बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी	राज्य विधान सभा सदन में प्रस्तुति की तारीख	विभागीय उत्तर प्राप्त होने की नियत तिथि
1.	2016-17 (राजस्व क्षेत्र)	राजस्व विभाग	03	09.01.2019	09.04.2019
2.	2017-18 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	03	21.09.2020	21.12.2020
		राजस्व विभाग	01		
03	2017-18 (राजस्व क्षेत्र)	राजस्व विभाग	02	21.09.2020	21.12.2020
04	2017-18 (आर्थिक क्षेत्र)	जल संसाधन विभाग	01	21.09.2020	21.12.2020
05	2018-19 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01	21.12.2021	21.03.2022
		गृह विभाग	02		
		जनजातीय कार्य विभाग	01		
06	2018-19 (राजस्व क्षेत्र)	राजस्व विभाग	03	21.12.2021	21.03.2022
07	2018-19 (आर्थिक क्षेत्र)	जल संसाधन विभाग	01	21.12.2021	21.03.2022
		पशुपालन एवं डेयरी विभाग	01		
		किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	01		
योग			20		

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: कंडिका सं. 1.6.4, पृष्ठ सं. 8)

31 मार्च 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थी

क्र.सं.	विभाग का नाम	चतुर्दश विधान सभा 2013-2018		पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक		योग	
		ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	03	04	01	02	04	06
2.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	01	04	01	01	02	05
3.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	01	01	-	-	01	01
4.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	01	01	-	-	01	01
5.	राजस्व विभाग	07	26	-	-	07	26
6.	जनजातीय कल्याण विभाग	01	01	-	-	01	01
7	गृह विभाग	01	02	-	-	01	02

क्र.सं.	विभाग का नाम	चतुर्दश विधान सभा 2013-2018		पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक		योग	
		ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं
8	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	02	02	-	-	02	02
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	06	01	02	03	08
10	श्रम विभाग	01	01	-	-	01	01
11	जल संसाधन विभाग	01	03	-	-	01	03
12	सामाजिक न्याय विभाग	01	01	-	-	01	01
13	सहकारी विभाग	01	01	-	-	01	01
14	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	-	02	02	02	02
		योग		योग		28	60

परिशिष्ट 2.1.1
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.6, पृष्ठ क्रमांक 19)
योजनावार व्यय का विवरण

स. क्र.	अवधि	जिला	योजना 5504	योजना 7249	योजना 2018	योजना 6422	योग
							(₹ करोड़ में)
1	2018-22	आगर-मालवा	6.77	143.22	206.69	0.00	356.68
2	2018-22	छतरपुर	19.21	0.01	60.34	84.48	164.05
3	2018-22	दमोह	16.13	56.83	89.01	81.49	243.47
4	2018-22	देवास	24.76	296.00	133.60	0.00	454.36
5	2018-22	खंडवा	18.54	0.02	180.92	0.00	199.48
6	2018-22	मन्दसौर	18.52	0.03	362.66	0.00	381.20
7	2018-22	रायसेन	14.07	78.34	85.74	0.00	178.15
8	2018-22	सतना	22.05	0.02	16.50	47.32	85.90
9	2018-22	सीहोर	13.96	240.49	161.82	0.00	416.27
10	2018-22	सिवनी	25.39	7.92	68.47	0.00	101.78
11	2018-22	श्योपुर	3.84	0.02	172.37	8.44	184.67
12	2018-22	शिवपुरी	14.07	0.03	40.85	190.77	245.72
13	2018-22	विदिशा	19.52	370.75	81.47	208.32	680.05
योग			216.83	1,193.68	1,660.44	620.82	3,691.78

(स्रोत: राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.2 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 26)

सिवनी जिले में वित्तीय सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का विवरण

स. क्र.	जाली स्वीकृति आदेश में अंकित अनधिकृत व्यक्ति का नाम	खाता संख्या जिसमें राशि का भुगतान किया गया	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक अभिलेखों के अनुसार उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें वास्तव में भुगतान किया गया	खाते में किए गए लेनदेनों की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	रमेश	32074932189	एसबीआईएन0010825	श्रेष्ठ अवधिया	30	120.00
2	द्वारकाबाई	2227576357	सीबीआईएन0281101	ललित सरयाम	29	116.00
3	रामकुमार	3680264092	सीबीआईएन0281101	अजय यादव	19	76.00
4	विष्णु	32074932677	एसबीआईएन0010825	विशेष अवधिया	19	76.00
5	हरेंद्र	35839726100	एसबीआईएन0000478	श्री सुमित रजक	19	76.00
6	दीपक	31791364692	एसबीआईएन0002850	दीपक	17	68.00
7	कमलाबाई	32892112473	एसबीआईएन0012187	नितिन सेहोसे	14	56.00
8	विकास	40914873639	एसबीआईएन0000390	राधेश्याम	13	52.00
9	देवीप्रसाद	32924550232	एसबीआईएन0010825	श्रीमती रुक्मणी अवधिया	11	44.00
10	हर्षित	3860006046	सीबीआईएन0282041	प्रशांत अवधिया	10	40.00
11	शुभम	40928419442	एसबीआईएन0000478	संजय कुमार राय	10	40.00
12	हरीश	20229701688	एमएचबी0000644	अटल सिंह फतू लाल राय	9	36.00
13	जानकी	25006469095	एमएचबी0000689	राधेश्याम	8	32.00
14	सुखचैन	5156926050	सीबीआईएन0281049	विशेष अवधिया	6	24.00
15	हरिदास	32535815623	एसबीआईएन0002840	अक्षांश चौहान	6	24.00
16	प्रदीप	200541030059672	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	शिवम अग्रवाल	5	20.00
17	लोचन	922010030888887	यूटीआईबी0001035	सरोज	5	20.00
18	भीवराम	3525279075	सीबीआईएन0281049	निखिल कहार	4	16.00
19	संतकुमार	3669349530	सीबीआईएन0281101	पारस दुबे	4	16.00
20	मनीष	32064376290	एसबीआईएन0010825	मनीष बंदेवार	4	16.00
21	विकास	20068231577	एमएचबी0000421	बंटी	3	12.00
22	आशा	31855310260	एसबीआईएन0010825	चित्रा सिंह	3	12.00
23	दयाशंकर	32074930192	एसबीआईएन0010825	अनुज कुमार बघेल	3	12.00
24	लामू और सुमार	2292467169	सीबीआईएन0281780	लामू लाल सोकलू	2	8.00
25	ईश्वरदास	20322718121	एसबीआईएन0010825	श्रेयस तिवारी	2	8.00
26	शांतिबाई	60148347903	एमएचबी0000644	प्रभुलाल	2	8.00
27	कुसुम	200501030037731	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	अनिल कुमार	2	8.00
28	लोचन	2251063628	सीबीआईएन0281987	दीनदयाल साहू	1	4.00
29	मोहित	2993337632	सीबीआईएन0281101	मोहित सिंह बघेल	1	4.00

स. क्र.	जाली स्वीकृति आदेश में अंकित अनधिकृत व्यक्ति का नाम	खाता संख्या जिसमें राशि का भुगतान किया गया	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक अभिलेखों के अनुसार उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें वास्तव में भुगतान किया गया	खाते में किए गए लेनदेनों की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
30	सूरज	3157056588	सीबीआईएन0281987	अंकित साहू	1	4.00
31	द्वारकाबाई	3215757921	सीबीआईएन0281987	दीपक बंजारा	1	4.00
32	दुर्गाबाई	3714986386	सीबीआईएन0281101	दुर्गाबाई चंदेल	1	4.00
33	रामकुमार	3768311648	सीबीआईएन0281987	प्रिंस साहू	1	4.00
34	फैजा	5127175846	सीबीआईएन0282359	फैजा मोहम्मद अजीज़ शेख	1	4.00
35	कृष्णाबाई	5262935836	सीबीआईएन0282672	कृष्णा बाई	1	4.00
36	दीपक	20068305982	एमएचबी0000421	गगन दिलीप विश्वकर्मा	1	4.00
37	सुरेश	20229746596	एमएचबी0000644	सुरेश	1	4.00
38	हेमराज	20231812013	एमएचबी0001058	गोरेलाल हेमराज	1	4.00
39	कैलाश	32995889725	एसबीआईएन0003179	सुजीत सिंह विशेन	1	4.00
40	सुजीत	37786707329	एसबीआईएन0012187	अनिल सनोडिया	1	4.00
41	हरेंद्र	40257242610	एसबीआईएन0012187	श्रीमती प्रीती	1	4.00
42	हरेंद्र	60130560716	एमएचबी0001058	हरेंद्र	1	4.00
43	महेश	60175536873	एमएचबी0000689	महेश	1	4.00
44	तेजनलाल	60199177280	एमएचबी0000689	तेजन लाल	1	4.00
45	जगू	60231970285	एमएचबी0000644	जगू	1	4.00
46	हरोजबाई	60248961330	एमएचबी0000689	हरोज बाई	1	4.00
47	ललिता	60333128506	एमएचबी0000689	ललिता बाई	1	4.00
48	सूरज	100167422827	आईएनडीबी 0000861	सरोज	1	4.00
49	संपतिया	32250110005699	यूसीबीए0003225	नितिन कुमार सिहोसे	1	4.00
50	दुर्गेश	200091030086166	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	दुर्गेश	1	4.00
51	बिश्तोबाई	200091030090323	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	खोदश्याम बिश्तोबाई	1	4.00
52	गजानंद	200091030126930	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	गजानंद	1	4.00
53	सुमरन	200091030133228	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	सुमरन	1	4.00
54	देवीप्रसाद	200521030048942	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	देवीप्रसाद	1	4.00
55	प्रहलाद	200541010000183	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	सुधीर अग्रवाल	1	4.00
56	पातिराम	200541030021402	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	पातिराम	1	4.00
57	हरिलाल	806410110000800	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	हरिलाल	1	4.00
58	जीवनलाल	806411010004072	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	जीवनलाल	1	4.00
59	सुकवारोबाई	806510110000257	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	सुकवारोबाई	1	4.00
योग					291	1,164.00

(स्रोत: तहसीलदार, केवलारी द्वारा प्रदत्त भुगतान आदेश सूचियां एवं बिल/स्वीकृतियां)

परिशिष्ट-2.1.2 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 27)

सिवनी जिले में मजदूरी मद से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	ई-भुगतान में उल्लिखित कर्मचारी का नाम जिसके नाम पर राशि निकाली गई	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	लेखाशीर्ष
1	द्वारकाबाई	2227576357	सीबीआईएन0281101	ललित सरयाम	31-03-20	12,000	20005943617	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					31-03-20	12,000	20005943666	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	12,000	20006131166	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	12,000	20006144017	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					05-08-20	4,000	20006779488	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					05-08-20	4,000	20006778466	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					05-08-20	4,000	20006779088	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
2	रामकुमार	3680264092	सीबीआईएन0281101	अजय यादव	31-03-20	12,000	20005943617	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					31-03-20	12,000	20005943666	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	12,000	20006131166	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	12,000	20006144017	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					05-08-20	4,000	20006779488	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					05-08-20	4,000	20006778466	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					05-08-20	4,000	20006779088	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
3	रमेश	32074932189	एसबीआईएन0010825	श्रेष्ठ अवधिया	31-03-20	8,000	20005943666	2053-00-094-9999-0441-00000000-12

स. क्र.	ई-भुगतान में उल्लिखित कर्मचारी का नाम जिसके नाम पर राशि निकाली गई	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	लेखाशीर्ष
					31-03-20	8,000	20005943617	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	8,000	20006131166	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	8,000	20006144017	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
4	विष्णु	32074932677	एसबीआईएन0010825	विशेष अवधिया	31-03-20	8,000	20005943617	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					31-03-20	8,000	20005943666	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	8,000	20006131166	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
					01-05-20	8,000	20006144017	2053-00-094-9999-0441-00000000-12
योग						1,84,000		

(स्रोत: तहसीलदार, केवलारी द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां)

परिशिष्ट-2.1.2 (ग)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 27)

सिवनी जिले में ओलावृष्टि, बाढ़/अतिवृष्टि हेतु संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार भुगतान किया गया	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	योजना
1	द्वारकाबाई	2227576357	सीबीआईएन0281101	ललित सरयाम	28-01-21	53,000	20008333883	रिफंड
					03-03-21	52,734	20008676373	रिफंड
					24-03-21	70,000	20008864200	ओला-वृष्टि
					24-03-21	48,000	20008867055	ओला-वृष्टि
					08-06-21	29,172	20009530949	रिफंड
					30-06-21	89,564	20009695009	रिफंड
					17-09-21	53,982	200010336098	रिफंड
					17-02-22	5,000	200011673949	अत्यधिक वर्षा
					26-03-22	18,450	200012093776	रिफंड
					25-04-22	20,900	200012358110	अत्यधिक वर्षा
					25-04-22	1,20,000	200012369997	अत्यधिक वर्षा
					25-04-22	1,20,000	200012359653	अत्यधिक वर्षा
					01-07-22	1,20,000	200012902099	अत्यधिक वर्षा
2	राम कुमार	3680264092	सीबीआईएन0281101	अजय यादव	03-03-21	1,650	20008676373	रिफंड
					24-03-21	1,650	20008917558	अत्यधिक वर्षा
					24-03-21	47,115	20008864200	ओला-वृष्टि
					24-03-21	48,000	20008867055	ओला-वृष्टि
					08-06-21	19,734	20009530949	रिफंड
					30-06-21	1,650	20009695009	रिफंड
					17-09-21	59,101	200010336098	रिफंड
					18-10-21	21,633	200010591255	रिफंड
					17-02-22	5,000	200011673949	अत्यधिक वर्षा
					25-04-22	77,080	200012358110	अत्यधिक वर्षा
					25-04-22	1,18,146	200012369997	अत्यधिक वर्षा
					25-04-22	1,20,000	200012359653	अत्यधिक वर्षा
योग						13,21,561		

(स्रोत: तहसीलदार, केवलारी द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां)

परिशिष्ट-2.1.3 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 28)

श्योपुर जिले की बड़ौदा और श्योपुर तहसीलों में किए गए संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण-
लाभार्थियों के नामों में विसंगति

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया	खाता संख्या	बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	तहसील	इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	राजेंद्र सिंह मकड़ावदाखुर्द	1563104000062550	लोमेश गोरछिया	बड़ौदा	4	1.77
2	नाथूरोजी	6132000100093708	लोमेश लक्ष्मीनारायण	बड़ौदा	13	3.15
3	संतराश्रीपुरा	754302010001880	लोमेश पुत्र लक्ष्मी नारायण	बड़ौदा	8	2.59
4	जगमोहन मकड़ावदा खुर्द	35884656965	गोबरधनी	बड़ौदा	14	3.30
5	दसा बावड़ीचापा	6132001700247692	गोबरधनी	बड़ौदा	6	1.52
6	कडुमा कडवदा खुर्द	37888358257	मीनू गोरछिया पुत्री लक्ष्मीनारायण	बड़ौदा	14	3.21
7	कैलाशरोजी	34793684187	राम अवतार सुमन	बड़ौदा	24	6.77
8	मुकेशरोजी	907510110001304	रामअवतार सुमन	बड़ौदा	21	4.70
9	मांगीलालरोजी	4116101000032	रामअवतार सुमन	बड़ौदा	19	4.74
10	मथुरिरोजी	183000491820	राम अवतार सुमन पुत्र हरिप्रसाद सुमन	बड़ौदा	18	4.77
11	दसा बावड़ीचापा	754302010003275	फरहीन नाज़ कुरैशी	बड़ौदा	15	3.86
12	रामकुंवररोजी	683502020367	हरिप्रसाद सुमन पुत्र गोपाल सुमन	बड़ौदा	14	3.71
13	सुखवीररोजी	907518210013416	आकाश	बड़ौदा	13	1.97
14	गुजरी बावड़ीचापा	35596351541	फरहीन नाज़ कुरैशी	बड़ौदा	12	3.09
15	बल्लुरोजी	33680406910	लेखराज सुमन	बड़ौदा	11	1.73
16	अर्जुन बमोरीजात	754302010003430	पवन सुमन	बड़ौदा	11	3.56
17	राधे श्याम राडेप	20281130381	धनजीत मीना	बड़ौदा	10	1.00
18	रामजीलाल करवड़िया	35159430160	रामरूप सुमन	बड़ौदा	10	2.56
19	कमालिरोजी	36129944415	भरोसी बाई	बड़ौदा	10	1.91
20	हंसराजरोजी	38217220486	कलावती सुमन	बड़ौदा	10	1.83
21	कैलासी भिलवाडिया	6132001700245630	आकाश आदिवासी	बड़ौदा	10	2.05
22	गोलूबोरदादेव	6132001700245667	राजवीर	बड़ौदा	10	2.56
23	गिर्राज हलगांवा खुर्द	3701885270	प्रमोद सुमन	बड़ौदा	9	2.00
24	ओमप्रकाश इंद्रपुरा	32703301093	श्यामसुंदर जाटव	बड़ौदा	9	0.59
25	दुलीचंद्र रोजी	33680406716	कुमारी सुरेशा माली	बड़ौदा	9	1.50
26	गुलाब ललितपुरा	38226792714	अलका शर्मा	बड़ौदा	9	0.83
27	कंचन बोरदादेव	39175690552	हसीना आदिवासी	बड़ौदा	9	2.01
28	बजरंग नयागोलाखा	183002358297	रामरूप सुमन पुत्र भेरूलाल	बड़ौदा	9	2.89
29	कडु हलगांवाडा खुर्द	4116101003639	सतीश पुत्र धर्मा	बड़ौदा	9	2.54
30	जगदीश रामकुमार फिलोजपुरा	907510110004001	आरती रमेश चंद्र गोयल	बड़ौदा	9	4.12

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया	खाता संख्या	बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	तहसील	इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
31	मोसमी मकड़ावदाखुर्द	1563104000031860	लक्ष्मीबाई	बड़ौदा	9	2.77
32	ज्योति बोरदादेव	31295584259	कृष्ण जग	बड़ौदा	8	2.29
33	रामहेत गोवर्धन फिलौजपुरा	31999532096	श्रीमती पारस गुप्ता	बड़ौदा	8	3.90
34	सियाराम मकड़ावदाखुर्द	36205429022	महावीर आदिवासी	बड़ौदा	8	1.24
35	किशना हलगनवाड़ाखुर्द	3956107037	शिशुपाल बंशी आदिवासी	बड़ौदा	7	1.40
36	लेखराज कलमुंडा	39752307686	श्री पवन सुमन	बड़ौदा	7	2.59
37	प्रकाश रदीप	63042185143	रमाशंकर मीना	बड़ौदा	7	1.45
38	प्रकाश बोरदादेव	683502009988	हरिनारायण सुमन पुत्र गोपाल सुमन	बड़ौदा	7	2.30
39	ओमप्रकाश बोरदादेव	683502016293	कल्याणी बाई माली पत्नी हरि नारायण सुमन	बड़ौदा	7	2.71
40	बद्रीलाल मकड़ावदाखुर्द	754302010004432	आकाश आदिवासी	बड़ौदा	7	2.01
41	मोसमी मकड़ावदाखुर्द	754302120003016	शिखा	बड़ौदा	7	1.44
42	दिनेश बसौंद	907510110011122	किरण शर्मा	बड़ौदा	7	1.63
43	विष्णु कुदायथा	907510110013291	श्याम सुंदर जाटव पुत्र बाबूलाल	बड़ौदा	7	0.87
44	रामश्री मकड़ावदाखुर्द	3943364318	बजरंगी श्यामलाल आदिवासी	बड़ौदा	6	1.24
45	कन्या बैकालू खेलडी	20307232708	श्रीमती अनुसूया नागर	बड़ौदा	6	1.34
46	लल्लू हलगनवाड़ाखुर्द	32143358772	राजाराम आदिवासी	बड़ौदा	6	1.32
47	सीताराम धरमपुरा	33361104233	सूरजमल	बड़ौदा	6	1.50
48	रामवीररोजी	35922126290	श्रीमती कांति बाई सुमन	बड़ौदा	6	1.20
49	घनश्याम बोरदादेव	36617612850	हरिनारायण सुमन	बड़ौदा	6	1.86
50	अजय कुदायथा	39522033547	पवन कुशवाह	बड़ौदा	6	1.38
51	रामबंदी रतौदन	63053171114	श्रीमती सावंदी	बड़ौदा	6	1.24
52	रामचरण कलौनी	183004810506	राजतिलक सुमन पुत्र महावीर सुमन	बड़ौदा	6	1.60
53	ब्रजमोहन कलौनी	183004957800	शोभा सुमन पुत्री महावीर सुमन	बड़ौदा	6	1.82
54	कुंती बोरदादेव	4116101003922	विजय सिंह जागा	बड़ौदा	6	1.77
55	श्याम कलमुंडा	10820110087213	संतोष	बड़ौदा	6	1.60
56	रामस्वरूप राधापुरा	11673210000607	श्यामसुंदर	बड़ौदा	6	0.63
57	मोदुबनदी	754302010001577	भारती गोरछिया पुत्री मेवई	बड़ौदा	6	1.86
58	घीसी कलमुंडा	907518210014606	वर्षा पत्नी संतोष	बड़ौदा	6	1.82
59	मंगला नयागोलखा	31821253856	लवकुश सुमन	बड़ौदा	5	1.36
60	रामस्वरूप बोरदादेव	31892796526	लोकेश सुमन	बड़ौदा	5	1.73
61	मोती बोरदादेव	32263883704	सुश्री विद्या बाई	बड़ौदा	5	1.60
62	ब्रजमोहन बद्रीपाचीपुरा	32356250562	लाखन सिंह मीना	श्योपुर	5	1.01
63	रामस्वरूप करवडिया	32445467507	सीता	बड़ौदा	5	0.92

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया	खाता संख्या	बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	तहसील	इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
64	मंशारोजी	32710625010	राधेश्याम सुमन	बड़ौदा	5	1.36
65	जयमल हलगांवदाखुर्द	33760433194	विष्णु सुमन	बड़ौदा	5	1.09
66	कांति बाला जाट फिलोजपुरा	34514828337	श्री कलिल खान	बड़ौदा	5	1.91
67	ढोडी महाराजपुरा	35363177602	देवीशंकर नगोफ विशाखा	बड़ौदा	5	1.12
68	विद्या बायवार्ड 15	38673471542	राजकुमार सेन	बड़ौदा	5	0.89
69	शेरा हलगनवाड़ा खुर्द और रामचरण कुनु सहर क्यारपुरा	40511626790	राममुकुट आदिवासी	बड़ौदा	5	1.24
70	गिराज हलगांवा खुर्द	63018146873	बनवारी सुमन	बड़ौदा	5	1.38
71	रामकिशन ललितपुरा	63046428048	रामकिशन सुमन	बड़ौदा	5	1.50
72	भीमराज बोरदादेव	907510110003367	अशोक कुमार पुत्र ब्रम्हमोहन जागा	बड़ौदा	5	1.89
73	राकेश मेखदाहेड़ी	907510110015828	काशीराम मीना	बड़ौदा	5	4.47
74	कपूरी हलगनवाड़ाखुर्द	907518210026087	उर्मिला बाई	बड़ौदा	5	1.01
75	धनु हलगनवाड़ाखुर्द	907518210032162	सलमा आदिवासी	बड़ौदा	5	0.87
76	महावीर हलगनवाड़ाखुर्द	1563104000004428	बनवारी सुमन	बड़ौदा	5	1.32
77	जना बाई बेहदावद	20412415782	नागेंद्र सिंह राय	बड़ौदा	4	1.19
78	हरिशंकर परसरमा फिलोजपुरा एवं सलीम पुत्र बुन्दू वार्ड 22 श्योपुर	20412416809	श्री शफीक	बड़ौदा	4	1.49
79	गोपी नयागोलाखा	31325383427	पुरुषोत्तम शर्मा	बड़ौदा	4	1.56
80	धन्नालाल बोरदादेव	31797997776	कुमारी जसोदा	बड़ौदा	4	1.36
81	सरवन हलगनवाड़ाखुर्द	32755234079	रूप सिंह आदिवासी	बड़ौदा	4	1.06
82	मोडू ईश्वरीय फिलोजपुरा और कैलाशी बीरबल मीना कचरमुली	35108329615	श्रीमती रुखसार खानम	बड़ौदा	4	1.65
83	शीताराम हरबक्स जैनी	35425559025	रामलखन मीना	श्योपुर	4	1.00
84	राजेंद्रभीलवाडिया	37945843794	राहुल सनेरिया	बड़ौदा	4	1.16
85	कामली लातूर फिलोजपुरा	38194984080	श्रीमती साहिना बानो	बड़ौदा	4	1.86
86	मलखान महाराजपुरा एवं रामलखन धुडिया लाडपुरा	40314083462	रजनी वैष्णव	बड़ौदा एवं श्योपुर	4	1.08
87	दिगम्बर भीलवाडिया	63030669319	जगदीश नाथ	बड़ौदा	4	0.91
88	सोन्यानायागोलाखा	683502000259	पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र शंभूदयाल	बड़ौदा	4	1.54
89	गिरधारी शंकर भीलवाडिया एवं त्रिलोकभीलवाडिया	906910110001435	मुलायम सिंह चौहान	बड़ौदा	4	1.30
90	रामस्वरूप बड़ोदियाबिंदी	907510110006540	धर्मन्द्र जाटव पुत्र देवीराम जाटव	बड़ौदा	4	1.03
91	रणवीरबनदी	907510110008813	रामदेव पुत्र दुल्लीचंद आदिवासी	बड़ौदा	4	0.83

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया	खाता संख्या	बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	तहसील	इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
92	गिरजम अकड़ावदा खुर्द	907510110012027	गणेश सेन पुत्र रामगोपाल सेन	बड़ौदा	4	0.82
93	नारायण हलगांवा खुर्द एवं नाथीबाई बाबू सिंह गुर्जर काशीपुर	907518210007691	सोनी बाई	बड़ौदा एवं श्योपुर	4	0.72
94	नरोत्तम मकड़ावड़ाखुर्द	907518210029362	गुड्डी बाई मीना	बड़ौदा	4	1.10
95	रघुवीर कुदायथा	907518210039879	धनराज आदिवासी पुत्र प्रहलाद आदिवासी	बड़ौदा	4	1.11
96	मेघराज हलगांवाखुर्द	907518210040973	विजय सिंह गोरछिया	बड़ौदा	4	0.67
97	कल्याण सोरम माली जैनी	32193371272	चिरंजी सुमन	श्योपुर	3	1.05
98	नंदकिशोर मेखदाहेड़ी	33761350499	महावीर प्रजापति	बड़ौदा	3	0.84
99	गुरुप्रताप दिलबाग सिंह फिलोजपुरा	34495899464	शकीलाखान खान	बड़ौदा	3	1.20
100	मोरपाल काना मकरोड़	34702217357	मंशाराम माहोर	श्योपुर	3	1.04
101	मंशाराम मनारन मीना कचरमुली और मोहरपाल सर्वन्या चंद्रपुरा	35423067068	तीज्या ग्यारसा	श्योपुर	3	1.17
102	बैचेन सिंह मंगल बागडुआ बद्दीलाल बलदेव धाकड़ फिलोजपुरा	35423067104	पाना धन्नालाल	श्योपुर एवं बड़ौदा	3	0.98
103	केलाश बिदाखेड़ली	36691011383	गणेश तिवारी	बड़ौदा	3	1.05
104	कुन्दन श्यामाराम सेमल्डा एवं कुन्ती महाराजपुरा	38663568207	संदीप सिंह राठौड़	श्योपुर एवं बड़ौदा	3	1.03
105	गोविंद पंडोला	10820100008046	ओम प्रकाश	बड़ौदा	3	1.11
106	मुकेश महाराजपुरा एवं रामकिशन रामनारायण कीर मकरोड़	10820110088609	आशा जांगिड़	बड़ौदा एवं श्योपुर	3	0.89
107	समद खा सुल्तान मेवाड़ा कछार	907510110001601	शबाना पठान पत्नी दिलशाद खान पठान	श्योपुर	3	0.78
108	धन्ना ग्यारसा फिलोजपुरा एवं गोविंद जनार्दन शर्मा कचरमुली	907510110003282	अमरीन खान पत्नी मोहम्मद इकत्यार खान	बड़ौदा एवं श्योपुर	3	1.18
109	मोरपाल नाथुआ आदिवासी देरोली	907518210003955	तरुण तोमर	श्योपुर	3	0.81
110	मनफुल कर्णखेड़ली	921010037518667	मनीष धाकड़	बड़ौदा	3	0.92
111	धर्म सिंह मलखान जैनी	10702966472	धारा सिंह मीना	श्योपुर	2	1.20
112	रामनारायण सोराम चंद्रपुरा	34715901138	रिजवाना बानो	बड़ौदा	2	0.96
113	धन्नी अमारा फिलोजपुरा	34983083395	सद्दाम ओ	बड़ौदा	2	0.95

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया	खाता संख्या	बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	तहसील	इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
114	जुगराज हरनारायण गोथरा और रामजीलाल महाराजपुरा	35060471742	अशोक मीना	शयोपुर एवं बड़ौदा	2	0.91
115	राधा सूरजमल चंद्रपुरा	35076335882	मोहित गौड़	बड़ौदा	2	0.97
116	किशनगोपाल गप्पु फिलोजपुरा और सुनीता पवन वैश्य कचरमुली	35315523414	शाहरुख अंसारी	बड़ौदा एवं शयोपुर	2	0.92
117	जनरेल सिंह चिंगार सिंह फिलोजपुरा	35442683358	रुकमल ओ	बड़ौदा	2	0.95
118	बजरंग नारायण चंद्रपुरा और रामजी कन्निराम मीना कचरमुली	35442683461	जोगा ओ	बड़ौदा एवं शयोपुर	2	0.90
119	बद्रीलाल बलदेव धाकड़ फिलोजपुरा	35486756532	कमलाबेवा मड्डू	बड़ौदा	2	0.90
120	शंकरलाल सुखदेव धाकड़ फिलोजपुरा	35486756611	विष्णुदेव नंदकिशोर	बड़ौदा	2	0.92
121	प्रकाश प्रह्लाद चंद्रपुरा	35551881071	पवन गौड़	बड़ौदा	2	0.97
122	रामावतार घनश्याम चंद्रपुरा	36190479393	अन्नो	बड़ौदा	2	0.95
123	मलखान मोती जैनी	37313751563	धारा सिंह मीना	शयोपुर	2	1.16
124	श्याम गिराज फिलोजपुरा	38032045794	अफसाना बानो	बड़ौदा	2	0.98
125	प्रभुलाल हरदेव फिलोजपुरा	38641040691	शानू बानो	बड़ौदा	2	0.98
126	हरवंश सिंह फोजा सिंह कचरामुली और नरोत्तम गोपीलाल फिलोजपुरा	39340175678	फरहीन	शयोपुर एवं बड़ौदा	2	0.92
127	परसुया बाला कचरमुली और रामकिशन प्रह्लाद चंद्रपुरा	39700938929	मनबर बाई	शयोपुर एवं बड़ौदा	2	0.93
128	गुरुबाई ललितपुरा	40454772369	रामरूप	बड़ौदा	2	1.08
129	दिनेश मीना अभिभावक राम मुकेश	144801500799	सुगीव मीना	शयोपुर	2	0.34
130	साहब सिंह करनाल सिंह फिलोजपुरा	144801501589	रईश खान	बड़ौदा	2	0.82
131	गणेश शंकर शामरा फिलोजपुरा	144801503226	रमेश चंद्र गोयल	बड़ौदा	2	0.97
132	भंवरलाल महाराजपुरा एवं मुनेश राहकिशन बागड़िया	754302010003474	जागेश्वर सिंह	बड़ौदा एवं शयोपुर	2	0.65
133	मुन्ना छितरिच्छनखेडली	754302010004087	हिमांशु शर्मा	शयोपुर	2	1.15
134	लोदुराम जगन्नाथ मीना जैनी और उर्मिला राजोरा	907510110000005	बरमा बाई पत्नी दारा सिंह मीना	शयोपुर एवं बड़ौदा	2	0.62

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया	खाता संख्या	बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	तहसील	इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
135	बाबूलाल गोपाल चंद्रपुरा	907510110001562	बारिश खान पुत्र इस्लाम खान	बड़ौदा	2	0.97
136	शयोराम बरखेड़ा	907510110010835	किशनगोपाल पुत्र देवीराम	बड़ौदा	2	0.42
137	प्रकाश प्रह्लाद चंद्रपुरा और सिसुपाल हजारी कचरमुली	921010037519691	इमरान खान	बड़ौदा एवं शयोपुर	2	0.90
138	आशा इन्द्रगज फिलोजपुरा	921020019197090	बारिश खान	बड़ौदा	2	0.93
139	रासबिहारी बाबूलाल चंद्रपुरा	34223174744	इमरान खान	बड़ौदा	1	0.47
योग					804	221.56

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.3 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 28)

श्योपुर जिले की बड़ौदा और कराहल तहसीलों में अन्य संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसके खाते में वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक पैसा जमा किया गया	खाता संख्या	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	खड़क सिंह गुरीबाज सिंह और ललित भोला बगदुआ	50400100005429	बड़ौदा	9	4.33
2	गोपाल बमोरीजाट और कन्हियालाल नारायणपुरा	53052341367	बड़ौदा	16	4.07
3	प्रभुलाल हरदेव फिलोजपुरा	50400100005430	बड़ौदा	8	3.84
4	बनवारी वार्ड 15	32906081995	बड़ौदा	16	3.47
5	विजया नयागोलाखा	63050656918	बड़ौदा	18	2.84
6	कमला बावडीचापा	50408100010985	बड़ौदा	16	2.53
7	रामरेखा बावडीचापा	50408100010981	बड़ौदा	13	2.29
8	मनोज नयागोलाखा	202781030082717	बड़ौदा	13	2.27
9	विमलेश कुमारी बघेल	30986933634	कराहल	5	2.20
10	इंदरसिंह हलगनवाडा खुर्द	50400100006203	बड़ौदा	9	2.13
11	मोरपाल बावडीचापा	6132001700247708	बड़ौदा	7	2.11
12	दासनायगौलखा	32994892412	बड़ौदा	17	2.11
13	धीरज ललितपुरा	32122619210	बड़ौदा	8	2.09
14	कैलासी भिलवाडिया	6132001700245630	बड़ौदा	10	2.05
15	ललित कुमार जांगिड़	20306926162	कराहल	5	1.94
16	श्यामवरण	32615903178	कराहल	5	1.92
17	मनीष चौहान	20429815497	कराहल	5	1.86
18	मनीषा बावडीचापा	50408100010978	बड़ौदा	10	1.78
19	लाखन बावडीचापा	50408100011100	बड़ौदा	10	1.78
20	मंजीत सिंह अवतार सिंह	50200038290251	बड़ौदा	4	1.76
21	गुरुमीत सिंह बोरदादेव	6132001700250881	बड़ौदा	5	1.70
22	विष्णु बासोंड	38439573960	बड़ौदा	9	1.69
23	गुजरि नयागोलाखा	907518210028713	बड़ौदा	14	1.65

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसके खाते में वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक पैसा जमा किया गया	खाता संख्या	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
24	जगजीतश्रीपुरा	520331003366541	बड़ौदा	7	1.64
25	मोरपाल नयागोलखा	63030169598	बड़ौदा	16	1.61
26	योगेश कुदायथा	20410485296	बड़ौदा	8	1.55
27	दिनेश जाटव पुत्र मांगीलाल जाटव	683501020710	कराहल	6	1.52
28	प्रवीण कुमार बघेल	32357494789	कराहल	3	1.50
29	प्रवीण कुमार बघेल पुत्र राजकुमार	183002384737	कराहल	3	1.49
30	कपिल गोस्वामी नयागाँव	32065704460	बड़ौदा	6	1.47
31	राहुल सिंह तोमर	40521629450	कराहल	3	1.46
32	जीतेन्द्र ललितपुरा	63048581683	बड़ौदा	12	1.44
33	दिनेश जाटव पुत्र मांगीलाल जाटव	63037940080	कराहल	4	1.43
34	कैलाश पुत्र रामनारायण जांगिड़	183000023306	कराहल	3	1.42
35	चायनाबोरदादेव	6132001700249520	बड़ौदा	6	1.42
36	आशा जांगिड़ पत्नी कैलाश	32048999973	कराहल	3	1.41
37	सतेंद्र सिंह तोमर	10703005360	कराहल	3	1.39
38	मनोज ओझा	33981456789	कराहल	3	1.35
39	कस्तूरीबोरदादेव	6132001700249539	बड़ौदा	6	1.34
40	हरिरामरिझा	50408100011312	बड़ौदा	9	1.33
41	शम्भूदयाल ललितपुरा	63013816051	बड़ौदा	12	1.32
42	मानसिंह पंडोली	907510110012307	बड़ौदा	7	1.29
43	लक्ष्मी चौहान	907518210035895	कराहल	4	1.28
44	राहुल सिंह तोमर	907518210003975	कराहल	3	1.27
45	गुड़िया बावड़ीछापा	50408100010987	बड़ौदा	12	1.27
46	राम नयागोलखा	6132001700249627	बड़ौदा	5	1.26
47	रामसिया नयागोलखा	6132001700249636	बड़ौदा	5	1.25
48	रामसिया हलगंवादाखुर्द	6132001700003663	बड़ौदा	4	1.25
49	ज्योतिबोरदादेव	20154163292	बड़ौदा	7	1.25
50	श्रीमती अम्बिका	20217201385	कराहल	4	1.22
51	संत्यश्रीपुरा	183003609944	बड़ौदा	5	1.22

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसके खाते में वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक पैसा जमा किया गया	खाता संख्या	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
52	मुकेशबावड़ीछापा	6132001700247717	बड़ौदा	5	1.22
53	रामअवतार अलगनवाड़ाखुर्द	4116108001425	बड़ौदा	4	1.21
54	राहुल सिंह तोमर	921010025725398	कराहल	3	1.20
55	गिराज सिंह तोमर	35390154466	कराहल	3	1.13
56	प्रदीप कुमार बघेल	31813913495	कराहल	2	1.00
57	कुमारी सुमन जाटव दिनेश	34076640633	कराहल	4	0.99
58	मोहरपाल पुत्र चिट्टू	35286919370	कराहल	5	0.98
59	कुमारी सुआबाई जाटव मांगीलाल	35135311877	कराहल	3	0.97
60	तरुण तोमर	907518210003955	कराहल	3	0.96
61	लीला गुर्जर अमर सिंह	35385363681	कराहल	4	0.94
62	संतोषी	38137897446	कराहल	2	0.93
63	राजधर सिंह	30266976780	कराहल	2	0.91
64	सुरेश जगन्नाथ चंद्रपुरा	50408100004706	बड़ौदा	2	0.91
65	सतेंद्र सिंह तोमर	916010072723044	कराहल	2	0.85
66	ललिता आदिवासी	39003881453	कराहल	2	0.82
67	महेश पुत्र मांगीलाल जाटव	183000573394	कराहल	3	0.80
68	कुमारी मालती जाटव महेश	34289953304	कराहल	4	0.78
69	विजय सिंह	34209200332	कराहल	2	0.77
70	विपीन जाटव रमेश	36368645355	कराहल	3	0.76
71	संजय मंगल	53038269013	कराहल	2	0.74
72	मांगीलाल जाटव	35135311822	कराहल	2	0.61
73	अतबल पुत्र धनीराम टिकटोली	906710110000095	कराहल	2	0.60
74	सुवरन जाटव	34501706605	कराहल	3	0.47
75	बलवंत उमरिया	63034079144	कराहल	1	0.43
76	राधा जाटव	32925137030	कराहल	2	0.38
77	मोहन पुत्र चिरौंगी मोरावन	36368645605	कराहल	1	0.31
योग				472	114.73

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदाय भुगतान आदेश सूचियां, भौतिक बिल और स्वीकृति आदेश)

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 28)

सीहोर जिले की तहसीलों में किये गये संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान स्वीकृत किया गया था	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	राकेश एवं मोहनसिंह घासीराम	325302010095358	प्रमोद चौरसिया	कलेक्टर एवं तहसीलदार इछावर	77	29.33
2	रामसिंह राजू	32229812621	प्रमोद चौरसिया पुत्र प्रहलाद	कलेक्टर एवं तहसीलदार इछावर	32	7.49
3	कृष्णा बाई धूलसिंह और सारदा बाई	39700297043	प्रीति चौरसिया	तहसीलदार इछावर एवं कलेक्टर	18	10.50
4	धर्म	996910110004399	धर्म सिंह पुत्र अठनिया कर्मचारी	तहसीलदार, रेहटी	30	3.48
5	निर्मिला बाई	907810110001631	धर्म सिंह पुत्र अठनिया	कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी	28	2.86
6	सुमन बाई	996910110007856	अठनिया पुत्र पार सिंह	कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी	21	2.00
7	शोरभ बाई और मुकेश	902410110000671	अठनिया पुत्र पार सिंह	तहसीलदार, रेहटी	11	1.04
8	वीमला बाई	32152649125	जेतन बारेला पत्नी धरम सिंह	तहसीलदार, रेहटी	11	1.22
9	गीता बाई और सेर सिंह	907816710000003	जेतन पत्नी धरम सिंह	तहसीलदार, रेहटी	17	1.21
10	लक्ष्मी बाई और सोरभ बाई	902410510004165	झूना बाई पत्नी अठनिया	कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी	14	1.45
11	प्रेमनारायण एवं रमेश एवं शिवचरण दरियाव	325302010105941	सुशील कुमार रायकवार	तहसीलदार इछावर एवं कलेक्टर	40	15.64
12	समीखान	996910110000924	अभिषेक शर्मा पुत्र दिनेश	तहसीलदार, रेहटी	38	3.10
13	कुलदीपसिंह सरदार सिंह गुलाटी	996910110005930	शेख इरफान पुत्र शेख शफीक	तहसीलदार, रेहटी	26	2.58
14	मीरा बाई और राजली बाई	907810110000926	नेहा पुत्री अदानिया	कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी	23	1.77
15	शरवन	9979000100025622	अनिल राजपूत	तहसीलदार, रेहटी	18	1.31
16	राम विलास	954118210003048	अनिल राजपूत	तहसीलदार, रेहटी	17	1.15
17	सुंदर	996910110004770	राकेश विश्वकर्मा	तहसीलदार, रेहटी	17	1.30
18	देवचंद	30249665958	अभिषेक शर्मा पुत्र दिनेश	तहसीलदार, रेहटी	14	0.91
19	मधुसूदन और कन्हैया	33827747017	विजेंद्र व्यास	तहसीलदार, रेहटी	13	1.29
20	दुलूसिंह और दीपक	901010110004080	विजेंद्र व्यास पुत्र हरि प्रसाद	तहसीलदार, रेहटी	13	0.96
21	विश्रान्ति	918010111540805	शेख इरफान पुत्र शेख शफीक	तहसीलदार, रेहटी	13	1.72
22	फरहान	32786586773	शिवम कुमार	तहसीलदार, रेहटी	10	0.54

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान स्वीकृत किया गया था	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
23	नारायण	38546937983	सिपाही मन मोहन जयसवाल	कलेक्टर	10	0.60
24	गंगा बाई	901510110018025	नरेंद्र राठौड़	कलेक्टर एवं तहसीलदार रेहटी	10	1.33
25	देवेन्द्र श्यामल	902410410000102	धर्मन्द्र यादव पुत्र भरमा	तहसीलदार, रेहटी	10	0.75
26	कृष्ण कुमार	996910110014867	संतोष कुमार पुत्र लखन लाल	तहसीलदार, रेहटी	10	1.08
27	शोभा राम और शेर सिंह	996910110006224	सुष्मा बाई पत्नी अनार सिंह	तहसीलदार, रेहटी	9	0.65
28	सरिता	1068104000029096	अनिल कुमार नागर	तहसीलदार, रेहटी	9	2.71
29	नारायणा और गुड्डू	20218567496	गौरव गुप्ता	कलेक्टर एवं तहसीलदार इछावर	8	2.14
30	शेख मुनब्वर	32124878422	दीपक यादव	तहसीलदार, रेहटी	8	1.27
31	कर्ण सिंह	996910110003790	नारायण प्रसाद उइके कर्मचारी	तहसीलदार, रेहटी	8	1.39
32	फारूक खान और शाहनबाजखान	1326670399	संजय कुमार	तहसीलदार, रेहटी	7	0.80
33	भेरूसिंह एवं सोबलसिंह	20323542461	सोभाल सिंह	कलेक्टर एवं तहसीलदार आष्टा	7	1.69
34	रामसिंह	31769008959	श्रीमती प्रतिभा तिवारी	तहसीलदार आष्टा	7	0.76
35	खलील दुपाड़िया	35746106330	अनिल मेवाड़ा	तहसीलदार आष्टा	6	0.67
36	वैशाली	902410110002806	अनिल यादव पुत्र मधुसूदन यादव	तहसीलदार, रेहटी	7	0.85
37	परसराम	902410110010556	दीपक यादव पुत्र रामराज यादव	तहसीलदार, रेहटी	7	1.17
38	भगवान सिंह और शीला बाई	903210110005244	गीता परमार	तहसीलदार, रेहटी	7	0.84
39	अनन्यासिंह जवाहरसिंह अनुपमसिंह जवाहर सिंह	907610110000343	संदीप यादव पुत्र मोहन यादव	तहसीलदार, रेहटी	7	1.13
40	राजकुमार	53000846630	सतवीर सिंह यादव	तहसीलदार, रेहटी	6	0.81
41	रमियाबाई	902410510004191	हयाद खां पुत्र कल्लू खां	तहसीलदार, रेहटी	6	0.78
42	बानो बाई	907810110000228	मुकेश कुमार पुत्र संतोष	तहसीलदार, रेहटी	6	0.57
43	रीसाम्बई	907810110000267	रामबाबू पटेल पुत्र हरनाम सिंह	तहसीलदार, रेहटी	6	0.92
44	विमलसिंह	9979000100047208	पूजा राजपूत	तहसीलदार, रेहटी	5	0.53
45	रायसिंह	20155700450	मुकेश कुमार रजक	तहसीलदार, रेहटी	4	1.15
योग					671	117.44

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.5 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 29)

शिवपुरी जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया	अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	दिलीप सिंह	3350038841	कोलारस	5	0.88
2	ममता बाई	3350038013	कोलारस	13	2.24
3	प्रदीप कुमार जाटव	63006072222	कोलारस	10	1.30
4	अजय सविता	53035113568	खनियाधाना	4	0.85
5	अजय सविता	80002394279	खनियाधाना	7	3.49
6	अभय सविता	4781101001753	खनियाधाना	5	2.31
7	अभय सविता	50180013840686	खनियाधाना	6	3.61
8	लक्ष्मी सविता	53035127559	खनियाधाना	2	0.81
9	कल्ला उर्फ श्याम	63002391414	खनियाधाना	9	2.19
10	अजीतरामकुसमी	35133866151	पिछोर	6	1.66
11	अंजू कुसमी	35841337664	पिछोर	6	2.11
12	गंगाकुसमी	37160879902	पिछोर	9	2.23
13	बलराम मनका	32072636579	पिछोर	10	2.24
14	बाबूलाल (बैंक में पिंकी चौहान)	33000612168	पिछोर	3	0.65
15	मणिकांत जैन	672063037552	पोहरी	3	1.08
16	संतोष (बैंक में संगीता जैन)	8025230993	पोहरी	5	4.97
17	संजय (बैंक में संगीता जैन)	20463936985	पोहरी	3	2.90
18	यशपाल (बैंक में यश जैन)	20308583620	पोहरी	4	3.29
19	नवलसिंह	53036238225	पोहरी	10	2.49
20	नीलम जाल्क्सो	33428272668	पिछोर	16	4.72
21	राकेश जाटव	20220429100	खनियाधाना	9	3.64
22	संजय	172110034877	कोलारस	16	3.37
23	सीताराम	1431783244	कोलारस	15	3.30
24	कलाबती जाटव	8025813307	खनियाधाना	7	3.28
25	राजेश	33940754103	कोलारस	15	3.28
26	रामनिवास	33326263296	खनियाधाना	7	3.09
27	रामनिवास	172001963477	खनियाधाना	5	2.90
28	मानसिंह	80002780990	खनियाधाना	8	2.86
29	प्रागीलाल अहिरवार	32999778599	पिछोर	10	2.86
30	शुभम	888010110012149	कोलारस	12	2.85
31	गोविंद सिंह	8025813613	खनियाधाना	7	2.79
32	रजनी	80027435016	खनियाधाना	8	2.66
33	श्यामलाल	80020789877	खनियाधाना	7	2.63
34	बालकिशन	10743847265	कोलारस	15	2.61
35	अरविंद	1431759685	कोलारस	14	2.58
36	अरविन्द अहिरवार	33551049080	खनियाधाना	7	2.52

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया	अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
37	शुभम कुमार	242001000004762	कोलारस	11	2.44
38	ऋचा बाई	917010070317268	कोलारस	12	2.44
39	नीलेश कुमार	888110110009049	कोलारस	11	2.40
40	रामचरण बिस्कर्मा	80012248046	खनियाधाना	7	2.37
41	कमलकांत	63042809560	पोहरी	6	2.30
42	रचना बाई	32390260545	कोलारस	13	2.27
43	राजेश	34558648239	पिछोर	8	2.23
44	ऋचा बाई	888110110001235	कोलारस	13	2.20
45	प्रियंका बाई	34283367236	कोलारस	13	2.20
46	राकेश लोधी	20290179879	कोलारस	14	2.19
47	मंजू	33849310004	पिछोर	6	2.19
48	अतरसिंह	888110110000235	कोलारस	12	2.18
49	अहशान	4921000034510	खनियाधाना	4	2.16
50	पुरुषोत्तम	31418045030	कोलारस	12	2.14
51	राजकुमार	888110110007175	कोलारस	7	2.14
52	राघवेंद्र सिंह	916010029306564	कोलारस	7	2.14
53	नीलेश	5977108000034	कोलारस	9	2.13
54	उपै धाकड़	63034166775	कोलारस	8	2.05
55	अभिलाषा	906510410000185	खनियाधाना	4	2.04
56	बलराम यादव	80012654681	खनियाधाना	7	2.04
57	शिशुपाल लोधी	32107167247	खनियाधाना	6	1.95
58	बलबीर सिंह ठाकुर	8025803387	खनियाधाना	7	1.94
59	ज्योति	80028929648	खनियाधाना	5	1.94
60	नीलेश बाई	32908090099	कोलारस	11	1.94
61	दिनेश	31786775869	कोलारस	7	1.93
62	दिनुआ	31569307344	कोलारस	9	1.88
63	राजा बाबू	80028210863	खनियाधाना	5	1.87
64	अनिल कुमार	36315315168	कोलारस	12	1.85
65	मेहरबान	172001963466	खनियाधाना	5	1.85
66	अमित कुमार	53037143750	कोलारस	7	1.85
67	साधना बाई कोमलबाई	945210110014168	कोलारस	8	1.83
68	रामस्वरूप	33168381503	कोलारस	9	1.82
69	रामकुमार	32333564610	खनियाधाना	7	1.82
70	सेवराज पाल	8025803489	खनियाधाना	5	1.78
71	परसराम लोधी	80011502559	खनियाधाना	6	1.78
72	गायत्री गुप्ता	31713108132	कोलारस	8	1.76
73	सुरेंद्र (बैंक में मनोज साहू)	80030160609	खनियाधाना	4	1.74
74	सुरेश	32518271079	खनियाधाना	3	1.74
75	बृजमोहन	31902390198	कोलारस	7	1.72
76	तुलसीराम	172002289063	खनियाधाना	5	1.72

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया	अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
77	कलावती	172002289007	खनियाधाना	5	1.72
78	हरिचरण	63002319787	कोलारस	5	1.71
79	रघुबीर	34413506685	पोहरी	8	1.70
80	सुनील	8028574771	खनियाधाना	4	1.59
81	शैल वर्मा	50150081046337	कोलारस	6	1.59
82	माजो	2567000100101728	खनियाधाना	4	1.56
83	पराग	3389003597	कोलारस	5	1.55
84	अर्चना	613202010006582	कोलारस	7	1.55
85	बचन लाल पुत्र मानाराम धाकड़	53029555673	कोलारस	7	1.55
86	गजेन्द्र	31014417576	कोलारस	6	1.53
87	दिलीप सिंह	31494306547	कोलारस	6	1.53
88	रागराज	8025846275	खनियाधाना	6	1.50
89	सोनुआ सोमा	30209039686	कोलारस	8	1.48
90	मलखान आदिवासी	34754527572	खनियाधाना	6	1.47
91	राकेश	2567000100102745	खनियाधाना	4	1.46
92	सियाराम लोधी	80002437317	खनियाधाना	5	1.45
93	मीना बाई	888110310000712	कोलारस	7	1.44
94	मोहर सिंह यादव	8025839176	खनियाधाना	4	1.43
95	रविंद्र	53021014041	पिछोर	7	1.42
96	रामबती अहिरवार	8025813862	खनियाधाना	7	1.41
97	विश्वनाथ	10547318223	कोलारस	5	1.40
98	कल्पना गोहरी	63051903005	कोलारस	6	1.39
99	हरिशंकर शर्मा	32633962111	खनियाधाना	4	1.39
100	स्नेहा	3483729032	कोलारस	4	1.38
101	रिंकू रघुवंसी	3305700518	कोलारस	8	1.38
102	अभिषेक	34312218491	पिछोर	4	1.37
103	अपर्णा	888110510000691	कोलारस	4	1.37
104	रजनी	32666280200	खनियाधाना	4	1.37
105	हजारी	888110110007160	कोलारस	5	1.35
106	बबीता	945110110014678	कोलारस	9	1.35
107	कणिका	38529321933	कोलारस	4	1.35
108	निब्बा	80012329377	खनियाधाना	5	1.35
109	रतिराम	33690838155	खनियाधाना	5	1.34
110	हक्की	80023903034	पोहरी	6	1.33
111	रामप्यारी लोधी	172000471306	खनियाधाना	5	1.33
112	रणधीरा	33461631153	पिछोर	6	1.32
113	अमरचंद	34681578303	पोहरी	5	1.32
114	मेहरून बानो	3162121006549	खनियाधाना	3	1.31
115	आदेश	32092586088	खनियाधाना	4	1.30
116	अतरसिंह	34658542079	पोहरी	6	1.30

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया	अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
117	धर्मेन्द्र	80030447377	खनियाधाना	3	1.29
118	बेजनाथ	34419418477	पोहरी	6	1.28
119	सीताराम	672057018388	खनियाधाना	4	1.27
120	संजय कुमार	31046773692	कोलारस	4	1.26
121	विश्वनाथ	28301515153	कोलारस	4	1.23
122	रेखा देवी	16810100092567	कोलारस	6	1.21
123	प्रगति सिंह	4760101000203	कोलारस	4	1.21
124	अशरफी	888110110014522	कोलारस	3	1.21
125	विनीत सिंह	63042974953	कोलारस	5	1.21
126	दौजा (बैंक में नंदलाल धाकड़)	34500408928	पोहरी	6	1.18
127	दिनेश (बैंक में गीता देवी)	53021050567	पिछोर	4	1.17
128	सिलवन्ती	172001987295	पिछोर	4	1.16
129	लक्ष्मी बाई	906510110009574	खनियाधाना	5	1.16
130	रामेश्वर	3162191036668	कोलारस	4	1.16
131	गुनिया	80002753740	खनियाधाना	6	1.13
132	रामेश्वर पचावाला	917010042486253	कोलारस	5	1.11
133	राजेश	63011006693	खनियाधाना	2	1.10
134	बद्री (बैंक में प्राणीलाल अहिरवार)	34688023206	पिछोर	6	1.03
135	भूपत आदिवासी	8025812961	खनियाधाना	6	1.02
136	लक्ष्मी बाई	31029300831	खनियाधाना	5	1.00
137	आरती	31888627087	खनियाधाना	4	0.96
138	सोराव	32699663613	पिछोर	4	0.95
139	संजीव	919010028862864	कोलारस	3	0.88
140	अवतार	63035306815	पोहरी	8	0.87
141	जशोदा	919010028862709	कोलारस	3	0.86
142	रश्मी गुप्ता	172000493681	पिछोर	3	0.86
143	राजकुमारी	919010028862819	कोलारस	3	0.84
144	रेवाराम	919010028862848	कोलारस	3	0.83
145	सोनाली	945110110008424	कोलारस	4	0.83
146	दीपक	919010028862712	कोलारस	3	0.82
147	बबीता बाई	2964001500031005	कोलारस	4	0.82
148	रामकिशन	919010028862615	कोलारस	3	0.82
149	गीता बाई	919010028862411	कोलारस	3	0.81
150	राकेश	8025812790	खनियाधाना	2	0.81
151	रामनिवास	919010028862466	कोलारस	3	0.80
152	गोलू सिंह	919010028862660	कोलारस	3	0.80
153	मलखान	34500408587	पोहरी	5	0.79
154	रामरतन	919010028862372	कोलारस	3	0.79
155	महेंद्र यादव	32436612536	खनियाधाना	3	0.78

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया	अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
156	केदारी	919010028862440	कोलारस	3	0.78
157	मुनेश	919010028862644	कोलारस	3	0.77
158	सुरेश (बैंक में, श्रीमान अध्यक्ष जे.एम.एम. एस.एच.जी. वाचोन)	53021034997	पिछोर	3	0.72
159	बाबूलाल	80002494490	खनियाधाना	5	0.72
160	लालाराम	37088179662	पिछोर	5	0.67
161	अखंचा	34312218605	पिछोर	2	0.66
162	देवेन्द्र	63001213975	कोलारस	3	0.65
163	तेज प्रकाश	34497795305	पिछोर	4	0.61
164	शिशुपाल	32045908092	पोहरी	6	0.57
योग				1030	277.30

(स्रोत: कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूचियां और बिल)

परिशिष्ट-2.1.5 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 29)

शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में वेतन एवं अन्य मदों से
संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण का विवरण

स. क्र.	कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया	खाता संख्या	आई.एफ. एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	लेखा शीर्ष
1	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	26-04-21	1,324	एफ.वी.सी. बिल/ 20009226844	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
2	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	17-06-21	17,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20009588346	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
3	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	19-02-21	4,600	एफ.वी.सी. बिल/ 20008578943	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
4	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	04-02-21	13,549	एफ.वी.सी. बिल/ 20008461092	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
5	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	23-06-20	15,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20006478215	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
6	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	19-02-21	19,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20008579019	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
7	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	28-02-20	3,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20005729795	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
8	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	28-02-20	2,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20005730635	2053-00-094-9999- 0619-00000000-33
9	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	28-02-20	1,750	एफ.वी.सी. बिल/ 20005730465	2053-00-094-9999- 0619-00000000-22
10	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	11-02-19	27,483	एरियर बिफोर 2006/ 20002368193	2029-00-102-9999- 2503-00000000-11
11	सफीक मोहम्मद	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	23-06-20	26,606	वेतन बिल / 20006477363	2053-00-094-9999- 0619-00000000-11
12	सुनीता रावत	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	30-06-20	27,603	वेतन बिल / 20006532063	2029-00-103-9999- 1472-00000000-11
13	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	03-08-19	20,000	वेतन बिल / एरियर/ 20003772913	2029-00-103-9999- 1472-00000000-11
14	मणिकांत जैन	67206303 7552	सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई	मणिकांत जैन	12-07-19	20,000	वेतन बिल / एरियर/ 20003636729	2029-00-103-9999- 1472-00000000-11

स. क्र.	कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया	खाता संख्या	आई.एफ. एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	लेखा शीर्ष
15	कैलाशनारायण बड़ौदी	672063037552	सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई	मणिकांत जैन	21-11-19	59,716	वेतन बिल / 20004801768	2053-00-094-9999-0619-00000000-11
16	पवन कुमार शर्मा	8025230933	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
17	संतोष	8025230933	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	08-02-22	19,875	एफ.वी.सी. बिल/ 200011609502	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
18	संतोष	8025230933	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	08-02-22	19,500	एफ.वी.सी. बिल/ 200011609638	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
19	कप्तान सिंह यादव	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	28-01-22	28,548	वेतन बिल / 200011469523	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
20	दीपक गुप्ता	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
21	ज्योति राठोर	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
22	अनिल कुमार स्वर्णकार	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
23	आशा धाकड़	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	24,408	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
24	दिनेश स्वर्णकार	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
25	अंबेत सिंह जाटव	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,678	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
26	संतोष	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	11-02-19	77,020	एरियर बिफोर 2006/ 20002368134	2053-00-094-9999-0619-00000000-11
27	देवेन्द्र सिंह गौड़	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	05-07-21	21,202	वेतन बिल / 20009765357	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
28	देवेन्द्र सिंह गौड़	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	17-06-21	7,067	वेतन बिल / 20009584827	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
29	देवेन्द्र सिंह गौड़	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	05-07-21	14,832	वेतन बिल / 20009765337	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
30	संतोष	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	17-06-21	18,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20009588374	2053-00-094-9999-0619-00000000-22

स. क्र.	कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया	खाता संख्या	आई.एफ. एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	लेखा शीर्ष
31	संतोष	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	09-04-20	75,000	अनुदान/ 20006020943	2245-80-800-9999-5504-00000000-51
32	संतोष	8025230993	एसबीआईएन0आरआरएमबीजीबी	श्रीमती संगीता जैन	19-02-21	7,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20008579170	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
33	संतोष शर्मा	20463936985	एसबीआईएन0030086	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
34	पूजा शर्मा	20463936985	एसबीआईएन0030087	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,678	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
35	स्मि लक्ष्मी शर्मा	20463936985	एसबीआईएन0030088	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	32,018	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
36	विक्रम रावत	20463936985	एसबीआईएन0030089	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
37	सुनीता रावत	20463936985	एसबीआईएन0030090	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	38,948	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
38	रवि कुमार वर्मा	20463936985	एसबीआईएन0030091	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
39	संदीप वर्मा	20463936985	एसबीआईएन0030092	श्रीमती संगीता जैन	25-11-21	28,703	वेतन बिल / 200010903530	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
40	राकेश यादव	20463936985	एसबीआईएन0030093	श्रीमती संगीता जैन	11-02-19	102,496	एरियर बिफोर 2006/ 20002369587	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
41	राकेश यादव	20463936985	एसबीआईएन0030094	श्रीमती संगीता जैन	11-02-19	77,020	एरियर बिफोर 2006/ 20002368134	2053-00-094-9999-0619-00000000-11
42	राकेश यादव	20463936985	एसबीआईएन0030095	श्रीमती संगीता जैन	26-11-19	100,000	अनुदान /20004841599	2245-80-800-9999-6097-00000000-44
43	योगेन्द्र शर्मा	20308583620	एसबीआईएन0030086	यश कुमार जैन	03-11-21	22,482	वेतन बिल / 200010798109	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
44	अभिषेक मिश्रा	20308583620	एसबीआईएन0030087	यश कुमार जैन	01-11-21	16,398	वेतन बिल / 200010718332	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
45	राजेश कुमार धाकड़	20308583620	एसबीआईएन0030088	यश कुमार जैन	28-01-22	28,703	वेतन बिल / 200011469531	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
46	अशोक कुमार मिश्र	20308583620	एसबीआईएन0030089	यश कुमार जैन	01-11-21	32,908	वेतन बिल / 200010718288	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
47	विवकानंद शर्मा	20308583620	एसबीआईएन0030090	यश कुमार जैन	01-11-21	20,332	वेतन बिल / 200010718398	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
48	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030091	यश कुमार जैन	11-02-19	77,020	एरियर बिफोर 2006/ 20002368134	2053-00-094-9999-0619-00000000-11
49	पुष्पिता शर्मा	20308583620	एसबीआईएन0030092	यश कुमार जैन	05-07-21	15,241	वेतन बिल / 20009765372	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
50	पुष्पिता शर्मा	20308583620	एसबीआईएन0030093	यश कुमार जैन	17-06-21	15,241	वेतन बिल / 20009584840	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
51	रामस्वरूप आदिवासी	20308583620	एसबीआईएन0030094	यश कुमार जैन	29-04-20	132,591	वेतन बिल / 20006112869	2053-00-094-9999-0619-00000000-11

स. क्र.	कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया	खाता संख्या	आई.एफ. एस.सी. कोड	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	लेखा शीर्ष
52	रामस्वरूप आदिवासी	20308583620	एसबीआईएन0030095	यश कुमार जैन	28-04-20	25,800	वेतन बिल / 20006112504	2053-00-094-9999-0619-00000000-11
53	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030096	यश कुमार जैन	17-06-21	17,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20009588473	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
54	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030097	यश कुमार जैन	17-06-21	18,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20009588299	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
55	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030098	यश कुमार जैन	09-04-20	75,000	अनुदान/ 20006020943	2245-80-800-9999-5504-00000000-51
56	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030099	यश कुमार जैन	19-02-21	16,000	एफ.वी.सी. बिल/ 20008579125	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
57	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030100	यश कुमार जैन	22-05-19	18,485	एफ.वी.सी. बिल/ 20003208955	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
58	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030101	यश कुमार जैन	26-11-19	90,000	अनुदान/ 20004841599	2245-80-800-9999-6097-00000000-44
59	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030102	यश कुमार जैन	28-02-20	12,820	एफ.वी.सी. बिल/ 20005729977	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
60	भगत सिंह	20308583620	एसबीआईएन0030103	यश कुमार जैन	28-02-20	11,150	एफ.वी.सी. बिल/ 20005730260	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
61	रामकुमार	917010074182077	यूटीआईबी 0001022	हर्ष कुमार जैन	25-03-22	19,950	एफ.वी.सी. बिल/ 200012011699	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
62	रामकुमार	917010074182077	यूटीआईबी 0001023	हर्ष कुमार जैन	28-01-22	19,925	एफ.वी.सी. बिल/ 200011488069	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
63	रामकुमार	917010074182077	यूटीआईबी 0001024	हर्ष कुमार जैन	16-11-21	10,000	एफ.वी.सी. बिल/ 200010844368	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
64	रामकुमार	917010074182077	यूटीआईबी 0001025	हर्ष कुमार जैन	28-01-22	19,850	एफ.वी.सी. बिल/ 200011487789	2053-00-094-9999-0619-00000000-22
65	माला दुबे	917010074182077	यूटीआईबी 0001026	हर्ष कुमार जैन	28-01-22	28,199	वेतन बिल / 200011469517	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
66	गजन लाल बाथम	917010074182077	यूटीआईबी 0001027	हर्ष कुमार जैन	17-12-21	26,135	वेतन बिल / 200011129212	2053-00-094-9999-0619-00000000-11
67	जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव	917010074182077	यूटीआईबी 0001028	हर्ष कुमार जैन	17-12-21	46,492	वेतन बिल / 200011129177	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
68	रानू कुशवाह	917010074182077	यूटीआईबी 0001029	हर्ष कुमार जैन	13-01-22	32,411	वेतन बिल / 200011384066	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
69	अमित गुप्ता	917010074182077	यूटीआईबी 0001030	हर्ष कुमार जैन	17-12-21	27,024	वेतन बिल / 200011129195	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
70	राजेंद्र प्रसाद ओझा	917010074182077	यूटीआईबी 0001031	हर्ष कुमार जैन	28-01-22	20,348	वेतन बिल / 200011469510	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
71	सुनीता	1431797916	सीबीआईएन 0280780	कंप्यूटर प्रो श्रीमती सुनीता	11-02-19	154,000	एरियर बिफोर 2006/ 20002369587	2029-00-103-9999-1472-00000000-11
योग						22,86,753		

(स्रोत: तहसीलदार, पोहरी द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.6

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 30)

देवास जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण राहत वितरण का विवरण

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	अजय गणपत	63046327822	अजय चौधरी	कलेक्टर	13	3.05
2	किरण चौधरी	892610110001326	अजय चौधरी	कलेक्टर	22	4.99
3	अजय चौधरी और शांतिलाल पुत्र सालगराम	892610110004990	अजय चौधरी	कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द	17	3.78
4	अजय गणपत	520101201851357	अजय चौधरी पुत्र गणपत	कलेक्टर	12	2.85
5	गणपत चौधरी	154000442530	गणपत	कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द	17	3.04
6	गणपत चौधरी	892618210003157	गणपत चौधरी	कलेक्टर	13	3.01
7	गणपत उमराव सिंह	11210110000063	गणपत सिंह	कलेक्टर	15	3.26
8	सरोज विजय चौधरी	892618210003030	सरोज विजय चौधरी	कलेक्टर	13	2.94
9	सौरमन बाई गणपत	892618210003165	सौरमन बाई पुत्र गणपत चौधरी	कलेक्टर	14	2.94
10	विजय चौधरी	31852475475	विजय गणपत	कलेक्टर	12	2.90
11	विजय गणपत	892610110003278	विजय पुत्र गणपत	कलेक्टर	13	3.05
12	लकड़ीबाई हरबकस	13310100005057	लडकीबाई पुत्री हरबाई पत्नी महेन्द्र मंडलोई	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	20	2.45
13	लाडकी मंडलोई और लाडकीबाई हरबकस	654118021376	लडकीबाई गुर्जर पत्नी महेन्द्र मंडलोई	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	10	1.74
14	शुभम मंडलोई	891410510001088	शुभम मंडलोई	तहसीलदार खातेगांव	17	1.89
15	राहूल मंडलोई और रमेश राधेश्याम	892310110000914	राहूल मंडलोई पुत्र महेन्द्र मंडलोई	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	16	2.10
16	महेन्द्रराधेश्याम	13310100005004	महेन्द्र सिंह	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	15	1.17
17	सुरेश नर्मदा प्रसाद	154005913801	राहूल मंडलोई पुत्र महेन्द्र मंडलोई	तहसीलदार खातेगांव	12	1.91

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
18	रामबाई राधेश्याम और रामबाई नाथू	654118003606	रमाबाई मंडलोई पत्नी राधेश्याम	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	11	1.61
19	राहुल पुत्र महेंद्र	13310100004241	राहुल पुत्र महेंद्र	तहसीलदार खातेगांव	8	1.04
20	राजेंद्र मंडलोई और राजेंद्र राधेश्याम	892310110001828	राजेंद्र सिंह, राधेश्याम मंडलोई	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	10	1.36
21	सुलोचना शिवराम	154004541264	सुलोचना बाई पत्नी राजेंद्र मंडलोई	तहसीलदार खातेगांव	9	1.21
22	जुगलाय गोविंद	53031515035	महेंद्र सिंह मंडलोई	तहसीलदार खातेगांव	8	0.71
23	रामनिवाश	53031503629	श्री दिनेश कुमार सिसौदिया	कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव	11	1.33
24	चेनसिंह और अजुध्या बाई	891410510000708	विशाल सिसिदिया पुत्र दिनेश सिसौदिया	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	14	2.27
25	कमल और पंकजवरम	35378266440	श्रीमती रेखाबाई सिसौदिया	कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव	12	0.86
26	राहुल लालसिंह	919010064625478	राहुल कर्मा	कलेक्टर	4	1.36
27	प्रीति	5680101002721	प्रीति कर्मा पत्नी राहुल कर्मा	कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद	11	3.50
28	दीपिका	208000100218420	दीपिका ठाकुर पुत्री लाल सिंह कर्मा	कलेक्टर	4	1.29
29	ताराबाई लालसिंह	53031530018	ताराबाई कर्मा	कलेक्टर	4	1.50
30	अमित कुशवाह और अनिल मोहन	891410110002005	अमित कुशवाह	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	4	0.84
31	बालराम देवा और सिलाबाई रामचंद	5680101000527	अमित कुशवाह	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	12	1.97
32	नंदकिशोर शर्मा	53031542183	नंदकिशोर शर्मा	कलेक्टर	3	1.01
33	रतनलाल हाजरी	5680101002943	नंदकिशोर शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा	कलेक्टर	6	1.38

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
34	महेश बाबूलाल	5680101002945	सिद्धि पुत्री नंदकिशोर शर्मा	कलेक्टर	6	1.36
35	भागीरथ दशरथ और हेमराज हंसराज	13510110001703	रामचन्द्र सैनी	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	20	1.70
36	रतनसिंह हीरालाल और नब्बू बाई खुशाल	891410110005611	रामचन्द्र सोनी पुत्र मनोहर	कलेक्टर	15	2.71
37	तरनजाट	891210510001787	वैष्णव शर्मा	तहसीलदार सतवास	14	1.71
38	सीताराम श्रीराम और कामबाई अजय	892310110005128	सरस्वतीबाई पत्नी कैंडा	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	14	1.61
39	अजयसिंह शंकर, योगेश और बैथलीबाई बैशला	38791279477	श्री योगेश चौहान	कलेक्टर, तहसीलदार बागली एवं तहसीलदार कन्नौद	13	2.76
40	हरिराम बलदेव	891210110008991	छोटेलाल पुत्र नत्थूलाल पिपलोदिया	तहसीलदार सतवास	13	0.94
41	दिनेश	20238112434	श्री राकेश जोनवाल	तहसीलदार सतवास	13	0.75
42	पेवन हरिप्रसाद	63019761717	श्री कपिल बेनीवाल पुत्र मोडूराम	कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव	12	2.49
43	शिवनारायण लक्ष्मीनारायण और रामोतार मायाराम	13510110001438	दुर्गा पत्नी राम विलास	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	12	2.02
44	रामनारायण और बालमुकुंद राजेंद्र पुत्र बाबूलाल	892310310000001	कुलदीप गुर्जर	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	12	1.83
45	रामभरोसे भेरा	33213921222	कुमारी दीपिका भास्कर पुत्री महेश भास्कर	कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द	12	1.40
46	शिशुपालसिंह	20254492797	श्री दीपेन्द्र सोलंकी	तहसीलदार सतवास	12	1.25
47	नबूलाल	413102010012523	नितिन विश्कर्मा	तहसीलदार सतवास	11	1.51

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
48	गणपतराव आनंदराव और प्रेमनारायण बाबूलाल	31553866355	कुमारी आरती पुत्री महेश भास्कर	कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द	11	1.36
49	कर्ण पिता गणपत, संतोषी बाई और सुरेश मनीराम	20341015249	श्री करण गणपति उड़के	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	11	1.01
50	धन्नीबाई और करण	20238112105	श्री पुनम चंद्र	तहसीलदार सतवास	11	0.72
51	रोहित प्रकाश और रामोतार रामनिवाश	34072350357	श्री अजय पँवार	कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव	11	0.59
52	तपनकुमार मनलक्रांति	63004105230	श्री शिवराम कन्हयालाल	तहसीलदार खातेगांव	11	0.57
53	विष्णु गुर्जर एवं गोसिन्द	13310400004385	विष्णु गुर्जर	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	10	2.23
54	कोशलया बाई पत्नी हरिनारायण और लाइकुंवरबाई	1512092842	नंदिनी बागवान	कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द	10	1.70
55	सोन् चंदर	63000915770	प्यारसिंह सोलंकी	तहसीलदार सतवास	8	0.49
56	कृष्ण वेबा तुलसीराम	33959693488	कुमारी मुस्कान शर्मा	कलेक्टर	6	1.11
57	अरमान मालदार, अरमान और गोविंदप्रसाद हरिशंकर	34006046800	रामकृष्ण सैनी पुत्र मनोहर सैनी	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	5	1.68
58	कांताबाई हरिशंकर	53031503471	दिलीपसिंह यादव	तहसीलदार खातेगांव	5	0.70
59	नारायणदास	654106017975	पृथ्वीराज पुत्र सूर्यदमन	कलेक्टर	4	1.40
60	छोटी बाई	654116035620	रामेश्वर सोलंकी	तहसीलदार सतवास	4	1.32
61	रवीन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह	3254956486	धर्मन्द्र सिंह	कलेक्टर	1	16.90
योग					669	126.13

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.7

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 30)

छतरपुर जिले में रिफंड, सूखा एवं अतिवृष्टि संबंधी बिलों के माध्यम से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर ई-भुगतान किया गया	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	गणेशी बाई और ओम नारायण	2612215612	बुन्देलखण्ड विकास निधि लिमिटेड	10	4.74
2	मुकेश राममिलन	3249294803	वैभव खरे	38	6.00
3	महेश मोहनलाल	20254462467	वैभव खरे	37	5.76
4	शुकदा वरव	20304285051	रोहित प्रभाकर	15	1.47
5	नट्टू रज्जुपाल	20306095919	लीला अहिरवार	14	0.97
6	जयसिंह छतहीदीन लोधी	20355970408	राजेंद्र राजपूत	10	0.55
7	रामोतार बुधुवा पाल	30350236320	अजय कुमार नाहर	29	3.43
8	रामदेवी पत्नी अरविन्द्र कुशवाह	30371079349	मनोज कुमार कुशवाह	9	0.71
9	शम्भू देशा	32778781752	कुमारी बबीता अहिरवार	13	2.99
10	कुरा	33613649376	नत्थू अहिरवार	10	0.66
11	रामबहोरी रजोला राजेश उमरी	80004644060	मीरा तिवारी	9	0.54
12	बलुवा मिडवा	80006903953	चन्द्र प्रकाश तिवारी	10	0.95
13	रमकू दो घसीटा	80013384826	मनोज कुमार कुशवाह एवं अभिलाषा	23	1.81
14	अहमद कुजादा	58510100004519	रविशंकर रावत	8	1.02
15	शिवनन्दन पुत्र भवानीदीन	64820100001944	कौशलेंद्र वर्मा	9	1.39
16	कल्लू रघुनाथ	594502010001192	लीला अहिरवार पुत्री भगवान	14	0.91
17	सचिन	594502010018583	सचिन रावत पुत्र रविशंकर रावत	7	0.96
18	आनंद	594502010023078	हिरदाश रावत पुत्र रामकुमार रावत	8	1.22
19	कलुवा	594502010024123	यश रावत	7	1.39
20	दुर्जा प्रजापति	1424001500004137	नरेंद्र कुमार वर्मा	34	4.49
योग				314	41.96

(स्रोत: कलेक्टर, छतरपुर और तहसीलदार, गौरिहार द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.8

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

खंडवा जिले की खालवा तहसील में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर राशि आहरित की गई	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या
1	नाटू झापू	11255020989	एसबीआईएन0001472	भगवान सिंह	02-01-20	48,124	अनुदान /20005209921
					02-01-20	49,574	अनुदान/20005163538
					22-12-20	27,500	अनुदान/20007995366
2	शिवलाल भुता	27410410013929	बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी	भगवान सिंह	31-12-20	48,101	अनुदान/20008098833
					23-12-20	27,500	अनुदान/20008005531
					31-12-20	48,101	अनुदान/20008098178
					31-12-20	48,101	अनुदान/20008098103
					01-01-21	48,101	अनुदान/20008100645
					01-01-21	48,101	अनुदान/20008102074
					31-03-21	48,101	अनुदान/20009058713
					28-05-21	48,100	अनुदान/20009457839
3	बाबूलाल शिवराम	36893642014	एसबीआईएन0004517	नरेंद्र सिंह	02-01-20	47,854	अनुदान/20005174989
					20-11-19	5,000	एम.पी.टी.सी. 66/20004797987
					27-12-19	49,854	अनुदान/20005105200
					20-08-20	13,200	एम.पी.टी.सी. 66/20006941782
					30-12-20	47,101	अनुदान/20008073830
					01-01-21	48,101	अनुदान/20008102262
					01-01-21	48,101	अनुदान/20008102586
					02-01-21	27,500	अनुदान/20008142838
					01-01-21	48,101	अनुदान/20008102779
					25-03-21	27,500	अनुदान/20008927807
					31-03-21	47,101	अनुदान/20009046246
					31-03-21	48,101	अनुदान/20009046114
					31-03-21	48,101	अनुदान/20009054786
4	हरिओम लखनलाल	952510410000408	बीकेआईडी0009525	नरेंद्र सिंह	22-12-20	39,200	अनुदान/20007996745
					28-12-20	44,100	अनुदान/20008041125
					25-03-21	39,200	अनुदान/20008928258
					25-03-21	44,100	अनुदान/20008925132
कुल						11,61,619	

(स्रोत: आई.एफ.एम.आई.एस. से निकली भुगतान आदेश सूचियां और बैंकों से प्राप्त के.वाई.सी.)

परिशिष्ट-2.1.9 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ और सीतामऊ तहसीलों में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण-
लाभार्थियों के नामों में विसंगति

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
मल्हारगढ़ तहसील					
1	सूरजबाई बापूसिंह	20395244266	दीपक व्यास	26	2.56
2	कमलकुमार बापूलाल	31902581922	दिलीप शर्मा	22	2.43
3	राधाबाई मगीलाल	35208645491	बीना व्यास	24	2.68
4	खुमानसिंह नाथूसिंह	50150008903	चंद्रा	22	2.06
5	लीलाबाई बेवा कवरलाल	50157482379	जीतेन्द्र व्यास	19	3.11
6	रामचंद्र कचरू	50248124171	प्रहलाद	16	1.86
7	जमना बर्थ शंकरलाल	63050510707	नरेंद्र सिंह जाट	19	1.82
8	प्रताप सिंह लाल सिंह	162001912904	गोपाल जाट	23	1.24
9	रमेश चंद्र भेरूलाल कुलमी	162002135367	ललिता देवी व्यास	23	1.68
10	मोहनलाल सीताराम	162006174540	रतनबाई गायरी	15	1.57
11	नवलसिंह भवरसिंह	5561101000517	जीतेन्द्र व्यास	7	1.90
12	रामकिशन पिता हरिशचंद्र	5561101002192	दिलीप कुमार शर्मा	23	1.62
13	रामकिशन कारूलाल	5561101002209	बलराम शर्मा	20	1.71
सीतामऊ तहसील					
14	श्रीमहंत श्याम भारती	162001962354	गोविंद मोड़	8	1.40
15	कारूलाल पिता रामलाल	162006165376	बालमुकुंद पुत्र रामचन्द्र	7	1.41
16	बापू सिंह	162010600494	हरि सिंह गुर्जर	7	2.16
योग				281	31.21

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.9 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध
कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक राहत का भुगतान किया गया	खाता संख्या	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	राजेंद्र कवरलाल	32551718084	18	1.57
2	अभिषेक भंवरलाल	33785984870	15	1.64
3	बलराम कृष्ण	35217808718	35	3.67
4	आजाद कुंवर लक्ष्मणसिंह	59161205780	17	1.40
5	गोपाल प्यारचंद	63051502173	26	2.41
6	प्रेम बाई दुर्गाशंकर	5561101000124	30	2.25
7	देवीलाल पिता हरिराम	5561101002168	24	1.31
8	कलुआ सिंह भेरुआ सिंह	203471010003196	19	2.15
9	वीरम सिंह हरिसिंह	203471010005197	17	1.93
10	माया मदनलाल	203471030037311	27	3.07
योग			228	21.40

(स्रोत: तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)

परिशिष्ट-2.1.9 (ग)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील में रिफंड बिलों से संदिग्ध कपटपूर्ण निकासी

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्तियों के नाम जिनके नाम पर जाली रिफंड बिल तैयार किया गया	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक अभिलेख में अनधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम मिला	भुगतान दिनांक	राशि का भुगतान र में	रिफंड बिल संदर्भ संख्या	टिप्पणी
1	राधेश्याम	913310310000627	बीकेआईडी0009133	राधेश्याम नकुम	21-05-21	63,784	20009405265	वह एक कर्मचारी है जिसने जाली रिफंड बिलों के माध्यम से कपटपूर्ण निकासी की और इसे अपने और तीन रिश्तेदारों के खातों में जमा किया। असफल लेनदेन रिपोर्ट में, न तो उनके और न ही उनके तीन रिश्तेदारों के नाम पर कोई राशि असफल पाई गई।
					07-05-21	50,000	20009348043	
					22-06-21	64,192	20009637989	
					16-07-21	64,192	20009859882	
					27-10-21	27,336	200010644068	
					22-10-21	10,080	200010609099	
					29-01-21	100,000	20008354635	
					23-02-21	50,000	20008605680	
					18-02-21	30,000	20008569000	
17-03-21	48,600	20008831272						
2	विशाल	3692573302	सीबीआईएन0281819	विशाल	07-05-21	25,000	20009348043	राधेश्याम नकुम के रिश्तेदार
					21-05-21	18,720	20009405265	
					22-06-21	44,064	20009637989	
					16-07-21	44,064	20009859882	
					22-10-21	86,496	200010609099	
					27-10-21	69,538	200010644068	
					29-01-21	20,000	20008354635	
					23-02-21	25,000	20008605680	

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्तियों के नाम जिनके नाम पर जाली रिफंड बिल तैयार किया गया	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक अभिलेख में अनधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम मिला	भुगतान दिनांक	राशि का भुगतान ₹ में	रिफंड बिल संदर्भ संख्या	टिप्पणी
					18-02-21	20,000	20008569000	
					25-03-21	5,000	8932455	
					17-03-21	27,810	20008831272	
					11-12-20	30,000	20007932618	
3	कमलाबाई	913310110000643	बीकेआईडी0009133	कमला बाई	21-05-21	63,784	20009405265	राधेश्याम नकुम के रिश्तेदार
					07-05-21	37,000	20009348043	
					22-06-21	47,736	20009637989	
					16-07-21	47,736	20009859882	
					27-10-21	65,688	200010644068	
					22-10-21	64,192	200010609099	
					29-01-21	95,000	20008354635	
					23-02-21	35,000	20008605680	
					25-03-21	2,100	8932455	
					11-12-20	25,000	20007932618	
4	अजय राधे	32534576671	एसबीआईएन0030061	अजय कुमार	07-05-21	3,200	20009348043	राधेश्याम नकुम के रिश्तेदार
					21-05-21	14,080	20009405265	
					22-06-21	35,360	20009637989	
					16-07-21	35,360	20009859882	
					22-10-21	16,800	200010609099	
					27-10-21	16,000	200010644068	
					29-01-21	95,000	20008354635	
					23-02-21	20,000	20008605680	
					11-12-20	45,000	20007932618	
योग						16,87,912		

(स्रोत: तहसीलदार, सीतामऊ द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूचियाँ और असफल लेनदेन प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-2.1.10 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

रायसेन जिले में राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	जिस तहसील से सम्बंधित	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	बाबूलाल	3174594232	अनुराग राजपूत	बेगमगंज	9	3.22
2	बाबूसी शीलाबाई	3239696163	नत्थू सिंह दांगी	बेगमगंज	5	1.16
3	चंदन पुत्र फूल सिंह	3717497520	रुचि राजपूत	सुल्तानपुर	8	1.71
4	रामसेवक पुत्र लक्ष्मण	3717499877	कृष्णा सिंह	सुल्तानपुर	10	2.29
5	जगदीश पुत्र रामदयाल	3743710775	अमितेश सिंह राजपूत	सुल्तानपुर	8	2.80
6	भावर	3749892690	राम रानी	बेगमगंज	5	1.21
7	प्रीतम शिवलाल आ परम	20189412680	प्रशांत राज	बेगमगंज	15	1.30
8	सुरेश हो कोमल बाई	20312908011	संजय सिंह चौहान	सुल्तानपुर	8	1.41
9	कुलदीप	30954360341	कुलदीप शर्मा	बेगमगंज	14	1.75
10	भगवती बाई	31623511509	शोभा बाई कानस	बेगमगंज	37	9.95
11	राकेश पुत्र हरिशंकर	32558670520	रमेश कुमार शर्मा	सुल्तानपुर	5	1.89
12	कुन्दन पुत्र भवानी	34996119851	शुभम शर्मा	सुल्तानपुर	5	2.27
13	दयाशंकर जगन्नाथ जा	35379757391	श्रीमती कमलेश अठिया	बेगमगंज	5	1.26
14	गया प्रसाद	36180552469	मनोज सृष्टि	बेगमगंज	12	2.39
15	रूपसिंह	36613439649	मास्टर निखिल कनाश	बेगमगंज	8	3.82
16	मुन्ना माखन	165000753927	चैन सिंह	बेगमगंज	5	1.32
17	बाबूलाल पुत्र बलिराम	4773101001100	सचिन कुमार मुजाल्दा	सुल्तानपुर	10	1.33
18	माधो प्रसाद रमानाथ	201251030000483	राधेश्याम पुत्र रामनाथ	बेगमगंज	6	1.80
19	थानसिंह	201461030037427	कुलदीप शर्मा पुत्र गोविंद शर्मा	बेगमगंज	14	2.30
20	अभय जसवन्त	900610110007147	रूप सिंह	बेगमगंज	12	3.68
21	श्रीबाई पत्नी नन्हेबाई यादव	942210510000575	ऋषिराज राजपूत	बेगमगंज	7	1.27
22	प्रहलाद	942210510000710	शिवांक राजपूत पुत्र रूपसिंह	बेगमगंज	6	1.27
योग					214	51.40

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.10 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

रायसेन जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय राहत का भुगतान किया गया	खाता संख्या	तहसील	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	सविता बाई	3190260242	बेगमगंज	5	1.21
2	ब्रजमोहन, कृष्णपाल और संतोष	27810049190	उदयपुरा	6	1.42
3	राघवेन्द्रसि पिता त्रिलोकसि	32529798239	बेगमगंज	3	0.54
4	पासोत्तम	33752494771	बेगमगंज	4	1.05
5	जयराम	35519156279	बेगमगंज	10	3.40
6	मुन्नीलाल पुत्र गोरेलाल	37873979859	गौरतगंज	3	0.07
7	राम बाबू	165000259654	बेगमगंज	4	0.80
8	सुनीता बाई	282501002474	बेगमगंज	2	0.65
9	गजराज	665003005317	बेगमगंज	4	0.95
10	दरयाबासिह, राजरानी और राजकुमार	50100087126832	बेगमगंज	6	4.97
11	सुनीता और विजय	50100106430181	बेगमगंज	7	4.60
12	जशरथ भरोसे	50100106430372	बेगमगंज	6	4.34
13	अजेंद्र और अभय	50100305566409	बेगमगंज	8	3.64
14	कुंजना सिंह	201251010000968	बेगमगंज	2	0.61
15	चेनसिंह अर्जन सिंह यादव	201251010001982	बेगमगंज	11	1.28
16	बीरेंद्र सिंह	201251010003200	बेगमगंज	4	0.40
17	पंचमासी	201251030130104	बेगमगंज	3	0.91
18	पूरन सिंह	201461010001676	बेगमगंज	7	1.55
योग				95	32.39

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)

परिशिष्ट-2.1.11 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 32)

दमोह जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	कडोरी	37834461700	प्रेमलता पटेल	कलेक्टर	5	2.03
2	बोलाराम	50296261520	राम शंकर पुत्र राम चंद्र त्रिपाठी	कलेक्टर	11	1.96
3	रामनाथ	30933211008224	आकाश मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा	कलेक्टर	7	1.39
4	अशोक	8015055310	लटोरी लखेरा	कलेक्टर	7	1.19
5	भगवानदास पटेल	390802010004388	किशोरीलाल पुत्र मोतीलाल पटेल	कलेक्टर	3	1.17
6	विक्रम	594602010022124	जनकरानी कुर्मी पत्नी रमेश	कलेक्टर	14	0.98
7	कमल	10408951777	वहाबुद्दीन राईन	कलेक्टर	7	0.96
8	कुंदन	3519153458	समीना पत्नी शेख रियाज खान	कलेक्टर	3	0.87
9	श्याम	594702010011344	मधुकान्त उपाध्याय	कलेक्टर	8	0.71
10	गोपाल	3166268027	अंजना पत्नी लटोरी लखेरा	कलेक्टर	8	0.61
11	पंनु	594602010017531	रमेश प्रसाद कुर्मी	कलेक्टर	11	0.47
12	प्यारेलाल	35606149637	मु आशिक	कलेक्टर	1	0.30
योग					85	12.64

(स्रोत: कलेक्टर दमोह एवं बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.11 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 32)

दमोह जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय राहत का भुगतान किया गया	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	लटोरी लखेरा	2101689604	कलेक्टर	13	2.20
2	अंजनी	20469146562	तहसीलदार पटेरा	19	1.27
3	रजनीकांत	30362075039	तहसीलदार पटेरा	19	1.34
4	राजेश कुमार शुक्ला	31069373790	कलेक्टर	2	0.32
5	माधुरी	31304449203	तहसीलदार पथरिया	4	0.83
6	माधव सिरोठिया	32148732188	कलेक्टर	1	0.30
7	पवन	32736315973	तहसीलदार पटेरा	19	1.35
8	पार्वती	33090664290	तहसीलदार पटेरा	17	1.24
9	भारत	33436694704	तहसीलदार पटेरा	20	1.78
10	राज (बैंक में राम सिंह ठाकुर)	75801503218	कलेक्टर	4	1.29
11	कनछेदी इमारत	179000044522	कलेक्टर एवं तहसीलदार दमोह	13	3.31
12	रामशंकर पुत्र रामचंद	179000124088	कलेक्टर	2	0.43
13	कडोरी	679168005430	कलेक्टर	2	0.37
14	श्याम	594702010011344	कलेक्टर	1	0.19
15	महंत, मुन्नी और राजेश	990001500002255	कलेक्टर एवं तहसीलदार पथरिया	16	2.09
योग				152	18.31

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)

परिशिष्ट-2.1.12

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 32)

सतना जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय राहत का भुगतान किया गया था	खाता संख्या	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	होरिल प्रसाद	8075020001	9	1.21
2	होरिल प्रसाद	59061740946	7	1.06
3	होरिल प्रसाद	10115810285	9	1.13
4	कौशल्या पत्नी होरिल प्रसाद	8075020012	7	1.16
5	कौशल्या पत्नी होरिल प्रसाद	59060536678	6	1.10
6	राजेश कुमार चर्मकार	30370901533	7	0.41
7	राम सकोची गौतम	31833616909	4	1.65
8	प्रिया भारती	33190894470	8	1.30
9	रामसुफल साकेत	33412972497	6	1.24
10	सत्य नारायण पांडे पुत्र तेजपाल	355602010404284	4	0.85
11	मानवती साकेत	636902010014889	5	0.69
12	सतेंद्र प्रजापति	636902010015507	6	1.19
योग			78	12.99

(स्रोत: कलेक्टर, सतना द्वारा प्रदत्त भुगतान आदेश सूचियां एवं बिल)

परिशिष्ट-2.1.13 (क)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 33)

आगर-मालवा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	भगवानसिंह पुत्र इंदरसिंह और घीसी बाई पत्नी रामसिंह	956710110010296	मुकेश चौहान पुत्र मदनलाल	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	26	4.58
2	मंगू पुत्र भग्गा, देवीसिंह पुत्र गणपत और मोहन पुत्र रामलाल	956710110012042	केसर पत्नी मुकेश	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	22	2.75
3	पर्वतसिंह ऊंकारसिंह, मोतीलाल शिवसिंह, उदयसिंह	955618210025308	लाभ कुँवर परिहार पत्नी तूफान	कलेक्टर, तहसीलदार आगर एवं तहसीलदार बड़ौद	16	1.25
4	रायसिंह पुत्र मंगू	37172892783	शैलेन्द्र शिवनारायण	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	15	3.30
5	नारायण पुत्र राम और किशन पुत्र पुरा	956710110007520	मदनलाल चौहान	कलेक्टर	14	1.88
6	लालसिंह अमरसिंह और कमलाबाई पति हीरालाल	956810110002186	निर्भय सिंह पुत्र रामलाल	कलेक्टर एवं तहसीलदार सुसनेर	14	1.36
7	सिमरन पुत्र मोटलैब	39508578782	कुमारी सोनू सोनी	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	13	1.50
8	दुर्गालाल पुत्र घीसूलाल	39508593631	कुमारी पवित्रा बाई	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	13	2.01
9	कैलाश चंद्र शर्मा और राजेश पुत्र राधाकिशन	5625101000957	फूल सिंह	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	11	1.48
योग					144	20.11

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.13 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 33)

आगर-मालवा जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

स. क्र.	अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे राहत का भुगतान किया गया	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	मोइसिंह पुत्र सीताराम और रमेश पुत्र प्रभु	14110400008351	तहसीलदार नलखेड़ा एवं कलेक्टर	9	1.84
2	लाडसिंह पुत्र सीतारमन	171001111612	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	12	1.01
3	रामनारायणगे	63003299768	कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा	9	0.98
4	सजनबाई फतजी	171000336523	कलेक्टर	7	0.50
5	हीरालाल नारायणसिंह	171000451376	तहसीलदार नलखेड़ा	1	0.30
6	गोपाल सिंह दुलेसिंह	956118210003983	कलेक्टर	2	0.29
7	रमेशलाल मना बागरी	955618210008025	कलेक्टर	5	0.14
8	रमेश गुर्जर	956710110012429	कलेक्टर	2	0.13
योग				47	5.19

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)

परिशिष्ट-2.1.14

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 33)

विदिशा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में राशि का भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	गुलाब सिंह पुत्र गौरैलाल	53035963037	जय नारायण साहू	कलेक्टर	12	0.60
2	महेंद्र कुमार पुत्र गोविंद प्रसाद शर्मा	34349263723	राज कुमार जाटव	कलेक्टर	7	1.31
3	बसोरा सोडु पुत्र अल्मा	53039550672	मिट्टू सिंह सोलंकी	कलेक्टर	7	0.56
4	महेश जयराम पुत्र गुलाबसिंह माला	31730595676	अरविन्द कुमार अहिरवार	कलेक्टर	5	0.77
5	तखत सिंह पुत्र चंदन सिंह उल्लाखेड़ा एवं रामराज सिंह पुत्र रामचरण धतुरिया	33332700727	तेज सिंह कोरी	कलेक्टर	5	0.77
6	शोभाराम पुत्र गुआम सिंह अंबर	34066543110	अनिल कुमार पंथी	कलेक्टर	5	0.75
7	यामीन नूर पुत्र हबीबनूर	9003101010001 88	जय नारायण साहू	कलेक्टर	10	1.18
8	कलाबाई पुत्री मेहरबान सिंह	3734020109927 41	सुनीता साहू पत्नी जय नारायण साहू	कलेक्टर	9	0.64
9	निर्मलकुमारी पत्नी पुरुषोत्तमन्	30650312631	आदित्य शर्मा	कलेक्टर एवं तहसीलदार कुरवाई	12	2.90
10	भगवान सिंह प्राण सिंह	34640840007	सोनू सेन अवधनारायण	कलेक्टर	16	2.28
11	अशोककुमार पुत्र कृपाराम मुंगवाड़ा	31870463682	राहुल दीक्षित	कलेक्टर	6	1.94
12	राकेश गोवर्धन और रमेश	31988799905	सोनू बाबू सेन	कलेक्टर	12	1.67
13	तलत पत्नी आरिफ अली खुजरहार	31101722852	प्रीति राजपूत	तहसीलदार गुलाबगंज	10	1.67
14	देवी सिंह पुत्र बाबूलाल मुंगवारा	6460101000017 55	जीतेन्द्र पांडे	तहसीलदार गुलाबगंज	9	1.61
15	गोरव पुत्र वीरेन्द्रकुमा	53048857615	वीरेंद्र कुमार शर्मा	कलेक्टर	4	1.54
16	खिलान सिंह पुत्र बाबूलाल मह्आखेड़ा	20436498591	श्रीमती रीता जैन	तहसीलदार गुलाबगंज	19	1.46
17	नरसिंहदास राम विलास	9035101100081 96	मनीष सेन पुत्र हकुम सिंह	तहसीलदार गुलाबगंज	9	1.45

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में राशि का भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
18	सुम्मा पुत्र इमरत सिंह करैया	30597542393	महेश अहिरवार	तहसीलदार गुलाबगंज	6	1.39
19	अमरसिंह पुत्र उरेद सिंह और यश पुत्र आरके	31912591236	कुमारी मोनिका नामदेव	कलेक्टर	6	1.26
20	राजमल पुत्र मिश्रलाल	31497241257	लीला बाई पंथी	तहसीलदार कुरवाई	4	1.25
21	कृष्ण मुरारी पुत्र सखाराम	31706366077	सुनील मोघे	तहसीलदार कुरवाई	8	1.24
22	पोमप्रकाश पुत्र मुंशीलाल मुंगवाड़ा	53031883021	दिनेश कुमार दीक्षित	तहसीलदार गुलाबगंज	8	1.24
23	राजाराम पुत्र निर्भया सिंह	906610110000787	मनीष प्रजापति पुत्र धनराज	तहसीलदार गुलाबगंज	6	1.22
24	आयशा बानो पत्नी तुराबाखाम	6195101000654	बबीता पंथी	तहसीलदार कुरवाई	6	1.21
25	हकुमचंद पुत्र श्रीलाल और कल्याण पुत्र मंगलिया	34542426789	जीवनलाल जाटव	कलेक्टर	7	1.21
26	छत्रपाल पुत्र बलवंत सिंह महुआखेड़ा	32720076938	मनीष प्रजापति	तहसीलदार गुलाबगंज	8	1.20
27	जानकीबाई पुत्री दोजा	3117000100084977	जय नारायण पुत्र मूलचंद	कलेक्टर	11	1.18
28	कमलकुमार सागरमल अनल कुमार पुत्र मुल्ला	995710110006847	प्रीती जाटव पुत्र चुन्नी लाल	कलेक्टर	7	1.15
29	चैनसिंह और मान सिंह पुत्र धनजी	31930727460	ललिता बाई	कलेक्टर	4	1.10
30	विनायकरा गोविंदराव	6195101003443	पद्माकर मोघे	कलेक्टर	5	1.09
31	बन्नेखाम पुत्र अल्लीखाम	35168975580	साविर खा	कलेक्टर	7	1.08
32	खुमणसिंह पुत्र लालजीराम आदि	4048001500018036	लाखन सिंह जाटव	कलेक्टर	7	0.93
33	शांति बाई पुत्री जसाराम	6195101002534	राजमल शर्मा	कलेक्टर	4	0.90
34	पूरणिया धन्ना पुत्रगण मर्दन	33599771862	दुर्गा बाई	कलेक्टर	4	0.85
35	प्रागसिंह रघुवीरसिंह प्रहलाद	53029671043	महाराज एस ठाकुर	कलेक्टर	4	0.83
36	रुघनाथसिंह पुत्र हरलाल	4048001500006778	प्रदीप कुमार जाटव	कलेक्टर	5	0.83
37	रूप सिंह मालम सिंह	32572026655	शनमिया श्री	कलेक्टर	5	0.69
38	जानकी बाई पत्नी परमानंद	1818446085	गर्जेद्र सिंह	कलेक्टर	5	0.61
39	फोल बाई पत्नी फेरन सिंह आदि	35200859090	श्रीमती आशा सेन	कलेक्टर	5	0.55

स. क्र.	लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई	खाता संख्या	बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में राशि का भुगतान किया गया	डी.डी.ओ.	खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
40	मल्लो बाई पत्नी उंकार सिंह	31943025445	भूपेन्द्र सिंह	कलेक्टर	5	0.54
41	एसमोहन पुत्र श्रीनिवासन आदि	63056179755	प्रदीप कुमार जाटव	कलेक्टर	4	0.50
योग					298	47.15

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.15

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 34)

शिवपुरी जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिससे कई लेनदेन किए गए	खाता संख्या	तहसील	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	रामस्वरूप	8021663749	बैराड़	5	1.35
2	दामोदर	8021664889	बैराड़	5	0.94
3	रवीन्द्र सिंह	8023156465	करेरा एवं नरवर	4	1.14
4	महेन्द्र	8025800091	खनियाधाना	3	0.79
5	रामजीलाल	20251703155	बैराड़	4	1.32
6	रामपाल	20308806218	खनियाधाना	3	1.29
7	समीना	20448534682	खनियाधाना	2	1.09
8	अरविन्द कुमार	30631617558	खनियाधाना	3	0.86
9	ममता साहू	31154992656	खनियाधाना	3	0.74
10	संदीप	31725686438	बदरवास	5	1.23
11	आदिराम	31798076639	खनियाधाना	4	1.39
12	महेश कुमार पाल	31866322615	करेरा एवं नरवर	8	1.44
13	रेखा	32385952205	पिछोर	4	0.98
14	संजय लोधी	33039106420	खनियाधाना	3	1.20
15	शिवकुमार	33451381894	बैराड़ एवं पिछोर	5	1.73
16	पर्वत और सिमवती	34089991802	पिछोर	11	2.48
17	अमन	34668446498	खनियाधाना	2	1.05
18	नरेश	35928522833	बैराड़	6	1.32
19	दीपक	37069429630	बैराड़	5	0.70
20	अरविन्द्र	37457429617	खनियाधाना	4	1.18
21	जयप्रकाश गुप्ता	53026748771	करेरा एवं नरवर	4	1.14
22	जगन्नाथ	53035099052	खनियाधाना	4	0.88
23	जयकुमार जैन	53035109313	खनियाधाना	7	1.74
24	कल्याण खंगार	63001272487	करेरा	5	0.94
25	केलाश नारायण	63025984442	बैराड़	5	1.08
26	शिवनारायण	63027094694	बैराड़	5	1.73
27	राकेश	63028079288	पोहरी	6	1.28
28	खलक सिंह	63040340010	पिछोर	6	1.74
29	रामेश्वरसिंह	63050145585	बैराड़	5	1.22
30	चंदाबैजनाथलावडी	80001230119	बदरवास	5	1.21
31	मेंडा	80005766246	बैराड़	5	1.21
32	जूली	80012162713	खनियाधाना	3	1.20
33	भूरी	80015611021	खनियाधाना	3	1.15
34	राहुल	80019499150	खनियाधाना	2	0.75
35	सलिकराम	80026724745	खनियाधाना	3	0.85

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिससे कई लेनदेन किए गए	खाता संख्या	तहसील	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
36	विद्या	80034471077	खनियाधाना	4	1.24
37	शिव कुमार	172000432980	पिछोर	6	1.08
38	अरविंद	172002289052	पिछोर	4	1.45
39	दीपक	2567000100067860	खनियाधाना	3	1.32
40	राजेंद्र कुमार	2567000100073840	खनियाधाना	6	0.82
41	रविंद्र	2567001700104640	खनियाधाना	3	1.39
योग				183	49.64

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदाय भुगतान आदेश सूचियां)

परिशिष्ट-2.1.16

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 34)

देवास जिले में एकाधिक लेनदेन के माध्यम से अनियमित संवितरण का विवरण

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए थे	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	बलराम रमाशंकर	50100009461827	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	19	2.25
2	रामोतार गब्बू	654117004179	तहसीलदार सतवास	17	1.72
3	हरिराम रामचन्द्र और रामसिंह किसान	13510400003264	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	17	1.56
4	रामेश्वर छोगालाल और सुनील	38550100007731	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	17	1.83
5	रेशम	654117003095	तहसीलदार सतवास	16	1.36
6	पप्पी रमेश	63053285203	कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद	15	4.63
7	अरविंद	154000751241	तहसीलदार सतवास	14	1.88
8	शुभम	891210310000026	तहसीलदार सतवास	14	1.12
9	बलराम धन्नालाल और चंदू बाई दिलीप सिंह	31879397802	तहसीलदार खातेगांव एवं कलेक्टर	12	2.83
10	रेखा बाई और सुखराम	38558100009894	तहसीलदार खातेगांव एवं कलेक्टर	12	1.59
11	रामचन्द्र मनोहर और शिवगिरि धनगिरि	31499583844	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	10	1.51
12	मेरा	63052937523	कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद	10	3.21
13	रामेश्वर हजारी	654105042131	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	10	3.34
14	हसनाबाई कमलसिंह	13510110000465	कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव	8	2.03
15	मुकेश साहू	63023127490	कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद	7	2.07
16	गोपाल बाबू रामू	10056888553	कलेक्टर	6	1.13
17	राहुल	50100233205111	कलेक्टर	4	1.40
योग				208	35.46

(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूची)

परिशिष्ट-2.1.17

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 35)

देवास जिले की बागली तहसील में अनियमित वितरण का विवरण

स. क्र.	व्यक्ति का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई राशि ₹ में	बिल संदर्भ संख्या	योजना शीर्ष
1	तेजपाल सिंह मेहरबान सिंह	154000399808	सीबीआईएन0एमपीडीसी एजे	27-04-21	30,000	20009221666	ओला-वृष्टि
2	मनोहरलाल हरि सिंह	891710110002290	बीकेआईडी 0008917	20-07-21	30,000	20009782564	ओला-वृष्टि
3	श्वेता रामलाल	20143638511	एफआईएनओ000144 6	27-09-21	75,000	200010330723	ओला-वृष्टि
4	सेवती बाई चेनशिंग	12411010003170	बीकेआईडी0एनएएमआ रजीबी	21-10-21	400,000	200010604639	ओला-वृष्टि
5	धनसिंह बुड़का	12411010002979	बीकेआईडी0एनएएमआ रजीबी	02-11-21	400,000	200010765487	ओला-वृष्टि
6	सरदार भुवनसिंह	124110410001985	बीकेआईडी0एनएएमआ रजीबी	02-11-21	55,000	200010765728	ओला-वृष्टि
7	अन्नासिंह	37709341829	एसबीआईएन0030165	17-11-21	40,000	200010837816	ओला-वृष्टि
8	हकुम सिंह भगवत सिंह	154002253959	सीबीआईएन0एमपीडीसी एजे	21-03-22	25,000	200011986868	ओला-वृष्टि
9	रामशिंग गुलाब	44538100008235	बीएआरबी0बीएजीएलआ ईएक्स	31-01-22	25,000	200011527185	ओला-वृष्टि
योग					10,80,000		

(स्रोत: तहसीलदार, बागली द्वारा प्रदाय अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.18

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 35)

विदिशा जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	संतोष पत्नी अरविंद	675020004624	कलेक्टर	18	2.55
2	राजेंद्र सिंह	1818430438	कलेक्टर	11	2.39
3	अशोक पालीवाल पुत्र डालचंद	175000952180	कलेक्टर	10	1.14
4	आसबाई पत्नी सुनील अहिरवार	34252924251	कलेक्टर	9	1.56
5	दीपिका पत्नी अरविंदा सिंह	175000349205	कलेक्टर	9	1.62
6	उदय सिंह पुत्र तूफान सिंह	373402010010737	कलेक्टर	8	0.79
7	राजवीर	3117000100225980	कलेक्टर	5	0.86
8	भैरो सिंह पुत्र कोमल सिंह	3154035594	कलेक्टर	7	0.76
9	कोमल पुत्र हिम्मत	20203720474	कलेक्टर	7	0.72
10	संस्कार चौकसे	33159181082	कलेक्टर	7	0.98
11	फिदा मो	53033162438	कलेक्टर	7	0.76
12	इदरीश खा	175000741351	कलेक्टर	7	2.13
13	राजेस सिंह	175000824216	कलेक्टर	7	1.31
14	थान सिंह गुर्जर	175001508201	कलेक्टर	7	1.35
15	फूलबाई	175004525304	कलेक्टर	7	1.09
16	शान्तोष शर्मा	675020008754	कलेक्टर	7	0.75
17	जंग सिंह पुत्र जसवन्त सिंह	675024012407	कलेक्टर	7	0.91
18	चंद्रकिसन पुत्र चतर सिंह	21461930000806	कलेक्टर	7	0.99
19	राजेंद्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह	2004131010007320	कलेक्टर	7	0.78
20	विजय पुत्र मथुरालाल	20445209203	कलेक्टर	6	1.02
21	खलील पुत्र अजीज	31039672015	कलेक्टर	6	0.90
22	कृष्णपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह और पारावत सिंह	32854629789	कलेक्टर	6	1.03
23	गुलाम अहमद	34387663374	कलेक्टर	6	1.33
24	संजय रामगोपाल	53032419012	कलेक्टर	6	1.09
25	अब्दुल सलाम पुत्र मोकाहन	53033161514	कलेक्टर	6	1.18
26	साविर खान सरदार खान	53033169976	कलेक्टर	6	1.39
27	इरफान अली पुत्र रोशन अली	53035941207	कलेक्टर	6	1.22
28	खलील खान अब्दुल सत्तार खान	63045219783	कलेक्टर	6	1.05
29	कल्याणसिंह पुत्र दातारसिंह	63055108912	कलेक्टर	6	0.73
30	जयनारायण	175000365668	कलेक्टर	6	0.79
31	वसीम खाम पुत्र कासिम खाम	175000631484	कलेक्टर	6	0.84
32	फैलेराम खेमा	175000721083	कलेक्टर	6	0.79
33	रूप सिंह पुत्र अजब सिंह	175000812563	कलेक्टर	6	0.76
34	धीरजसिंह पुत्र उंकार सिंह	175001364868	कलेक्टर	6	0.75

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
35	हेत सिंह	675006006120	कलेक्टर	6	1.77
36	हरिनारायण पुत्र मोहर सिंह	675015034498	कलेक्टर	6	0.75
37	जालमसिंह पुत्र धीरजसिंह	675101018887	कलेक्टर	6	1.25
38	धीरज सिंह मीना	174500101003009	कलेक्टर	6	0.78
39	करण सिंह पुत्र बरजोर सिंह	684002010001616	कलेक्टर	6	0.75
40	कमर सिंह	2004171010005920	कलेक्टर	6	0.92
41	अमन सिंह पुत्र निरंजन सिंह	2307778354	कलेक्टर	5	1.26
42	नेताराम उर्फ तुलसीराम पुत्र सालकराम	11563395858	कलेक्टर	5	0.87
43	माखन सिंह पुत्र खुमान सिंह	31175561557	कलेक्टर	5	0.78
44	गफफार खान पुत्र अल्लादीन खान	31749343027	कलेक्टर	5	0.81
45	ब्रजमोहन	32185710829	कलेक्टर	5	0.83
46	गनी खान अब्दुल सतार खान	32887168570	कलेक्टर	5	0.82
47	जयमण्डल पुत्र बहारदार सिंह	36754584537	कलेक्टर	5	0.93
48	कामोद सिंह पुत्र धीरज सिंह और सोनू पुत्र कामोद सिंह	53033163612	कलेक्टर	5	0.94
49	महेंद्रपाल सिंह	63005750289	कलेक्टर	5	2.17
50	चारण गाओ पुत्र खेमचंद	63032116103	कलेक्टर	5	0.91
51	जसवंत सिंह पुत्र बाबूलाल	63036501837	कलेक्टर	5	1.12
52	सुनील पुत्र बंशीलाल अहिरवार	63038999293	कलेक्टर	5	1.29
53	गिरजाप्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद	63044726828	कलेक्टर	5	0.72
54	गुलाबबाई ब्रह्माण्ड और हमीर पुत्र नारायण	151000389246	कलेक्टर	5	0.79
55	महेश कुमार पुत्र हेतसिंह	175000272296	कलेक्टर	5	1.17
56	तेजेन्द्र पुत्र गुरुचरण सिंह बैरीघाट	175000703971	कलेक्टर	5	0.79
57	समंदर सिंह पुत्र नारायण सिंह	175000740288	कलेक्टर	5	0.83
58	छोटेलाल राजपूत	175000746406	कलेक्टर	5	0.94
59	राजेश भार्गव	175000796457	कलेक्टर	5	0.93
60	मोआरिफ खाम पुत्र अय्यूब खाम	175000807494	कलेक्टर	5	1.07
61	भानु पुत्र फूलसिंह	175000852969	कलेक्टर	5	0.77
62	उमर मोहम्मद खान	175000870499	कलेक्टर	5	1.21
63	ब्रजभानसिंह ठाकुर	175000961842	कलेक्टर	5	0.87
64	बारेलाल अमर सिंह	175001019196	कलेक्टर	5	0.92
65	अनवर खान	175001420803	कलेक्टर	5	0.95
66	लक्ष्मी बाई	175001456444	कलेक्टर	5	0.89
67	मोजफर अली पुत्र नबाब सरवर अली	175001595874	कलेक्टर	5	0.85
68	इंद्रजीत पुत्र बुंदेल सिंह	175001713764	कलेक्टर	5	0.88
69	लाखन सिंह	675015021886	कलेक्टर	5	1.17
70	गोवर्धन पुत्र कुन्दनलाल	675024008831	कलेक्टर	5	0.91
71	दीपक रघुवंशी	373402010994098	कलेक्टर	5	0.93
72	रूपा पत्नी धन्नालाल	680001500024853	कलेक्टर	5	0.88

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
73	अजयराव पुत्र नीलकंठराव और लक्ष्मीकांत राव पुत्र नारायण राव	2004171310005570	कलेक्टर	5	1.70
74	राजेंद्र सिंह बघेल और वरुण प्रताप पुत्र राजेंद्र सिंह	2671000100012960	कलेक्टर	5	2.12
75	सज्जाद हुसैन	3117000100010990	कलेक्टर	5	0.83
76	ब्रांदावन	1954503296	कलेक्टर	4	1.07
77	मशानराम पुत्र वलीराम	3261170484	कलेक्टर	4	1.07
78	कल्याण पुत्र भैया लाल	3599769335	कलेक्टर	4	0.80
79	कृष्णा बाई	3681372041	कलेक्टर	4	0.80
80	इंदर सिंह राजपूत	20336320996	कलेक्टर	4	0.82
81	देवेन्द्र रघुवंशी	30630444505	कलेक्टर	4	1.54
82	फेजुलहक पुत्र मो. इकबाल खान	31215754148	कलेक्टर	4	0.80
83	उमा देवी आदि पत्नी जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव सिमरहर	31447748243	कलेक्टर	4	0.97
84	यशवन्त पुत्र शिवप्रकाश	31610711841	कलेक्टर	4	0.78
85	जगदीश हजारीलाल	31716293878	कलेक्टर	4	0.75
86	अमोल सिंह पुत्र मंगल और रामकुमार पुत्र अमोल सिंह	31883069647	कलेक्टर	4	1.07
87	मलखान सिंह पाल	32128918270	कलेक्टर	4	0.91
88	राजेश अखलेश पुत्र गजराज सिंह रामप्यारी बेवा गजराज सिंह	32797592864	कलेक्टर	4	1.38
89	भोगीराम पुत्र पंचम	32924297733	कलेक्टर	4	0.90
90	अहमदुद्दीन	33876974857	कलेक्टर	4	0.84
91	ऋषभ कुमार पुत्र रतन चंद जैन	34672374071	कलेक्टर	4	0.75
92	ओमप्रकाश पुत्र बालाप्रसाद	53032397993	कलेक्टर	4	0.71
93	गणेशी बाई	53033168780	कलेक्टर	4	0.98
94	बृजेन्द्रकुमार	53037489813	कलेक्टर	4	0.73
95	शहीद बेग	53037725433	कलेक्टर	4	0.73
96	मोहम्मददीन खान पुत्र याकूब खान	53039523558	कलेक्टर	4	1.34
97	रघुवीर पुत्र रतनलाल	53039540574	कलेक्टर	4	1.14
98	इशाकखाम असफाक खाम	53048853892	कलेक्टर	4	1.11
99	उमर खान	63009666064	कलेक्टर	4	1.32
100	दिनेश पुत्र कृष्णानंद	100100005560	कलेक्टर	4	0.93
101	चंद्रेश उर्फ शुधीर तिवारी	175000131254	कलेक्टर	4	1.01
102	दलीप सिंह पुत्र चुन्नीलाल	175000268382	कलेक्टर	4	0.70
103	जयप्रकाश सिंह	175000269329	कलेक्टर	4	0.70
104	राजकुमार शुक्ल	175000278538	कलेक्टर	4	0.72
105	संजय पुत्र रामाबतार सिंह मामा रणजीत सिंह पुत्र हरिसिंह	175000280525	कलेक्टर	4	0.82
106	हरीबै पत्नी बटूला खाँ जानमबी	175000291195	कलेक्टर	4	0.71
107	गजेंद्र सिंह दांगी	175000316304	कलेक्टर	4	0.97

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
108	भूरेखां पुत्र मुंशीखां	175000318006	कलेक्टर	4	1.06
109	सैम मान सिंह बैगेल	175000343995	कलेक्टर	4	0.87
110	तिलकसिंह पुदेवेसिहादागे निग्राम मदा	175000350844	कलेक्टर	4	0.80
111	हरिकेश	175000365828	कलेक्टर	4	1.07
112	सलीम खाम पुत्र अहमद नूर खाम	175000385834	कलेक्टर	4	0.81
113	खिलान सिंह	175000395808	कलेक्टर	4	0.76
114	अरसद बेग पुत्र हनीफ बेग	175000415113	कलेक्टर	4	1.86
115	कल्याण सिंह पुत्र मोबत सिंह	175000424966	कलेक्टर	4	2.32
116	अमित	175000450077	कलेक्टर	4	0.83
117	अज़हरुद्दीन खान	175000659228	कलेक्टर	4	0.80
118	किशन सिंह पुत्र मोहन लाल	175000661838	कलेक्टर	4	0.90
119	रामकृष्ण पुत्र गजराज	175000867192	कलेक्टर	4	0.71
120	मान सिंह पुत्र नाथू	175000959708	कलेक्टर	4	1.12
121	केशव सिंह पुत्र नारायण सिंह	175001023157	कलेक्टर	4	1.13
122	इंद्रभान सिंह	175001078684	कलेक्टर	4	0.76
123	ईमाम	175001278436	कलेक्टर	4	2.00
124	विक्रम	175001459739	कलेक्टर	4	0.95
125	कृष्णमुरारि मोघेपुत्र सखाराम मोघे	175001513970	कलेक्टर	4	0.95
126	यादराम	175001547412	कलेक्टर	4	0.73
127	राधेश्याम यादव	175001652926	कलेक्टर	4	0.77
128	शरीफ खान रियाज खान	175005198613	कलेक्टर	4	0.70
129	अतीक खां पुत्र नामदारखां	175006006635	कलेक्टर	4	0.75
130	असलम खान पुत्र हमीद खान	675006013569	कलेक्टर	4	0.83
131	कमलसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत	675007010613	कलेक्टर	4	0.82
132	पूरणसिंह पुत्र विष्णुप्रसाद	675013005594	कलेक्टर	4	0.93
133	गोपाल उर्फ रामगोपाल	675016002385	कलेक्टर	4	0.74
134	मंदिर श्री देवलक्ष्मी	12890100002115	कलेक्टर	4	0.81
135	मो इसहाक खान पुत्र अच्छे खान	21461530001057	कलेक्टर	4	1.22
136	वीर सिंह पुत्र दयाराम आठसेमर	38920100004570	कलेक्टर	4	0.92
137	भानुप्रताप रघुवंशी	38920100005215	कलेक्टर	4	1.04
138	खालिद पुत्र इस्हाक	50100075296486	कलेक्टर	4	0.99
139	अलीम खान पुत्र बट्टू खान	50100205485483	कलेक्टर	4	0.82
140	शैलेन्द्र सिंह	373402010999038	कलेक्टर	4	0.89
141	चन्द्रभान पुत्र पूरण	520291016687421	कलेक्टर	4	0.72
142	पर्वतसिंह राजपूत	680000100139570	कलेक्टर	4	1.55
143	पवनकुमार पुत्र सीताराम	680000100208700	कलेक्टर	4	1.29
144	वीर सिंह	906610110007280	कलेक्टर	4	0.70
145	भगवान सिंह	2004171030051450	कलेक्टर	4	0.79
146	अजयराव पुत्र और राहुल पुत्र मदनराव	2004171310009050	कलेक्टर	4	1.15

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए	खाता संख्या	डी.डी.ओ.	खाते में किए गए लेनदेन की संख्या	खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में)
147	शांति बाई पत्नी छगन लाल	675007001552	कलेक्टर	3	1.40
148	पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र सालिगराम	50200020266100	कलेक्टर	3	1.35
149	पप्पू रामू अरविंद	175000880781	कलेक्टर	4	0.71
योग				749	152.57

(स्रोत: डी.डी.ओ. द्वारा प्रदाय भुगतान आदेश सूचियां)

परिशिष्ट-2.1.19

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.10, पृष्ठ क्रमांक 37)

खंडवा जिले में समितियों के खातों में ₹164.31 करोड़ जमा करने का विवरण

स. क्र.	सहकारी समिति का नाम	समिति का खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.	जमा की गई राशि (₹ लाख में)
1	सेवा सहकारी समिति सुलगांव	659014038223	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	893.20
2	सेवा सहकारी समिति बांगरदा	659008000046	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	812.09
3	सेवा सहकारी समिति बोराडी	659010026038	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	666.56
4	सेवा सहकारी समिति मोहना	659010030044	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	555.65
5	सेवा सहकारी समिति भोगावा	659014038303	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	549.37
6	सेवा सहकारी समिति रिछफल	659009000034	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	522.67
7	सेवा सहकारी समिति पुनासा	659009000023	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	519.39
8	सेवा सहकारी समिति खुटलकला	659010026027	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	518.77
9	सेवा सहकारी समिति मुंदी	659008000104	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	513.62
10	सेवा सहकारी समिति दौलतपुरा	659009000045	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	496.80
11	सेवा सहकारी समिति चीचली	659008000080	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	432.55
12	सेवा सहकारी समिति जामकोटा	659008000126	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	424.20
13	सेवा सहकारी समिति भगवानपुरा	659008000091	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	398.48
14	सेवा सहकारी समिति गौल	659014038245	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	397.32
15	सेवा सहकारी समिति धामनगांव	659009000012	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	383.55
16	सेवा सहकारी समिति फिफ्राड	659010026129	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	357.40
17	सेवा सहकारी समिति पलसूद	659008000013	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	343.14
18	सेवा सहकारी समिति सक्तापुर	659009000056	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	317.68
19	सेवा सहकारी समिति जलकुवा	659008000024	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	315.95
20	सेवा सहकारी समिति अटूटखास	659010026152	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	314.17
21	सेवा सहकारी समिति सोमगांव	659008000035	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	254.54
22	आदिम जाति सेवा सह समिति पड़लिया	659020059324	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	229.91
23	सेवा सहकारी समिति गुडदा	659008000079	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	225.09
24	आदिम जाति सेवा सह समिति खालवा	659016000401	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	205.14
25	सेवा सहकारी समिति बीड	659008000068	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	187.19
26	आदिम जाति सेवा सह समिति खेड़ी	659019010315	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	181.99
27	आदिम जाति सेवा सह समिति आशापुर	659018000170	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	179.96
28	आदिम जाति सेवा सह समिति खरकला	659019010291	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	177.82
29	आदिम जाति सेवा सह समिति धावडी	659020059346	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	169.87
30	सेवा सहकारी समिति सदियापानी	659018000261	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	146.83
31	सेवा सहकारी समिति बड़केश्वर	659009000067	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	145.70
32	सेवा सहकारी समिति बोरीसराय	659018000136	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	144.43
33	सेवा सहयोगी समीरि गंभीर	659017029770	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	136.10
34	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सहजला	659011000031	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	133.47
35	आदिम जाति सेवा सह समिति सुकवि	659019010337	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	127.46

स. क्र.	सहकारी समिति का नाम	समिति का खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.	जमा की गई राशि (₹ लाख में)
36	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भामगढ़	659004017805	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	124.30
37	सेवा सहकारी समिति किलोद	659017029816	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	115.99
38	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिंहड़ा	659011000020	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	115.54
39	सेवा सहकारी समिति सोमगांव	659017029861	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	115.17
40	सेवा सहकारी समिति छनेरा	659018000272	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	111.50
41	सेवा सहकारी समिति घोघलगांव	659014038278	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	101.60
42	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कालमुखी	659010029845	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	100.70
43	सेवा सहकारी समिति बोथिया खुर्द	659018000169	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	95.46
44	सेवा सहकारी समिति बरुद	659018000147	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	89.16
45	आदिम जाति सेवा सह समिति कलामखुर्द	659016000036	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	88.27
46	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बडगाओगुर्जर	659004017816	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	87.25
47	आदिम जाति सेवा सह समिति देवलिकला	659019010304	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	86.97
48	सेवा सहकारी समिति बिल्लोद	659017029792	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	85.49
49	आदिम जाति सेवा सह. समिति रोशनी	659020059335	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	84.26
50	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अहमदपुरखैगांव	659004017758	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	83.52
51	सेवा लाभकारी समिति पूर्ण	659008000115	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	82.83
52	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भगवानपुरा	659007000014	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	81.79
53	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अत्तार	659010029709	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	78.56
54	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित केहलारी	659011000053	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	76.13
55	सेवा सहकारी समिति मर्यादित मण्डी शाखा खण्डवा	659004017736	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	73.11
56	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जावर	659011000019	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	72.81
57	आदिम जाति सेवा सह समिति गुलाईमल	659016000423	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	72.17
58	सेवा सहकारी समिति रेवापुर	659018000318	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	68.97
59	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बरुद	659006000151	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	67.41
60	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जसवाडी	659004017792	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	67.10
61	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खिदगाओ	659007000058	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	61.15
62	सेवा सहकारी समिति पिपलानी	659017029872	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	59.30
63	आदिम जाति सेवा सह समिति कोठा	659016000025	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	57.52
64	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रमेश्वर	659004017747	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	54.12
65	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रणगांव	659011000064	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	52.14

स. क्र.	सहकारी समिति का नाम	समिति का खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.	जमा की गई राशि (₹ लाख में)
66	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छैगांवखान	659006000173	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	51.10
67	सेवा सहकारी समिति मर्यादित आरुद तहसील पंधाना	659005000027	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	49.09
68	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पिपलोद	659012006429	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	48.58
69	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धनगांव	659006000162	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	47.95
70	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रामपुरा	659007000047	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	47.30
71	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कोहडद	659013002649	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	47.21
72	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पाडलिया	659007000069	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	46.52
73	सेवा सहकारी समिति इमलानी	159000211379	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	45.65
74	सेवा सहकारी समिति दगड़खेड़ी	659018000158	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	45.14
75	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुड़ीखेड़ा	659012003767	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	44.76
76	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुगवाड़ा	659010046827	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	44.40
77	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिरा	659004017770	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	44.24
78	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित टेमीकला	659004017769	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	43.85
79	जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित समिति पोखरकला	659006000139	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	43.67
80	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित हर्षवाड़ा	659006000140	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	43.46
81	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कुमठा	659012006236	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	42.63
82	आदिम जाति सेवा सह समिति कलामखुद	659016000412	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	40.11
83	सेवा सहकारी समिति मर्यादित घाटाखेड़ी	659005000016	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	39.86
84	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंधाना तहसील पंधाना	659005000049	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	39.36
85	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बडगांवमाली	659004017781	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	39.19
86	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़	659012005890	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	39.07
87	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित चमाति	659006000128	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	38.89
88	सेवा सहकारी समिति मर्यादित रुस्तमपुर तहसील पंधाना	659013002650	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	36.25
89	सेवा सहकारी समिति बोरखेड़ा	659008000057	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	36.18
90	सेवा सहकारी समिति मर्यादित दीवाल तहसील पंधाना	659005000038	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	35.90

स. क्र.	सहकारी समिति का नाम	समिति का खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.	जमा की गई राशि (₹ लाख में)
91	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित हीरापुरा	659012003756	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	35.40
92	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरगांव बुजुर्ग	659013002638	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	34.02
93	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सैयदपुर तहसील पंधाना	659005000050	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	33.80
94	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बलवाड़ा	659007000036	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	33.36
95	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंधवा	659007000070	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	33.14
96	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बामंदा	659012003778	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	32.82
97	सेवा सहकारी मंडला	659011000042	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	32.11
98	आदिम जाति सेवा सह समिति सेधवाल	659016000503	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	31.91
99	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नहल्दा	659004017827	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	29.98
100	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिंगोट	659007000025	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	28.62
101	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित चिचगोहन	659010046838	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	26.78
102	आदिम जाति सेवा सह समिति खोथ	659016000615	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	25.65
103	सेवा सहकारी समिति खुड़िया	659017029805	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	22.11
104	सहकाई समिति आवल्या खरवा	659006000117	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	19.13
105	सेवा सहकारी समिति मालूद	659017029781	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	16.83
106	सेवा सहकारी समिति मर्यादित छैगांव माखन तहसील खंडवा	659006000173	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	14.98
107	आदिम जाति सेवा सह समिति धावड़ी	659016011572	सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर	11.26
योग				16,430.61

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूचियां और मिलान प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-2.1.20

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.10.2, पृष्ठ क्रमांक 38)

सहकारी समितियों और तहसीलदारों के आंकड़ों के बीच ₹ 8.28 करोड़ की विसंगति का विवरण

स. क्र.	समिति का पंजीकरण क्रमांक	सहकारी समिति का नाम	समिति का खाता संख्या	तहसीलदारों द्वारा 2019-21 में किया गया कुल भुगतान (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार 2019-21 में समितियों द्वारा प्राप्त कुल राशि (₹ लाख में)	तहसीलदारों द्वारा भुगतान की गई राशि और समितियों द्वारा दी गई जानकारी के बीच अंतर (₹ लाख में)
1	78	सेवा सहकारी समिति अटूटखास	659010026152	314.17	117.49	196.68
2	327	सेवा सहकारी समिति बांगरदा	659008000046	812.09	632.89	179.20
3	646	सेवा सहकारी समिति सोमगांव	659008000035	254.54	115.17	139.38
4	241	सेवा सहकारी समिति जलकुवा	659008000024	315.95	219.76	96.19
5	172	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सहजला	659011000031	133.47	93.74	39.73
6	200	सेवा सहयोगी समीरि गंभीर	659017029770	136.10	98.80	37.30
7	234	सेवा सहकारी समिति बिल्लोद	659017029792	85.49	57.13	28.36
8	674	आदिम जाति सेवा सह समिति खरकला	659019010291	177.82	152.65	25.17
9	64	जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित समिति पोखरकला	659006000139	63.50	63.35	0.15
10	614	सेवा सहकारी समिति पिपलानी	659017029872	59.30	45.71	13.60
11	744	सेवा सहकारी समिति किलोद	659017029816	115.99	102.57	13.42
12	581	सेवा सहकारी समिति बोथिया खुर्द	659018000169	95.46	86.63	8.83
13	1551	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित केहलारी	659011000053	76.13	67.45	8.68
14	715	सेवा सहकारी समिति खुडिया	659017029805	22.11	14.60	7.51
15	431	सेवा सहकारी समिति बरुद	659018000147	89.16	82.60	6.55
16	477	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कालमुखी	659010029845	100.70	94.33	6.37
17	490	सेवा सहकारी समिति भोगावा	659014038303	549.37	543.11	6.26
18	228	सेवा सहकारी समिति मालूद	659017029781	16.83	13.29	3.54
19	546	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिंहड़ा	659011000020	115.54	112.50	3.04
20	820	सेवा सहकारी समिति दौलतपुरा	659009000045	496.80	495.30	1.50
21	499	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पिपलोद	659012006429	48.58	47.67	0.91
22	418	सहकाई समिति आवल्या खरवा	659006000117	19.13	18.30	0.83
23	233	सेवा सहकारी समिति पलसूद	659008000013	343.14	342.53	0.60
24	701	सेवा सहकारी समिति दगड़खेड़ी	659018000158	45.14	44.56	0.59

स. क्र.	समिति का पंजीकरण क्रमांक	सहकारी समिति का नाम	समिति का खाता संख्या	तहसीलदारों द्वारा 2019-21 में किया गया कुल भुगतान (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार 2019-21 में समितियों द्वारा प्राप्त कुल राशि (₹ लाख में)	तहसीलदारों द्वारा भुगतान की गई राशि और समितियों द्वारा दी गई जानकारी के बीच अंतर (₹ लाख में)
25	425	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जावर	659011000019	72.81	72.27	0.54
26	550	सेवा सहकारी समिति मर्यादित दीवाल तहसील पंधाना	659005000038	35.90	35.43	0.46
27	773	सेवा सहकारी समिति गौल	659014038245	397.32	397.03	0.29
28	443	सेवा सहकारी समिति मर्यादित आरुद तहसील पंधाना	659005000027	49.09	48.81	0.29
29	1552	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रणगांव	659011000064	52.14	51.89	0.25
30	413	सेवा सहकारी समिति छनेरा	659018000272	111.50	111.28	0.22
31	440	सेवा सहकारी समिति मर्यादित घाटाखेड़ी	659005000016	39.86	39.66	0.21
32	417	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिंगोट	659007000025	28.62	28.43	0.19
33	710	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सैयदपुर तहसील पंधाना	659005000050	33.80	33.62	0.18
34	1550	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नहल्दा	659004017827	29.98	29.83	0.15
35	682	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंधाना तहसील पंधाना	659005000049	39.36	39.21	0.15
36	799	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बडगांवमाली	659004017781	39.19	39.08	0.11
37	829	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित हीरापुरा	659012003756	35.40	35.31	0.10
38	642	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंधवा	659007000070	33.14	33.04	0.09
39	397	सेवा सहकारी समिति बोरखेड़ा	659008000057	36.18	36.10	0.08
40	782	सेवा सहकारी समिति इमलानी	159000211379	45.65	45.57	0.07
41	620	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भामगढ़	659004017805	124.30	124.27	0.03
योग				5,690.75	4,862.96	827.80

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और समितियों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.21

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.15, पृष्ठ क्रमांक 44)

तहसीलदारों द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से परे किए गए भुगतान का विवरण

स. क्र.	जिला	तहसीलदार	बिल सन्दर्भ संख्या	बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है	₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1	आगर मालवा	आगर	20006296207	1	0.59
			20006727058	11	8.30
			20007391097	2	1.36
			20009018274	1	0.79
			20009023396	1	0.59
			20009042130	1	0.83
			20006095142	4	3.16
			20006297202	3	2.07
			20006471505	4	2.57
			20007146235	3	2.05
			20007345635	1	0.52
			बड़ौदा	20004916450	1
		20004916553		1	0.52
		20004918993		2	1.10
		20004919677		2	1.36
		20005580551		22	14.10
		20005581752		8	5.29
		20005583350		13	7.35
		20005583797		4	2.50
		20005584488		9	7.43
		20005585443		11	7.82
		20005585738		15	9.36
		20005586401		10	6.30
		नलखेड़ा	20005972907	5	3.35
			20006657177	6	4.05
			20002568983	129	111.68
			20002583955	99	93.60
			20002583962	32	29.73
			20002596115	112	106.92
			20002598580	18	16.10
			20002599163	79	68.77
			20002601008	69	67.52
			20002601037	11	9.65
			20002622100	15	11.50
			20002688041	16	12.67

स. क्र.	जिला	तहसीलदार	बिल सन्दर्भ संख्या	बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है	₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
			20002696407	87	68.65
			20002697909	31	27.91
			20002699714	13	10.58
			20002933980	28	23.55
			20004764169	28	17.51
			20004764232	11	7.23
			20004923712	4	2.76
			20004925191	18	11.71
			20004925225	26	17.29
		नलखेड़ा	20005427267	9	7.09
			20005439316	3	2.35
			20005473284	8	5.27
			20005597615	4	3.06
			20005597725	2	2.02
			20005598205	1	0.59
			20005599387	2	1.19
			20005626338	7	5.25
		सुसनेर	20005421227	36	25.15
			20005425489	155	104.94
			20005430821	44	30.49
			20005513903	173	120.56
			20005580531	131	93.92
			20005583506	224	152.44
			20005610016	73	53.60
			20005616078	53	38.41
			20005637214	27	19.51
			20005654860	1	0.71
			20005671876	11	7.34
			20006677215	20	14.62
			20007211196	11	9.37
		20008998083	1	1.19	
		20008998200	1	0.53	
2	मन्दसौर	मल्हारगढ़	20004489119	5	3.20
			20004489676	1	0.51
			20004495856	3	1.88
			20004503490	10	6.81
			20004505025	12	8.14
			20004506890	6	4.58
			20004507969	5	3.08

स. क्र.	जिला	तहसीलदार	बिल सन्दर्भ संख्या	बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है	₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
			20004522334	29	21.72
			20004524696	1	0.72
			20004524928	8	5.46
			20004525125	4	2.34
			20004526410	17	11.45
			20004528404	5	3.04
			20004528818	2	1.37
			20004529199	11	6.97
			20004530039	2	1.31
			20004530060	14	10.76
			20004530120	6	4.26
			20004530161	4	2.84
			20004530545	4	3.54
			20004531038	4	2.13
			20004531145	3	1.81
			20004531426	11	8.27
			20004531473	26	17.68
			20004531531	5	3.60
			20004531801	2	1.04
			20004531872	4	2.66
			20004531932	13	8.30
			20004533839	7	4.62
			20004543347	3	2.10
			20004763560	12	8.17
			20004763929	8	5.97
			20004764005	5	4.26
			20004764153	26	18.94
			20004764165	3	1.73
			20004764241	2	1.77
			20004764268	2	1.40
			20004764280	18	12.27
			20004764304	2	1.09
			20004764349	5	4.19
			20004764367	1	0.65
			20004764411	2	1.34
			20004764425	2	1.39
			20004764457	12	7.61
			20004764461	5	3.38
			20004764490	2	1.64

स. क्र.	जिला	तहसीलदार	बिल सन्दर्भ संख्या	बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है	₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	
			20004764510	4	2.55	
3	रायसेन	बेगमगंज	20006042990	3	1.63	
			20006043012	8	6.17	
			20006043087	18	12.56	
			20006044369	6	3.63	
			20006049664	14	10.33	
			20006049790	5	2.94	
			20006050274	6	5.48	
			20006051445	4	2.63	
			20006051847	5	3.56	
			20006052349	3	1.75	
			20006056661	2	1.54	
			20006058203	4	2.86	
			20006465542	10	7.68	
			20006468091	7	5.80	
			20008430302	2	1.37	
			20008942412	1	0.66	
			20008942721	3	1.55	
			गौहरगंज	20008903102	1	0.53
		20008937285		4	2.30	
		20008963666		2	1.07	
		रायसेन	20007207969	3	1.95	
			20007972291	2	1.15	
			200011671331	23	17.24	
			200011672343	11	6.77	
		सुल्तानपुर	20003487286	50	41.15	
			20007977894	1	0.75	
सुल्तानपुर	20008901647	2	1.43			
	20008906819	1	0.62			
उदयपुरा	20004211540	1	0.59			
	20008971628	3	2.37			
4	सिवनी	छपारा	20008875825	40	33.34	
			20008876173	27	19.67	
5	शयोपुर	बड़ौदा	200010129803	1	0.60	
6	विदिशा	बासौदा	20008899347	1	0.65	
			गुलाबगंज	20006468378	63	45.66
				20006469706	129	122.27
				20006469877	56	47.12
20006470084	38	32.09				

स. क्र.	जिला	तहसीलदार	बिल सन्दर्भ संख्या	बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है	₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
			20006470215	6	3.62
			20006471793	8	6.42
			20006488433	61	48.70
			20006503325	15	12.82
			20006518415	1	1.32
			20006526378	14	10.74
			20006526788	3	2.41
			20006528002	4	4.81
			20006529068	2	1.40
			20006529623	3	2.11
			20006530037	1	1.15
			20006532521	69	48.83
			20006532724	7	6.28
			20006889928	1	0.59
			20006889948	9	8.14
			20007090746	3	2.04
			20008918672	1	0.79
			20008918828	1	0.72
			20008919443	1	0.56
			20008919708	1	0.74
			20008952935	3	2.33
			20008970103	3	1.60
			20008998302	2	1.25
		कुरवाई	20004999114	1	0.82
			20008893371	1	0.60
			20008894487	1	0.52
			20008898967	1	0.59
			20008899235	3	1.83
			20008904740	2	1.06
			20008914173	1	0.54
			20008914852	2	1.43
			20008918664	1	0.55
			20008919353	1	0.55
			20008937167	2	1.05
			20008937512	2	1.17
			20008938889	3	1.72
			20008940105	3	1.75
			20008942362	7	4.49
			20008951641	5	3.18

स. क्र.	जिला	तहसीलदार	बिल सन्दर्भ संख्या	बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है	₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
			20008958849	5	3.41
		लटेरी	20006099345	2	1.75
			20006100494	2	3.85
			20008905455	1	0.57
			20008905776	3	2.53
			20008941611	1	0.60
			20008994418	1	0.57
			20009032214	2	1.41
			200011662729	16	14.56
			200011669437	93	76.35
			200011669939	80	63.49
			200011679952	2	1.10
			200011684351	4	2.74
			200011684353	2	1.18
			200011760339	3	1.89
			नटेरन	20008895585	2
		20009529733		1	1.20
		शमसाबाद	20008919074	1	0.74
		विदिशा	200074195	43	28.88
			20008915958	1	0.63
			20008995097	1	0.50
			20009022922	2	1.23
			20009131471	3	2.21
			20009136737	2	1.23
		विदिशा शहर	20008997049	1	0.54
योग				3,391	2,600.67

(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.2.1 (क)
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.5, पृष्ठ क्रमांक 49)
चयनित जिलों, तहसीलों और ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

स. क्र.	जिला	शासकीय भूमि का क्षेत्रफल	चयनित तहसील का नाम	शहरी/ ग्रामीण	शासकीय भूमि का क्षेत्रफल	चयनित ग्रामों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	धार	302256.6537	गंधवानी	ग्रामीण	38417.29	चुन्पया और डोलाहनुमान
2			कुक्षी	शहरी	47322.81	डेहरी और खानिआम्बा
3			सरदारपुर	शहरी	48105.32	गुमानपुरा और लाबरिया
4	शहडोल	266822.3928	बुढ़ार	ग्रामीण	11188.615	खो और सोन्हा
5			गोहपारू	शहरी	21953.915	भागा और दुधरिया
6			सोहागपुर	शहरी	11130.2721	लालपुर और नवलपुर
7	सिंगरौली	144079.4905	देवसर	शहरी	17350.5	खंडौली और मझिगावां
8			सिंगरौली ग्रामीण	ग्रामीण	9245.398	पतुलखी और विहारा
9			सिंगरौली शहरी	शहरी	19647.8	मेढोली और झिगुरदह
10	भोपाल	95567.9826	हुजूर	शहरी	44480.78	भोपाल और मुगलिया
11			बैरसिया	शहरी	43126.56	हिनोतिसडक और गुंगा
12	ग्वालियर	210542.1361	डबरा	शहरी	20247.17	सेरोही और इटायल
13			तानसेन	शहरी	19415.25	फुसावली और निरावली
14			मुरार	ग्रामीण	7970.129	भंडारी और लोहारपुर
15	इंदौर	74397.3361	जूनी इंदौर	शहरी	3861.167	लिंबोदी, निपानिया
16			डॉ. अम्बेडकर नगर	शहरी	32430.83	मतलबपुरा, सिलोटिया
17			हातोद	ग्रामीण	4799.045	मावलाखेड़ी, मुरखेड़ा
18	देवास	197312.6515	देवास शहरी	शहरी	4576.592	खजुरिया, मुकुंदखेड़ी
19			हाटपिपल्या	शहरी	12188.94	बोरखेड़ा, शिवपुरमुंडला
20			टोंकखुर्द	ग्रामीण	10617.71	मुरुखेड़ी, सौसर
21	जबलपुर	137397.3041	जबलपुर	शहरी	24731.63	जोगीढाना, घुंसौर
22			रांझी	शहरी	8195.234	डुमना
23			पनागर	ग्रामीण	9730.498	सिंघलदीप, लखना
	कुल क्षेत्रफल	1428375.9474			470733.4551	

परिशिष्ट 2.2.1 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.5, पृष्ठ क्रमांक 49)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित स्थलों की सूची

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
1	भोपाल	146 और 178	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	औद्योगिक पार्क की स्थापना	32.955	21-12-2022
2	भोपाल	94, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 258, 259, 263, 264 और 265	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक पार्क की स्थापना	26.59	06-12-2022
3	भोपाल	40 और 51	अजीम प्रेमजी फाउंडेशन	निजी विश्वविद्यालय का निर्माण	20.234	21-12-2022
4	भोपाल	14/1/1/1	जनजातीय विभाग	अनुसूचित जनजाति (लड़कियों) के लिए छात्रावास का निर्माण	13.354	21-12-2022
5	भोपाल	367, 368, 369, 381, 382	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक पार्क की स्थापना	7.00	21-12-2022
6	भोपाल	119	शहरी स्थानीय निकाय	पीएम आवास योजना का निर्माण	1.285	22-12-2022
7	भोपाल	114	शहरी स्थानीय निकाय	पीएम आवास योजना का निर्माण	1.141	22-12-2022
8	भोपाल	136/42	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	जल क्रीड़ा अकादमी की स्थापना	0.809	22-12-2022
9	भोपाल	161	गृह (पुलिस) विभाग	प्रशासनिक भवन का निर्माण	0.287	22-12-2022

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
10	भोपाल	170	गृह (पुलिस) विभाग	पुलिस स्टेशन का निर्माण	0.119	22-12-2022
11	ग्वालियर	20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64	रक्षा अनुसंधान विकास स्थापना	क्रिटिकल सुविधा का निर्माण	56.685	07-11-2022
12	ग्वालियर	1176, 1178, 1179, 1180 और 1181	उच्च शिक्षा	नवीन विश्वविद्यालय का निर्माण	16	20-10-2022
13	ग्वालियर	388/1, 390, 395 और 397	बागवानी विभाग	नवीन शासकीय पुष्प उद्यान की स्थापना	12.866	19-01-2023
14	ग्वालियर	109, 110 और 111	मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग	दिव्यांगों के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण	7.902	19-01-2023
15	ग्वालियर	109, 110, 111, 112, 113/1, 116/1, 118/1, 119, 120/1, 172/1, 173, 174, 175/1, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 और 189	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल	नवीन बस्ती थाटीपुर का पुनर्घनत्वीकरण	7.086	18-01-2023
16	ग्वालियर	682	राजस्व विभाग	तहसील भवन का निर्माण	1.18	23-01-2023
17	ग्वालियर	89	गृह (पुलिस) विभाग	यातायात जागरूकता एवं प्रशिक्षण केन्द्र	0.846	18-01-2023

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
18	ग्वालियर	77	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	0.805	20-01-2023
19	ग्वालियर	1346	गृह (पुलिस) विभाग	डबरा में पुलिस थाने का निर्माण	0.17	21-01-2023
20	ग्वालियर	361	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	गारमेट पार्क की स्थापना	0.15	19-01-2023
21	इंदौर	50/1, 50/14, 135/6, 228/13, 347/2, 388/1/2, 390/1, 395/2, 437/2, 228/1	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	फर्नीचर क्लस्टर के लिए	185.02	06-09-2022
22	इंदौर	313/1/1	न्याय विभाग	आवासीय भवन का निर्माण	6.364	30-01-2023
23	इंदौर	487	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधानमंत्री आवास योजना	4.892	31-01-2023
24	इंदौर	16	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधानमंत्री आवास योजना	3.788	31-01-2023
25	इंदौर	994/1, 997/2, 1001/1	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधानमंत्री आवास योजना	2.907	30-01-2023
26	इंदौर	313/1	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधानमंत्री आवास योजना	1.5	30-01-2023
27	इंदौर	226	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	एक्सपोर्ट पैक हाउस आलू प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण हेतु	1	30-01-2023
28	इंदौर	1061	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधानमंत्री आवास योजना	0.7	30-01-2023
29	इंदौर	203	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	नवीन स्वास्थ्य केन्द्र गुजरखेड़ा का निर्माण	0.092	01-02-2023
30	इंदौर	87/1/1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	नवीन स्वास्थ्य केन्द्र घोसीखेड़ा का निर्माण	0.092	01-02-2023

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
31	देवास	618	गृह (पुलिस) विभाग	यातायात थाना गोलघर के निर्माण हेतु	0.014	18-01-2023
32	देवास	897	न्याय विभाग	न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय गृहों के निर्माण हेतु	2	18-01-2023
33	देवास	968	न्याय विभाग	पारिवारिक न्यायालय भवन के निर्माण हेतु	0.15	18-01-2023
34	देवास	339	देवास विकास प्राधिकरण	आवासीय भवनों के निर्माण हेतु	0.38	12-10-2022
35	देवास	272/2, 273, 274, 275/2, 581/1, 581/3	शहरी स्थानीय निकाय	आवासीय भवनों के निर्माण हेतु	4.023	12-10-2022
36	जबलपुर	6/1, 6/17	न्याय विभाग	न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु	22.7	17-11-2022
37	जबलपुर	176,179,180	परिवहन विभाग	ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण हेतु	6.14	23-10-2022
38	जबलपुर	243/1	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	बालाजी बायो सॉल्यूशन फ्यूल एलएलपी भोपाल	15	17-11-2022
39	जबलपुर	461	मप्र भण्डारण एवं रसद निगम	गेहूं के भण्डारण एवं साइलो बैग के निर्माण हेतु	20	17-11-2022
40	जबलपुर	94,119	मप्र भण्डारण एवं रसद निगम	गेहूं के भण्डारण एवं साइलो बैग के निर्माण हेतु	9.97	22-11-2022

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
41	जबलपुर	78	मप्र भण्डारण एवं रसद निगम	अस्थाई कैम्प एवं साइलो बैग निर्माण हेतु	7.8	22-11-2022
42	जबलपुर	107	जनजातीय विभाग	सामुदायिक भवन एवं मंदिर निर्माण हेतु	0.1	22-11-2022
43	जबलपुर	809/2	जनजातीय विभाग	छात्रावास निर्माण हेतु	0.4	23-11-2022
44	जबलपुर	541	जनजातीय विभाग	छात्रावास निर्माण हेतु	0.404	23-11-2022
45	जबलपुर	11,10/2	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल	आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसर के निर्माण हेतु	0.269	24-11-2022
46	जबलपुर	23	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	आयुर्वेद चिकित्सालय के निर्माण हेतु	0.05	24-11-2022
47	शहडोल	219	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	औद्योगिक केन्द्र का विकास	15.00	18-12-2022
	शहडोल	718 से 726, 728, 731/1 से 731/5, 732/1, 732/2, 433/1 से 433/5, 733, 736/1 से 736/7, 737, 738/1 से 738/9, 739/1 से 739/8, 740/1, 740/2, 741/1 से 741/2, 742 से 745, 1036, 1037/1 से 1037/3, 1050 से 1152, 1436 से 1497	मप्र पर्यटन विभाग	रिसॉर्ट का निर्माण	34.714	17-12-2022

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
48		451/1 से 451/14, 452/1 से 452/3, 505/1 से 505/2, 506/1 से 506/2, 507/1 से 507/2, 540/1 से 540/2, 541/1 से 541/2, 542, 543		रिसॉर्ट का निर्माण (काम शुरू नहीं हुआ)	45.00	
49	शहडोल	1247/1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	ओपन कैप का निर्माण	2.023	13-12-2022
50	शहडोल	113	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड मुंबई	गैस पाइपलाइन	0.360	14-12-2022
51	शहडोल	9, 12, 13, 14	पर्यटन विभाग	खाद्य शिल्प संस्थान	2.591	14-12-2022
52	शहडोल	29/1	मप्र ऊर्जा विभाग	33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	0.405	13-12-2022
53	शहडोल	317/1, 318	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	ओपन कैप का निर्माण	4.046	13-12-2022
54	शहडोल	925/1, 56/1/1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	ओपन कैप का निर्माण	2.023	13-12-2022
55	शहडोल	242/2 और 243	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड	आवासीय कालोनियों का निर्माण	5.000	08-10-2022
56	शहडोल	173, 174, 175 और 184	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	ओपन कैप का निर्माण	3.840	10-10-2022

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
57	सिंगरौली	1231/2	जनजातीय विभाग	छात्रावास का निर्माण	0.405	24-11-2022
58	सिंगरौली	646/1, 647, 649 और 653	उच्च शिक्षा विभाग	शासकीय महाविद्यालय माडा	4	23-11-2022
59	सिंगरौली	513	पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सालय	0.1	23-11-2022
60	सिंगरौली	700/1/1	सहकारिता विभाग	खरीद केंद्र	0.4	23-11-2022
61	सिंगरौली	1260/1, 1261, 1262	उच्च शिक्षा विभाग	आदर्श महाविद्यालय	3.1	14-11-2022
62	सिंगरौली	755	नगरीय प्रशासन विभाग	ट्रेनिंग ग्राउंड का निर्माण	08	14-11-2022
63	सिंगरौली	333/1, 334, 338/2, 338/1	चिकित्सा शिक्षा विभाग.	चिकित्सा महाविद्यालय	10	12-11-2022
64	सिंगरौली	1604/1, 1605/1, 1606/1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	ओपन कैप का निर्माण	2	02-12-2022
65	सिंगरौली	678, 694, 695/1, 697, 698, 699	जनजातीय विभाग	छात्रावास भवन	0.301	02-12-2022
66	सिंगरौली	561/1	पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सालय	0.05	30-11-2022
67	धार	291/1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उप स्वास्थ्य केंद्र	0.06	27-01-2023
68	धार	369/1	गृह (पुलिस) विभाग	पुलिस स्टेशन भवन	0.547	25-01-2023
69	धार	86/1/1/1	पर्यटन विभाग	पर्यटन गतिविधियाँ	50	25-01-2023
70	धार	94	स्कूल शिक्षा विभाग	स्कूल भवन, किचन शेड, पंचायत कार्यालय	0.4	18-01-2023
71	धार		वन विभाग	वनीकरण	23	07-01-2023

स.क्र.	जिले का नाम	खसरा संख्या	भूमि आवंटित की गई	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि
		23, 26, 32, 81, 33, 34, 37, 80 और 27				
72	धार	116	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	नवीन औद्योगिक केंद्र	81.534	04-01-2023
73	धार	38/1, 69/1, 61, 92/1, 205/1, 205/45, 217/1, 217/2, 226/1, 229/1, 261/1, 268, 284/1, 289/1, 295, 412/1, 445, 520, 558/1, और 563/1	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	नवीन औद्योगिक केंद्र	632.501	04-01-2023
74	धार	4, 3/4, 3/3, 20	वन विभाग	वनीकरण	35	03-01-2023
75	धार	68, 70	नगरीय प्रशासन विभाग	सीवरेज लाइन	0.175	03-01-2023
76	धार	614	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उप स्वास्थ्य केंद्र	0.059	03-01-2023

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.6.1, पृष्ठ क्रमांक 50)

मार्गदर्शिका दरों के गलत अनुप्रयोग द्वारा बाजार मूल्य का कम मूल्यांकन

(₹ लाख में)

विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा संगणित किया गया	राजस्व विभाग द्वारा गणना के अनुसार/ पट्टेदार द्वारा किया गया भुगतान	
आवंटित भूमि का बाजार मूल्य	10926.36 X 2 (भूमि खंड राष्ट्रीय राज मार्ग बाईपास पर स्थित है)	10926.36 (तहसीलदार द्वारा)	
पट्टा विलेख के लिए बाजार मूल्य (एमवी)	21852.72	3884.93 (लीज डीड के अनुसार)	
भुगतान किये जाने वाले राजस्व का विवरण	देय	पट्टेदार द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान	पट्टेदार द्वारा किया गया कम भुगतान
प्रीमियम (धर्मार्थ संस्थान के मामले में एमवी का 25%)	5463.18	971.23	4491.95
99 वर्षों के लिए पट्टा विलेख पर आरोपण योग्य एसडी (प्रीमियम तथा औसत वार्षिक पट्टा किराये के योग का पांच प्रतिशत या संपत्ति का बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो)	एसडी 21852.72 (एमवी) X 5% = 1092.63 पंचायत उपकर (मुख्य कर का 10%) = ₹109.26 कुल एसडी = ₹1201.89	53.86	1148.03
पंजीकरण शुल्क	एसडी का तीन चौथाई = ₹901.42	36.72	864.7
		प्रीमियम, एसडी और आरएफ की कम वसूली/कम भुगतान के कारण शासन को कुल हानि	₹6504.68

परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.7.4, पृष्ठ क्रमांक 56)

एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. को शून्य प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि

(₹ लाख में)

स.क्र.	प्रकरण संख्या	विभाग आवंटित गया है	जिसे किया	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आदेश की तिथि	मार्गदर्शिका दर का वर्ष	प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित)	खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं.	भूमि बाजार (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5)	का मूल्य (कॉलम 9)	प्रीमियम (कॉलम 9*0.30)	वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुज्ञप्ति शुल्क (0.005*महीनों की संख्या)	कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुज्ञप्ति शुल्क)	पट्टे की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)
1	52/ वी - 19(3)/2 019-20	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, जबलपुर	मप्र एवं	2.93	18-02-2020	2019-20	4.64	बगराई, पीएच नंबर 72, आरआई सर्कल चरगावां, खसरा नंबर 279/1 (4.00 हेक्टेयर), तहसील शाहपुरा, जिला। जबलपुर	20.39		6.12	0.46	6.58	3 वर्ष
2	53	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, जबलपुर	मप्र एवं	4.4	19-02-2020	2019-20	10.96	ग्राम दर्शनी, पीएच नंबर 66, सर्किल पौडा, तहसील मझौली, खसरा नंबर 119 (4.40 हेक्टेयर)	72.34		21.70	1.63	23.33	3 वर्ष

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स.क्र.	प्रकरण संख्या	विभाग आवंटित गया है	जिसे किया गया	आवंटित का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आदेश की तिथि	मार्गदर्शिका दर का वर्ष	प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित)	खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं.	भूमि बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5)	का प्रीमियम (कॉलम 9*0.30)	वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुसूचित शिल्क (0.005*महीनों की संख्या)	कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुसूचित शिल्क)	पट्टे की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	54	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, जबलपुर	मप्र एवं	20	22-02-2020	2019-20	4.80	मौजा सालीवाड़ा, पीएच नंबर 58, आरआई सर्कल बरगी, खसरा नंबर 461 (क्षेत्रफल 65.30 हेक्टेयर, तहसील जबलपुर)	144.00	43.20	3.24	46.44	3 वर्ष
4	55	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, कॉर्पोरेशन, जबलपुर	मप्र एवं	15	24-02-2020	2019-20	3.64	मौजा बंदरकोला, पीएच नंबर 34, आरआई सर्कल मझगावां, तहसील सिहोरा, खसरा नंबर 18 (क्षेत्रफल 45.62 हेक्टेयर)	81.90	24.57	1.84	26.41	3 वर्ष
5	56/ 19(3)/2 019-20	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स	मप्र एवं	8.09	26-02-2020	2019-20	5.52	खसरा नंबर 515, ग्राम कसाही पीएच	66.99	20.10	1.51	21.60	3 वर्ष

स.क्र.	प्रकरण संख्या	विभाग आवंटित गया है	जिसे किया	आवंटित का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आदेश की तिथि	मार्गदर्शिका दर का वर्ष	प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित)	खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं.	भूमि बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5)	का प्रीमियम (कॉलम 9*0.30)	वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुसूचित श्रुलक (0.005*महीनों की संख्या)	कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुसूचित श्रुलक)	पट्टे की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6	0011/ए 19(3)/2 019-20	कॉर्पोरेशन, जबलपुर	मप्र शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शहडोल	2.023	20-02-2020	2019-20	21.35	नंबर 51 (23.07 हेक्टेयर), आरआई सर्कल पनागर, तहसील पनागर	64.79	6.48	0.49	6.97	3 माह (1 वर्ष तक प्रीमियम की दर बाजार मूल्य का 10% है)
7	0057/ए 19(3)/2 020-21	कॉर्पोरेशन, शहडोल	क्षेत्रीय प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, बुरहार शहडोल	2.023	04-01-2021	2020-21	21.35	पटवारी हल्का नं. 64 खसरा नंबर 2929, 2930, 2938	64.79	0.00	0.97	0.97	3 माह

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स.क्र.	प्रकरण संख्या	विभाग आवंटित किया गया है	जिसे किया	आवंटित का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आदेश की तिथि	मार्गदर्शिका दर का वर्ष	प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित)	खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं.	भूमि बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5)	कॉलम 9*0.30	वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुसूचित शूल्क की संख्या)	कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुसूचित शूल्क)	पट्टे की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
8	13/19(3)/2020-21	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, जबलपुर	मप्र एवं	7.8	02-01-2021	2020-21	10.96	मौजादर्शनी, आरआई सर्कल पौडा, तहसील मझौली, खसरा नंबर 18 पीएच नंबर 66	128.23	0.00	23.08	23.08	अगले आदेश तक
9	15/19(3)/2020-21	जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, जबलपुर	मप्र एवं	6.7	02-01-2021	2020-21	10.80	मौजा गंगाई, पीएच नंबर 75, खसरा नंबर 493, 497/1तहसील शाहपुरा	108.54	0.00	19.54	19.54	अगले आदेश तक
कुल				68.966							कुल	174.92	

परिशिष्ट 2.2.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.2, पृष्ठ क्रमांक 59)

प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम मूल्यांकन और बकाया राशि पर ब्याज का अनारोपण

स. क्र.	प्रकरण क्र.	ग्राम	तहसील	जिला	कुल आवंटित भूमि		मार्गदर्शिका दर		बाजार मूल्य		कुल बाजार मूल्य	प्रीमियम, बाजार मूल्य का 100%	वार्षिक पट्टा किराया, प्रीमियम का 5%
					(हेक्टेयर में)	वर्ग मीटर में	आवासीय भूखंड की दर प्रति वर्ग मीटर	सिंचित कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेयर	500 वर्ग मीटर तक (आवासीय भूखंड की दर)	500 वर्ग मीटर से अधिक (कृषि अधिकतम दर)*1.5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(500 वर्ग मीटर *8)	11 (1.973 हेक्टेयर *9)*1.5	12 (10+11)	13	14
1	24/अ-20 (1) / 2011-12	सोहागपुर	सोहागपुर	शहडोल	2.023	20230	8000	8900000	4000000	26339550	30339550	30339550	1516977.5

(₹ लाख में)

	2022-23 तक प्रीमियम पर ब्याज का गणना पत्रक						2022-23 तक पट्टा किराये पर ब्याज का गणना पत्रक					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
कुल देय प्रीमियम	303.40	202.53	202.53	202.53	159.80	159.80	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	75.85
भुगतान किया गया प्रीमियम	100.87	0.00	0.00	42.73	0.00		5.04	0.00	0.34	0.00	0.00	5.38
कुल बकाया प्रीमियम (देय-भुगतान) वर्ष के अंत में शेष, प्रारंभिक शेष राशि होगी यानी अगले वर्ष के लिए देय	202.53	202.53	202.53	159.80	159.80	159.80						70.46
ब्याज गणना के लिए विचार किया प्रीमियम (प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया प्रीमियम)	202.53	202.53	202.53	159.80	159.80	159.80	10.13	25.30	40.47	55.29	70.46	0.00
पट्टा किराया पर ब्याज 15 प्रतिशत की दर से	30.38	30.38	30.38	23.97	23.97	139.08	1.52	3.79	6.07	8.29	10.57	30.25
							भुगतान की जाने वाली कुल राशि: ₹399.59 लाख					

परिशिष्ट- 2.2.5
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.3, पृष्ठ क्रमांक 60 व 61)
स्थायी पट्टे का नवीनीकरण न होने से शासकीय राजस्व की हानि

स.क्र.	पट्टेदार का नाम	जिला	पट्टा अवसान दिनांक	पट्टा नवीनीकरण की नियत तिथि	अंतिम पट्टा किराया	म.प्र.न.भू.नि.नि. के पैरा 81(2) के अनुसार गणना किया गया				कुल पट्टा किराया		
						2020-21 तक		वर्ष 2021-22				
						पट्टा किराया वर्षों की संख्या	पट्टा किराया = नियत अंतिम पट्टा किराया का 6 गुना	पट्टा किराया	क्षेत्र वर्गमीटर में		नवीनीकरण की तिथि पर प्रचलित दर का दो गुना	पट्टा किराया
1	श्री अजय विजय गुप्ता	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कॉलम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
2	मुन्नालाल चौधरी	शहडोल	31-03-2016	01-04-2016	28.2	5	169.2	846	238.5	3	715.5	1561.5
3	रोशन खान		31-03-2005	01-04-2005	9.55	16	57.3	916.8	111	3	333	1249.8
4	रुक्मणी वर्मा		31-03-2007	01-04-2007	43.35	14	260.1	3641.4	180.1	3	540.3	4181.7
5	ओमप्रकाश चौधरी		31-03-2011	01-04-2011	56.8	10	340.8	3408	93	3	279	3687
6	फुलमती तिवारी		31-03-2005	01-04-2005	11.95	16	71.7	1147.2	139.4	3	418.2	1565.4
6	फुलमती तिवारी		31-03-2006	01-04-2006	36.6	15	219.6	3294	560	3	1680	4974

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
7	राजभान सिंह		31-03-2006	01-04-2006	44	15	264	3960	501.7	3	1505.1	5465.1
8	राम मिलन		31-03-2005	01-04-2005	11.65	16	69.9	1118.4	135.5	3	406.5	1524.9
9	संतोष		31-03-2005	01-04-2005	20	16	120	1920	229	3	687	2607
10	संतोष		31-03-2005	01-04-2005	7.65	16	45.9	734.4	90	3	270	1004.4
11	अध्यक्ष जिला पत्रकार संघ		31-03-2014	01-04-2014	464.2	7	2785.2	19496.4	204.5	6	1227	20723.4
12	विमला देवी		31-03-2018	01-04-2018	47	3	282	846	116	3	348	1194
	कुल 12 प्रकरण											49738.2
1	अध्यक्ष लघु वेतन सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी संघ	धार	31-03-2019	01-04-2019	18559	2	111353	222705	45523	3	136569	359274
2	शासकीय कर्मचारी अधिकारी हाउसिंग बोर्ड सोसायटी		31-03-2019	01-04-2019	12493	2	74958	149916	38688	3	116064	265980
3	अध्यक्ष जिला सहकारी भूमि विकास बैंक		31-03-2020	01-04-2020	2840.6	1	17043.6	17043.6	696.77	3	2090.31	19133.91
4	केसरीमल जैन अध्यक्ष हिंदुस्तान सेवासंघ		31-03-2022	01-04-2022	1726	0	0	0	40900	1.5	61350	61350
5	मुतावलीवक्फ मस्जिद काजीपुरा धार		31-03-2013	01-04-2013	18.5	8	111	888	66.33	3	198.99	1086.99
	कुल 05 प्रकरण											706824.9
1	श्री सेनी विद्या निकेतन इंदौर	इंदौर	31-03-2014	01-04-2014	970	7	5820	40740	660	4	2640	43380
2	कर्मचारी राज्य बीमा निगम इंदौर		31-03-2004	01-04-2004	1473.3	17	8839.7	150275.5	15985.1	6	95910.5	246186.0
							4	8	1			6

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
3	ऑक्ट्रॉय नाका देवास रोड, इंदौर		31-03-1999	01-04-1999	53	22	318	6996	557.41	8	4459.28	11455.28
4	महिला कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति		31-03-2014	01-04-2014	6952.2	7	41712.9	291990.3	21529.3	4	86117.1	378107.3
5	श्री रमेश पुत्र टीकाराम छत्रीबाग		31-03-2006	01-04-2006	48.5	15	291	4365	46.45	4	185.8	4550.8
6	एम.बी. खालसा एजुकेशन सोसायटी		31-03-2002	01-04-2002	1510.7	19	9063.9	172215.2	8255.5	4	33022.3	205237.5
7	राजस्व तृतीय श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति		31-03-1998	01-04-1998	1533.6	23	9201.6	211636.8	17846.6	4	71386.3	283023.1
8	माहेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छत्रीबाग		31-03-2000	01-04-2000	5.6	21	33.6	705.6	613.16	4	2452.64	3158.24
9	अध्यक्ष, मुल्तान सहकारी समिति		31-03-2012	01-04-2012	38877	9	233264	2099374.2	52609.1	4	210436.4	2309810.6
10	भगवान बाहुबली दिगंबर जैन समाज गौमतगिरि इंदौर		31-03-2013	01-04-2013	5311	8	31866	254928	214929	6	128957	1544499
11	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल (किला मैदान इंदौर)		31-03-2018	01-04-2018	36918	3	221508	664524	22217.29	6	133303.74	797827.7
12	कारसदेव गृह निर्माण सहकारी समिति		31-03-2013	01-04-2013	9612	8	57672	461376	22581.4	4	90325.6	551701.5
13	आईटीआई कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति इंदौर		31-03-2015	01-04-2015	2352.5	6	14114.9	84689.28	8093.7	4	32374.8	117064.1

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
14	गांधी बेघर स्लम गृह निर्माण सहकारी समिति इंदौर		31-03-2005	01-04-2005	4934	16	29604	473664	85914. 8	4	343659	817323.0 4
15	अध्यक्ष, दाधीच ब्राह्मण समाज इंदौर		31-03-2010	01-04-2010	993.12	11	5958.7 2	65545.92	384.43	6	2306.58	67852.5
16	श्री निरंजन कुमार-पूनमचंद सोनी चन्नीबाग इंदौर		31-03-2018	01-04-2018	412	3	2472	7416	55.74	4	222.96	7638.96
17	भगवानदास वधुमुल ठाकुर झूलैलाल अखण्डज्योति प्याऊ झूलैलाल मंदिर इंदौर		31-03-2010	01-04-2010	86	11	516	5676	266.35	6	1598.1	7274.1
18	साधु वासवानी सहकारी समिति साधु वासवानी नगर इंदौर		31-03-2006	01-04-2006	318.75	15	1912.5	28687.5	394.83	6	2368.98	31056.48
19	इंडियन कैनेडियन प्रेस ब्रिटोनियन मिशन इंदौर		31-03-1957	01-04-1957	154.11	64	924.66	59178.24	28206. 59	4	112826. 36	172004.6
20	इंदौर राजस्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारी समिति दशहरा मैदान इंदौर		31-03-2016	01-04-2016	11761	5	70567. 2	352836	40468. 6	6	242811 6	595647.3 6
	कुल 20 प्रकरण											8194798.5
1	देवकीनंदन, दुर्गाप्रसाद पुत्र भूरूलाल और पंतनारायण, गंगाप्रसाद कपिमितमदबम लक्ष्मीनारायण	देवास	31-03-2010	01-04-2010	126	11	756	8316	252	3	756	9072

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
2	घांसीराम पुत्र रघुनाथ		31-03-2009	01-04-2009	25.2	12	151.2	1814.4	132.5	3	397.5	2211.9
3	कुरवानखान खान पुत्र याशमीन खान गनीमतबाई पत्नी याशमीन खान		31-03-2009	01-04-2009	9.3	12	55.8	669.6	49	3	147	816.6
4	नेमीचंद्र पुत्र हजरीलाल		31-03-2011	01-04-2011	19	10	114	1140	38	3	114	1254
5	गुलाम मुहम्मद पुत्र शेख चन्द्र भाई		31-03-2008	01-04-2008	10.3	13	61.8	803.4	47.7	3	143.1	946.5
6	अनंत नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण		31-03-2011	01-04-2011	89.5	10	537	5370	179	3	537	5907
7	अब्देल रहमान पुत्र गुलाम नबी कुरेशी		31-03-2008	01-04-2008	14.5	13	87	1131	76.50	3	229.5	1360.5
8	इश्माएलभाई पुत्र कासम भाई		31-03-2009	01-04-2009	20.75	12	124.5	1494	109	3	327	1821
9	मंजूर हुसैन पुत्र शेख चंदेश		31-03-2009	01-04-2009	5.95	12	35.7	428.4	31.25	3	93.75	522.15
10	अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद खान		31-03-2008	01-04-2008	10.1	13	60.6	787.8	53.3	3	159.9	947.7
11	चतुर्भुज पुत्र नगजीराम		31-03-2011	01-04-2011	24	10	144	1440	48	3	144	1584
12	यासीन खान पुत्र आमिर खान		31-03-2011	01-04-2011	36	10	216	2160	189.5	3	568.5	2728.5
13	श्यामसुंदर पुत्र मूलचंद		31-03-2010	01-04-2010	39.25	11	235.5	2590.5	78.5	3	235.5	2826
14	राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण, बाबूलाल पुत्र नानूराम		31-03-2008	01-04-2008	9.6	13	57.6	748.8	50.45	3	151.35	900.15
15	शेख बरकत पुत्र शेख निज़ाम		31-03-2011	01-04-2011	10.75	10	64.5	645	56.5	3	169.5	814.5
16	आनंदीबाई के पति रामनारायण और जगदीश चंदा पुत्र रामनारायण	देवास	31-03-2011	01-04-2011	118.25	10	709.5	7095	236.5	3	709.5	7804.5

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
17	करीमखान पुत्र अमीरभाई		31-03-2012	01-04-2012	14.25	9	85.5	769.5	75	3	225	994.5
18	मिर्जा अजबखान पुत्र मनुबेग		31-03-2011	01-04-2011	24.25	10	145.5	1455	127.50	3	382.5	1837.5
19	अब्दुलरहमान पुत्र शेखनाथ भाई		31-03-2011	01-04-2011	43.7	10	262.2	2622	230	3	690	3312
20	सावित्रीबाई, रमेशचंद्र पुत्र कशनाराव जोशी		31-03-2010	01-04-2010	151.4	11	908.4	9992.4	302.8	3	908.4	10900.8
21	मजूर हुसैन पुत्र चान्दखान		31-03-2009	01-04-2009	20.65	12	123.9	1486.8	90.6	3	271.8	1758.6
22	नासिरखान पुत्र सेखकल्लू खान		31-03-2011	01-04-2011	52.85	10	317.1	3171	278	3	834	4005
23	हबीबमुर, रहमत अली		31-03-2012	01-04-2012	49.4	9	296.4	2667.6	260.5	3	781.5	3449.1
24	नूरजाहाबाई पत्नी हाजी शेख मोहम्मद		31-03-2010	01-04-2010	5.6	11	33.6	369.6	29.5	3	88.5	458.1
25	भागीरथ, गेंदालाल पुत्र गोपालजी		31-03-2008	01-04-2008	13.3	13	79.8	1037.4	70	3	210	1247.4
26	साबिर हुसैन पुत्र अहमद हुसैन		31-03-2011	01-04-2011	12.45	10	74.7	747	66	3	198	945
27	इंदरमल पुत्र गिरिराज		31-03-2010	01-04-2010	54.9	11	329.4	3623.4	95.5	3	286.5	3909.9
28	मुस्तखशेख पुत्र नजीरशेख		31-03-2011	01-04-2011	6.6	10	39.6	396	32	3	96	492
29	सत्तारखान पुत्र इंदु खान		31-03-2011	01-04-2011	7.8	10	46.8	468	41.5	3	124.5	592.5
30	अब्दुल रहमान पुत्र गुलाब सिंह		31-03-2011	01-04-2011	13.7	10	82.2	822	70	3	210	1032
31	हसोबाई, बानोबाई पति नजीरखान		31-03-2009	01-04-2009	12.2	12	73.2	878.4	64.5	3	193.5	1071.9
32	लक्ष्मीनारायण पुत्र हजारीलाल		31-03-2008	01-04-2008	13.75	13	82.5	1072.5	72.3	3	216.9	1289.4

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
33	गफूरखां पुत्र माडेखान	देवास	31-03-2010	01-04-2010	9.9	11	59.4	653.4	52	3	156	809.4
34	कमलादेवी पत्नी हिम्मत सिंह		31-03-2011	01-04-2011	107.5	10	645	6450	215	3	645	7095
35	ओम प्रकाश पुत्र पून सिंह		31-03-2011	01-04-2011	114	10	684	6840	228	3	684	7524
36	सेराजबी पत्नी तवारक अली		31-03-2008	01-04-2008	12.35	13	74.1	963.3	65	3	195	1158.3
37	अब्दुलगनी पुत्र शेखचंद		31-03-2010	01-04-2010	11	11	66	726	58	3	174	900
38	मांगीलाल पुत्र भेरूलाल		31-03-2011	01-04-2011	29	10	174	1740	58	3	174	1914
39	कुर्वान खान पुत्र यासीनखान गनीमत बी पत्नी यासीन खान		31-03-2009	01-04-2009	21.5	12	129	1548	113	3	339	1887
40	अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल हकीम, अब्दुल कादिर पुत्र शेख अहमद		31-03-2009	01-04-2009	30.15	12	180.9	2170.8	158.75	3	476.25	2647.05
41	घासीराम पुत्र रघुनाथ		31-03-2009	01-04-2009	5.7	12	34.2	410.4	30	3	90	500.4
42	सिराजे अहमद, शेख रफीकअहमद पुत्र बसीरअहमद शेख		31-03-2011	01-04-2011	74.6	10	447.6	4476	392.5	3	1177.5	5653.5
43	मोहम्मद अयातुल्ला पुत्र मुल्लाअल्लाबेली		31-03-2011	01-04-2011	24.7	10	148.2	1482	130	3	390	1872
44	अब्दुल रहमान, अब्दुल हुसैन पुत्र हाजी शेख मोहम्मद		31-03-2011	01-04-2011	7.8	10	46.8	468	41.5	3	124.5	592.5
45	बतुलबाई पत्नी नजीर अहमद		31-03-2009	01-04-2009	4.2	12	25.2	302.4	22	3	66	368.4
46	जमुनाबाई पत्नी ओंकारलाल		31-03-2009	01-04-2009	14.8	12	88.8	1065.6	51	3	153	1218.6
47	परवामीबाई पत्नी चिरौजीलाल		31-03-2009	01-04-2009	78.45	12	470.7	5648.4	334.5	3	1003.5	6651.9

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
48	आरिफ हुसैन पुत्र हबीब नवाब		31-03-2009	01-04-2009	10.75	12	64.5	774	56.5	3	169.5	943.5
49	सुंदरबाई पत्नी सेवकनाथ		31-03-2008	01-04-2008	11.5	13	69	897	48	3	144	1041
50	जमनालाल, धरमचंद पुत्र भेरूलाल, सज्जनबाई पत्नी भेरूलाल		31-03-2010	01-04-2010	36.35	11	218.1	2399.1	63.5	3	190.5	2589.6
51	मोहनलाल पुत्र हीरालाल	देवास	31-03-2010	01-04-2010	39	11	234	2574	72	3	216	2790
52	गुलाबबाई पत्नी मोहनलाल		31-03-2010	01-04-2010	32.65	11	195.9	2154.9	48.5	3	145.5	2300.4
53	भगवतीनाथ पुत्र नारायणनाथ		31-03-2010	01-04-2010	12.85	11	77.1	848.1	20.7	3	62.1	910.2
54	बरकत अली, अजगरअली पुत्र अब्बास अली		31-03-2009	01-04-2009	18.8	12	112.8	1353.6	159	3	477	1830.6
55	मोतीलाल बाबूलाल पुत्र नगजीराम		31-03-2009	01-04-2009	41.5	12	249	2988	195.5	3	586.5	3574.5
56	शिवनारायण, बद्रीनारायण, रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, पन्नालाल, बाबूलाल पुत्र मोतीलाल		31-03-2008	01-04-2008	248.85	13	1493.1	19410.3	405	3	1215	20625.3
57	नारायण पुत्र बलवंत सिंह		31-03-2008	01-04-2008	22.2	13	133.2	1731.6	44.45	3	133.35	1864.95
58	फातिमाबाई पत्नी खजुखा		31-03-2008	01-04-2008	19.95	13	119.7	1556.1	105	3	315	1871.1
59	अशोक/सत्यनारायण पुत्र किशनलाल		31-03-2011	01-04-2011	148.2	10	889.2	8892	288	3	864	9756
60	जगन्नाथ पुत्र गिरधारीलाल		31-03-2008	01-04-2008	58	13	348	4524	116	3	348	4872
61	बसंतबाई पत्नी हीरालाल		31-03-2009	01-04-2009	23.95	12	143.7	1724.4	27	3	81	1805.4
62	सम्पतिबाई पत्नी छोगालाल		31-03-2009	01-04-2009	36.65	12	219.9	2638.8	141.5	3	424.5	3063.3

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
63	अनंतनारायण पुत्र माखनलाल, रामप्यारी पत्नी माखनलाल		31-03-2009	01-04-2009	42.25	12	253.5	3042	62.15	3	186.45	3228.45
64	माखनलाल पुत्र होतचंद		31-03-2009	01-04-2009	93.75	12	562.5	6750	143	3	429	7179
65	गणेशीबाई पत्नी बाबूलाल		31-03-2010	01-04-2010	51.8	11	310.8	3418.8	93.3	3	279.9	3698.7
66	मनीहरलाल पुत्र खडक सिंह		31-03-2010	01-04-2010	29.5	11	177	1947	59	3	177	2124
67	सतीश पुत्र बसंतीलाल कानूनगो		31-03-2008	01-04-2008	90.75	13	544.5	7078.5	181.5	3	544.5	7623
68	शमीमबाई पत्नी नसरुद्दीन		31-03-2009	01-04-2009	45.25	12	271.5	3258	156	3	468	3726
69	अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रजाक पुत्र मोती खान	देवास	31-03-2010	01-04-2010	9.5	11	57	627	59	3	177	804
70	इदुखान, मुंसी खान पुत्र नूरखान		31-03-2009	01-04-2009	13.7	12	82.2	986.4	72	3	216	1202.4
71	वसीरखां, तक्काखां पुत्र नन्हेखां		31-03-2009	01-04-2009	12.3	12	73.8	885.6	64.5	3	193.5	1079.1
72	रसूलखान पुत्र घोशा अली		31-03-2008	01-04-2008	15.5	13	93	1209	81.5	3	244.5	1453.5
73	अब्दुल गफ्फार पुत्र नसरुल्ला खान		31-03-2010	01-04-2010	9.5	11	57	627	50	3	150	777
74	हसीबाई पत्नी अब्दुलरहमान		31-03-2009	01-04-2009	26.8	12	160.8	1929.6	141	3	423	2352.6
75	बाबूखां पुत्र हसनखां,		31-03-2009	01-04-2009	34.2	12	205.2	2462.4	180	3	540	3002.4
76	वजीर मोहम्मद पुत्र नजीर मोहम्मद		31-03-2008	01-04-2008	25.8	13	154.8	2012.4	135	3	405	2417.4
77	करीमबाग पुत्र बुद्दुबेग		31-03-2009	01-04-2009	10.45	12	62.7	752.4	55.5	3	166.5	918.9
78	जबरियाइर पुत्र करीम अहमद		31-03-2009	01-04-2009	13	12	78	936	68.5	3	205.5	1141.5

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
79	वर्धमान पुत्र कन्हैयालाल		31-03-2009	01-04-2009	18.55	12	111.3	1335.6	78	3	234	1569.6
80	विजयप्रकाश, नंदकिशोर पुत्र मूलचंद		31-03-2009	01-04-2009	50.15	12	300.9	3610.8	173	3	519	4129.8
81	मोहम्मद, बाबूखं पुत्र भूरेखं		31-03-2009	01-04-2009	18.5	12	111	1332	97.5	3	292.5	1624.5
82	बतुलबाई पत्नी नजीर अहमद		31-03-2009	01-04-2009	8.95	12	53.7	644.4	47	3	141	785.4
83	रतनलाल पुत्र हीरालाल		31-03-2012	01-04-2012	47	9	282	2538	89.5	3	268.5	2806.5
84	रईसाबाई पत्नी रहमत अली		31-03-2011	01-04-2011	13.1	10	78.6	786	70	3	210	996
85	रईसाबाई पत्नी रहमत अली		31-03-2009	01-04-2009	10.35	12	62.1	745.2	54.5	3	163.5	908.7
86	नन्हेखां, छोटेखां पुत्र हसनखां		31-03-2009	01-04-2009	26.6	12	159.6	1915.2	140	3	420	2335.2
87	बदरुद्दीन पुत्र रसूलखां		31-03-2010	01-04-2010	11.2	11	67.2	739.2	59	3	177	916.2
88	सुवालाल पुत्र गोविंदराम	देवास	31-03-2012	01-04-2012	66.65	9	399.9	3599.1	120.5	3	361.5	3960.6
89	संपूर्ण सिंह पुत्र मथुरा सिंह		31-03-2012	01-04-2012	85.1	9	510.6	4595.4	100.14	3	300.42	4895.82
90	श्रीमती शीला देवी पत्नी शंकरराव धोबजे		31-03-2012	01-04-2012	19.65	9	117.9	1061.1	39.23	3	117.69	1178.79
91	कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास, कमलमल पुत्र टेकनदास		31-03-2012	01-04-2012	76.3	9	457.8	4120.2	132.63	3	397.89	4518.09
92	मोहनलाल पुत्र बलदेवप्रसाद		31-03-2008	01-04-2008	66.3	13	397.8	5171.4	132.62	3	397.86	5569.26
93	रामरतन पुत्र पीराजी		31-03-2011	01-04-2011	12.2	10	73.2	732	71.65	3	214.95	946.95
94	गोवर्धनलाल पुत्र बाबूलाल		31-03-2011	01-04-2011	35.75	10	214.5	2145	71.5	3	214.5	2359.5

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
95	शक्रअली पुत्र सरदारअली		31-03-2012	01-04-2012	52.5	9	315	2835	101	3	303	3138
96	इंदुमती पत्नी बलवंत सिंह		31-03-2011	01-04-2011	36.5	10	219	2190	73.5	3	220.5	2410.5
97	गंगाबाई पत्नी भेरूलाल		31-03-2011	01-04-2011	39.75	10	238.5	2385	79.5	3	238.5	2623.5
98	बाबू पुत्र रामजी		31-03-2011	01-04-2011	96.5	10	579	5790	193	3	579	6369
99	रामजी पुत्र दुलीचंद		31-03-2011	01-04-2011	67	10	402	4020	134	3	402	4422
100	सुंदाबाई पत्नी गेन्डालाल		31-03-2007	01-04-2007	55.4	14	332.4	4653.6	110.82	3	332.46	4986.06
101	बद्रीप्रसाद पुत्र नारायण सिंह		31-03-2010	01-04-2010	35.85	11	215.1	2366.1	71.6	3	214.8	2580.9
102	परसराम, छोटेराल पुत्र नवारीलाल		31-03-2011	01-04-2011	237.1	10	1422.6	14226	132	3	396	14622
103	कासम पुत्र मनुभाई		31-03-2011	01-04-2011	46.55	10	279.3	2793	84	3	252	3045
104	रामरतन पुत्र चीमाजी		31-03-2010	01-04-2010	5.1	11	30.6	336.6	95	3	285	621.6
105	रहमत बाई पत्नी अहमद खान	देवास	31-03-2011	01-04-2011	9.9	10	59.4	594	184	3	552	1146
106	भगवान सिंह, अमर सिंह, श्रीराम पुत्र लक्ष्मण सिंह, सरस्वतीबाई पत्नी लक्ष्मण सिंह		31-03-2010	01-04-2010	3.2	11	19.2	211.2	75	3	225	436.2
107	मथुराप्रसाद पुत्र राजचन्द्र		31-03-2007	01-04-2007	11.4	14	68.4	957.6	176	3	528	1485.6
108	लक्ष्मीबाई पत्नी रघुनाथ राव		31-03-2010	01-04-2010	9.65	11	57.9	636.9	179.25	3	537.75	1174.65

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
109	रामचन्द्र पुत्र नारायण सिंह		31-03-2011	01-04-2011	114	10	684	6840	228	3	684	7524
110	लक्ष्मीनारायण, मुन्नालाल पुत्र धारीलाल, ललिताबाई पत्नी धारीलाल		31-03-2011	01-04-2011	10.2	10	61.2	612	60	3	180	792
111	बाबूलाल, चैनसिंह पुत्र मधुजी		31-03-2011	01-04-2011	113.75	10	682.5	6825	227.5	3	682.5	7507.5
112	दामोदर पुत्र देवाजी		31-03-2009	01-04-2009	145.5	12	873	10476	291	3	873	11349
113	रामचन्द्र, रामकिशन पुत्र बालमुकुन्द		31-03-2009	01-04-2009	62.9	12	377.4	4528.8	119	3	357	4885.8
114	नर्मदाबाई पत्नी गणपत सिंह		31-03-2011	01-04-2011	206	10	1236	12360	328	3	984	13344
115	शिवशंकर पुत्र हेमराज		31-03-2009	01-04-2009	219.3	12	1315.8	15789.6	258	3	774	16563.6
116	बाबूलाल पुत्र नारायण सिंह		31-03-2010	01-04-2010	76	11	456	5016	152	3	456	5472
117	अंबाराम, मदन पुत्र धुलजी		31-03-2007	01-04-2007	7.3	14	43.8	613.2	137.5	3	412.5	1025.7
118	भेरूलाल पुत्र धासीराम		31-03-2008	01-04-2008	21.1	13	126.6	1645.8	32.75	3	98.25	1744.05
119	दयाराम पुत्र घांसीराम		31-03-2008	01-04-2008	23.7	13	142.2	1848.6	37.05	3	111.15	1959.75
120	घांसीराम पुत्र चतुर्भुज		31-03-2008	01-04-2008	15.85	13	95.1	1236.3	31.65	3	94.95	1331.25
121	नंदराम पुत्र घांसीराम	देवास	31-03-2008	01-04-2008	26.7	13	160.2	2082.6	31.41	3	94.23	2176.83
122	अब्दुल माजिद पुत्र यासीन खान		31-03-2007	01-04-2007	5.3	14	31.8	445.2	91.75	3	275.25	720.45
123	राजाराम पुत्र नाथूजी		31-03-2007	01-04-2007	4.15	14	24.9	348.6	77	3	231	579.6

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
124	भागीरथ पुत्र मोहनलाल		31-03-2011	01-04-2011	16.6	10	99.6	996	87.5	3	262.5	1258.5
125	रहमतबाई पुत्र इब्राहीम		31-03-2011	01-04-2011	3.9	10	23.4	234	81	3	243	477
126	छतरसिंह पुत्र रामप्रसाद		31-03-2011	01-04-2011	17.2	10	103.2	1032	90.5	3	271.5	1303.5
127	रामचंद्र पुत्र गरीबलाल और रामबैर पत्नी सुंदरलाल		31-03-2010	01-04-2010	6.35	11	38.1	419.1	117	3	351	770.1
128	मोहम्मद अनवरखान पुत्र अकबरखान		31-03-2009	01-04-2009	39.5	12	237	2844	79	3	237	3081
129	टीकमचंद्र पुत्र खूबचंद्र और कावेरीबाई पत्नी खूबचंद्र		31-03-2010	01-04-2010	19.75	11	118.5	1303.5	370.75	3	1112.25	2415.75
130	भंवरसिंह पुत्र उमरावसिंह		31-03-2011	01-04-2011	14.9	10	89.4	894	78.5	3	235.5	1129.5
131	गोरीबाई पत्नी भगवान सिंह, दुर्गा सिंह पुत्र भगवान सिंह		31-03-2010	01-04-2010	35	11	210	2310	70	3	210	2520
132	संपतबाई पत्नी मोतीलाल		31-03-2011	01-04-2011	15.4	10	92.4	924	285.75	3	857.25	1781.25
133	बाजीराव पुत्र राजाराम		31-03-2010	01-04-2010	4.3	11	25.8	283.8	79.9	3	239.7	523.5
134	दत्तात्रेय पुत्र शंकरराव		31-03-2008	01-04-2008	9.45	13	56.7	737.1	175.2	3	525.6	1262.7
135	देवीलाल पुत्र घांसीराम		31-03-2011	01-04-2011	24.7	10	148.2	1482	130	3	390	1872
136	सावित्रीबाई, जावित्रीबाई पुत्री कन्हैयालाल		31-03-2007	01-04-2007	15.1	14	90.6	1268.4	280.25	3	840.75	2109.15

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8(6 गुना * कालम 6)	9=7*8	10	11	12=10 *11	13=9+12
137	रामचन्द्र, चतुर्भुज, गोपालकृष्ण, लक्ष्मीनारायण कपितम दबबम कूकाजी	देवास	31-03-2010	01-04-2010	23	11	138	1518	423.45	3	1270.35	2788.35
138	शेख रमजान पुत्र शेख गुलाब		31-03-2011	01-04-2011	7.25	10	43.5	435	38	3	114	549
139	मूलचंद पुत्र गोविंद जी		31-03-2010	01-04-2010	4	11	24	264	74	3	222	486
140	सोनाबाई पत्नी निर्भय सिंह		31-03-2011	01-04-2011	38.25	10	229.5	2295	76.5	3	229.5	2524.5
141	सुन्दर सिंह पुत्र चन्द्रशान सिंह		31-03-2011	01-04-2011	37.5	10	225	2250	197.5	3	592.5	2842.5
142	केशरीमाप पुत्र शंकरलाल		31-03-2011	01-04-2011	88.75	10	532.5	5325	467	3	1401	6726
143	चुन्नीलाल पुत्र दौलाजी		31-03-2011	01-04-2011	8.1	10	48.6	486	42.5	3	127.5	613.5
144	श्यामलाल पुत्र दौलाजी		31-03-2011	01-04-2011	10.45	10	62.7	627	55	3	165	792
145	दामोदर पुत्र जावरचंद		31-03-2009	01-04-2009	12	12	72	864	24	3	72	936
146	मोहम्मद शकील पुत्र अब्दुल गफूर		31-03-2011	01-04-2011	44	10	264	2640	88	3	264	2904
147	काशीबाई पत्नी आंकारलाल		31-03-2012	01-04-2012	26	9	156	1404	52	3	156	1560
148	नूरमोहम्मद पुत्र अनुददीन		31-03-2011	01-04-2011	55.55	10	333.3	3333	79.5	3	238.5	3571.5
	कुल 148 प्रकरण											434505.3
	महा योग 185 प्रकरणों के लिए											9385867

परिशिष्ट-2.2.6
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.4, पृष्ठ क्रमांक 62)
म.प्र. राज्य भण्डारगृह निगम को भूमि आवंटन पर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का अनारोपण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	प्रकरण संख्या	ग्राम	तहसील	जिला	कुल आवंटित भूमि			मार्गदर्शिका दर		बाजार मूल्य			कुल बाजार मूल्य	प्रीमियम (बाजार मूल्य का 75%)	पट्टा किराया		पंचायत उपकर (पट्टा किराया एवं प्रीमियम के योग का 50%)
					आवंटन की तिथि	(हेक्टेयर में)	(वर्ग मीटर में)	वाणिज्यिक भूखंड की दर प्रति वर्ग मीटर	सिंचित कृषि भूमि की दर	300 वर्ग मीटर तक (वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले भूखंड की दर)	शेष क्षेत्र हेक्टेयर में	300 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि की उच्चतम दर *1.5			वार्षिक पट्टा किराया	वार्षिक पट्टा किराया की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(300*कॉलम 9)	12	13= कॉलम 12*1.5* कॉलम 10	14=11+13	15	16	17	18= 0.50*(कॉलम 15 + कॉलम 17)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	0018/ 2021- 22	अमलाई	जैतपुर	शहडोल	02- 12- 2021	2.023	2023 0	900	508000	270000	1.993	1518666	1788666	1341499. 5	6 प्रति वर्ग मीटर	121380	731439.75
2	0023/ 2021- 22	जखारा	जैसिंगनगर	शहडोल	02- 12- 2021	4.046	4046 0	500	277400	150000	4.016	1671057. 6	1821057. 6	1365793. 2	6 प्रति वर्ग मीटर	242760	804276.6
3	0019/ 2021- 22	चंनोदी	जैतपुर	शहडोल	02- 12- 2021	2.023	2023 0	800	456000	240000	1.993	1363212	1603212	1202409	6 प्रति वर्ग मीटर	121380	661894.5
4	0015/ 2019- 20	छतवाई	सोहागपुर	शहडोल	17- 03- 2020	2.428	2428 0	3400	1993800	102000	2.398	7171698. 6	8191698. 6	6143773. 95	बाजार मूल्य का 7.5 %	614377.3 95	3379075.67
5	0010/ 2019- 20	रामसोहरा	जय सिंह नगर	शहडोल	19- 02- 2020	4.046	4046 0	500	312800	150000	4.016	1884307. 2	2034307. 2	1525730. 4	बाजार मूल्य का 7.5 %	152573.0 4	839151.72
6	0009/ 2019- 20	करी	गोहपरू	शहडोल	04- 01- 2020	3.84	3840 0	800	306400	240000	3.81	1751076	1991076	1493307	बाजार मूल्य का 7.5 %	149330.7	821318.85
7	0016/ 2021- 22	खुशार्वाह	जय सिंह नगर	शहडोल	02- 12- 2021	1.214	1214 0	1200	784700	360000	1.184	1393627. 2	1753627. 2	1315220. 4	6 प्रति वर्ग मीटर	72840	694030.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(30 0* कॉलम 9)	12	13= कॉलम 12*1.5* कॉलम 10	14=11+1 3	15	16	17	18= 0.50*(कॉलम 15 + कॉलम 17)
8	0033/ 2019- 20	गन्नाई	सराई	सिंगरौली	02- 06- 2020	4	4000 0	1800	1571200	540000	3.97	9356496	9896496	7422372	बाज़ार मूल्य का 7.5 %	742237.2	4082304.6
9	0012/ 2020- 21	गन्नाई	सराई	सिंगरौली	12- 11- 2020	2	2000 0	1800	1571200	540000	1.97	4642896	5182896	3887172	6 प्रति वर्ग मीटर	120000	2003586
						25.62	कुल							2569727 7.5		2336878. 34	14017077.9
						महायोग											42051233.7

परिशिष्ट-2.2.7

संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.9.2, पृष्ठ क्रमांक 65)

शास्ति लगाने और आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि को खाली न करना/
शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा जारी रखने पर शास्ति की वसूली न करना

(₹ लाख में)

जिला	स.क्र.	तहसील	जांच किये गए प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रकरणों का विवरण जिनमें बेदखली का आदेश जारी किया गया				प्रकरणों का विवरण जिनमें अधिरोपित शास्ति वसूल की गई			प्रकरणों का विवरण जहां अनधिकृत कब्जा जारी रहा			
					प्रकरणों की संख्या	अधिरोपित शास्ति	पटवारी द्वारा प्रस्तुत न किये गए बेदखली प्रतिवेदन (प्रकरणों की संख्या)	पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गए बेदखली प्रतिवेदन (प्रकरणों की संख्या)	पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गए बेदखली प्रतिवेदन (प्रकरणों की संख्या)	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	शास्ति की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
शहडोल	1	सोहागपुर	249	46.944	249	15.79	243	6	39	1.60	243	1279.37	45.898	525.80	
	2	गोहपारू	351	111.915	350	11.35	309	41	188	5.50	309	991.45	100.637	498.67	
	3	बुढ़ार	109	10.672	109	2.99	92	17	32	0.66	92	390.01	8.320	108.81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सिंगरौली	4	सिंगरौली शहरी	19	0.522	19	0.32	19	0	19	0.32	19	309.28	0.522	13.73
	5	देवसर	156	334.51	156	2.24	156	0	1	0.00	156	706.99	334.51	4846.59
	6	सिंगरौली ग्रामीण	19	7.448	19	1.06	19	0	2	0.08	19	62.91	7.448	197.48
धार	7	सरदारपुर	142	32.819	142	3.64	97	45	0	0.00	97	440.99	21.485	121.80
	8	गंधवानी	114	22.358	114	3.75	4	110	112	3.69	4	18.46	0.609	5.32
ग्वालियर	9	कुक्षी	613	5665.291	613	7.12	84	529	611	7.02	84	838.00	346.729	19235.22
	10	डबरा	49	10.03	49	2.02	49	0	0	0.00	49	63.95	10.03	150.33
	11	तानसेन	19	4.365	17	0.46	12	5	4	0.11	12	180.26	2.732	17.45
भोपाल	12	मुरार	53	1.544	53	1.38	53	0	3	0.30	53	152.38	1.544	3088.40
	13	बैरागढ़	7	0.85	7	0.06	7	0	0	0.00	7	119.28	0.853	698.48
	14	बैरसिया	8	0.202	8	0.10	8	0	0	0.00	8	31.38	0.202	36.25
इंदौर	15	टीटी नगर	18	0.681	18	0.01	18	0	0	0.00	18	276.10	0.681	435.18
	16	हुजूर (ग्रामीण)	86	2.744	86	2.88	85	1	0	0.00	85	441.82	2.9347	172.14
	17	एमपी नगर	12	5.242	12	1.79	12	0	0	0.00	12	227.54	5.242	6721.08
इंदौर	18	डॉ. अम्बेडकर नगर	44	13.389	44	1.08	44	0	44	1.08	44	194.88	13.38976	248.06
	19	हातोद	29	21.676	29	0.48	0	29	24	0.48	0	0.00	0	0

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
देवास	20	हाटपिपल्या	120	77.49	120	6.00	3	117	120	6.00	3	7.16	0.0302	0.44
	21	टॉक खुर्द	105	136.194	105	9.01	105	0	105	9.01	105	307.80	136.1943	1921.08
जबलपुर	22	रांझी	21	0.08	21	0.33	21	0	21	0.33	21	23.38	0.0813	0.66
	23	पनागर	28	86.86	24	1.08	22	2	2	0.10	22	104.51	84.65508364	780.10
		कुल	2371	6593.826	2364	74.90	1462	902	1327	36.26	1462	7167.85	1124.72734	39823.07

ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें लगाया गया जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका (कॉलम 6-10) - 1037 प्रकरण I

वसूल नहीं किया गया जुर्माना (कॉलम 7-11) - ₹38.64 लाख

परिशिष्ट-2.2.8
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.10.3, पृष्ठ क्रमांक 68)
राज्य शासन के विभागों को आवंटित शासकीय भूमि का अनुपयोगी रहना

जिला	वर्ष	प्रकरण क्र.	पूर्व आवंटन का विवरण						वर्तमान आवंटन का विवरण				भूमि की अधिकता, यदि कोई हो	क्या अतिरिक्त भूमि का उपयोग पूर्व विभाग द्वारा किया गया या भूमि अप्रयुक्त रही
			विभाग का नाम	आवंटन का वर्ष/ तिथि	सर्वे नं.	आवंटन का क्षेत्रफल	उद्देश्य	विभाग का नाम	आवंटन की तिथि	सर्वे नं.	आवंटन का क्षेत्रफल	उद्देश्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14 (7-12))	(15)
ग्वालियर	2020-21	001/ए(20-3)/2019-20	म.प्र. पर्यटन	2009-10	109, 110, 111	5.686	उल्लेख नहीं	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	07-12-2020	109, 110, 111	5.686	खेल स्टेडियम	निरंक	अप्रयुक्त रही

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 (7-12)	(15)	
म्बालियर	2021-22	007ए (20- 3)/2021- 22	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	30-06-2009	255, 284 से 287, 290 से 291, 293 से 296, 298 से 301, 305 से 311, 314 से 317, एवं अन्य	40	उल्लेख नहीं	आयुक्त, नगर निगम	16-12- 2021	255, 284 से 287, 290 से 291, 293 से 296, 298 से 301, 305 से 311, 314 से 317	14.245	आई.एस.बी.टी.	25.755	अप्रयुक्त रही	
कुल											45.686		19.931	25.755	

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.11.1, पृष्ठ क्रमांक 69)

राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर शासकीय भूमि की हानि

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	मिसल अभिलेख में दर्शाया गया क्षेत्रफल	वर्तमान खसरे के अनुसार क्षेत्रफल	मिसल क्षेत्रफल के सन्दर्भ में कमी	
1	जबलपुर	जबलपुर	जोगीढाना	16	0.45	0.045	0.405	
2	देवास	देवास शहरी	खजुरिया	10	2.78	2.6	0.18	
3	ग्वालियर	मुरार	भंडेरी	448/1	3.67	2.686	0.984	
4				319/1	2.91	2.283	0.627	
5				76/2	2.26	2.247	0.013	
6			लोहारपुर	105	0.42	0.167	0.253	
7				91	0.82	0.157	0.663	
8				तानसेन	किरावली	20	3.19	1.39
9		17	3.2			0.84	2.36	
10		299	0.22			0.09	0.13	
11		271	0.18			0.08	0.1	
12		208	0.04			0.03	0.01	
13		211	0.14			0.02	0.12	
14		सिंगरौली	सिंगरौली ग्रामीण	पतुलखी	271	6.37	5.57	0.8
15					284	5.06	4.66	0.4
16	धार	गंधवानी	दोलाहनुमान	259/1	123.87	121.17	0.962	
				259/2		0.4		
				259/3		0.466		
				259/4		0.763		
				259/5		0.109		
17				1	104.66	104.602	0.058	
18				27/1	105.07	99.375	5.695	
19		सरदारपुर	गुमानपुरा	2034/1949	220.296	216.736	3.56	
20		कुक्षी	डेहरी	1/1	20.2	18.796	1.404	
21				350/1	6.976	6.774	0.202	
22			खनियाअंबा	1	116.75	116.58	0.17	
23		506/1		89.013	86.009	3.004		

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	मिसल अभिलेख में दर्शाया गया क्षेत्रफल	वर्तमान खसरे के अनुसार क्षेत्रफल	मिसल क्षेत्रफल के सन्दर्भ में आधिक्य
1	ग्वालियर	मुरार	भंडेरी	31	4.21	4.4	-0.19
2			भंडेरी	97	2.73	2.853	-0.123
3			भंडेरी	9	0.22	0.23	-0.01
4			भंडेरी	347	0.22	0.23	-0.01
5			भंडेरी	29	0.21	0.219	-0.009
6			भंडेरी	56/2	0.01	0.073	-0.063
7			भंडेरी	152	0.07	0.073	-0.003
8			लोहारपुर	45	0.06	20.324	-20.264
9			लोहारपुर	59	0.09	7.458	-7.368
10			लोहारपुर	27	0.24	1.76	-1.52
11			लोहारपुर	9	0.2	3.26	-3.06
12			लोहारपुर	20	0.24	3.627	-3.387
13		तानसेन	फुसावली	271	4.98	5.205	-0.225
14				238	4.8	5.017	-0.217
15				242	4.8	5.017	-0.217
16				41	4.72	4.944	-0.224
17				44	4.4	4.599	-0.199
18				939	0.44	0.46	-0.02
19				170	0.41	0.428	-0.018
20				किरावली	256	0.2	0.59
21			369		0.4	0.47	-0.07
22			219		0.35	0.39	-0.04
23					141	0.01	0.09
24	भोपाल	हुजूर	मुंगालिया	573	3.17	13.93	-10.76
25			564	3.77	6.31	-2.54	
26			303	0.101	1.19	-1.089	
27			167	0.081	1.77	-1.689	
28	धार	गंधवानी	दोलाहनुमान	260	340.879	341.125	-0.246
29			76/1	57.89	57.672	-0.011	
			76/2		0.229		
30			263	0.209	0.408	-0.199	
31		कुक्षी	डेहरी	383/1	7.595	7.641	-0.046
32				299	1.687	1.731	-0.044
33			खनियाअंबा	2	108.262	108.283	-0.021
34				8	61.738	61.751	-0.013
35				83	55.228	55.238	-0.01

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	मिसल अभिलेख में दर्शाया गया क्षेत्रफल	वर्तमान खसरे के अनुसार क्षेत्रफल	मिसल क्षेत्रफल के सन्दर्भ में आधिक्य
36		कुक्षी	खनियाअंबा	162	0.261	0.263	-0.002
37				506/4	0.219	0.261	-0.042
38				206	0.24	0.261	-0.021
39				418/2	0.052	0.084	-0.032
40	शहडोल	सोहागपुर	लालपुर	2093/4/1	44.126	34.991	-1.09
				2093/1/1/1		0.041	
				2093/1/1/2		0.202	
				2093/1/1/3		0.162	
				2093/1/2		0.809	
				2093/2		0.405	
				2093/3		0.607	
				2093/4/2		1	
				2093/4/3		1	
				2093/4/4		1	
				2093/4/5		1	
				2093/4/6		1	
				2093/4/7		1	
				2093/4/8		2	
41	शहडोल	बुढार	सोनहा	152/1	29.863	31.097	-1.2337
42				162/1/1	3.61	2.217	-0.607
				162/1/2		2	
43	सिंगरौली	सिंगरौली शहरी	झिगुरदह	400/1/1	24.28	23.69	-0.04
				400/2/2		0.551	

परिशिष्ट-2.2.10

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.12.2, पृष्ठ क्रमांक 73)

**जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए और मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल में दर्शाए गए आंकड़ों में अंतर
(31 मार्च 2022 की स्थिति में)**

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

स.क्र.	ज़िला	जिलों द्वारा उपलब्ध कराया गया शासकीय भूमि का क्षेत्रफल			एमपी भूलेख पोर्टल के अनुसार शासकीय भूमि का क्षेत्रफल	अंतर
		(3)	(4)	(5)		
(1)	(2)	शहरी	ग्रामीण	कुल	(6)	7 (5-6)
1	आगर-मालवा	3306.72	73752.63	77059.35	76811.01	248.34
2	बालाघाट	6716.78	376261.59	382978.37	316238.50	66739.87
3	बड़वानी	6269.00	127054.00	133323.00	137946.01	-4623.01
4	भोपाल	33065.36	76370.63	109435.99	95567.98	13868.01
5	छिंदवाड़ा	6514.08	286763.13	293277.21	375316.36	-82039.15
6	डिंडोरी	38.82	76852.18	76891.00	78703.38	-1812.38
7	कटनी	1676.58	6005.91	7682.49	153041.66	-145359.17
8	रतलाम	3276.57	73930.98	77207.55	139891.08	-62683.53
9	उमरिया	7830.14	225942.24	233772.38	233755.91	16.47
10	बुरहानपुर	205.98	9499.33	9705.31	35437.14	-25731.83
11	इंदौर	11690.80	72885.91	84576.71	74397.34	10179.38
12	खरगौन	221.13	13617.32	13838.45	194522.62	-180684.17
13	नरसिंहपुर	6.00	99569.00	99575.00	125428.13	-25853.13
14	पन्ना	12935.59	158192.82	171128.40	149162.62	21965.78
15	श्योपुर	3373.00	486443.00	489816.00	445336.33	44479.67
16	सीधी	271.00	296761.00	297032.00	83306.77	213725.23
17	नीमच	7200.43	144182.58	151383.01	192933.76	-41550.75

परिशिष्ट-2.2.11

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.12.4, पृष्ठ क्रमांक 75)

एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का पालन न करने के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ

परियोजना स्थल का सारांश			
परियोजना का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	सर्वे नं.	स्थान
परियोजना ए (नई कलेक्ट्रेट भवन)	12,500 वर्गमीटर		वर्तमान कलेक्ट्रेट परिसर
परियोजना बी (72 शासकीय आवास इकाइयाँ)	11159 वर्गमीटर		सिविल लाइंस
	सी.एल.पी. का क्षेत्र	सर्वे नं.	स्थान
सीएलपी-1	4,500 वर्गमीटर	110/2	वर्तमान कलेक्ट्रेट परिसर, देवास जूनियर
सीएलपी-2	4,960 वर्गमीटर (413.87+4,546.13 वर्गमीटर)	415/2 440/1/2	शासकीय आवास भूमि, मेढाकी रोड, देवास जूनियर के पास
सी.एल.पी. का कुल क्षेत्रफल	9,460 वर्ग मीटर		

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5, पृष्ठ संख्या 87)

चयनित जिलों, जनपद पंचायत/नगर निगम/पालिका एवं ग्राम पंचायत/वार्ड का विवरण

क्र.सं.	संभाग	जिला	चयनित जनपद पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका का नाम	ग्राम पंचायत /वार्ड
1	भोपाल	भोपाल	जनपद पंचायत, फंदा ग्रामीण	नरोन्हा सांकल
			नगर निगम, भोपाल	वार्ड क्रमांक 42
2	ग्वालियर	ग्वालियर	जनपद पंचायत, घाटीगांव	बरई
			नगर निगम, ग्वालियर	वार्ड क्रमांक 60
3	नर्मदापुरम	होशंगाबाद	जनपद पंचायत, सोहागपुर	शोभापुर
			नगर पालिका, होशंगाबाद	वार्ड क्रमांक 25
4	चंबल	भिंड	जनपद पंचायत, गोहद	बिरखेड़ी
			नगर पालिका, भिण्ड	वार्ड क्रमांक 10
5	इंदौर	इंदौर	जनपद पंचायत, इंदौर ग्रामीण	कलारिया
			नगर निगम, इंदौर	वार्ड क्रमांक 76
6	जबलपुर	जबलपुर	जनपद पंचायत, सिहोरा	फनवानी
			नगर निगम, जबलपुर	वार्ड क्रमांक 78
7	रीवा	सतना	जनपद पंचायत, मैहर	जीतनगर
			नगर निगम, सतना	सतना वार्ड क्रमांक 22
8	सागर	छतरपुर	जनपद पंचायत, छतरपुर/ईशानगर	मोरवा
			नगर पालिका, छतरपुर	वार्ड क्रमांक 8
9	शाहडोल	उमरिया	जनपद पंचायत, मानपुर	चाँदवार
			नगर पालिका, उमरिया	वार्ड क्रमांक 3
10	उज्जैन	देवास	जनपद पंचायत, कन्नौद	नन्सा
			नगर निगम, देवास	वार्ड क्रमांक 7

परिशिष्ट-2.3.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.6.1, पृष्ठ संख्या 89)

अपील प्रकरणों जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने आवेदक को पंजीकरण के लिए पात्र घोषित किया का विवरण

स. क्र.	अपीलीय प्राधिकारी	अपील प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अपील अस्वीकृत/रद्द की गई	प्रकरणों की संख्या जिनमें अपील स्वीकार की गई/विसंगतियां सुधारी गई	अन्य मुद्दों अर्थात मृत्यु के दिनांक में संशोधन आदि की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने अपात्र श्रमिक को पात्र घोषित किया
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड	23	0	23	03	20
2	कलेक्टर, भोपाल	317	0	317	0	317
3	अपर कलेक्टर, छतरपुर	101	31	70	0	70
4	जिला कलेक्टर, देवास	126	0	126	0	126
5	अपर कलेक्टर, ग्वालियर	265	0	265	159	106
6	अपर कलेक्टर, होशंगाबाद	51	16	35	0	35
7	कलेक्टर, इंदौर	286	0	286	0	286
8	कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर	0	0	0	0	0
9	अपर कलेक्टर, सतना	42	1	41	21	20
10	अपर कलेक्टर, उमरिया	109	4	105	0	105
	योग	1,320	52	1,268	183	1,085

परिशिष्ट-2.3.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.6.1, पृष्ठ संख्या 89)

असंगठित श्रमिकों के लंबित भौतिक सत्यापन का विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों के नाम	पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संख्या	श्रमिकों जिनका भौतिक सत्यापन किया गया की संख्या	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित असंगठित श्रमिकों की संख्या
1	जनपद पंचायत, गोहद, भिंड	42,189	41,071	1,118
	नगर पालिका, भिंड	51,708	46,060	5,648
2	नगर पालिका, छतरपुर	33,931	31,497	2,434
	जनपद पंचायत छतरपुर	70,445	64,256	6,189
3	नगर निगम, देवास	51,955	51,935	20
	जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास	60,896	59,752	1,144
4	जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर	41,437	39,799	1,638
	नगर निगम, ग्वालियर	2,20,747	1,45,833	74,914
5	जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद	40,116	39,939	177
	नगर पालिका, होशंगाबाद	22,677	22,341	336
6	जनपद पंचायत, ग्रामीण, इंदौर	58,641	53,362	5,279
	नगर निगम, इंदौर	4,37,234	4,37,234	0
7	नगर निगम, जबलपुर	2,56,544	2,56,197	347
	जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	46,739	46,728	11
8	नगर निगम, सतना	63,065	62,515	550
	जनपद पंचायत, मैहर, सतना	67,788	67,415	373
9	नगर पालिका, उमरिया	3,640	3,506	134
	जनपद पंचायत मानपुर उमरिया	75,844	75,218	626
	योग	16,45,596	15,44,658	1,00,938

परिशिष्ट-2.3.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.2(अ), पृष्ठ संख्या 96)

व्यक्तियों जो मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य नहीं थे के बैंक खातों में किए गए
भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	मृत असंगठित श्रमिक का नाम/श्रमिक आई.डी./ जनपद पंचायत	भुगतान की गई अनुग्रह राशि	अनुग्रह राशि जिसे भुगतान की गयी	समग्र के परिवार डेटा के सत्यापन से पता चला
1.	कलावती / श्रमिक आई.डी. 117790247/ जनपद पंचायत, शाहपुर, बैतूल	2.00	पुनिया	लाभार्थी मृत असंगठित श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
2.	राधा बाई राधेश्याम/ श्रमिक आई.डी. 105382457/ जनपद पंचायत, सेगॉन, खरगौन	2.00	लीलाबाई ख्यालसिंह	लाभार्थी मृत असंगठित श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
3.	वन्दना कोरी/ श्रमिक आई.डी. 104618843 / जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	2.00	संतोष कुमार चौधरी	ई.पी.ओ. पर नवनीत कोरी (मृतक श्रमिक का पति) का उल्लेख था। जबकि, अनुग्रह राशि संतोष कुमार चौधरी के बैंक खाते में जमा की गई थी, जो मृत श्रमिक से संबंधित नहीं है।
4.	ओमप्रकाश गोटिया/ श्रमिक आई.डी. 126484716 जनपद पंचायत, कटनी	2.00	श्यामलाल चौधरी	लाभार्थी मृत असंगठित श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
5.	राम जी कुशवाहा, श्रमिक आई.डी. 134034705 जनपद पंचायत, घनसोर, सिवनी	2.00	मंती बाई उड़के	लाभार्थी मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
6.	महेश धुर्वे श्रमिक आई.डी. 121462902 जनपद पंचायत, छिंदवाड़ा	2.00	मैना चंद्रवंशी	लाभार्थी मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
7.	रामचरण चिड़ार श्रमिक आई.डी. 186586708 जनपद पंचायत, शिवपुरी	2.00	जगदीश कुशवाहा	लाभार्थी मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
योग		14.00		

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.5

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.2 (स), पृष्ठ संख्या 98)

प्रकरणों जिनमें संबल एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दोनों योजनाओं से सहायता राशि का भुगतान किया गया का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का भुगतान का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								दिनांक	दिनांक	
1	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	करण सिंह	190503021	KS2041337	संबल	गोजा बाई	2.00	03.09.2019	10.07.2020	दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु तिथि वाले मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु तिथि 05.08.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 28.11.2020 था) तथा दोनों योजनाओं से लाभ वितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) से सत्यापित किया गया था, हालांकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु डेटा में अभिलिखित नहीं पाया गया। आगे के जांच से पता चला कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दावे में ई.पी.ओ. गुजा बाई (वास्तविक लाभार्थी) का नाम दर्ज करके तैयार किया गया था, लेकिन प्रयुक्त किया गया खाता नंबर किसी

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का भुगतान का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								भुगतान का दिनांक	भुगतान का दिनांक	
2	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	बाहिदा बेगम	180347112	निरंक	संबल	इस्तखार अली	2.00	26.08.2021	27.09.2021	अन्य व्यक्ति श्री अब्दुल मजीद का था, जिसके परिणामस्वरूप कपटपूर्ण भुगतान हुआ। संबल में उत्तराधिकारी इस्तखार अली को भुगतान किया गया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में इस्तखार अली को भुगतान स्वीकृत किया गया, लेकिन भुगतान अन्य व्यक्ति, श्री मोहम्मद अजरुद्दीन अंसारी के खाते में जमा किया गया, जो मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था।
3	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	सोमनाथ कुमार	176167875	SK2027664	संबल	शकुन केवट	2.05	07.08.2020	22.01.2021	दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु तिथि वाले मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 02.04.2020 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 27.09.2020 था) एवं लाभ संवितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) के रेकार्ड से सत्यापित किया गया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग में लिए गए मृत्यु प्रमाणपत्र का विवरण मृत्यु डेटा में नहीं
						शकुन बाई केवट	2.06	15.10.2020	16.10.2020	

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								दिनांक	भुगतान का दिनांक	
4	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	गणेश कुमार रजक	171352966	GR2027655	संबल	गुड्डी बाई	2.05	22.10.2019		दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु के दिनांक वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 30.09.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 28.09.2020 था) तथा लाभ संवितरित किया गया। संबल में भुगतान लाभार्थी गुड्डी बाई को किया गया परन्तु बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में भुगतान अन्य व्यक्ति श्री महमूद खान एवं श्रीमती नज़मा परवीन को किया गया जो मृतक श्रमिक से संबंधित नहीं थे।
								22.01.2021		
								06.10.2020		
								07.10.2020		
5	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	शीला दहिया	169847247	SD2027046	संबल	नरेश कुमार दहिया	2.00	19.09.2019		दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु के दिनांक वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								भुगतान का दिनांक	भुगतान का दिनांक	
					बी.ओ.सी. डब्ल्यू.	नरेश कुमार दहिया	2.06	06.10.2020	07.10.2020	किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 10.06.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 26.09.2020 था) तथा लाभ संवितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) से किया गया, यद्यपि, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग में आए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकार्ड मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। संबल में भुगतान वास्तविक लाभार्थी को किया गया, लेकिन बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में भुगतान सुश्री मुन्नी बेगम को किया गया जो मृत श्रमिक के परिवार की सदस्य नहीं थीं।
6	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	सुनीता कोरी	169711826	SK2030748	संबल	मुकेश कोरी	4.00	06.08.2019	07.11.2019	दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु के दिनांक वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 18.06.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 16.11.2020 था) तथा लाभ संवितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा
					बी.ओ.सी. डब्ल्यू.	अंशुल कोरी	2.06	27.11.2020	30.11.2020	

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								भुगतान का दिनांक		
7	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	नीतू साहू	159362957	NS2023336	संबल	मुन्ना साहू	2.00	24.09.2019		(सांख्यिकीय विभाग) से सत्यापित किया गया। यद्यपि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग में आए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का अभिलेख मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। आगे की जाँच में पता चला कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दावे में लाभ अंशुल कोरी के नाम पर स्वीकृत किया गया था, लेकिन कपटपूर्वक श्री सिराजुद्दीन का बैंक खाता संख्या का उपयोग किया गया जो मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था। दोनों योजनाओं में अलग-अलग दिनांकों वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 15.05.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 16.10.2020 था) तथा लाभ स्वीकृत किया गया। संबल में प्रयुक्त मृत्यु प्रमाणपत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) से सत्यापित किया गया। यद्यपि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में प्रयुक्त मृत्यु प्रमाणपत्र मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। बैंक विवरण से पता चला कि संबल योजना के अंतर्गत किया गया
					बी.ओ.सी. डब्ल्यू.	मुन्ना साहू	2.06	23.10.2020		
								26.10.2020		

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								भुगतान का दिनांक		
8	आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुरैना	मंगल सिंह	172555058	निरंक	संबल	पूनम	4.00	04.06.2018		भुगतान लाभार्थी (मुन्ना साहू) के बैंक खाते में जमा किया गया था। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के अंतर्गत किया गया भुगतान अन्य व्यक्ति (सुश्री शिखा कहार खाता संख्या xxxxxxxx2783 आई.एफ.एस.सी. एम.ए.एच.बी.0001135) के बैंक खाते में जमा किया गया था।
					बी.ओ.सी. डब्ल्यू.	मंगल सिंह	4.00	12.07.2018		संबल योजना में अनुग्रह सहायता पूनम (खाता सं. xxxxxxxxxxxx9288
								11.06.2018		बी.के.आई.डी.0009028) के नाम पर
								12.06.2018		स्वीकृत की गई थी, जबकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना में ई.पी.ओ. मृतक मंगल सिंह के नाम का उपयोग करके तैयार किया गया था एवं सुरजीत सिंह, जो मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था, के बैंक खाते (खाता सं. xxxxxxxx2588 एस.बी.आई.एन.0005782) का उपयोग राशि जमा करने के लिए किया गया था।
9			161391503	JD2053437	संबल		2.00	23.09.2020		

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								भुगतान का दिनांक	भुगतान का दिनांक	
	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना	जसवंत धाकड़			बी.ओ.सी. डब्ल्यू	कंचनिया धाकड़	2.06	15.02.2021	12.06.2021	संबल योजना में अनुग्रह सहायता लाभार्थी सुश्री कंचनिया (खाता सं. xxxxxx1764 सी.बी.आई.एन.0282175) के नाम पर स्वीकृत की गई। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना में ई.पी.ओ. कंचनिया के नाम से तैयार किया गया, लेकिन राशि भेजने के लिए बैंक खाता रवि कुमार धाकड़ (खाता सं. xxxxxx7721, सी.बी.आई.एन. 0280782) नाम के अन्य व्यक्ति का उपयोग किया गया जो मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था।
10	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलन, सतना	रमेश आदिवासी	105016775	RA1924472	संबल	कुसुमकली आदिवासी	4.00	29.08.2019	06.05.2021	संबल एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू.योजना अंतर्गत, प्रत्येक योजना में राशि ₹ 4.00 लाख कुसुमकली आदिवासी के नाम पर स्वीकृत की गई थी। यद्यपि, बैंक खाते के विवरण से पता चला कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के ₹ 4.00 लाख का भुगतान अन्य व्यक्ति श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह को किया गया था, जो मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था।
11			159169226	SP2339326	संबल	कुसुमकली आदिवासी	4.00	25.06.2019	26.09.2019	
					संबल		2.00	12.02.2022		

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								दिनांक	भुगतान का दिनांक	
12	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	संजय पिल्ले	172826207	KR2382071	बी.ओ.सी. डब्ल्यू.	नमिता पिल्ले	2.06	17.05.2022	17.05.2022	संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया।
								14.01.2022	14.01.2022	
								15.01.2022	15.01.2022	
13	सी.एम.ओ., नगर पालिका, होशंगाबाद	कैलाश राव	172826207	KR2382071	संबल	पगरुटकर गीताबाई	2.00	29.07.2021	29.07.2021	संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया।
								23.05.2022	23.05.2022	
								15.12.2021	15.12.2021	
14	आयुक्त, नगर निगम, इंदौर	राहुल मिश्रा	114692376	RM191694 0	संबल	दीपिका मिश्रा	2.05	05.12.2019	05.12.2019	संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया।
								28.09.2021	28.09.2021	
								11.02.2020	11.02.2020	
14	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	उषा शर्मा	172130948	US2041329	संबल	विजय शर्मा	4.05	06.02.2019	06.02.2019	दोनों योजनाओं में अलग-अलग दिनांकों वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों (संबल में मृत्यु दिनांक 03.12.2018 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु दिनांक 07.12.2020) का उपयोग किया गया एवं दोनों योजनाओं में लाभ वितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय
								08.05.2019	08.05.2019	
								21.12.2020	21.12.2020	
							2.06	17.05.2022	17.05.2022	

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
								दिनांक	भुगतान का दिनांक	
15	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	खलिक अंसारी	171392957	KA2303497	संबल	शाहीन	2.00	07.02.2019		विभाग) से सत्यापित किया गया एवं सही पाया गया जबकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दावे में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया।
16	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	मनोज कुमार	170112011	MK192631 6	संबल	सावित्री बाई	2.00	20.04.2019		दोनों योजनाओं में अलग-अलग दिनांकों वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों (संबल में मृत्यु का दिनांक 21.11.2018 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में दिनांक 13.10.2021) का उपयोग किया गया एवं दोनों योजनाओं में लाभ वितरित किया गया।
								03.02.2022		
								09.02.2022		
								03.09.2019		
17	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	राजेंद्र प्रसाद मल्लाह	121489028	RM233931 4	संबल	दीपा मल्लाह	2.00	20.04.2019		संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया।
								22.02.2020		
								24.02.2020		
								19.04.2022		
18			190729929	SK2293235	संबल	दीपा	2.06	17.05.2022		समान लाभार्थी को दिया गया।
								28.10.2021		
								02.11.2021		
							2.05	07.07.2020		

स. क्र.	पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पंजीकृत श्रमिक का नाम	संबल आई.डी.	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	भुगतान राशि	स्वीकृति का दिनांक		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	
								भुगतान का दिनांक	भुगतान का दिनांक		
	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना	सुनीता कुशवाह			श्री निवास कुशवाह	श्री निवास कुशवाह		04.01.2021	24.09.2021	संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया।	
19	आयुक्त नगर पालिका निगम मुरैना	अविनाश वामिक	137583544	निरंक	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. संबल	घनश्याम	2.00	05.07.2018	28.09.2021	संबल में लाभ लाभार्थी श्री घनश्याम को दिया गया जबकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना में लाभ घनश्याम के नाम पर स्वीकृत किया गया परन्तु ई.पी.ओ. में उपयोग किया गया खाता नंबर श्री सोनू माहेश्वरी का था एवं इस खाते में कपटपूर्वक ₹ 2.00 लाख जमा किया गया।	
							संबल राशि कुल	46.25			
							बी.ओ.सी.डब्ल्यू. राशि कुल	42.96			
							कुल योग	89.21			

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.6

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.2(द), पृष्ठ संख्या 98)

प्रकरणों जिनमें संबल लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता का भुगतान किया गया का विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
1	नगर पालिका, भिण्ड	167516496	2,00,000	10.02.2019	20,000	07.10.2019
2		168555027	2,00,000	10.02.2019	20,000	07.10.2019
3		168577984	2,00,000	21.04.2020	20,000	07.10.2019
4		169086239	2,00,000	10.02.2019	20,000	07.10.2019
5		185660223	2,00,000	10.02.2019	20,000	21.06.2019
6		186599661	2,00,000	21.04.2020	20,000	07.10.2019
7		189221817	2,00,000	31.12.2018	20,000	07.10.2019
8		189684692	2,00,000	10.02.2019	20,000	21.06.2019
9		190147956	2,00,000	21.04.2020	20,000	07.10.2019
10		168151938	2,00,000	13.06.2018	20,000	09.01.2019
11		183045353	2,00,000	15.01.2021	20,000	07.10.2019
12		169276343	2,00,000	26.12.2019	20,000	07.10.2019
13	जनपद पंचायत, गोहद, भिंड	190366204	2,00,000	16.05.2019	20,000	21.06.2019
14		186042590	2,00,000	16.05.2019	20,000	31.08.2018
15		133817466	2,00,000	14.08.2019	20,000	26.09.2018
16		140279806	4,00,000	27.10.2021	20,000	15.06.2020
17		142629013	2,00,000	12.04.2021	20,000	06.12.2019
18		149439902	2,00,000	14.01.2021	20,000	25.09.2019
19		163298875	2,00,000	15.01.2020	20,000	15.06.2020
20		165048753	2,00,000	15.07.2020	20,000	22.10.2019
21		140607677	2,00,000	14.06.2019	20,000	29.03.2019
22		168721579	2,00,000	15.01.2020	20,000	22.10.2019
23	जनपद पंचायत, छतरपुर	115750421	2,00,000	13.03.2019	20,000	24.07.2020
24		154805650	2,00,000	13.03.2019	20,000	17.02.2020
25		113078693	2,00,000	13.03.2019	20,000	07.10.2019
26		173538319	2,00,000	07.01.2020	20,000	09.09.2020

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
27		175348706	2,00,000	04.01.2020	20,000	24.07.2020
28		127670642	2,00,000	07.01.2020	20,000	24.07.2020
29		152518925	2,00,000	01.06.2020	20,000	09.09.2020
30		180119522	4,00,000	23.04.2020	20,000	24.07.2020
31		125342034	2,00,000	04.01.2020	20,000	17.02.2020
32		140450572	4,00,000	04.01.2020	20,000	17.02.2020
33		123901664	4,00,000	14.05.2021	20,000	07.10.2019
34		167504257	4,00,000	23.04.2020	20,000	24.07.2020
35		151035195	2,00,000	23.07.2020	20,000	09.09.2020
36		117411997	2,00,000	07.01.2020	20,000	17.02.2020
37	जनपद पंचायत, छतरपुर	149501838	2,00,000	14.05.2021	20,000	07.10.2019
38		118420703	2,00,000	23.07.2020	20,000	17.02.2020
39		153510927	2,00,000	05.08.2020	20,000	09.09.2020
40		134118412	2,00,000	01.07.2020	20,000	24.07.2020
41		180949642	2,00,000	16.12.2019	20,000	06.12.2019
42		166813830	2,00,000	16.12.2019	20,000	05.12.2019
43		138620416	4,00,000	23.04.2020	20,000	24.07.2020
44		113525346	2,00,000	23.04.2020	20,000	24.07.2020
45		131533232	2,00,000	23.04.2020	20,000	24.07.2020
46		148526156	2,00,000	23.12.2020	20,000	17.02.2020
47		123256548	4,00,000	03.08.2018	20,000	09.10.2018
48		147352200	2,00,000	12.06.2018	20,000	01.10.2018
49		155248428	2,00,000	13.08.2018	20,000	01.10.2018
50		134395436	2,00,000	19.09.2018	20,000	01.10.2018
51		168861492	2,00,000	03.05.2019	20,000	01.10.2018
52		125081063	4,00,000	13.03.2019	20,000	09.10.2018
53		166901382	2,00,000	13.03.2019	20,000	05.02.2019
54		153911175	2,00,000	13.08.2019	20,000	09.10.2018
55		166478073	2,00,000	13.08.2019	20,000	05.02.2019
56		175593329	2,00,000	13.03.2019	20,000	03.08.2019

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
57		150200714	2,00,000	18.11.2019	20,000	02.08.2019
58		169781528	2,00,000	16.08.2019	20,000	05.02.2019
59	नगर पालिका, छतरपुर	189721675	2,00,000	04.02.2019	20,000	09.01.2019
60		191047025	2,00,000	07.03.2020	20,000	01.02.2021
61		200154136	2,00,000	12.06.2018	20,000	05.01.2019
62		152994973	2,00,000	12.06.2018	20,000	05.01.2019
63		181671195	2,00,000	17.09.2019	20,000	04.09.2019
64		133269366	4,00,000	17.09.2019	20,000	24.07.2019
65		133332473	4,00,000	17.09.2019	20,000	24.07.2019
66		125450627	2,00,000	17.09.2019	20,000	24.07.2019
67		110248904	2,00,000	17.09.2019	20,000	24.07.2019
68		180834655	2,00,000	04.02.2019	20,000	11.09.2018
69		180368200	2,00,000	16.03.2022	20,000	04.09.2019
70		108843438	2,00,000	04.02.2019	20,000	16.08.2018
71		154877968	2,00,000	22.02.2022	20,000	05.11.2019
72		129671003	2,00,000	17.09.2019	20,000	05.03.2019
73	जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास	109486729	2,00,000	04.09.2019	20,000	27.09.2019
74		100316405	2,00,000	09.12.2019	20,000	17.03.2020
75		100389856	2,00,000	09.12.2019	20,000	17.03.2020
76		119377458	2,00,000	04.09.2019	20,000	25.09.2019
77	जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास	100865490	2,00,000	28.12.2020	20,000	27.09.2019
78		100109723	4,00,000	12.12.2019	20,000	17.03.2020
79		117367007	4,00,000	28.12.2020	20,000	31.12.2018
80	नगर निगम, इंदौर	166961548	4,00,000	18.06.2020	20,000	24.10.2021
81		196665266	2,00,000	07.01.2021	20,000	24.11.2021
82		188008928	2,00,000	18.08.2020	20,000	15.10.2020
83		154571254	2,00,000	02.01.2020	20,000	05.12.2019
84		166855810	2,00,000	23.11.2020	20,000	20.12.2021
85		172790180	2,00,000	24.08.2018	20,000	15.07.2019
86		167995735	2,00,000	02.01.2020	20,000	11.09.2019

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
87	नगर निगम, इंदौर	168700395	2,00,000	01.02.2021	20,000	24.12.2021
88		167403015	2,00,000	05.12.2019	20,000	11.12.2020
89		173286851	2,00,000	28.07.2020	20,000	28.10.2020
90		167114975	2,00,000	09.01.2021	20,000	24.11.2021
91		174206624	2,00,000	07.01.2021	20,000	21.10.2021
92		166799973	4,00,000	21.06.2018	20,000	04.02.2019
93		167130567	4,00,000	03.01.2021	20,000	18.07.2021
94		167793995	2,00,000	22.07.2020	20,000	26.03.2021
95		167747028	2,00,000	03.10.2018	20,000	11.09.2019
96		197340586	2,00,000	22.07.2020	20,000	22.12.2020
97		167971522	2,00,000	02.07.2020	20,000	15.07.2019
98		165924381	2,00,000	30.12.2021	20,000	04.11.2019
99		176134354	2,00,000	09.10.2020	20,000	26.11.2020
100		165614687	2,00,000	01.08.2022	20,000	05.11.2019
101		166840843	2,00,000	13.01.2021	20,000	20.11.2019
102		173187115	2,00,000	15.01.2020	20,000	23.02.2019
103		167476556	2,00,000	13.06.2018	20,000	11.09.2018
104		165777700	2,00,000	15.01.2020	20,000	03.09.2019
105		167192674	2,00,000	11.12.2019	20,000	04.01.2020
106		168288671	2,00,000	22.12.2021	20,000	05.12.2019
107	167845980	2,00,000	09.07.2020	20,000	22.06.2019	
108	168066940	2,00,000	20.07.2020	20,000	22.06.2019	
109	165806634	2,00,000	12.07.2021	20,000	19.08.2021	
110	168015194	2,00,000	19.08.2021	20,000	11.09.2019	
111	192922100	2,00,000	16.11.2019	20,000	04.01.2020	
112	166985575	2,00,000	13.01.2021	20,000	06.12.2019	
113	167174796	2,00,000	03.11.2021	20,000	21.09.2021	
114	167306317	2,00,000	23.10.2019	20,000	19.08.2019	
115	175730006	2,00,000	28.01.2022	20,000	20.12.2021	
116	168621131	2,00,000	12.01.2021	20,000	15.07.2019	

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता		
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक	
117	नगर निगम, इंदौर	174121338	4,00,000	30.09.2020	20,000	20.06.2019	
118		196706545	2,00,000	28.07.2021	20,000	19.08.2019	
119		199510673	2,00,000	09.01.2021	20,000	15.07.2019	
120		168138267	2,00,000	14.08.2020	20,000	20.02.2020	
121		167764991	2,00,000	17.10.2022	20,000	21.10.2021	
122		165679174	2,00,000	23.09.2020	20,000	13.05.2020	
123		167186108	2,00,000	08.11.2021	20,000	26.03.2021	
124		176445148	2,00,000	23.12.2022	20,000	26.03.2021	
125		168955715	2,00,000	28.01.2022	20,000	01.06.2021	
126		166960270	2,00,000	02.01.2020	20,000	04.02.2019	
127		173204640	2,00,000	10.01.2022	20,000	26.03.2021	
128		168212544	2,00,000	22.12.2021	20,000	31.01.2019	
129		168166964	2,00,000	02.01.2020	20,000	31.01.2019	
130		174567740	2,00,000	02.01.2020	20,000	31.01.2019	
131		167811534	2,00,000	03.03.2022	20,000	26.03.2021	
132		174516685	2,00,000	28.01.2022	20,000	06.01.2021	
133		168328653	2,00,000	02.02.2022	20,000	16.02.2021	
134		168328419	2,00,000	02.03.2022	20,000	06.01.2021	
135		199952055	2,00,000	08.11.2021	20,000	07.09.2020	
136		141487469	2,00,000	08.11.2021	20,000	24.08.2020	
137		168612964	2,00,000	08.11.2021	20,000	24.08.2020	
138		199512627	2,00,000	08.11.2021	20,000	15.01.2020	
139		168105606	2,00,000	08.11.2021	20,000	05.12.2019	
140		176761754	2,00,000	10.03.2021	20,000	19.08.2019	
141		जनपद पंचायत इंदौर (ग्रामीण)	200427714	2,00,000	10.02.2019	20,000	27.09.2019
142			169453503	2,00,000	04.09.2018	20,000	21.02.2019
143			101975695	2,00,000	29.04.2019	20,000	27.09.2019
144			169522389	2,00,000	07.06.2018	20,000	01.09.2018
145			118103872	2,00,000	30.07.2018	20,000	06.11.2018
146			119159074	2,00,000	30.07.2018	20,000	06.11.2018

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
147		118187944	2,00,000	15.07.2019	20,000	27.09.2019
148		119284050	2,00,000	24.12.2019	20,000	19.02.2020
149		119287065	2,00,000	15.07.2020	20,000	20.11.2020
150		122587635	2,00,000	16.07.2020	20,000	20.11.2020
151		122696280	2,00,000	10.10.2019	20,000	26.10.2019
152		144356898	2,00,000	06.06.2020	20,000	22.07.2020
153		123211157	2,00,000	05.02.2020	20,000	19.02.2020
154		119991060	4,00,000	01.08.2019	20,000	10.12.2019
155		122518177	2,00,000	25.07.2019	20,000	27.09.2019
156		164543450	2,00,000	11.01.2022	20,000	10.12.2019
157	जनपद पंचायत	100267971	2,00,000	20.12.2021	20,000	27.09.2019
158	इंदौर (ग्रामीण)	100954927	2,00,000	20.12.2021	20,000	27.09.2019
159		122949937	2,00,000	20.12.2021	20,000	27.09.2019
160	जनपद पंचायत,	100307679	2,00,000	21.03.2020	20,000	12.02.2020
161	सिहोरा, जबलपुर	100530545	2,00,000	21.01.2020	20,000	20.12.2019
162		100695001	2,00,000	25.07.2019	20,000	29.09.2018
163		101002724	2,00,000	15.02.2021	20,000	03.06.2020
164		101540938	2,00,000	08.07.2020	20,000	07.08.2020
165		101637674	2,00,000	28.08.2019	20,000	29.06.2019
166		102013115	2,00,000	25.04.2020	20,000	03.06.2020
167		102437040	2,00,000	25.07.2019	20,000	19.11.2019
168		102793629	2,00,000	28.08.2019	20,000	05.07.2019
169		103478357	2,00,000	19.11.2019	20,000	29.06.2019
170		103553644	2,00,000	28.08.2019	20,000	10.11.2019
171		103712762	2,00,000	28.08.2019	20,000	28.08.2019
172		104087301	2,00,000	28.08.2019	20,000	29.06.2019
173		104292257	2,00,000	25.07.2019	20,000	27.02.2019
174		104372347	2,00,000	15.02.2021	20,000	27.02.2019
175		104409200	2,00,000	21.01.2020	20,000	20.02.2020
176		104473952	2,00,000	02.03.2020	20,000	19.11.2019

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
177		104544404	2,00,000	21.01.2020	20,000	19.11.2019
178		104720752	2,00,000	21.01.2020	20,000	19.11.2020
179		105205955	2,00,000	21.01.2020	20,000	03.06.2020
180		105212877	2,00,000	21.01.2020	20,000	27.02.2019
181		105330388	2,00,000	06.08.2019	20,000	29.09.2018
182		105800634	2,00,000	26.02.2020	20,000	28.08.2019
183		105825123	2,00,000	21.01.2020	20,000	12.02.2020
184		106290792	2,00,000	21.01.2020	20,000	10.11.2019
185		106309768	2,00,000	25.04.2020	20,000	03.06.2020
186		106749050	2,00,000	15.02.2021	20,000	27.02.2019
187		107011152	4,00,000	21.01.2020	20,000	12.02.2020
188		107269612	2,00,000	02.03.2020	20,000	28.02.2020
189		107298466	2,00,000	08.07.2020	20,000	08.09.2020
190		107594479	2,00,000	17.09.2020	20,000	08.09.2020
191		107791817	2,00,000	15.02.2021	20,000	29.09.2018
192		107924889	2,00,000	25.07.2019	20,000	29.12.2018
193		108078144	2,00,000	08.07.2020	20,000	07.08.2020
194		108096520	2,00,000	28.08.2019	20,000	13.07.2019
195		109520530	2,00,000	26.02.2020	20,000	12.02.2020
196		109723315	2,00,000	07.03.2019	20,000	04.09.2018
197	जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	109835914	2,00,000	15.02.2021	20,000	27.02.2019
198		110470514	2,00,000	25.02.2020	20,000	28.02.2020
199		110546722	2,00,000	25.07.2019	20,000	13.07.2019
200		110767679	2,00,000	21.01.2020	20,000	29.06.2019
201		111305857	4,00,000	15.02.2021	20,000	12.02.2020
202		111621177	2,00,000	21.05.2019	20,000	27.02.2019
203		111799494	2,00,000	19.11.2019	20,000	19.11.2019
204		112145153	2,00,000	25.02.2020	20,000	28.02.2020
205		113031001	2,00,000	15.02.2021	20,000	20.02.2020
206		113342213	2,00,000	21.01.2020	20,000	20.02.2021

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
207	जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	113896868	2,00,000	21.01.2020	20,000	20.02.2020
208		114040597	2,00,000	15.09.2021	20,000	28.02.2020
209		114342544	2,00,000	21.01.2021	20,000	12.02.2020
210		114775716	2,00,000	28.08.2019	20,000	27.02.2019
211		115302030	4,00,000	15.09.2019	20,000	28.08.2019
212		116453598	2,00,000	25.04.2020	20,000	21.09.2020
213		117774049	2,00,000	25.04.2020	20,000	03.06.2020
214		118354177	2,00,000	21.05.2019	20,000	04.09.2018
215		120301831	2,00,000	02.03.2020	20,000	10.11.2019
216		120819709	2,00,000	02.03.2020	20,000	29.02.2020
217		122089824	4,00,000	08.07.2020	20,000	07.08.2020
218		124625372	2,00,000	02.03.2020	20,000	19.11.2019
219		126695914	2,00,000	02.03.2020	20,000	28.02.2020
220		126899704	2,00,000	02.03.2020	20,000	28.02.2020
221		127412228	2,00,000	25.07.2019	20,000	29.12.2018
222		130171172	4,00,000	28.08.2019	20,000	29.06.2019
223		130886059	2,00,000	31.12.2019	20,000	24.09.2019
224		131191903	2,00,000	19.11.2019	20,000	28.08.2019
225		132391784	2,00,000	21.05.2019	20,000	27.02.2019
226		132921218	2,00,000	28.08.2019	20,000	12.02.2020
227		135303580	2,00,000	21.01.2020	20,000	20.02.2020
228		140528008	2,00,000	26.02.2020	20,000	20.02.2020
229		143276402	2,00,000	21.01.2020	20,000	12.02.2020
230		163545104	2,00,000	30.01.2021	20,000	19.11.2019
231		169213008	2,00,000	21.01.2020	20,000	12.02.2020
232		177628664	2,00,000	21.05.2019	20,000	20.02.2020
233	177729916	2,00,000	01.01.2020	20,000	13.07.2019	
234	177969292	2,00,000	21.01.2020	20,000	12.02.2020	
235	180087293	2,00,000	30.01.2021	20,000	28.08.2019	
236	181202147	2,00,000	17.06.2020	20,000	07.08.2020	

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
237	जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	184992858	2,00,000	28.12.2021	20,000	28.02.2020
238		186143972	2,00,000	15.09.2021	20,000	04.09.2018
239		194027971	2,00,000	27.10.2021	20,000	10.11.2020
240		194146450	2,00,000	30.12.2021	20,000	20.09.2021
241		194755169	2,00,000	19.11.2019	20,000	19.11.2019
242		303303370	2,00,000	25.07.2019	20,000	29.12.2018
243		नगर निगम, जबलपुर	119302958	2,00,000	08.05.2019	20,000
244	128603497		2,00,000	26.02.2020	20,000	26.05.2020
245	129980005		2,00,000	14.08.2018	20,000	05.08.2019
246	131795588		2,00,000	15.06.2021	20,000	04.12.2019
247	136125007		2,00,000	02.03.2019	20,000	02.03.2019
248	137565145		2,00,000	05.11.2018	20,000	02.03.2019
249	140574331		2,00,000	17.10.2018	20,000	14.12.2018
250	156008257		2,00,000	20.05.2019	20,000	04.12.2019
251	156716792		2,00,000	05.11.2018	20,000	02.03.2019
252	168278550		2,00,000	05.03.2019	20,000	17.06.2019
253	169776431		2,00,000	05.06.2021	20,000	05.10.2020
254	169888775		2,00,000	29.06.2019	20,000	17.06.2019
255	170022575		2,00,000	10.09.2018	20,000	04.08.2018
256	170125586		2,00,000	28.06.2021	20,000	26.05.2020
257	170128101		2,00,000	18.08.2021	20,000	10.09.2021
258	170469058		2,00,000	28.12.2018	20,000	02.03.2019
259	170481606		2,00,000	13.06.2018	20,000	25.02.2021
260	170572869		2,00,000	06.11.2019	20,000	02.03.2019
261	171223051		2,00,000	12.10.2021	20,000	27.10.2020
262	171273439		2,00,000	29.12.2021	20,000	01.09.2021
263	171300722		2,00,000	18.08.2021	20,000	25.02.2021
264	171359648		2,00,000	13.06.2018	20,000	02.06.2018
265	171449864		2,00,000	13.06.2018	20,000	02.06.2018
266	172278039		2,00,000	06.11.2019	20,000	05.08.2019

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
267		175600855	2,00,000	02.03.2019	20,000	28.07.2021
268		177681815	2,00,000	29.01.2021	20,000	30.09.2020
269		178708633	2,00,000	23.12.2021	20,000	20.12.2021
270		181218379	2,00,000	29.09.2018	20,000	12.04.2020
271		192178613	2,00,000	28.01.2022	20,000	25.10.2021
272		193423263	2,00,000	06.12.2021	20,000	15.03.2021
273		197843816	2,00,000	15.07.2019	20,000	07.09.2019
274	जनपद पंचायत, मैहर, सतना	101337440	2,00,000	30.12.2021	20,000	23.06.2021
275		101620820	2,00,000	25.03.2021	20,000	04.02.2021
276		103616813	2,00,000	12.01.2021	20,000	05.11.2020
277		104331607	2,00,000	19.11.2020	20,000	05.11.2020
278		104839548	2,00,000	01.12.2021	20,000	04.02.2021
279		105936250	2,00,000	01.12.2021	20,000	03.07.2020
280		107821644	2,00,000	01.04.2022	20,000	05.11.2020
281		114667299	2,00,000	19.08.2021	20,000	19.07.2021
282		115013736	2,00,000	19.08.2021	20,000	31.03.2021
283		115333120	2,00,000	28.08.2020	20,000	07.08.2020
284		116158973	2,00,000	19.06.2020	20,000	03.07.2020
285		117039235	2,00,000	01.12.2021	20,000	08.01.2021
286		118751353	2,00,000	19.08.2021	20,000	09.11.2021
287		120001631	2,00,000	13.10.2021	20,000	09.11.2021
288		121270105	2,00,000	08.01.2019	20,000	04.11.2019
289		122674530	2,00,000	25.03.2021	20,000	08.01.2021
290		123310192	2,00,000	08.06.2022	20,000	23.06.2021
291		123440985	4,00,000	13.10.2021	20,000	09.11.2021
292		124037724	2,00,000	19.08.2021	20,000	19.07.2021
293		126636247	4,00,000	19.08.2021	20,000	07.09.2021
294		127551590	2,00,000	08.06.2022	20,000	04.02.2021
295		128117642	2,00,000	12.10.2021	20,000	07.09.2021
296		128311488	2,00,000	19.08.2021	20,000	07.09.2021

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
297		128744865	2,00,000	09.12.2021	20,000	08.01.2021
298		129255025	2,00,000	09.09.2020	20,000	07.10.2020
299		130375774	2,00,000	19.08.2021	20,000	19.07.2021
300		131208791	2,00,000	19.06.2022	20,000	11.06.2020
301		131732649	2,00,000	19.08.2021	20,000	19.07.2021
302		131822616	2,00,000	12.01.2021	20,000	03.07.2020
303		132528723	2,00,000	19.08.2021	20,000	31.03.2021
304		133408252	2,00,000	29.09.2019	20,000	11.06.2020
305		133644981	2,00,000	29.10.2021	20,000	05.11.2020
306		133761658	2,00,000	25.08.2021	20,000	05.11.2020
307		133999417	2,00,000	08.06.2022	20,000	08.01.2021
308		135252819	2,00,000	13.03.2020	20,000	03.07.2020
309		135627516	2,00,000	25.08.2022	20,000	05.03.2021
310		136128927	2,00,000	01.12.2021	20,000	04.02.2021
311		137164464	2,00,000	19.08.2021	20,000	05.03.2021
312		139540761	4,00,000	08.06.2022	20,000	08.01.2021
313		144051089	2,00,000	19.08.2021	20,000	31.03.2021
314		144860964	2,00,000	13.10.2021	20,000	07.10.2021
315		145233002	2,00,000	30.12.2021	20,000	07.10.2021
316		152605086	2,00,000	18.08.2020	20,000	03.07.2020
317	जनपद पंचायत,	152626641	2,00,000	29.10.2020	20,000	05.11.2020
318	मैहर, सतना	152628293	2,00,000	29.10.2020	20,000	07.10.2020
319		152675687	2,00,000	18.08.2020	20,000	03.07.2020
320		153374109	2,00,000	19.11.2020	20,000	05.11.2020
321		153613941	2,00,000	19.08.2021	20,000	31.08.2021
322		153614077	2,00,000	19.06.2020	20,000	03.07.2020
323		153771817	2,00,000	13.10.2021	20,000	31.08.2021
324		154726699	2,00,000	30.12.2021	20,000	07.10.2021
325		154751842	2,00,000	19.11.2020	20,000	05.11.2020
326		154756594	2,00,000	08.06.2022	20,000	04.02.2021

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
327	जनपद पंचायत, मैहर, सतना	154971230	4,00,000	18.08.2020	20,000	03.07.2020
328		155017005	2,00,000	25.11.2021	20,000	07.10.2020
329		155024961	2,00,000	13.10.2021	20,000	07.10.2021
330		156378389	2,00,000	01.12.2021	20,000	05.11.2020
331		156452366	2,00,000	12.10.2021	20,000	31.03.2021
332		157222433	2,00,000	30.11.2022	20,000	08.01.2021
333		157390347	4,00,000	19.11.2020	20,000	07.08.2020
334		157743305	2,00,000	19.08.2021	20,000	04.02.2021
335		158079083	2,00,000	30.12.2021	20,000	09.11.2021
336		158356184	2,00,000	08.02.2019	20,000	30.08.2018
337		158825537	2,00,000	04.12.2021	20,000	05.11.2020
338		159008819	2,00,000	09.09.2020	20,000	07.08.2020
339		159149894	2,00,000	05.05.2020	20,000	11.06.2020
340		159349761	4,00,000	19.06.2020	20,000	03.07.2020
341		159381853	2,00,000	19.08.2021	20,000	04.02.2021
342		159758601	2,00,000	19.08.2021	20,000	23.06.2021
343		159888068	2,00,000	19.08.2021	20,000	19.07.2021
344		159913368	2,00,000	13.10.2021	20,000	07.10.2021
345		159940571	2,00,000	19.06.2020	20,000	03.07.2020
346		160011727	2,00,000	30.12.2021	20,000	09.11.2021
347		160030989	2,00,000	13.10.2021	20,000	07.09.2021
348		160295562	2,00,000	18.08.2020	20,000	03.07.2020
349		160577736	2,00,000	19.06.2020	20,000	03.07.2020
350		162285365	2,00,000	01.12.2021	20,000	05.11.2020
351		176777881	2,00,000	12.01.2021	20,000	05.11.2020
352		177204246	2,00,000	01.12.2021	20,000	23.06.2021
353		177665452	2,00,000	13.10.2021	20,000	07.10.2021
354		177806981	2,00,000	18.08.2020	20,000	03.07.2020
355		181069949	2,00,000	30.12.2021	20,000	04.02.2021
356		185145553	2,00,000	08.12.2021	20,000	08.01.2021

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	संबल योजना के अंतर्गत सहायता		राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता	
			राशि (₹)	भुगतान दिनांक	राशि (₹)	भुगतान दिनांक
357	जनपद पंचायत, मैहर, सतना	186134225	2,00,000	30.12.2021	20,000	09.11.2021
358		186493860	4,00,000	12.01.2021	20,000	19.07.2021
359		187454970	4,00,000	20.10.2020	20,000	31.08.2021
360		190321053	2,00,000	01.12.2021	20,000	05.11.2020
361		192575550	2,00,000	07.06.2021	20,000	05.03.2021
362		194442140	2,00,000	19.08.2021	20,000	04.02.2021
363		300199241	2,00,000	30.12.2021	20,000	09.11.2021
		योग		7,86,00,000		72,60,000

परिशिष्ट-2.3.7

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.3, पृष्ठ संख्या 100)

प्रकरणों जिनमें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को संबल योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता स्वीकृत की गई का विवरण (राशि ₹)

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालय का नाम	नाम/ श्रमिक आई.डी.	मृत्यु का दिनांक	अनुग्रह राशि	ई.पी.ओ. का दिनांक	संबल योजना में पंजीकरण का दिनांक	आई.जी.एन.ओ.पी .एस. में पंजीकरण का दिनांक	पेंशन के रूप में प्राप्त राशि
1	नगर निगम, इंदौर	मांगीलाल देवड़ा 167278899	09.07.2021	2,00,000	17.11.2021	03.05.2018	29.07.2019	14,400
2		सीताराम जी 169119197	30.05.2021	2,00,000	29.12.2021	14.05.2018	31.07.2020	9,000
3		शेख रशीद 200269469	19.01.2021	2,00,000	08.04.2021	31.07.2018	05.08.2020	14,400
4		रमेश दुरखुरे 173103863	05.04.2019	2,00,000	03.01.2020	29.04.2018	26.02.2019	1,200
5	नगर निगम, जबलपुर	दसई लाल चौधरी 170153684	26.08.2019	2,00,000	25.09.2019	02.05.2018	18.12.2018	5,400
6		आशीष मेश्राम 157102459	12.12.2020	2,00,000	17.02.2021	17.05.2018	27.06.2019	12,600
7		हरप्रसाद जी 161756040	25.09.2019	2,00,000	04.05.2020	03.05.2018	20.08.2019	11,400
8		मंगल प्रसाद 167252524	08.07.2020	2,00,000	30.01.2021	04.05.2018	15.11.2019	12,600

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालय का नाम	नाम/ श्रमिक आई.डी.	मृत्यु का दिनांक	अनुग्रह राशि	ई.पी.ओ. का दिनांक	संबल योजना में पंजीकरण का दिनांक	आई.जी.एन.ओ.पी .एस. में पंजीकरण का दिनांक	पेंशन के रूप में प्राप्त राशि
9	नगर निगम, देवास	नारायण सिंह 143991908	07.04.2021	2,00,000	18.08.2021	23.04.2018	01.08.2019	14,400
10	जनपद पंचायत, कन्नोद, देवास	लक्ष्मी बाई गजानंद 196564636	20.08.2021	2,00,000	10.12.2021	13.05.2018	20.09.2018	14,400
योग								1,09,800

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.8

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.3, पृष्ठ संख्या 100)

प्रकरणों जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृतक का नाम	जन्म दिनांक	मृत्यु दिनांक	अनुग्रह राशि स्वीकृति का दिनांक	राशि (₹ लाख में)	भुगतान का दिनांक
1	जनपद पंचायत, अलीराजपुर	146882507	जगरसिंह	01.01.1958	05.09.2018	29.09.2018	2.00	19.06.2019
2	जनपद पंचायत, पुष्पराज गढ़, अनूपपुर	173575279	सुरती लाल	01.01.1958	09.05.2018	02.08.2018	4.00	15.03.2021
3	जनपद पंचायत, चंदेरी, अशोकनगर	137633547	रत्न कुमार	01.01.1958	17.07.2018	29.08.2018	2.00	07.03.2019
4	जनपद पंचायत, किरनापुर, बालाघाट	141186836	कारूलाल पांचे	01.01.1958	13.08.2018	20.08.2018	2.00	17.06.2019
5	जनपद पंचायत, आठनेर, बैतूल	107487026	संपत धुर्वे	05.01.1958	19.07.2018	14.09.2018	2.00	04.01.2019
6	जनपद पंचायत, रौन, भिंड	120948935	रामबरन	01.01.1958	17.05.2018	06.09.2018	2.00	06.10.2018
7	जनपद पंचायत, सौंसर छिंदवाड़ा	133199654	मीरा भक्ते	01.01.1958	26.05.2018	10.06.2018	2.00	24.09.2018
8	जनपद पंचायत, हरई, छिंदवाड़ा	165331176	विपत	01.01.1958	26.05.2018	10.06.2018	2.00	17.07.2019
9	जनपद पंचायत, तेंदूखेड़ा, दमोह	139028006	जनकरानी सेन	01.01.1958	13.07.2018	06.09.2018	2.00	01.10.2018
10	नगर पालिका, दतिया	129756671	सुरेश यादव	01.01.1958	26.07.2018	29.09.2018	2.00	29.09.2018
11	जनपद पंचायत, कुक्षी धार	106037644	दुर्गाबाई	01.01.1958	25.07.2018	31.08.2018	2.00	09.07.2019
12	जनपद पंचायत, सरदारपुर, धार	145171247	जामसिंह	01.01.1958	05.04.2018	07.06.2018	2.00	06.08.2019
13	जनपद पंचायत, समनापुर, डिंडोरी	162730630	तिजिया जी	01.01.1958	20.07.2018	17.09.2018	2.00	18.03.2019

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृतक का नाम	जन्म दिनांक	मृत्यु दिनांक	अनुग्रह राशि स्वीकृति का दिनांक	राशि (₹ लाख में)	भुगतान का दिनांक
14	जनपद पंचायत, खिरकिया, हरदा	107067190	कमल सिंह	01.01.1958	09.05.2018	08.02.2019	2.00	07.04.2019
15	नगर पालिका, हरदा	145282443	सत्तार खान	01.01.1958	24.05.2018	17.07.2018	2.00	03.08.2018
16	नगर निगम, इंदौर	166494057	सवित्री बाई जी	01.01.1958	16.05.2018	08.06.2018	2.00	13.06.2018
17	जनपद पंचायत, महु, इंदौर	168345997	संतोष बाबू	01.01.1958	26.06.2018	17.09.2018	2.00	22.09.2018
18	नगर निगम, इंदौर	303541359	कैलाश राठौड़	01.01.1958	19.07.2018	03.08.2018	2.00	03.08.2018
19	नगर परिषद, सांवेर, इंदौर	306564235	लालचंद्र मोतीलाल	01.01.1958	29.08.2018	03.10.2018	2.00	26.07.2019
20	जनपद पंचायत, पाटन, जबलपुर	128126435	दशोदा बाई	01.01.1958	26.07.2018	06.09.2018	2.00	17.01.2019
21	नगर निगम, जबलपुर	141075024	फूलचंद केवट	01.01.1958	13.09.2018	01.12.2018	2.00	02.03.2019
22		153691334	श्याम लाल	01.01.1958	24.09.2018	22.12.2018	2.00	21.05.2019
23		154073754	तुलसी राम विश्वकर्मा	01.01.1958	07.07.2018	16.10.2018	2.00	28.12.2018
24	जनपद पंचायत, पनागर, जबलपुर	172141631	रतिराम धोवी	01.01.1958	15.08.2018	06.09.2018	2.00	04.04.2019
25	जनपद पंचायत, खालवा, खंडवा	123964255	नंदराम	01.01.1958	10.08.2018	01.09.2018	2.00	01.02.2019
26	जनपद पंचायत, महेश्वर, खरगोन	112434235	गोविंद	01.01.1958	03.08.2018	31.08.2018	2.00	31.08.2018
27	जनपद पंचायत, बड़वाह, खरगोन	124750798	चतरी बाई रूखड़िया	01.01.1954	02.09.2018	10.01.2019	2.00	13.05.2019
28	जनपद पंचायत, घुघरी, मंडला	135168453	किसनलाल साहो	01.01.1958	07.06.2018	24.07.2018	2.00	20.08.2018
29	जनपद पंचायत, मंदसौर	166507261	कवर लाल	01.01.1958	15.05.2018	13.06.2018	2.00	08.03.2019
30	जनपद पंचायत, सबलगढ़, मुरैना	102301851	रमेश गौड़	01.01.1958	03.09.2018	07.12.2018	2.00	28.03.2019

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृतक का नाम	जन्म दिनांक	मृत्यु दिनांक	अनुग्रह राशि स्वीकृति का दिनांक	राशि (₹ लाख में)	भुगतान का दिनांक
31	जनपद पंचायत, करेली, नरसिंहपुर	103249858	मुन्ना लाल मल्लाह	01.01.1958	02.08.2018	22.09.2018	2.00	24.09.2018
32	जनपद पंचायत, जावद नीमच	130982931	घीसा लाल भील	01.01.1958	14.08.2018	10.02.2019	2.00	10.02.2019
33	जनपद पंचायत, पिपलौदा, रतलाम	101586526	रणछोड़दास बैरागी	13.01.1957	20.07.2018	03.10.2018	2.00	09.01.2019
34	जनपद पंचायत, मालधौन, सागर	122779004	भागीरथ पटेल	01.01.1958	20.08.2018	09.02.2019	2.00	08.08.2019
35	जनपद पंचायत, शाहगढ़, सागर	125187058	नंदी रायकवार	01.01.1958	13.11.2018	02.01.2019	2.00	16.04.2019
36	जनपद पंचायत, बंडा, सागर	157695348	त्रिवेणीबाई अधिया	01.01.1958	03.06.2018	18.12.2018	2.00	31.12.2018
37	जनपद पंचायत, जैसीनगर, सागर	163302806	पन्ना लाल पटेल	01.01.1958	21.07.2018	11.02.2019	2.00	22.03.2019
38	नगर निगम, सतना	134295581	शेखर गौड़	01.01.1958	18.07.2018	05.12.2018	2.00	25.04.2019
39	जनपद पंचायत, कालापीपल, शाजापुर	123375890	प्रेम नारायण	01.01.1958	28.07.2018	17.01.2019	2.00	27.09.2018
40	जनपद पंचायत, विजयपुर, श्योपुर	152901183	चिरौजी जाटव	01.01.1958	09.07.2018	26.09.2018	2.00	17.01.2019
41	जनपद पंचायत, सिहावल, सीधी	135041286	श्री भूषण साकेत	01.01.1958	12.09.2018	22.05.2019	2.00	16.07.2019
योग							84.00	

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.9

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.4, पृष्ठ संख्या 101)

प्रकरणों जिनमें अनुग्रह सहायता का भुगतान अधिक दर पर किया गया का विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
1	जनपद पंचायत, गोहद	जबर सिंह	140279806	19.08.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
2	भिंड	हरिमोहन शर्मा	129117818	14.05.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
3		हरि सिंह	127239982	29.08.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
4	नगर पालिका परिषद, भिण्ड	मंगल राजावत	135515453	04.02.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
5	नगर निगम, भोपाल	जनक दुलारी	152108390	23.07.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
6		राम सिंह फोलवंशी	171571811	17.04.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
7		कमल प्रजापति	161796592	22.05.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
8	जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल	पर्वत सिंह	112809226	13.09.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
9		यशोदाबाई	141424980	13.08.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
10		प्रेम नारायण पथदार	116674506	02.07.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
11	जनपद पंचायत, छतरपुर	श्रीपत पटेल	127049200	26.02.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
12		हरिदास यादव	138951322	17.12.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
13		सुमन राजा	167114665	10.11.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
14		हाकिम सिंह	163384103	23.09.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
15		बबलू अहिरवार	181567924	31.05.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
16		नंदी कुशवाह	125081063	08.07.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
17		स्वामी यादव	115459419	15.09.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
18		पंकज विश्वकर्मा	179165197	16.03.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
19	नगर पालिका, छतरपुर	संजीव झारखड़िया	122683581	30.09.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
20		गिरजा नामदेव	306921063	06.03.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
21		लता कुशवाह	120901335	13.05.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
22	नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद	मुकेश गरेवाल	122320147	16.03.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
23	जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद	गणपत सिंह	113663556	19.05.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
24		आशा बाई	110335377	05.06.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
25	जनपद पंचायत इंदौर	धर्मेंद्र इंदरसिंग	303001247	13.06.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
26		सुरेश सिंह	164971001	03.12.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
27		राहुल किशोर	164575370	24.09.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
28		महेश रतनलाल	138916676	25.09.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
29		गणेश नाथ	126062762	23.12.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
30	नगर निगम, इंदौर	धापू मीना	303981326	15.05.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
31		आरती परमार	302838171	05.06.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
32		मनीष जी	199342797	31.12.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
33		राहुल मेघवाल	197963513	26.08.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
34		संतोष घायताकड़	197323916	11.03.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
35		राजेश चौहान	196912447	26.09.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
36		अनिल कुमार	193409727	07.10.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
37		राजेश	189607901	20.07.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
38		गुलाब बाई	175158098	09.08.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
39		कन्हैया जी	167621536	03.07.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
40		कैलाश जी	167276731	20.03.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
41		राधेश्याम मुराडिया	167130567	04.10.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
42		कैलाश झरने	157298912	27.08.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
43	नगर निगम, जबलपुर	राजेश सेन	127830133	15.02.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
44		संतोष झारिया	138707050	14.07.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
45		मोजी लाल चौधरी	151908630	22.10.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
46		प्रह्लाद	159591741	10.07.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
47		विनोद पासी	161648546	17.12.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
48		जान सिंह	163550817	26.06.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
49		राजू विश्वकर्मा	167969507	01.11.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
50		मुकेश मराकाम	162010448	26.02.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
51		सुनीला कुमार जैन	169592893	08.01.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
52	नगर निगम, जबलपुर	राजेंद्र सिंह परिहार	169670627	06.09.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
53		मोसमीन बानो	171971198	25.08.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
54		अशोक कुमार	176090657	16.06.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
55		भरत लाल गोठिया	182843552	07.02.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
56		मोहम्मद अबरार अंसारी	191527874	27.11.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
57		सुभाष राव कदम	192554749	01.04.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
58		रमेश प्रसाद साहू	169012721	03.07.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
59		जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	सरदार सिंह लोधी	141585176	06.07.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00
60	नन्द लाल दुबे		115200065	02.07.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
61	राहुल गाडरी		115452349	28.09.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
62	सीमा पटेल		107021881	16.08.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
63	अंकित गर्ग		104021259	10.12.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
64	अनिता कोल		112771979	13.02.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
65	सविता विश्वकर्मा		107919359	29.03.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
66		मुकेश बर्मन	194625919	01.04.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
67		गोविंद भूमिया	115302030	22.05.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
68		शीला बाई श्रीवास	105168509	04.09.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
69		इमरत लाल लोधी	107154044	28.07.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
70	जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया	अमरजीत यादव	167030638	23.06.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
71		खुन्नीलाल अगरिया	180944097	05.06.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
72		चन्द्रभान सिंह	144849541	06.04.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
73		राजाराम सिंह	156282261	20.06.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
74		बलराम बैगा	133251798	15.06.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
75		प्रेमलाल जयसवाल	156184089	29.06.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
76		श्यामसुन्दर दुवेदी	125892394	13.09.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
77		ममता सिंह	143053927	09.11.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
78		रामप्रताप पटेल	200510877	22.09.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
79	जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया	शिवकुमार बैगा	119062155	30.12.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
80		शुभम राय	121801527	09.07.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
81		बेदिया चौधरी	154702887	13.08.2018	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
82		ललन गौड़	154709291	06.08.2019	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
83	नगर पालिका, उमरिया	नथू लाल विश्वकर्मा	109605362	05.12.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
84		नीरज बर्मन	120768873	15.12.2021	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
85		दुर्गा चौधरी	112492146	03.06.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
86		हरिनारायण सिंह भदोरिया	124685271	25.01.2020	सामान्य	दुर्घटना	2.00	4.00	2.00
						योग	172.00	344.00	172.00

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.10

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.6, पृष्ठ संख्या 102)

प्रकरणों जिनमें सहायता का दोहरा भुगतान किया गया का विवरण

स. क्र.	यू.एल.बी./ पी.आर.आई. का नाम	श्रमिक का नाम एवं आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारी को किया गया दोहरा भुगतान	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गयी राशि (₹ लाख में)
1	जनपद पंचायत, गोहद, भिंड	सुनील कुमार (150061901)	20.08.2018	पार्वती	xxxxxx4357	सी.बी.आई.एन.0281094	19.06.2019	2.00
2	जनपद पंचायत,	हीरा नाजा (123535168)	11.08.2018	जालूबाई हीरा	xxxxxx4357	सी.बी.आई.एन.0281094	17.07.2019	2.00
3	राजपुर, बड़वानी	लक्ष्मण बाबू (131664397)	25.08.2018	सुमन बाई लक्ष्मण	xxxxxx3613	बी.के.आई.डी.0एन.ए.एम.आर.जी.बी.	15.01.2019	2.00
4		नारिया गुलाब (131016445)	15.05.2018	सुमन बाई लक्ष्मण	xxxxxx3613	बी.के.आई.डी.0एन.ए.एम.आर.जी.बी.	30.01.2019	2.00
5	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	धनराज बचली (163453354)	27.04.2019	सुमन बाई लक्ष्मण	xxxxxx1045	बी.के.आई.डी.0009925	15.01.2019	2.00
				मंजुला बाई	xxxxxx2394	बी.के.आई.डी.0009930	30.01.2019	2.00
				मंजुला बाई	xxxxxx2394	बी.के.आई.डी.0009930	08.08.2018	4.00
				रीता बाचले	xxxxxx1715	यू.बी.आई.एन.0558109	23.10.2018	4.00
				रीता बाचले	xxxxxx1715	यू.बी.आई.एन.0558109	12.01.2022	4.00
							08.04.2022	4.00
				कुल राशि				28.00
				दोहरा भुगतान राशि				14.00

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.11
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.9, पृष्ठ संख्या 105)
प्रकरणों जिनमें श्रमिक की मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया एवं उत्तराधिकारी को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालय का नाम	श्रमिक आई.डी.	नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक	पंजीकरण का दिनांक	मृत्यु दिनांक	लाभ स्वीकृति दिनांक	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	जनपद पंचायत, लहार, भिंड	146990050	सुभवानी त्यागी	29.05.2018	08.06.2018	19.05.2018	09.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
2	नगर पालिका, गोहद, भिंड	159487771	पिटू	12.05.2018	14.05.2018	09.05.2018	09.06.2018	4.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
3	नगर निगम, भोपाल	170692766	अब्दुल फहीम	09.04.2018	08.05.2018	06.04.2018	29.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
4		172046264	नौसाद	07.06.2018	10.06.2018	01.05.2018	29.06.2018	4.00	भुगतान नहीं हुआ
5		171788475	गफ्फर खान	04.04.2018	16.04.2018	01.04.2018	14.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
6		171323985	मनीष	28.05.2018	29.05.2018	27.05.2018	28.06.2018	2.00	भुगतान नहीं हुआ
7		303248443	मोहित श्रीवास्तव	05.06.2018	07.06.2018	08.04.2018	29.06.2018	4.00	भुगतान नहीं हुआ
8	जनपद पंचायत, बमनीघाट, छतरपुर	305653678	मन्नु लाल यादव	04.05.2018	04.06.2018	25.04.2018	07.06.2018	4.00	वसूली की गई
9	जनपद पंचायत, साबूखेड़ी, देवास	103250504	मेहरबान बालकदास	22.05.2018	30.05.2018	19.05.2018	13.07.2018	2.00	वसूली की गई
10	जनपद पंचायत, जमोदी, देवास	111281084	राजेंद्र प्रह्लाद	09.05.2018	18.05.2018	06.05.2018	09.06.2018	2.00	वसूली की गई

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालय का नाम	श्रमिक आई.डी.	नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक	पंजीकरण का दिनांक	मृत्यु दिनांक	लाभ स्वीकृति दिनांक	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
11	नगर परिषद, सोनकच्छ, देवास	167187058	प्रकाश जी	02.06.2018	04.06.2018	13.05.2018	05.06.2018	2.00	वसूली की गई
12	जनपद पंचायत, होशंगाबाद	121485081	गोवर्धन कुमार	07.06.2018	08.06.2018	10.05.2018	07.07.2018	2.00	भुगतान नहीं हुआ
13		129348205	शेख अलीम	15.06.2018	26.06.2018	12.06.2018	07.07.2018	4.00	भुगतान नहीं हुआ
14	जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद	103354579	विनय कुमार भार्गव	09.06.2018	25.06.2018	25.05.2018	30.06.2018	2.00	भुगतान नहीं हुआ
15		101466572	सुमनबाई पुरविया	09.06.2018	25.06.2018	23.05.2018	29.06.2018	2.00	भुगतान नहीं हुआ
16	नगर निगम, इंदौर	168296341	सतीश जी	16.04.2018	28.04.2018	15.04.2018	08.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
17		166233045	योगेश जी	19.04.2018	28.04.2018	04.04.2018	09.06.2018	2.00	भुगतान नहीं हुआ
18		144429226	सुरेंद्र चंदेले	07.06.2018	10.06.2018	30.05.2018	10.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
19		166488718	जगमोहन जी	24.04.2018	27.04.2018	09.04.2018	11.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
20		199851761	राजेश विश्वकर्मा	12.04.2018	02.05.2018	09.04.2018	10.06.2018	4.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
21		168463087	जमना बाई	25.04.2018	28.04.2018	11.04.2018	09.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालय का नाम	श्रमिक आई.डी.	नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक	पंजीकरण का दिनांक	मृत्यु दिनांक	लाभ स्वीकृति दिनांक	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
22	नगर निगम, जबलपुर	305576226	आशीष कुमार यादव	13.04.2018	15.05.2018	07.04.2018	05.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
23		179995608	दरजेश मलिक	28.05.2018	30.05.2018	30.04.2018	05.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
24	नगर परिषद, कटंगी, जबलपुर	145733212	सुरेश नामदेव	08.06.2018	02.07.2018	07.06.2018	03.08.2018	2.00	भुगतान नहीं हुआ
25	जनपद पंचायत, दौलतपुर (जाट), नीमच	101864608	शान्ति लाल धाकड़	22.06.2018	30.06.2018	14.04.2018	02.07.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
26	जनपद पंचायत, कठहा, सतना	118319952	अनिल कोल	08.04.2018	25.05.2018	07.04.2018	10.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
27	जनपद पंचायत, जवारिन, सतना	141517337	तीसमार मवासी	02.04.2018	30.05.2018	01.04.2018	10.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
28	जनपद पंचायत, नौगांव, सतना	103802971	गया प्रसाद सिंह	28.06.2018	01.07.2018	05.05.2018	01.07.2018	2.00	वसूली की गई
29	नगर निगम, सतना	181649437	सीता सिंह	05.05.2018	08.05.2018	22.04.2018	10.06.2018	4.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
30		176463964	अशोक द्विवेदी	05.05.2018	08.05.2018	27.04.2018	10.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
31	नगर पालिका, खाचरौद, उज्जैन	302907965	हुसैना बी	07.06.2018	08.06.2018	05.05.2018	09.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालय का नाम	श्रमिक आई.डी.	नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक	पंजीकरण का दिनांक	मृत्यु दिनांक	लाभ स्वीकृति दिनांक	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
32		137699424	मो एलियाश	21.06.2018	26.06.2018	19.06.2018	28.06.2018	4.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
33		136803080	मुमताज बी	27.06.2018	29.06.2018	21.06.2018	07.07.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
34		100904507	राधेश्याम राठौड़	01.06.2018	04.06.2018	27.04.2018	07.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
35		102302811	कल्लो बी	07.06.2018	08.06.2018	02.04.2018	09.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
36		106207955	आनंदीलाल कांवरिया	30.06.2018	02.07.2018	29.05.2018	03.07.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
37		122400111	केसुराम नायमा	07.06.2018	08.06.2018	23.04.2018	09.06.2018	2.00	भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी
योग								90.00	

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.12
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.10, पृष्ठ संख्या 106)
प्रकरणों जिनमें गलत उत्तराधिकारी को सहायता का भुगतान किया गया का विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृतक श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	राशि (₹ लाख में)	राशि प्राप्तकर्ता		योग्य उत्तराधिकारी		लेखापरीक्षा टिप्पणी
					नाम	मृतक के साथ संबंध	नाम	मृतक के साथ संबंध	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	नगर पालिका, भिण्ड	हुसैन खान	189020940	2.00	शाहिद	पुत्र	सजदा बेगम	पत्नी	मृतक के पुत्र को लाभ दिया गया, जबकि उसकी पत्नी जीवित थी।
2		मुन्नी बानो	170452738	2.00	सादिक खान	पुत्र	शाबुद्दीन खान	पति	समग्र पोर्टल पर पति के जीवित रहते हुए पुत्र को लाभ दिया गया। अन्य तीन बच्चों में से केवल बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को भुगतान की सहमति दी।
3	जनपद पंचायत, गोहद, भिंड	गजेंद्र सिंह	161090248	2.00	सोमता	माता	आशा	पत्नी	मृतक की माँ को लाभ दिया गया, जबकि उनकी पत्नी जीवित थी और उसने अनुग्रह राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
4		अमर सिंह	149579454	2.00	आकाश	पुत्र	मुन्नी	पत्नी	पत्नी के स्थान पर मृतक के पुत्र को लाभ दिया गया।
5		नारायणी देवी	168557267	2.00	राहुल	पुत्र	बलाराम यादव	पति	मृतक के पुत्र को लाभ दिया गया जबकि उसका पति जीवित था तथा उसके द्वारा अनुग्रह राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृतक श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	राशि (₹ लाख में)	राशि प्राप्तकर्ता		योग्य उत्तराधिकारी		लेखापरीक्षा टिप्पणी
					नाम	मृतक के साथ संबंध	नाम	मृतक के साथ संबंध	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	नगर निगम, ग्वालियर	आलोक शुक्ला	186485745	2.00	आयुष शुक्ला	पुत्र	श्री देवी	पत्नी	मृतक की पत्नी सुश्री श्री देवी के स्थान पर छोटे पुत्र को लाभ दिया गया।
7		राकेश	175341253	4.00	राजबेटी	माता	वन्दना, प्रियंका और संजय	पुत्री एवं पुत्र	वन्दना, प्रियंका एवं संजय मृतक श्रमिक के पुत्री एवं पुत्र थे तथा योजना के लाभ हेतु पात्र थे। दावा आवेदन में इनके नाम मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज थे।
8	जनपद पंचायत, छतरपुर	माणिक लाल अहिरवार	125085446	2.00	संजय अहिरवार	पुत्र	कट्टू अहिरवार	पत्नी	पत्नी की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
9	जनपद पंचायत, छतरपुर	भगुंता अहिरवार	131910400	2.00	पूजा अहिरवार	पुत्री	बिनी अहिरवार	पत्नी	पत्नी की सहमति के बिना पुत्री को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
10		सुरेंद्र चौबे	187948075	2.00	बाल्मीक चौबे	पिता	आशीष एवं रौशनी	पुत्र एवं पुत्री	अनुग्रह राशि का भुगतान अनियमित रूप से बच्चों के बजाय पिता को किया गया।
11		रवि अहिरवार	170109128	4.00	मंटू अहिरवार	पिता	नाम नहीं, सीमा अहिरवार	पत्नी, पुत्री	पुत्रियों की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
12		कालीचरण अहिरवार	143910145	2.00	संध्या अहिरवार	पुत्री	रामकुवर बाई अहिरवार	पत्नी	अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान पत्नी की जगह पुत्री को किया गया।

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृतक श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	राशि (₹ लाख में)	राशि प्राप्तकर्ता		योग्य उत्तराधिकारी		लेखापरीक्षा टिप्पणी
					नाम	मृतक के साथ संबंध	नाम	मृतक के साथ संबंध	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	नगर निगम, जबलपुर	अंजूलता बघेल	171270018	2.00	प्रिया बघेल	पुत्री	नरेंद्र बघेल	पति	मृतक के पति की जगह पुत्री को भुगतान किया गया जबकि पुत्री विवाहित थी एवं उसका नाम समग्र आईडी में नहीं था।
14	जनपद पंचायत, मानपुर उमरिया	ननकी बाई बैगा	115597624	2.00	शिव कुमार बैगा	पुत्र	सुंदर बैगा	पति	पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
15		सुकवरिया सिंह	114948235	2.00	ओमप्रकाश सिंह गोंड	पुत्र	तिलकधारी सिंह	पति	पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
16		शंखी बाई	133864763	2.00	माधव सिंह	पुत्र	रमेश सिंह	पति	पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
17		कमली बाई बैगा	130045440	2.00	मेहेलाल बैगा	पुत्र	बाबूलाल बैगा	पति	पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
18	नगर पालिका, उमरिया	अमृतलाल	167337149	2.00	दुर्गा कोल	पुत्र	दुर्गा कोल	पत्नी	पत्नी की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
				40.00	योग				

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.13

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.12(अ), पृष्ठ संख्या 108)

चयनित शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्था वार प्रकरणों जिसमें अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया गया की संख्या दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	पदाभिहित कार्यालयों का नाम	मृत असंगठित श्रमिकों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया गया	देय राशि (₹ लाख में)	लाभ से वंचित लाभार्थियों का प्रतिशत
1	जनपद पंचायत, गोहद, भिंड नगर पालिका, भिंड	261 196	48 77	2.40 3.85	18.39 39.29
2	जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल नगर निगम, भोपाल	421 873	52 292	2.60 14.60	12.35 33.45
3	नगर पालिका, छतरपुर	82	42	2.10	51.22
4	जनपद पंचायत, छतरपुर जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास नगर निगम, देवास	392 504 447	136 176 98	6.80 8.80 4.90	34.69 34.92 21.92
5	जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर नगर निगम, ग्वालियर	530 931	139 534	6.95 26.70	26.23 57.36
6	जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद नगर पालिका, होशंगाबाद	404 136	72 65	3.60 3.25	17.82 47.79
7	नगर निगम, इंदौर जनपद पंचायत, इंदौर (ग्रामीण)	1606 557	626 126	31.30 6.30	38.98 22.62
8	नगर निगम, जबलपुर जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर	2498 621	998 307	49.90 15.35	39.95 49.44
9	जनपद पंचायत, मैहर, सतना नगर निगम, सतना	676 188	297 63	14.85 3.15	43.93 33.51
10	जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया नगर पालिका, उमरिया	757 61	242 8	12.10 0.40	31.97 13.11
	कुल	12,141	4,398	219.90	36.22

परिशिष्ट-2.3.14

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.8.3, पृष्ठ संख्या 114)

चयनित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त, उपयोग किये गए एवं अव्ययित निधि का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्यालयों का नाम	निधि आवंटन का उद्देश्य	संबल योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त निधि	प्राप्त निधि से किया गया कुल व्यय	श्रम आयुक्त को वापस की गई राशि	बैंक खाते में अव्ययित राशि
1	जिला पंचायत, भिण्ड	अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि	92.89	63.69	0.00	29.20
	जनपद पंचायत, गोहद, भिंड	अनुग्रह सहायता	252.00	252.00	0.00	0.00
	नगर पालिका, भिंड	अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि सहायता	149.35	144.15	0.00	5.20
2	जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल	अनुग्रह सहायता	381.20	380.79	0.00	0.41
	नगर निगम, भोपाल	अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि सहायता	1051.50	1043.60	0.00	7.90
	जिला पंचायत, भोपाल	अनुग्रह राशि का भुगतान, संबल कार्ड का मुद्रण, कम्प्यूटर मानदेय, आदि	359.08	342.93	0.00	16.15
3	जिला पंचायत, छतरपुर	अनुग्रह राशि का भुगतान, संबल कार्ड का मुद्रण, कम्प्यूटर मानदेय एवं अन्य जनपद पंचायत से प्राप्त अप्रयुक्त निधि, आदि।	405.25	266.26	0.00	138.99
	नगर पालिका, छतरपुर	अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान	93.00	93.00	0.00	0.00
	जनपद पंचायत, छतरपुर	अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान	185.85	185.85	0.00	0.00
4	नगर निगम, देवास	अंत्येष्टि एवं अनुग्रह निधि	298.00	298.00	0.00	0.00
	जनपद पंचायत, कन्नोद, देवास	अंत्येष्टि एवं अनुग्रह निधि	298.00	272.00	0.00	26.00

स. क्र.	कार्यालयों का नाम	निधि आवंटन का उद्देश्य	संबल योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त निधि	प्राप्त निधि से किया गया कुल व्यय	श्रम आयुक्त को वापस की गई राशि	बैंक खातों में अव्ययित राशि
5	जिला पंचायत, देवास	अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर मुद्रण, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	673.59	562.84	110.75	0.00
	जिला पंचायत, ग्वालियर	अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि	294.12	241.92	0.00	52.20
	जनपद पंचायत, घाटीगांव ग्वालियर	अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि	343.00	332.01	0.00	10.99
	नगर निगम, ग्वालियर	अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि	725.71	722.02	0.00	3.69
6	जिला पंचायत, होशंगाबाद	अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि	356.06	314.18	0.00	41.88
	जनपद पंचायत, सोहागपुर होशंगाबाद	अनुग्रह राशि एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि	249.20	229.00	0.00	20.20
	नगर पालिका, होशंगाबाद	अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि	74.00	74.00	0.00	0.00
7	जिला पंचायत इंदौर	अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड मुद्रण, अंत्येष्टि अग्रिम आदि	697.57	667.13	0.00	30.44
	जनपद पंचायत, इंदौर ग्रामीण	अनुग्रह सहायता	390.38	390.05	0.00	0.33
	नगर निगम, इंदौर	अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता	1228.85	1105.07	0.00	123.78
8	जिला पंचायत, जबलपुर	स्मार्ट कार्ड एवं ब्रोशर प्रिंटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय, कंप्यूटर प्रिंटर एवं स्टेशनरी	72.27	39.16	0.00	33.11
	नगर निगम, जबलपुर	अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता	1798.30	1756.95	0.00	41.35
	जनपद पंचायत, सिहोरा जबलपुर	अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता	265.00	265.00	0.00	0.00

स. क्र.	कार्यालयों का नाम	निधि आवंटन का उद्देश्य	संबल योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त निधि	प्राप्त निधि से किया गया कुल व्यय	श्रम आयुक्त को वापस की गई राशि	बैंक खातों में अव्ययित राशि
9	जिला पंचायत, सतना नगर निगम, सतना	अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता	422.65 148.00	350.73 148.00	71.92 0.00	0.00 0.00
10	जिला पंचायत, उमरिया नगर पालिका, उमरिया जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया	अनुग्रह राशि का भुगतान, संबल कार्ड का मुद्रण आदि अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान	301.29 22.00 431.00	257.78 22.00 430.50	0.00 0.00 0.00	43.51 0.00 0.50
कुल			12,059.11	11,250.61	182.67	625.83

परिशिष्ट-2.3.15(क)
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.9.3, पृष्ठ संख्या 119)
प्रकरणों जिनमें पदाभिहित अधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ से इंकार किया का विवरण

सं. क्र.	मृतक श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	अपात्र घोषित किये जाने के कारण	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1	लक्ष्मी बाई	196162097	15.02.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	मृतका के पति के नाम 1.250 हेक्टेयर भूमि का 1/40 हिस्सा था।
2	बादामी लाल	147936142	13.12.2020	सामान्य	पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी
3	छोटन बाई	104453512	15.04.2019	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	मृतका के पति के नाम पर का 1.88 हेक्टेयर भूमि का 1/6 हिस्सा था।
4	दशरथ सिंह	146447258	29.04.2019	सामान्य	पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी
5	नवीन कुमार मीना	102507962	31.05.2020	दुर्घटना	पिता पेंशनर हैं एवं उनके नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	4.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी। इसके अलावा न तो मृतक और न ही उसकी पत्नी शासकीय सेवक थे।
6	राम सिंह	108893639	16.08.2020	सामान्य	मृतक के नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	संयुक्त खाते में 0.965 हेक्टेयर भूमि मृतक के हिस्से में थी
7	महेंद्र सिंह	118702096	26.01.2019	सामान्य	पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी
8	बसंत कुमार	101246271	13.01.2019	दुर्घटना	पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	4.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी

स. क्र.	मृतक श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	अपात्र घोषित किये जाने के कारण	भुगतान की राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
9	सोनिया अहिरवार	307008452	10.05.2019	सामान्य	ससुर के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतका या उसके पति के नाम पर नहीं थी
10	राजकुमार	110766791	04.12.2020	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	मृतक के नाम पर 1.17 हेक्टेयर भूमि का 1/24 हिस्सा था।
11	राम विलास	130789573	26.05.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	संयुक्त खाते की 1.691 हेक्टेयर भूमि के 6 हिस्सेदार थे।
12	बृजलाल	125650544	17.03.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	मृतक के नाम पर भूमि का हिस्सा 1.70 हेक्टेयर का 1/4 था।
13	पदम सिंह	138269296	13.09.2020	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	मृतक के नाम पर 4.740 हेक्टेयर भूमि का 1/9 हिस्सा था।
14	-जगदीश पुरी	133055249	09.09.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	2.137 हेक्टेयर भूमि के संयुक्त खाते में मृतक पत्नी सहित 6 हिस्सेदार थे।
15	अमर सिंह	106185486	12.04.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	मृतक के नाम पर भूमि का हिस्सा 0.558 हेक्टेयर था
16	सोमेश सिंह	103854276	07.08.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी
17	प्रीतम बाई	130735156	27.04.2021	सामान्य	ससुर के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतका या उसके पति के नाम पर नहीं थी
18	श्रीप्रकाश चतुर्वेदी	104113060	09.11.2021	सामान्य	पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी

स. क्र.	मृतक श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	अपात्र घोषित किये जाने के कारण	भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
19	जितेंद्र	139345571	15.06.2019	सामान्य	पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी
20	सुगंधी बाई	147668588	29.09.2021	सामान्य	संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि	2.00	संयुक्त खाते की 0.591 हेक्टेयर भूमि में मृतका के पति सहित 5 हिस्सेदार थे। शेष 0.610 हेक्टेयर भूमि मृतक अथवा उसके पति के नाम नहीं थी।
योग						44.00	

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

परिशिष्ट-2.3.15(ख)
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.9.3, पृष्ठ क्रमांक 119)
प्रकरणों जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ अस्वीकृत कर दिया का विवरण

स. क्र.	अपील जिसके विरुद्ध किया गया	अपीलकर्ता का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सोहागपुर	प्रेमशंकर बरगोती	धर्मद्व	101395394	15.12.2020	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील निरस्त कर दिया कि मृतक के पिता शासकीय सेवक थे एवं अब वह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
2.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, होशंगाबाद	ज्योति सराठे	केदार सिंह	120800805	20.04.2021	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया।
3.		शाहनाज बी	शेख फिरदौस	165970843	02.01.2021	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील खारिज कर दिया कि संयुक्त खाते में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक था जबकि पटवारी ने प्रमाणित किया कि शेख फिरदौस के हिस्से में 0.2036 हेक्टेयर भूमि था।
4.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, माखन नगर	गोपाल प्रसाद	वन्दना यादव	300282508	07.07.2021	सामान्य	2.00	पटवारी ने प्रमाणित किया कि गोपाल यादव के नाम पर कोई भूमि नहीं था। भूमि उनके पिता के नाम पर थी लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दिया।

स. क्र.	अपील जिसके विरुद्ध किया गया	अपीलकर्ता का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
5.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सोहागपुर	रीता बाई	जितेंद्र	103033606	06.01.2021	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दी।
6.		ब्रिजेश नरें	हरभजन नरें	167431344	25.12.2018	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि संयुक्त खाते में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक थी जबकि पटवारी ने परिवार के 12 सदस्यों के संयुक्त खाते में 1.250 हेक्टेयर भूमि होना सत्यापित किया।
7.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, पिपरिया	दामोदर प्रसाद	मथुरा बाई	116139242	25.03.2019	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया।
8.		भगवानदास यादव	गुल्लो बाई	102238485	16.07.2021	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया।
9.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सिवनी मालवा	अंजू उर्फ अनिता बाई	संजू कुमार	107576435	18.07.2019	सामान्य	2.00	पटवारी ने प्रमाणित किया कि 2.00 हेक्टेयर भूमि मृतक की मां के नाम पर था, परन्तु अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दिया।

स. क्र.	अपील जिसके विरुद्ध किया गया	अपीलकर्ता का नाम	मृत असंगठित श्रमिक का नाम	श्रमिक आई.डी.	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का प्रकार	नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
10.	सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, केसला	शिवकुमार दुबे	अरुण कुमार दुबे	113617884	01.07.2020	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया।
11.	सी.एम.ओ., नगर पालिका परिषद, सिवनी मालवा	सुषमा बाई	नरेश मोरी	111570643	30.04.2021	सामान्य	2.00	अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया।
योग							22.00	

(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)

संक्षिप्तों की शब्दावली

क्रमांक	संक्षिप्त	पूर्ण रूप
प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा		
1.	डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
2.	एफ.आई.आर.	प्रथम सूचना प्रतिवेदन
3.	आई.एफ.एम.आई.एस.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
4.	आई.एफ.एस.सी.	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
5.	एम.पी.एफ.सी.	मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
6.	आर.बी.सी. 6-4	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4
7.	एस.डी.ओ.	अनुविभागीय अधिकारी
8.	एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन निधि
शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा		
9.	ए.डी.एम.	अपर जिला मजिस्ट्रेट
10.	सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
11.	सी.एल.आर.	आयुक्त, भू-अभिलेख
12.	सी.एल.पी.	प्रतिपूरक भू-खण्ड
13.	डी.डी.ए.	देवास विकास प्राधिकरण
14.	के.एम.एल.	कीहोल मार्कअप लेंगवेज़
15.	म.प्र.भू.रा.स.	मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता
16.	एम.पी.एन.बी.एन.एन.	मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश
17.	एम.एस.एम.ई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
18.	पी.एस.	प्रमुख सचिव
19.	आर.आई.	राजस्व निरीक्षक

क्रमांक	संक्षिप्त	पूर्ण रूप
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा		
20.	ए.एल.सी.	सहायक श्रम आयुक्त
21.	बी.ओ.सी.डब्लू.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
22.	सी.एम.ओ.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
23.	डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
24.	डी.एल.ओ.	जिला श्रम अधिकारी
25.	ई.पी.ओ.	इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश
26.	जी.पी.	ग्राम पंचायत
27.	आई.जी.एन.ओ.पी.एस.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
28.	जे.पी.	जनपद पंचायत
29.	के.वाई.सी.	अपने ग्राहक को जानो
30.	एल.सी.	श्रम आयुक्त
31.	एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
32.	एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
33.	एन.एन.	नगर निगम
34.	पी.आर.डी.डी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
35.	पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थान
36.	आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र
37.	यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
38.	यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
39.	जेड.पी.	जिला पंचायत

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi>